छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **पंचम सत्र**

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025

(फाल्गुन 28, शक सम्वत् 1946)

[अंक 15]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025

(फाल्गुन 28, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

फसल उत्पादन एवं परीक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

1. (*क्र. 1171) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनी, फसलों की नई किस्म/हाईब्रिड के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीक, उन्नत कृषि करना/उपकरण/संसाधन संरक्षण, मशीनरी, जल संरक्षण उपकरण आदि की जानकारी हेतु विगत 03 वर्षों में प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां-कहां आयोजित किये गये? आयोजन हेतु कितनी-कितनी राशि का व्यय, किस-किस योजना/मद से किया गया? प्रशिक्षण में कितने किसान/हितग्राही सम्मिलित हुये? प्रशिक्षणवार, प्रशिक्षण का प्रकार, प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वालों की संख्या की वर्षवार जानकारी देवें ? किस-किस प्रशिक्षण पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? योजनावार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : डोंगरगढ़ विधानसभा से संबद्ध विकासखण्ड-राजनांदगांव, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ हैं। प्रश्नाधीन अवधि में इन विकासखण्डों में वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में प्रश्नांकित विषयों से संबंधित कुल 39 प्रशिक्षण आयोजित किये गये, जिसमें 991 कृषक सम्मिलित हुए तथा राशि 2,66,808 का व्यय हुआ। वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार, प्रशिक्षणवार, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण का प्रकार, प्रशिक्षित किसानों की संख्या एवं प्रशिक्षण में किये गये व्यय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र[1] अनुसार है।**

[1] परिशिष्ट "एक"

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से फसल उत्पादन एवं परीक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय राशि के संबंध में प्रश्न किया था। मेरे डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनी, फसलों की नई किस्म/हाईब्रिड के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीक संबंधी ऐसे कई प्रशिक्षण होते हैं जिनकी जानकारी किसानों को दी जाती है, मैंने यह प्रश्न किया था कि विगत 03 वर्षों में कहां-कहां प्रशिक्षण हुआ है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट तौर से जानकारी दी है कि प्रश्नाधीन अवधि में माननीय विधायिका जी के क्षेत्र में इन विकासखण्डों में वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में प्रश्नांकित विषयों से संबंधित कुल 39 प्रशिक्षण आयोजित हुए, जिसमें 991 कृषक सम्मिलित हुए जिसमें 2,66,808 रुपये व्यय हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि डोंगरगढ़ में वर्ष 2021-22 में योजना का नाम सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) के तहत में किसान गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें लगभग 65 कसिान सम्मलिति हुए हैं। उसी तरीके से वहां पर सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाटिंग मटेरियल (आत्मा) योजना कृषक प्रशिक्षण के तहत 50-50, 50-27 इस तरीके से किसान प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं। ऐसे पूरे उदाहरण मैंने माननीय सदस्य का दिया हुआ है। और लगातार हमारे विभाग के माध्यम से किसानों को उन्नत करने की दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से कैसे उनको प्रशिक्षण दिया जाये, इस पर सरकार की मंशा रहती है और सरकार पूरी कोशिश करती है कि हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा सक्षम हों। किसानों को धान खरीदने के लिए माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार है और लगातार धान की बम्पर पैदावार हो रही है और उसकी खरीदी हो रही है, यह उसका परिणाम भी है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2021 से लेकर 2024 तक 39 प्रशिक्षण आयोजित हुए हैं लेकिन आपका जो विभागीय उत्तर आया है उसमें सिर्फ 18 प्रशिक्षण की ही जानकारी है। आप परिशिष्ट-एक में देख सकते हैं। सिर्फ 18 जगह प्रशिक्षण आयोजित हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या बाकी 21 प्रशिक्षण पेपर में ही हुआ है? क्योंकि मैं जहां पर भी अपने विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में जानकारी ले रही हूं वहां प्रशिक्षण हुआ ही नहीं है। यह आपका उत्तर ही गलत है।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछिये न।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि 21 प्रशिक्षण कहां आयोजित किये गये, उसकी जानकारी देवें ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2021-22 का बता रहा था, उसमें 20 प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित हुए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आपने वर्ष 2021 से लेकर 2024 तक कुल 39 प्रशिक्षण आयोजित होना बताया है। उसमें आपने पूरा विस्तार से बताया है।

सभापति महोदय :- आप दो मिनट सुनिये तो। आपने पहले प्रश्न पूछा है, उसका जवाब देने दीजिए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2021-22 में 20 स्थलों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया और उसमें 454 किसान सम्मिलित हुए। उसके बाद 2022-23 में 10 स्थानों पर प्रशिक्षण आयोजित हुआ जिसमें 139 कसिान सम्मलिति हुए। वर्ष 2023-24 में 9 स्थानों पर प्रशिक्षण आयोजित हुआ, जिसमें 398 कृषक उसमें सम्मिलित हुए इस तरीके से पूरे 39 स्थानों पर प्रशिक्षण हुआ है और इसकी जानकारी मैंने आपको दी है, आप एक-बार उसको देखियेगा ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय मंत्री जी, मैंने उसको देखा है । आपका जो उत्तर आया है उसमें परिशिष्ट-एक में फर्म**,** स्कूल और किसान गोष्ठी प्रशिक्षण दिया गया है तो क्या आप यह बतायेंगे यानी आप कृपया एक-एक करके समझा दें कि उक्त प्रशिक्षण में क्या-क्या एवं किस तरह का प्रशिक्षण दिये हैं ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, डोंगरगढ़ के तहत् में डोंगरगढ़ के विकासखण्ड में जो प्रशिक्षण स्थल बारागांवखुर्द है ।

सभापति महोदय :- हर्षिता जी, आप यह चाहती थीं कि कितनी जगह नहीं हुआ है तो उसको मंत्री जी ने बता दिया है । अब आप एक-एक इतना विस्तृत विवरण लेती रहेंगी तो आगे का प्रश्न भी सब प्रभावित होगा । आपका कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो तो पूछ लीजिये ।

श्री केदार कश्यप :- नहीं, मैं बता देता हूं । माननीय सभापति महोदय, मेरे पास पूरी जानकारी है, मैं पूरा बता देता हूं ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है वह उसी का उत्तर दे रहे हैं ।

सभापति महोदय :- इससे संबंधित कोई बात हो तो आप पूछ लीजिये न ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- जी-जी । माननीय सभापति महोदय, मैं उसी से संबंधित पूरक प्रश्न के आधार पर ही बात कर रही हूं । माननीय मंत्री जी ने अभी जो उत्तर दिया उसमें प्रशिक्षण केवल स्कूल फर्म और आपके किसान गोष्ठी के अलावा किसी भी प्रशिक्षण का विवरण नहीं है इसीलिये मैं यह जानकारी चाह रही थी कि उसमें ऐसा क्या प्रशिक्षण दिया गया है ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी बताईए, माननीय सदस्या बोल रही हैं कि यह दो के अलावा और कुछ नहीं हुआ है तो आप बता दीजिये कि क्या हुआ है ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, इसके तहत् हमने कृषक प्रशिक्षण, कृषक खेत पाठशाला, किसान गोष्ठी, फर्म स्कूल इन सब चीजों के घटक के तहत् में हमने प्रशिक्षण दिया हुआ है और इसके तहत् मैंने पूरा विस्तार से इसमें जानकारी दी है ।

सभापति महोदय :- ठीक है ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी । वह आपने परिशिष्ट में दिया है ।

सभापति महोदय :- आप एक आखिरी प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री केदार कश्यप :- यदि आपको किसी विषय को लेकर आपत्ति है तो आप उसकी जानकारी दीजिये ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- जी । माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे दो प्रश्न बचे हुए हैं । मैं आपसे संरक्षण चाहूंगी ।

सभापति महोदय :- नहीं, आप दोनों प्रश्न एक-साथ पूछ लीजिये ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, उपरोक्त प्रशिक्षण में उन्नत कृषि उपकरण संसाधन संरक्षण मशीनरी जल संरक्षण उपकरण हेतु किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया है तो यह कैसे संभव है ? किसान के प्रशिक्षण में यह सारी चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं तो मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि क्या यह प्रशिक्षण हुआ है कि खानार्पूति हुई है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, कोई खानापूर्ति नहीं हुई है । किसानों को उन्नत बनाने की दृष्टि से और अच्छी फसल की दृष्टि से उनको लगातार प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है ।

सभापति महोदय :- ठीक है । श्री बघेल लखेश्वर ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- नहीं हो गया । आप 3-4 प्रश्न पूछ चुकी हैं ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं विस्तार से बता देता हूं ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आप इसमें देखेंगे तो केवल 18 जगहों पर हुआ है और उसमें भी पूरा विवरण नहीं है । किसान मित्र बनाये जाते हैं और किसान मित्र को भी पता नहीं कि कहां प्रशिक्षण हुआ है तो यह कैसे संभव है कि प्रशिक्षण हुआ है । (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- यदि आपको कहीं की जानकारी है ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी बैठिए । आप दोनों बैठिए । हो गया ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि यदि प्रशिक्षण हुआ है तो आवासीय प्रशिक्षण भी हुआ होगा ।

सभापति महोदय :- आप भी अब बैठ जाईए । पूरा जवाब आ गया है । श्री बघेल लखेश्वर ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, पूरा जवाब नहीं आया है । यह अधूरा जवाब है, सीधी सी बात है कि किसानों के साथ x किया जा रहा है क्योंकि वर्ष 2023-24 और अभी वर्ष 2024-25 में कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ है।

सभापति महोदय :- श्री बघेल लखेश्वर ।

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में स्थित आश्रम/छात्रावासों में हुई मौतें

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 2271) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में स्थित किन-किन शासकीय आश्रम/छात्रावासों में विगत् 03 वर्षों में हुई मौतों की जानकारी कारण सहित बतावें? (ख) क्या इन प्रकरणों के लिए विभागीय स्तर अथवा जिला प्रशासन के स्तर पर जांच की गई? जांच का निष्कर्ष क्या आया? संक्षिप्त में बतावें? (ग) क्या इन प्रकरणों में कोई अधिकारी व कर्मचारी का अपने कर्तव्य के प्रति विपरीत आचरण करना पाया गया? यदि हां, तो की गई कार्यवाही बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) स्तर संभागान्तर्गत जिलों में संचालित शासकीय आश्रम/छात्रावासों में विगत् 03 वर्षों में हुई मौतों का कारण सहित जानकारी संलग्न प्रपत्र [2]अनुसार है। (ख) प्रकरणों के लिए विभागीय स्तर अथवा जिला प्रशासन के स्तर कराई गई जांच के निष्कर्ष की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) उक्त प्रकरणों में अपने कर्तव्य के प्रति विपरीत आचरण के दोषी पाये जाने वाले अधिकारी व कर्मचारी पर की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, आपके संरक्षण की जरूरत है। यह मामला बच्चों की मौत का है । छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे छात्रावास आश्रमों में हमारे बेटे-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं । लगातार इनके शासनकाल में लगभग 40 मौतें हुई हैं । मैंने 3 साल की मौत का डाटा मांगा था तो वर्ष 2022-23 में 4 मौत हुई, वर्ष 2023-24 में 4 एवं वर्ष 2024-25 में लगभग 17 मौतों की इन्होंने जानकारी दी है लेकिन इस संबंध में पिछली बार 20 दिसम्बर को अपने वर्षाकालीन सत्र में मैंने पूछा था

[2] परिशिष्ट "दो"

तो उन्होंने 11 मौतों का आंकड़ा दिया था और संशोधित आंकड़ा 14 के बाद उन्होंने दिया, मैंने वेबसाईट से निकाला है तो उसमें से भी जानकारी छोड़ दी है।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछ लीजिए न, जो चाहते हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- नहीं, सर, मैं जानकारी बता रहा हूं।

सभापति महोदय :- जानकारी मंत्री जी बताएंगे न। आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- मंत्री जी, आपसे जानना चाहूंगा कि वर्ष 2024-25 में कितनी मौतें हुई हैं?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पूरी जानकारी दी हुई है और उस जानकारी का माननीय सदस्य अवलोकन करें। वर्ष 2024-25 में दो मौतों की जानकारी है।

श्री बघेल लखेश्वर :- वर्ष 2024-25 में दो ही मौतें हुई हैं? अब ये जानकारी में तो वर्ष 2024-25 में नारायणपुर में एक, बीजापुर में एक, फिर बीजापुर में, फिर बीजापुर में कोंडागांव, कोंडागांव, कोंडागांव फिर कोंडागांव ऐसा करके..।

श्री केदार कश्यप :- कुल मिलाकर 25 मौतें हुई हैं। मैंने वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। जो माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं, उसकी पूरी विस्तृत तौर पर मैंने जानकारी दी हुई है। किन-किन हॉस्टल में, कौन-कौन से जिले में और किन-किन कारणों से हमारे उन विद्यार्थियों की मौत हुई है, उसकी पूरी विस्तृत तौर पर जानकारी दी हुई है। ये जो मैंने कहा कि वर्ष 2024-25 में दो मौत हुई है, वह नहीं, बल्कि उसमें ज्यादा मौतें हुई हैं। मैं उसकी पूरी accurate जानकारी आपको अलग से उपलब्ध कर दूंगा।

श्री बघेल लखेश्वर :- नहीं-नहीं, सर, आपने जानकारी तो उपलब्ध करायी है। वर्ष 2022-23 में कांकेर जिला में एक, बीजापुर जिला में एक, सुकमा जिला में मतलब चार और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव में निरंक है। तो सर वर्ष 2023-24 में आपका कांकेर में एक, बीजापुर में एक, जगदलपुर में एक, कोंडागांव में एक, इस प्रकार वर्ष 2023-24 में चार हैं।

सभापति महोदय :- सुनिए न, आप ये आंकड़े आप मत पढ़िए। वे समझ गए।

श्री बघेल लखेश्वर :- आंकड़े गलत बता रहे हैं। रिकॉर्ड में आना चाहिए।

सभापति महोदय :- मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप प्रश्न पूछ लीजिए न, इसी के बेस पर प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- प्रश्न पूछा हूं, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आंकड़ा बता दे रहा हूं, कम से कम विधान सभा की रिकॉर्ड में आंकड़ा आ जाये।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री बघेल लखेश्वर :- सर, मेरी जानकारी में बीजापुर में फिर से 10 को छिपाया गया है, उसकी जानकारी दिए ही नहीं हैं। मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। संगमपल्ली में 14 जुलाई, 2024 को मलेरिया से

मृत्यु हुई है। उसका नाम देविका जबाब है और वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है। आवासीय आश्रम तारलागुड़ा, बीजापुर में कुमारी जगजीता रेगा की 12 जुलाई में मलेरिया से मौत हुई है। बालिका आवासीय पोटा केबिन में कुमारी विमला कवासी 11 दिसंबर गंभीर रूप से सिकलिन से छात्रावास में ही मौत हुई है। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, क्योंकि मंत्री जी के पास आंकड़ा नहीं है। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं। माता रुकमणी आश्रम धनोरा बीजापुर में शिवानी तेलम की 10 दिसंबर, 2024 को फूड पॉइजनिंग से मृत्यु हुई है। इस संस्था में 35 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई हैं।

सभापति महोदय :- आप इसमें प्रश्न तो पूछिए। मैं यही तो कह रहा हूं।

श्री बघेल लखेश्वर :- सर, जानकारी नहीं मिल रही है। कम से कम हमारी विधान सभा में आ जाये।

सभापति महोदय :- आप जो भी हो, पूछिए न।

श्री बघेल लखेश्वर :- पूछे हैं। उनके पास जानकारी नहीं है। कम बता रहे हैं।

सभापति महोदय :- कुछ प्रश्न पूछिए न कि जानकारी है या नहीं है।

श्री बघेल लखेश्वर :- कम से कम विधान सभा की रिकॉर्ड में आ जाये कि इतने लोगों की मृत्यु हुई है, क्योंकि इनके विभाग के पास जानकारी है ही नहीं।

सभापति महोदय :- वे जवाब दे रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जो जानकारी दी है, उसके तहत में 3 वर्षों में 25 मौतें हुई हैं और मैंने उसकी जानकारी आपको परिशिष्ट में उपलब्ध भी कराया हुआ है और इसके अलावा कोई जानकारी और चाहिए तो वे अलग से उपलब्ध करा देंगे।

श्री बघेल लखेश्वर :- ठीक है, ये जानकारी दीजिए कि 10 मौतें और हुई हैं..।

श्री केदार कश्यप :- कौन सी?

श्री बघेल लखेश्वर :- 10 मौतें और हुई हैं, उसकी जानकारी आपके परिशिष्ट में नहीं है। मुझे यह जानकारी दीजिएगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, गंभीर बात है, माननीय सदस्य ने पूछा है तो गलत जानकारी दे रहे हैं। यह पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है।

सभापति महोदय :- आप बैठिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- 10 मौतें हुई हैं। मैंने प्रश्नकाल में 20 दिसंबर को आया था, उसमें विषय उठाया था और बार-बार गलत जानकारी दे रहे हैं। पिछले बार की जानकारी में आंकड़ा गलत आया।

सभापति महोदय :- बघेल साहब, मंत्री जी को बोलने तो दीजिए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ट्राइबल विभाग की जानकारी चाही है और हमने ट्राइबल विभाग की जानकारी दी है।

श्री बघेल लखेश्वर :- यह भी ट्राइबल विभाग का है। पोटा केबिन कौन चलता है?

श्री केदार कश्यप :- पोटा केबिन एज्यूकेशन के माध्यम से चलाया जाता है। आर.एम.एस.ए. के माध्यम से होता है।

श्री बघेल लखेश्वर :- जी-जी।

सभापति महोदय :- ठीक है, और कुछ पूछना है?

श्री लखेश्वर बघेल :- पिछली बार गोलावंड में मृत्यु हुई थी, उसकी जानकारी आपने इसमें उपलब्ध नहीं कराया है । गोलावंड में कब मृत्यु हुई उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा ? माता रूकमणि संस्था कौन चलाता है क्या यह ट्रायबल के अंदर नहीं आता है ? बालक छात्रावास कोयाबेकूर, सुकमा में ? कन्या आश्रम आवासीय तारलागुड़ा में कौन चलाता है ? 12 जुलाई को मौत हुई, बालिका आश्रम कोरा गादीरास में नवम्बर में मौत हुई, यह कौन चलाता है ?

सभापति महोदय :- बघेल साहब, आप सिर्फ अपनी जानकारी पढ़ रहे हैं, अगर प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ लीजिए ।

श्री लखेश्वर बघेल :- मंत्री जी का कहना है कि उन्होंने ट्रायबल की जी जानकारी दी है । क्या ये आश्रम ट्रायबल में नहीं आते हैं ?

सभापति महोदय :- तो पूछिये ना ।

श्री लखेश्वर बघेल :- पूछ रहा हूं सर । कब-कब हुई यह बता दीजिएगा ?

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ट्रायबल विभाग की जानकारी चाही है और हमने ट्रायबल विभाग की पूरी जानकारी दी है ।

सभापति महोदय :- चलिए ठीक है ।

श्री केदार कश्यप :- यदि माननीय सदस्य को अन्य कोई जानकारी चाही होगी तो उसकी अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आप प्रश्न पूछिये ।

श्री लखेश्वर बघेल :- धनोरा आश्रम ट्रायबल विभाग में नहीं आता है ?

श्री केदार कश्यप :- धनोरा आश्रम, माता रूकमणि आश्रम ..।

श्री लखेश्वर बघेल :- ट्रायबल देखरेख नहीं करता है सर ? अनुदान तो ट्रायबल देता है सर ।

श्री केदार कश्यप :- ट्रायबल विभाग उसको अनुदान देता है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- जी । फिर भी उसके अधीनस्थ आता है । ऐसे बोलेंगे तो कौन चलाता है ?

सभापति महोदय :- देखिए, वे अभी भारसाधक मंत्री के रूप में यहां जवाब दे रहे हैं ।

श्री लखेश्वर बघेल :- कोई भी जवाब दे लेकिन जवाबदारी से दे । ट्रायबल विभाग उनके पास पिछली बार 15 साल तक था ।

सभापति महोदय :- मुझे बोलने तो दीजिए । वे कह रहे हैं कि मैं जानकारी दे रहा हूं अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वे आपको उपलब्ध करा देंगे । श्रीमती भावना बोहरा ।

श्री लखेश्वर बघेल :- नहीं, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है । पिछली बार भी मंत्री जी ने बताया था कि जो जो गलत जानकारी दी है, कार्रवाई करूंगा । मैंने पिछले समय की भी जानकारी निकाली है, 20 दिसम्बर को आपने गलत जानकारी देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करूंगा, यह आपका वक्तव्य है । बता दीजिए आपने अभी तक क्या कार्रवाई की ?

सभापति महोदय :- बता दीजिए ।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का पूरा उत्तर मैंने दिया है । यदि किसी अधिकारी पर कार्रवाई की बात है तो उसके लिए अलग से करें तो कर देंगे ।

श्री लखेश्वर बघेल :- जिसने गलत जानकारी दी है ।

श्री केदार कश्यप :- गलत जानकारी किसने दी है ?

श्री लखेश्वर बघेल :- बिल्कुल गलत जानकारी दी है । मैं लिखकर दूंगा अगर किसी ने गलत जानकारी दी है तो कार्रवाई करेंगे क्या ?

सभापति महोदय :- अगर कोई तथ्य आपके पास हो, आप लिखकर मंत्री जी को दे दीजिए, उस पर वो दिखवा लेंगे ।

श्री लखेश्वर बघेल :- दिखवा लेंगे नहीं साहब । गलत जानकारी देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे क्या ? अगर कार्रवाई करेंगे तो कबूल करियेगा ?

सभापति महोदय :- आप इनकी चिट्ठी लेकर दिखवा लेंगे ।

श्री लखेश्वर बघेल :- दिखवाने से काम नहीं चलेगा साहब । यह गंभीर मामला है, छात्रावास, आश्रम में अभी तक पचासों मौत हुई हैं, मैंने पिछली बार भी बोला था। यह विभाग आदिवासियों के प्रति गंभीर नहीं है । आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री उसके बाद भी गंभीर नहीं है तो ;;।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, माननीय यदि भाषण दे रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा इनकी सरकार थी, आपकी सरकार थी और जगरगुंडा में चावल कौन खाया था ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- कोई भी सही जवाब नहीं दे पाते हैं ।

श्री केदार कश्यप :- आप लोग हमारे बच्चों का चावल खा गए, सभापति महोदय हम लोगों को धरना देना पड़ा ।

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई)

समय
11.19 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

कबीरधाम जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति के खेतों में ट्यूबवेल खनन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

3. (*क्र. 2311) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021 से 2024 तक में कबीरधाम जिले में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा हितग्राहियों के खेतों को ट्यूबवेल खनन कार्य हेतु चयनित किया गया था तथा ट्यूबवेल खुदाई कर पंप प्रतिस्थापन किया गया? (ख) क्या इस ट्यूबवेल खनन कार्य में अनियमितता होने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो अनियमितता से संबंधित अधिकारी / कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2021 से 2024 तक विभाग द्वारा कबीरधाम जिले में विशेष पिछड़ी जन-जाति बैगा हितग्राहियों के खेतों को नलकूप खनन हेतु चयनित नहीं किया गया है, अतः नलकूप खनन कर पम्प प्रतिस्थापन की जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश ‘‘क‘‘ के परिपेक्ष्य में प्रश्नाधीन अवधि में नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिस्थापन कार्य में अनियमितता होने संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, प्रश्न को लेकर कल से असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है और पता नहीं क्यों हो रहा है, इंटेशनली, कल भी मैंने वही सवाल पहले किया था और भी मैं वही सवाल पहले कर रही हूं । प्रश्न जो लगाया गया था, उस मूल प्रश्न को बदलकर फिर से जिस सन् से जानकारी मांगी गई थी, वर्ष 2021 से 2024 की जानकारी दी गई है। मैंने आदिवासी बैगा क्षेत्र के खेतों में ट्यूबवेल नलकूप खनन के विषय में जानकारी मांगी गई थी, मुझे वापस वर्ष 2021 से 2024 की जानकारी मिली है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम गलत प्रश्न कर रहे हैं या विभाग वर्ष बदलकर जानकारी नहीं देना चाह रहा है, क्या कारण है ? क्योंकि मेरा प्रश्न का उद्देश्य सिर्फ यही था कि वहां जो आदिवासी बैगा बाहुल्य क्षेत्र है, वहां के जो कृषक हैं, उनको खेती के लिए पानी मिल जाए। लेकिन

जिस तरीके से प्रश्न परिवर्तित कर दिया जाता है, पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि इसका कारण क्या है ? इसमें वर्ष का बदलाव किया गया है, वर्ष 2019 से 2024 तक की जानकारी मांगी गई थी, वर्ष 2019 की जानकारी हटा करके वर्ष 2021 से 2024 तक की जानकारी दी गई है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, आपने प्रश्न वर्ष 2021 से 2024 के बीच का लगाया है। हमने उसकी पूरी जानकारी दी है। उस अवधि में कोई भी नलकूप खनन या पंप स्थापन की कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, मेरे प्रश्न प्रश्न की कॉपी है, जो प्रश्न मैंने लगाया था।

सभापति महोदय :- भावना जी, आपने 6 वर्ष की व्यापक जानकारी मांगी थी जिसे नियमों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर आ सके, इस हेतु इसकी अवधि सचिवालय से कम की गई है।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, इसके पहले भी कई बार ये देखा गया है कि....।

सभापति महोदय :- उसके लिए मंत्री स्वयं जवाब नहीं दे पाएंगे, मैंने आपको बता दिया अब आप आगे प्रश्न पूछिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, हालांकि मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि उनको कृषि के लिए खेत में पानी मिल सके। मैं इसमें अपनी बातें जरूर रखना चाहूंगी, मंत्री जी, आगे जो उचित उत्तर समझे या कार्रवाई हो, मैं उनके उपर छोड़ती हूं। मैं पहले ये जानकारी चाहूंगी कि क्या अभी हमारे पास ऐसा कोई प्लान है कि बैगा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कृषि के लिए बोरवेल खनन का प्रावधान रखा है ? इसके बाद मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछूंगी।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी थी, मैंने उसका ही उत्तर दिया है। वहां पर विशेष पिछड़ी जनजाति के भाईयों के लिए पी.एम जन मन योजना के तहत् बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, उस योजना के तहत् उन विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान की दृष्टि से, उनके विकास की दृष्टि से चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हम अधोसंरचना के निर्माण में लगातार काम करते हैं और योजना बनाकर काम करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि उन वर्गों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा का लाभ दिया जाए। हम उसमें योजना बनाकर काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य की विशेष तौर पर किसी गांव या किसी क्षेत्र की बात है तो उसके संबंध में अवगत करायेंगे तो उसमें अलग से योजना बनायेंगे।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, यह चिंता का विषय भी था और इसमें आगे प्रावधान भी चाह रही थी, वर्ष 2019 के बाद वहां पर एक भी ट्यूबवेल खनन नहीं हुआ है, हमको पी.एम जन मन योजना के तहत् जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, वहां कितना सेंक्शन होना है, अगर वह जानकारी मिल जाए तो ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि वे कृषि पर ही निर्भर हैं, आप सब जानते हैं कि आदिवासी

वनांचल क्षेत्र है। मैं दूसरा विषय माननीय मंत्री जी के संज्ञान में जरूर लाना चाहूंगी, वर्ष 2019 में बैगा आदिवासी क्षेत्र में जो नलकूप खनन का काम हुआ था, वहां 93 नलकूप खनन स्वीकृत हुआ था, 93 नलकूप खनन में बहुत ज्यादा धांधली हुई है, अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो मैं उसकी सारी रिपोर्ट उपलब्ध करा दूंगी, मेरे पास जानकारी है, उसमें स्थिति ये थी कि जिस कंपनी को डॉयरेक्ट बोर खनन का टेंडर मिला था, उनके खाते में 94 हजार रूपए प्रति नलकूप खनन के हिसाब से भुगतान किया गया, उस समय के जो तत्कालीन अधिकारी थे, उनकी और कंपनी की मिलीभगत थी, जी.आई. पाईप की जगह प्लास्टिक पाईप का इस्तेमाल किया गया था।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछ लीजिए न।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगी कि वहां पर गड़बड़ी हुई है, मेरे पास पूरी जानकारी है, एक बार उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, जांच का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को दंडित किया जाए, जांच का उद्देश्य ये है कि जो बैगा आदिवासी क्षेत्र है, अगर उनके लिए कोई योजनाएं आती हैं तो बीच में जो गड़बड़ियां की गई है, उसके लिए लोगों को सबक मिले, इसलिए मैं चाह रही हूं कि इसमें आगे उचित कार्रवाई हो, मंत्री जी उसमें अपना संज्ञान जरूर लें।

सभापति महोदय :- मंत्री जी बताईए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, वह आप अलग से उपलब्ध करा दीजिए, हम उसको दिखवा लेंगे। बैगा समाज के लिए विकास के काम ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सके, इस पर सरकार की भी मंशा है, सरकार की इच्छा है कि उन क्षेत्रों में विकास हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की जन मन योजना हो, चाहे राज्य सरकार के माध्यम से हो, हम उन योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करेंगे।

सभापति महोदय :- ठीक है। श्रीमती शकुंतला पोर्ते।

श्रीमती भावना बोहरा :- धन्यवाद।

जिला बलरामपुर अंतर्गत विवाहों का पंजीयन

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

4. (*क्र. 1787) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 अंतर्गत विवाह पंजीयन के लिए अनिवार्य प्रपत्र कौन कौन से हैं? **(ख)** जिला बलरामपुर में वर्ष 2020-21 से 10.2.2025 तक प्रति वर्ष कितने विवाहों का पंजीयन किया गया? विकासखण्डवार सूची प्रदान करें? **(ग)** शत-प्रतिशत विवाह पंजीयन हो इस हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जानकारी प्रदान करें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रदेश में छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 अंतर्गत विवाह पंजीयन के लिए अनिवार्य प्रपत्र की सूची निम्नलिखित है :- (1) आवेदन पत्र, (2) वर-वधु का शपथ पत्र, (3) जन्म प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र, (4) निवास प्रमाण पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) जाति प्रमाण पत्र, (7) ज्वाईंट फोटो पासपोर्ट साईज, (8) गवाहों का आधार कार्ड एवं (9) विवाह अनुष्ठान सम्पन्न कराने वाले के सत्यापन के लिए तत समय उपस्थिति पंडित/पादरी/मौलवी/समाज का प्रमाण पत्र। **(ख)** जिला बलरामपुर में कार्यालय अपर कलेक्टर में 59, नगरीय निकाय में 137 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 13 कुल 209 विवाहों का पंजीयन वर्ष 2020-21 से 10.02.2025 तक हुआ है। विवाह पंजीयन की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[3] अनुसार है। **(ग)** शत प्रतिशत विवाह पंजीयन हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जिला स्तर पर सभी विकास खण्डों में एवं जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविरों में पोस्टर, पम्पलेट एवं ग्रामों में दीवाल लेखन के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- धन्यवाद, सभापति महोदय। मेरा प्रश्न महिलाओं के हितों से संबंधित है। मैं वित्त मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहती हूं कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 अंतर्गत विवाह पंजीयन के लिए अनिवार्य प्रपत्र कौन-कौन से हैं?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, जो छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 है, उसके अनुसार यदि पंजीयन के लिए कोई भी जाता है तो अनिवार्य रूप से जो प्रपत्र आवश्यक हैं, वह आवेदन पत्र, वर-वधु का शपथ पत्र, जन्म प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण प्रत्र, ज्वाइंट फोटो पासपोर्ट साइज, गवाहों का आधार कार्ड एवं विवाह अनुष्ठान संपन्न कराने वाले के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज जरूरी होते हैं। इसमें ये प्रावधान इसलिए किये गये हैं ताकि कोई व्यक्ति बहु विवाह की ओर बिना अपनी पूर्व पत्नी की जानकारी के न बढ़ सके। इस तरह की स्थितियों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ये प्रावधान किये गये हैं।

सभापति महोदय :- क्या आपको और कुछ पूछना है ?

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय सभापति महोदय, जिला बलरामपुर में वर्ष 2020-2021 से दिनांक 10.02.2025 तक प्रतिवर्ष कितने विवाहों का पंजीयन किया गया है ? मैरिज सर्टीफिकेट एक कानूनी दस्तावेज है, जो शादी की वैधता को प्रमाणित करता है।

सभापति महोदय :- शकुंतला जी, इस प्रश्नोत्तरी में आपके पूरे प्रश्न का लिखित में उत्तर है। जितना मंत्री ने बताया है, वह भी लिखा हुआ है, कितनी शादी हुई, वह भी लिखा हुआ है तो यदि आपको कोई और समस्या हो तो आप उनसे प्रश्न पूछ लीजिए।

---

[3] परिशिष्ट ''तीन''

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- जी, सभापति महोदय। शत-प्रतिशत विवाह पंजीयन हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? क्योंकि जहां तक मुझे ज्ञात है कि अभी भी इसकी पर्याप्त जागरूकता का अभाव है। जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस विषय में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। अभी तक मैं हर कार्यक्रम उपस्थित रहती हूं, लेकिन जागरूकता के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है तो मैं चाहती हूं कि महिलाओं के हित से संबंधित विवाह पंजीयन जरूरी है और इसके लिए इसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार होना चाहिए। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस दिशा में माननीय मंत्री जी के द्वारा और क्या प्रयास किये जाएंगे ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बता दीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, जो विवाह पंजीयन का नोडल डिपार्टमेंट है, उसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा और एक बड़ा ही मल्टी डिपार्टमेन्टल टाइप का situation create हो गया है। माननीय सदस्या ने यह प्रश्न पूछा है और उसके माध्यम से सदन में यह विषय उठा है तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि जन्म और मृत्यु का जो पंजीयन होता है, वह तो योजना एवं सांख्यिकी विभाग के माध्यम से किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में उसका नोडल डिपार्टमेंट अर्बन डिपार्टमेन्ट होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में उसका नोडल डिपार्टमेंट ग्राम पंचायत होता है, लेकिन विवाह के लिए अभी गवर्नमेन्ट में जो नोडल डिपार्टमेन्ट है, वह unexpected ढंग से विधि-विधायी विभाग बना हुआ है। विधि-विधायी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत विभाग के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय विभाग के माध्यम से जानकारी collect करता है। उसमें भी ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा नगरीय क्षेत्रों में तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है तो इसको हम लोग डिपार्टमेन्टवाइज सबसे पहले स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास करेंगे। जन्म-मृत्यु का पंजीयन योजना एवं सांख्यिकी विभाग कर रहा है और उसकी बराबर मॉनिटरिंग होती है और सारी चीजें होती हैं, लेकिन विवाह पंजीयन में चूंकि विधि-विधायी विभाग, अर्बन डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट एक खिचड़ी सा बन गया है तो उस दिशा में भी हम शासन की ओर से उचित कदम उठायेंगे ताकि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और पंजीयन के लिए जिस तरह से प्रयास होते हैं, एक ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है, उस तरह से विवाह के संबंध में भी सिस्टम डेव्हलप हो सके और उसमें हम जागरूकता लाने के लिए भी प्रयास करेंगे।

सभापति महोदय :- ठीक है। श्री किरण देव जी। नहीं हैं।

प्रश्न संख्या : 5 XX XX

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के नेशनल गेम्स के आयोजन हेतु राज्य को प्राप्त मेजबानी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

6. (*क्र. 2019) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के नेशनल गेम्स के आयोजन की मेजबानी करने के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को अधिकृत किया गया था? यदि हां, तो क्या नेशनल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ? यदि नहीं तो क्यों? कारण बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हाँ। जी नहीं। राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन किये जाने हेतु दिनांक 17.12.2024 से 21.12.2024 तक प्रस्तावित किया गया था, किन्तु राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा राज्य द्वारा प्रस्तावित तिथि के स्थान पर दिनांक 15.12.2024 से 19.12.2024 तक आयोजन हेतु अनुरोध किया गया। तद्नुसार आयोजन की तिथि 15.12.2024 से 19.12.2024 तक निर्धारित की गई है। उक्त तिथि में प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित होने तथा विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रतिभागियों के संख्या की जानकारी नहीं मिलने के कारण भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति को तिथि आगे बढ़ाने हेतु प्रस्तावित किया गया था, जिसके अनुक्रम में भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.12.2024 द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन को निरस्त करने की सूचना दी गई।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक समिति द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किये जाने हेतु दिनांक 17.12.204 से 21.12.2024 तक की तिथि प्रस्तावित की गई थी, किन्तु राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा राज्य द्वारा प्रस्तावित तिथि के स्थान पर दिनांक 15.12.2024 से 19.12.2024 तक आयोजन हेतु अनुरोध किया गया। इसके बाद दिनांक 15.12.2024 से 19.12.2024 निर्धारित करने के लिए विभाग ने अनुरोध किया तरे यह 4 दिवस का अंतर क्यों है ? आयोजन ही नहीं हुआ। नई दिल्ली ने नई खेल तिथि निर्धारित कर दिया है क्या?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के नेशनल गेम्स का आयोजन करने के लिए राज्य को मेजबानी मिली थी, उसकी एक तिथि थी, जो दिनांक 17.12.2024 से प्रस्तावित था। उसी मध्य विधान सभा सत्र आहुत होने की तिथि थी। अन्य कारण भी थे, अन्य राज्यों से छात्र आने वाले थे, उनको भी समय नहीं मिल पा रहा था। उसके कारण पूरे आयोजन को निरस्त किया गया। आने वाले समय में इस आयोजन को किया जायेगा।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं आयोजन को निरस्त किया है। आपको तो दिल्ली से नई तारीख मिल गई थी। इसलिए क्या आप पुन: खेल आयोजन कराने के लिए तिथि मंगाया है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा कि इसमें हमारे राज्य को मेजबानी मिली थी। मेजबानी की तिथि के दौरान ही विधान सभा सत्र की तिथि आहुत थी। उसी कारण से तथा दूसरे राज्यों से छात्र आने वाले थे। उन छात्रों की संस्था को भी वह तिथि match नहीं हो रही थी। उसके कारण उस पूरे आयोजन को निरस्त किया गया। मैंने कहा कि आने वाले समय में फिर से मेजबानी के लिए आग्रह करेंगे कि हमको आयोजन के लिए मेजबानी का अवसर प्रदान करें ताकि हमारे राज्य को मेजबानी का अवसर प्राप्त हो सके और इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से करें।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, आपने आयोजन किया ही नहीं है। सिर्फ तिथि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। आपने तिथि बढ़ाने हेतु अनुरोध कब किया था ? आपने तिथि बढ़ाने हेतु कब पत्र लिखा था, यह बता दें ? आयोजन निरस्त करने का क्या कारण था ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप एक बार में सब बात बता दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं तिथि की जानकारी माननीय सदस्य को अलग से उपलब्ध करा दूंगा।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, यही तो मेरा प्रश्न है। यही प्रश्न है कि जब आपको तिथि मालूम नहीं है तो फिर निरस्त कैसे हो गया ?

सभापति महोदय :- चलिये, वह आपको जानकारी दे देंगे।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मैं फिर वही बात बता रहा हूं, आप सुन लीजिये। वहां से 17.12.2024 से खेल आयोजन प्रस्तावित किया गया था। जब यहां से अनुरोध किया गया तब 15.12.24 से 19.12.2024 तक आयोजन की तारीख निर्धारित हुआ। परन्तु कब निरस्त हुआ ? इसको तो आपने लिखित में दिया है, इसलिए मैं उस बात को नहीं पूछ रहा हूं। इसमें लिखित जवाब में है कि नई दिल्ली के पत्र दिनांक 6.12.2024 को राष्ट्रीय खेल आयोजन निरस्त करने की सूचना मिल गई। इनको 6.12.24 को सूचना मिल गई। आप देखिये कि दिनांक 15.12.24 से 19.12.2024 तक आयोजन की तारीख निर्धारित थी, इसलिए निरस्त पहले हुआ या बाद में हुआ ? आप दोनों की तारीख का अंतर बता दीजिये ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप मोहले जी को बता दीजियेगा।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, खेल का आयोजन ही नहीं हुआ और उसके पहले ही आयोजन निरस्त हो गया, बात यहां पर यही है। (हंसी) आप तारीख देख लीजिये। पहले 17.12.2024 से प्रस्तावित था और उसके पहले ही आयोजन निरस्त हो गया।

सभापति महोदय :- वह बता रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, जो तिथि निर्धारित की गई थी, आपको उस तिथि की जानकारी उपलब्ध करा दी है। उसी मध्य विधान सभा सत्र आहुत था। उसके पहले हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री का भी कार्यक्रम था, 29.11.24 को उनकी उपस्थिति में बस्तर ओलंपिक का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इस कारण से तिथि clash हो रहे थे। उसके कारण हम लोगों ने इस सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, मोहले जी को और जो-जो जानकारी चाहिए, वह दे देंगे।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, जी।

सभापति महोदय :- श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, दिसम्बर माह में मेजबान.. (व्यवधान)

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है।

सभापति महोदय :- श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ हूं, मैं संतुष्ट होना चाहता हूं। जब प्रश्न लगा है तो आप उसको ignore मत कीजिये, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यह दिनांक 06.12.2024 को निरस्त हुआ, लेकिन आवेदन की तिथि दिनांक 17.12.2024 है। आप इसको क्लियर कीजिये कि आपने आवेदन कब दिया है?

सभापति महोदय :- मोहले जी, आप क्या चाहते हैं, यह पूछ लीजिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने बताया कि दिनांक 06.12.2024 को निरस्त हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 17.12.2024 को निर्धारित हुआ था और वह दिनांक 06.12.2024 को कैंसिल हो गया। यह दिल्ली वाले कैसे करेंगे?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बता दीजिये। तुलेश्वर जी, थोड़ा सा बैठिये।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, शादी हुआ ही नहीं, छट्ठी मनाना चालू हो गया। (हंसी) वह ठीक बोल रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही इस बात को कहा है कि अलग-अलग तिथि पर इसकी पूरी कार्यरेखा बनी है, उसके तहत में आग्रह किया गया। मैं पहले आपकी जानकारी में फिर से सिलसेलेवार बता देता हूं। विभागीय प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.11.2024 को छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न खेल संघों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगता आयोजन के संबंध में विभिन्न खेल विधाओं से संबंधित आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही प्रतिभागियों की आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु

प्रतिष्ठित हॉटल प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई। दिनांक 22.11.2024 को राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा, नई दिल्ली एवं राज्य स्तरीय सिमति की आयोजन से संबंधित जुड़े हुए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यू.आई. के माध्यम से रूचि के अभिव्यक्ति जारी करने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में 17.11.2024 को एकलव्य विद्यालयों की चतुर्थ राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजन के संबंध में विभिन्न विभाग के सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और कलेक्टर, रायपुर, पुलिस अधीक्षक, रायपुर की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 03.12.2024 को माननीय विभागीय मंत्री जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति संचालक मण्डल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता तैयारियों के अंतिम रूपरेखा के संदर्भ में चर्चा की गई। लेकिन मैंने जो कहा कि उस आयोजन तिथि के मध्य में हमारे विधान सभा शीतकालीन सत्र की तिथि और बस्तर में ओलंपिक की तिथि भी उसी मध्य में थी, उसके कारण से हमने इसको आगे बढ़ाने का आग्रह किया। पत्र बाद में गया था, लेकिन हमने आग्रह किया था, उस आग्रह को मानते हुए उन्होंने स्वीकार किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मेरा जवाब तो नहीं आया। मैं फिर दूसरा प्रश्न कर रहा हूं कि मंत्री जी तिथि बढ़ाने की बात ही नहीं की। प्रतियोगिता आयोजन की निर्धारित दिनांक से पहले ही निरस्त हो गया, एक। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या इन्होंने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन किये जाने हेतु पुन: पत्र व्यवहार किया? क्या इन्होंने पुन: मांग की है?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, क्या आपने पुन: मांग की है, यह बता दीजिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मंत्री जी, आपने मांग की तो कब की? उसका जवाब आया क्या?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2025 के फरवरी माह में हमने फिर से राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन किये जाने हेतु अनुरोध किया है।

सभापति महोदय :- हो गया। श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मेरा इसी में ध्यानाकर्षण है।

सभापति महोदय :- इसमें आपका ध्यानाकर्षण होगा।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- आपकी डबल इंजन की सरकार है तो आप घोषणा कर दीजिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, सितंबर माह में ही सरकार को पत्र जारी हो गया था। सरकार के पास 4 महीने का पर्याप्त समय था।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल में ध्यानाकर्षण का मामला नहीं आएगा। उनका भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, उनको प्रश्न पूछने दीजिये। श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदिवासी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस आयोजन से शुरूआत की थी और आज छत्तीसगढ़ की सरकार ..।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। आप आसंदी की बात को नहीं मानते हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मेरा भी इसी में ध्यानाकर्षण है।

सभापति महोदय :- आपका ध्यानाकर्षण होगा तो आप ध्यानाकर्षण के बारे में सचिवालय से बात करिये। आप बैठिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह प्रश्न आया है। इसीलिए मैं अनुपूरक प्रश्न के रूप में पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। पहले उनको प्रश्न पूछने दीजिये।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित आश्रम/छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

7. (*क्र. 2046) श्री तुलेश्वार हीरा सिंह मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कितने आश्रम/छात्रावास अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश "क" के आश्रम/छात्रावासों में उपरोक्त उल्लेखित अवधि में अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई? प्रदान की गई सुविधाओं पर प्रत्येक सुविधा के लिए आश्रम/छात्रावासों पर वर्ष 2023 तथा 2024 में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि व्यय की गई, जानकारी जिलावार/विकासखंडवार उपलब्ध करावें? **(ग)** उपरोक्त उल्लेखित अवधि में किस-किस जिले के किन-किन आश्रम/छात्रावासों से कितने-कितने विद्यार्थी पहाड़ी कोरवा एवं बैगा तथा अन्य संरक्षित जनजाति के लाभांवित हुए हैं, जानकारी जिलावार/विकासखंडवार उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1170 आश्रम एवं 1633 छात्रावास संचालित हैं। **(ख)** प्रश्नांश "क" के आश्रम/छात्रावासों में उपरोक्त उल्लेखित अवधि में अनुसूचित जनजाति के निवासरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत आवास, पौष्टिक आहार, साबून, तेल, पंलग, गद्दे, चादर, कंबल, तकिया, थाली, गिलास, खेल सामग्री सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। प्री मैट्रिक छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को राशि रू. 1500/- प्रतिछात्र प्रतिमाह शिष्यवृत्ति राशि प्रदाय की जाती है, जिसमें 80 प्रतिशत (राशि रू. 1275/-) राशि का उपयोग सामूहिक मेस एवं नाश्ता की प्रतिपूर्ति पर किया जा रहा है एवं 15 प्रतिशत (राशि रूपये 225/-) राशि का व्यय स्कूल बैग, पी.टी.शु., ब्लेक शु. मोजा (दो पेयर) स्वेटर, चप्पल, अंडर गारमेंट (दो-दो नग) आदि पर किया जा रहा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावसों में निवासरत विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना अंतर्गत रूपये 1200/- प्रति छात्र प्रतिमाह मेस संचालन हेतु प्रदाय किया जाता है। आश्रम/छात्रावासोंमें शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहाय की राशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जिलेवार सीधे छात्रावास अधीक्षक के खाते में

हस्तांतरित की जाती है। अतः विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। वर्ष 2023 तथा 2024 में व्यय राशि की जानकारी जिलेवार **संलग्न[4] प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाही थी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश पर अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए कितने छात्रावास/आश्रम संचालित हैं? इसकी जानकारी आ गई है। इसके साथ ही साथ मैंने शिष्यवृत्ति के संबंध में जानकारी चाही थी। परंतु हम वर्ष 2023 अंतर्गत कोरबा जिला या पूरे प्रदेश की बात करें वर्ष 2023 में कोरबा जिले में 11 करोड़ से अधिक की शिष्यवृत्ति आती है, वही वर्ष 2024 में 6 करोड़ रूपये से अधिक की राशि आती है। अर्थात् हम आधे शिष्यवृत्ति में आ जाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से इसका क्या कारण जानना चाहूंगा कि क्या शिष्यवृत्ति आवंटन कम था या छात्रों की दर्ज संख्या कम थी या शिष्यवृत्ति देना शेष है?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही थी, मैंने पूरे प्रदेश के संदर्भ में आश्रम, छात्रावास में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में उत्तर दिया हुआ है । सभापति महोदय, हमारे सरकार के माध्यम से शिष्यवृत्ति के रूप में 1500 रूपये हमारे विद्यार्थियों को दिया जाता है और भोजन सहायता योजना के तहत उन्हें 1200 रूपया दिया जाता है । सभापति महोदय, कोरबा के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, उसमें हमारे पास शिष्यवृत्ति की राशि है, वह उपलब्ध है और हम उसे प्रदान करेंगे । सभापति महोदय, जिलेवार जानकारी दी गई है, कही पर कोई परेशानी की स्थिति नहीं है । हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिये सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है । आपने देखा कि पूरी योजना के तहत में बच्चों को किस तरीके से उनको सुविधा देने का काम किया है, चाहे वह सामूहिक मेस का हो, नाश्ता को हो या फिर खेल सामग्री का हो, उनकी तकिया, थाली, चादर सब चीजों की चिन्ता सरकार के माध्यम से किया जा रहा है । सभापति महोदय, आपने जो कोरबा के संदर्भ में जानकारी चाही हैं, वहां पहले 11 करोड़ दिया गया था, अभी 6 करोड़ दिया गया है तो उसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि उनकी जो डिमांड है, उसे जल्द से जल्द राशि दी जायेगी ।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- सभापति महोदय, जल्द से जल्द कब तक कर दिया जायेगा ? वर्ष 2024 खत्म हो गया है और वर्ष 2025 शुरू हो चुकी है ? कृपया यह बतायें कि कब तक शिष्यवृत्ति दिया जायेगा, तिथि बतायें ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अचछा प्रश्न उठाये हैं, हमारे उन विद्यार्थियों को चाहे शिष्यवृत्ति हो या भोजन सहायता राशि हो समयसीमा के साथ में उन्हें

[4] परिशिष्ट "पाँच"

मिले, यह सरकार की मंशा है और हमारी कोशिश है कि इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करें । सभापति महोदय, हमारे विभाग के अधिकारी लगे हुये हैं, हमारा भी प्रयास है कि जल्द से जल्द इस राशि को विमुक्त करें । सरकार के माध्यम से कोशिश रहती है कि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके ।

सभापति महोदय :- श्री ...।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- सभापति महोदय, एक मिनट सर । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । जिला कोरबा में आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास रायपुर से परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा को आश्रम एवं छात्रावास के मरम्मत के लिये 6 करोड़ 62 लाख 29 हजार रूपये की राशि दी जाती है । सभापति महोदय, वहां के ठेकेदार के द्वारा 4 करोड़ 36 लाख बिना काम के ही आहरण कर लिया जाता है, जिस पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेंषण ब्यूरो से प्राप्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा जांच की जाती है । जांच में दोषी पाये जाते हैं और बिना काम के 4 करोड़ रूपये आहरण कर लिया जाता है । माननीय सभापति महोदय, वह ठेकेदार जो बिना वर्क के आहरण किया है, क्या माननीय मंत्री जी के द्वारा उनके ठेका को निरस्त करते हुये उस पर प्रतिबंध लगाया जायेगा ? मैं यह जानना चाहता हूँ ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके तहत यह उद्भूत नहीं होता है । यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है तो उपलब्ध करा दें...।

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी को बता दीजिएगा, वह दिखवा लेंगे ।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- जी ।

सभापति महोदय :- ठीक । श्री अजय चन्द्राकर जी ।

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित महाविद्यालय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

8. (*क्र. 989) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अंतर्गत प्रदेश में कौन-कौन से महाविद्यालय, कहां-कहां संचालित हैं? उनमें से कितने स्वयं के भवन में, उसके अंतर्गत कौन-कौन से, कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने भरे/रिक्त हैं? जनवरी, 2025 की अद्यतन स्थिति में कितने छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अंतर्गत कितने में अनुसंधान केन्द्र स्थापित हैं तथा उसके अंतर्गत स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने भरे/रिक्त हैं? **(ग)** उक्त छात्रों के रोजगार

नियोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्ययोजना बनायी गयी है तथा कितने रोजगार व बेरोजगार हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विश्वविद्यालय अंतर्गत 15 शासकीय महाविद्यालय एवं 4 निजी महाविद्यालय संचालित है। संचालित महाविद्यालयों के संचालन स्थल एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की अद्यतन स्थिति तथा भवन संबंधी **विवरण संलग्न प्रपत्र-अ**[5] **अनुसार** एवं महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध भरे/रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में अनुसंधान केन्द्र स्थापित नहीं है अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** विश्वविद्यालय स्थापना उपरांत 780 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुये है, इनमें से कुछ छात्र-छात्रायें उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है। छात्रों के रोजगार नियोजन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर प्लेसमेंट सेल की स्थापना कर विभिन्न निजी एवं शासकीय संस्थाओं यथा बैंक/बीज/ कीटनाशक इत्यादि कंपनी से समन्वय स्थापित कर रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे है। उत्तीर्ण छात्रों की रोजगार संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय स्तर पर वर्तमान में संधारित नहीं की जाती है अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं छोटा-छोटा प्रश्न करूँगा और छोटा-छोटा उत्तर दे दीजिएगा । यह जो आपका उद्यानिकी महाविद्यालय है, आपने पूरे 15 का उसका नाम रखा है, एक को पढ़ देता हूँ- किशोरी लाल शुक्ल उद्यानिकी उद्यान एवं अनुसंधान केन्द्र, वैसे पूरे 15 महाविद्यालय में अनुसंधान केन्द्र जुड़ा है । माननीय मंत्री जी मुझे यह बतायें कि वह अनुसंधान केन्द्र है या कॉलेज हैं ? यदि अनुसंधान केन्द्र हैं तो किस विषय के अनुसंधान होते हैं ?

श्री केदार कश्यप (संसदीय कार्य मंत्री) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, मैंने उपलब्ध कराया है, हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, उसके साथ में अनुसंधान केन्द्र के लिये आपने पूछा है, वहां भविष्य में भी अनुसंधान केन्द्र की दृष्टि से भी काम करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, भविष्य में बाद में जाएंगे न। मेरा एकदम छोटा-छोटा प्रश्न है, मैं प्रश्न फिर से दोहरा देता हूं । मैंने अभी जो पढ़ा है, उसको फिर से पढ़ देता हूं । किशोरी लाल शुक्ल उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, राजनांदगांव । यह कालेज है या कालेज और अनुसंधान केन्द्र दोनों हैं और यदि अनुसंधान केन्द्र हैं, परिशिष्ट में जो 15 महाविद्यालय के नाम दिए गए हैं, उन सभी में अनुसंधान केन्द्र लिखे गए हैं, एक महाविद्यालय में नहीं लिखा है । यदि इन 15 महाविद्यालयों में अनुसंधान होते हैं तो क्या अनुसंधान होता है, किसी एक कॉलेज का बता दीजिए । यदि अनुसंधान नहीं होता है तो नहीं होता है, ऐसा बता दीजिए । भविष्य में क्या करेंगे, उसको

[5] परिशिष्ट "छै:"

छोड़ दीजिए न । अभी वर्तमान में क्या अनुसंधान होता है या नहीं होता है या सिर्फ उसको नाम के लिए रखा गया है, यह बता दीजिए ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही ऊर्जावान हैं, जागरूक हैं । सभापति जी, आप स्वयं देख रहे हैं । अभी भारसाधक मंत्री हमारे साथ नहीं हैं, वे दिल्ली गए हुए हैं । उनके प्रश्नों का उत्तर मैं दे रहा हूं । बहुत सारे विषय में तो मुझे भी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं । उसके संदर्भ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं । अभी वर्तमान में वहां पर केवल महाविद्यालय का ही कार्य किया जा रहा है और अनुसंधान का कार्य वहां पर नहीं किया जा रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सिर्फ नाम के लिए है ?

श्री केदार कश्यप :- हां, नाम के लिए है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अभी वर्तमान में सिर्फ नाम के लिए है, यह हम तय कर लेते हैं । कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं । आप भारसाधक हैं इसीलिए मैंने छोटा-छोटा प्रश्न पूछा । साहब, अब आप यह बताईए कि स्वीकृत पद के विरूद्ध में कितने शैक्षणिक के पद और कितने प्रशासनिक के पद रिक्त हैं ? इतने प्रशासनिक पद स्वीकृत हैं, इतने शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं और उसके विरूद्ध भी इतने पद भरे हैं और इतने पद रिक्त हैं ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, 15 महाविद्यालयों में 692 पद स्वीकृत हैं । उसमें से 69 पद भरे गए हैं और 623 पद रिक्त हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं छोटा-छोटा प्रश्न ही करूंगा। आपने कहा कि 623 पद रिक्त हैं । 15 महाविद्यालय में 69 पद भरे हैं। अब आप यह अनुमान लगा लें कि पढ़ाई क्या हो रही होगी ? यदि आप बोल सकते हैं कि पढ़ाई के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है या आप प्रतिपूर्ति करने जा रहे हैं या भर्ती करने का कोई कार्यक्रम है, वर्तमान में कक्षाएं किस तरह से कैसे संचालित होती हैं और उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं ?

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, पिछले 5 साल में केवल कॉलेज खोला गया और पदों की भर्ती की पूर्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है, लेकिन अभी जो आपने पूछा है, उसके तहत इन संस्थाओं में 50 शिक्षकीय स्टाफ हैं, जो रेग्युलर हैं और गेस्ट टीचर के रूप में 41 पद पर कार्यरत् हैं । पार्ट टाईम शिक्षक के रूप में 62 पद पर कार्यरत् हैं । कुल लगभग 153 स्टाफ वहां पर कार्यरत् हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से मेरा एक अनुरोध है कि यह प्रश्न कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । खासतौर पर फसल चक्र परिवर्तन के लिए और खास तौर पर धान में आप खेती कर रहे हैं, उसके परिवर्तन के लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । पार्ट टाईम शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, इसके हैं, उसके हैं । आपने जो जानकारी दी है, उसमें जिस तारीख तक

प्रश्न दिया गया है और जिस तारीख तक उत्तर दिया गया है, उस तारीख तक इन पदों की व्यवस्था नहीं थी । आप जितना पद बता रहे हैं, क्या प्रश्न लगने के बाद इसकी भर्ती अभी 15 दिन में कर दी गई ? कम से कम मुझे ऐसा उत्तर विभाग से मत दिलवाईए। जो पद खाली हैं, उसके विरूद्ध 15 दिन के अंदर 153 स्टाफ की भर्ती कर ली गई क्या ? दूसरा, छोटा सा प्रश्न है । आपने लिखा है कि आप प्लेसमेंट करवाते हैं और उसका रिकॉर्ड नहीं रखते । आपने प्लेसमेंट एजेंसी कॉलेज स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर या जिस स्तर पर भी खोली होगी, उस प्लेसमेंट एजेंसी में कितने लोग हैं, कौन-कौन से स्तर के लोग हैं, उसका नाम और पदनाम बता दीजिए।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्लेसमेंट एजेंसी के संदर्भ में जो जानकारी चाही है, उसकी जानकारी मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसको बता दीजिए न ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, उसके साथ-साथ जो आपने कहा कि लगभग भर्ती के लिए हमने 181 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है और 38 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई है लेकिन भर्ती प्रक्रिया में राज्यपाल महोदय के यहां कुछ शिकायत प्राप्त हुई, उसके माध्यम से सब ज्यूडिश मामला होने के कारण अभी वह भर्ती रूकी हुई है। लेकिन आने वाले समय में इसे किया जाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बिल्कुल करेंगे। आप राज्यपाल जी का नाम लाए, तो विश्वविद्यालय में जो भर्ती हो रही है, उसमें शिकायत हुई है या महाविद्यालयों में जो भर्ती हो रही है, उसमें राज्यपाल महोदय के पास शिकायत हुई है? विश्वविद्यालय के बारे में कल मैंने उल्लेख किया था, विश्वविद्यालय में जो भर्ती हो रही है, उसमें कुरिल साहब के खिलाफ शिकायत हुई है। विश्वविद्यालय में जो भर्ती हो रही है उसमें या कालेज की भर्तियों में भी राज्यपाल महोदय के पास शिकायत हुई है? क्योंकि जिस दिन प्रश्न लगा, उत्तर आप अलग से भी देंगे तो चलेगा, बात विश्वविद्यालय की आ रही है और मैं आपसे महाविद्यालय के बारे में पूछा हूं। महाविद्यालय में 15 दिन के अंदर ये डेव्हलपमेंट है क्या? क्योंकि आपने उत्तर दिया है, उसमें तो आप ही ने स्वीकार किया कि 623 पद खाली हैं और सिर्फ 69 भरे, तो शैक्षणिक काम तो वहां नहीं हो रहे हैं। यदि प्रश्नाधीन अवधि में कोई भर्ती आपने की है, इसी दौरान आपने अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की क्या, ये बता दीजिए? क्योंकि मेरे हिसाब से ये जानकारी गलत दे रहे हैं और ऐसी जानकारी पर आपको कार्यवाही करनी चाहिए। 20 दिन में ये डेव्हलपमेंट नहीं हो सकता। बाकी आपके ऊपर है, आप मुझे बता दें।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही बताया कि यहां पर हमारे रेग्यूलर टीचर के रूप में जो 50 हमारे शिक्षकीय स्टाफ.....।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय आप सही बोल रहे हैं, अंतर थोड़ा सा यह है कि मुझे आपने जो उत्तर दिया, उसमें आपने 623 रिक्त बताया है। अभी आप बता रहे हैं कि इतने कार्यरत हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने इनमें टीचर का बताया, अब उसमें जो चपराशी हैं और जो निचले स्टाफ हैं, उसे लेकर मैंने बताया है।

सभापति महोदय :- एक कोई बोलिए ना। आप बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं क्लीयर कर देता हूं, जो आप बताए हैं उसी को। शैक्षणिक पद 249, 195 रिक्त एवं 54 भरे हुए। ड्राईवर, चपराशी को चलिए घटा दीजिए, मैं भी आपसे सहमत हूं। मैं इतना जानना चाहता हूं, बता देंगे, बाद में बता देंगे तो भी चलेगा कि मुझे जिस दिन उत्तर दिया गया, उसमें रिक्त बताया गया, तो आप अभी प्रश्नाधीन अवधि के बाद इसी अवधि के दौरान आपने भर्ती की क्या? जो संख्या बता रहे हैं, उसमें वह अंतर है, तो प्रश्न किया उस दौरान अभी भर्ती शुरू हुई क्या? ये मैं जानना चाहता हूं। इतनी तेजी से कर रहे हैं, तो पूछ रहा हूं, बस, और कुछ नहीं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मेरे पास जो जानकारी है, वह जानकारी मैंने माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आपके पास अगर जानकारी नहीं है, तो जानकारी लेकर बता दीजिएगा।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, जानकारी लेकर बता दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है साहब। धन्यवाद।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापित महोदय, मेरा एक प्रश्न है। इसी में मेरे भी क्षेत्र का मामला है। मंत्री जी, कुछ छात्र उत्तीर्ण भी हो गए हैं, ये दूसरा सत्र है और एक आदमी पढ़ा रहे हैं और छात्रों की संख्या 100 से ज्यादा 150, 185 है। इसलिए जैसा अजय जी ने पूछा कि अतिथि शिक्षक या दूसरे प्रकार के शिक्षक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। अब यदि हम बात करेंगे कि अब दूसरे सत्र में आ गए हैं और दूसरे सत्र में आने के बाद भी केवल सिंगल टीचर है, चाहे उसे अधिष्ठाता बोलें या जो भी बोलें लेकिन केवल सिंगल टीचर हैं। सेटअप तो आपका बना हुआ है, उसकी वैकेंसी जारी करना है, नियुक्ति करनी है। दूसरा, भवन का पैसा भी आ गया है, लेकिन भवन बनना शुरू नहीं हुआ है। तो क्या आप यह बतायेंगे कि इसकी प्रक्रिया कब शुरू करेंगे कि उसकी वैकेंसी कब जारी हो और नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, इसकी निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य ने इसमें निश्चित समयावधि पूछा है। सरकार की मंशा है कि हम इसको जल्द से जल्द करें और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े भी हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करायेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, एक सत्र है, अब हम मार्च में आ गये। इसके बाद अप्रैल है। आपने दो सत्र निकाल दिये, उसके आद भी आप समयावधि नहीं बतायेंगे तो आखिर उन छात्रों का क्या होगा ? इसलिए आप 30 दिनों की समयावधि मत बताईये। आप यह सुनिश्चित करें कि अगले सत्र के पहले नियुक्तियां हो जायेंगी। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या आगामी सत्र से पहले यह नियुक्तियां हो जायेंगी ? यदि रेगुलर नियुक्तियां नहीं हो रही है तो क्या आप किसी भी प्रकार की व्यवस्था करेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही बताया है कि इसमें अतिथि शिक्षक के रूप में लगभग 41 शिक्षक कार्यरत् हैं और 62 अंशकालिक शिक्षक हैं। इस तरीके से वहां पर शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। पिछले 3 वर्षों तक उसको देखने वाला कोई नहीं था लेकिन जब हमारी सरकार आयी तो सरकार बनने के बाद इस दिशा में लगातर प्रयास हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले शिक्षा सत्र में हम इसकी पूर्ती करवा लेंगे।

सभापति महोदय :- ठीक है। श्रीमती अनिला भेंडिया।

लौह अयस्क के लोडिंग/अनलोडिंग स्थलों में प्रदूषण नियंत्रण/ पर्यावरण नियमों का पालन

[आवास एवं पर्यावरण]

9. (*क्र. 1915) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालोद जिला में जनवरी, 2025 की स्थिति में किन-किन स्थानों में लौह अयस्क की लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य किया जा रहा हैं ? क्या सभी स्थानों में पर्यावरण नियमों का पालन किया जा रहा है तथा पानी का छिड़काव किया जाता है? **(ख)** संचालित माइंस/प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ (वेस्ट मटेरियल) को किन-किन शासकीय स्थानों अथवा निजी स्थानों पर डंप किया गया है अथवा किया जा रहा है तथा उक्त कार्य किनकी अनुमति से किन नियमों के तहत किया गया है ? क्या वेस्ट मटेरियल परिवहन/डंप करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** लोडिंग एवं अनलोडिंग स्थान में कार्यरत मजदूरों को क्या-क्या सुविधा दी जाती है, क्या मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 2022-23 से जनवरी 2025 के मध्य किनके माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) बालोद जिले में जनवरी, 2025 की स्थिति में संचालित 03 लौह अयस्क खदानों में (1). मेसर्स राजहरा मेकेनाईज्ड माईन (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) पोस्ट दल्लीराजहरा, जिला बालोद, (2). मेसर्स महामाया दुल्की माइंस (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) पोस्ट महामाया, जिला-बालोद (3). मेसर्स दल्ली मेकेनाईज्ड माईन (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया

लिमिटेड), पोस्ट दल्लीराजहरा, जिला-बालोद में लौह अयस्क का लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य लीज क्षेत्र के भीतर किया जा रहा है। इन लौह अयस्क खदानों में मंडल द्वारा प्रदत्त जल एवं वायु सम्मति में निहित शर्तों का पालन किया जा रहा है तथा जल का छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त बालोद जिले में 01 लौह अयस्क प्रसंस्करण इकाई मेसर्स निको माईनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम गिधाली, तहसील-डौण्डी, जिला-बालोद स्थापित / संचालित हैं जहां लौह अयस्क की लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य उद्योग परिसर के भीतर किया जाता है। उक्त इकाई में मंडल द्वारा प्रदत्त जल एवं वायु सम्मति में निहित शर्तों का पालन किया जा रहा है तथा जल का छिड़काव किया जाता है। **(ख)** प्रश्नांश क की जानकारी में उल्लेखित तीनों खदानों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट (वेस्ट रॉक/मटेरियल) को डम्पर/ट्रक द्वारा परिवहन कर भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खदान में चिन्हित वेस्ट डम्प क्षेत्र (लीज क्षेत्र के भीतर) में संग्रहित किया जाता है। अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार अपशिष्ट (वेस्ट रॉक/मटेरियल) का कुछ भाग खदान क्षेत्र में भू-भरण हेतु उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मेसर्स निको माईनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम गिधाली, तहसील-डौण्डी, जिला-बालोद से जनित होने वाले वेस्ट मटेरियल/अनुपयोगी टेलिंग को 03 शासकीय स्थानों तथा 72 निजी स्थानों पर डंप किये जाने हेतु मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बालोद द्वारा अनुमति दी गई है, उक्त स्थलों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ[6] अनुसार** है। इन स्थलों पर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बालोद द्वारा छ. ग. गौण खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के तहत वेस्ट मटेरियल/अनुपयोगी टेलिंग को डंप किए जाने की अनुमति दी गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 25.02.2025, 28.02.2025, 05.03.2025 एवं 06.03.2025 को इन सभी स्थलों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मेसर्स निको माईनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड से जनित वेस्ट मटेरियल/अनुपयोगी टेलिंग का डिस्पोजल उपरोक्त स्थलों में से 02 शासकीय स्थल तथा 50 निजी स्थलों पर पूर्व से किया गया है तथा शेष 01 शासकीय स्थल तथा 22 निजी स्थलों पर डंपिंग का कार्य आरंभ नही किया गया है। जी हाँ, वेस्ट मटेरियल परिवहन/डंप करने के सम्बन्ध में 02 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर की गयी कार्यवाही का **विवरण संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दुर्ग संभाग, जिला-दुर्ग द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार उद्योग मेसर्स निको माईनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड में प्रबंधन द्वारा लौह अयस्क की लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य में नियोजित श्रमिकों को कारखाना अधिनियम 1948 एवं छ.ग. कारखाना नियमावाली 1962 के प्रावधानानुसार स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। कारखाना प्रबंधन द्वारा नियोजित श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रारूप-21 में वर्ष 2022-23 से जनवरी 2025 की अवधि में

[6] परिशिष्ट "सात"

आऊटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से किया गया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-बालोद से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला-बालोद अंतर्गत गिधाली क्षेत्र में तथा आसपास रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य में माइन्स से संबंधित होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के आधार पर किसी भी प्रकार के बीमारी के लक्षण नही मिले तथा समय-समय पर माइन्स के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर उक्त क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार के गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं मिले।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से लौह अयस्क, लोडिंग, अनलोडिंग और पर्यावरण प्रदूषण के नियमों के बारे में जानकारी चाही थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहती हूं कि चाहे कच्चे माइंस हो, चाहे मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर की जितनी भी माइंस हो, चाहे दुल्की माइंस हो, इन सारी माइंस की गाड़ियां मेरे विधान सभा क्षेत्र की रोड से होते हुए निकलती है और धड़कते से हाई स्पीड में बिना ट्रेनिंग के ड्राईवर गाड़ियां चलाते हैं। उसमें इतनी ओव्हरलोडिंग होती है, जिससे कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। सड़कों की हालत बेहाल हो गयी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगी कि महामाया और कच्चे रोड की चौक में जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। आपने अभी तक कितने ओव्हरलोडिंग ट्रकों के ऊपर कार्रवाई की है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्या ने जिला बालोद में उनके विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जो बात रखी है, इसमें लौह अयस्क के तीन माइंस संचालित हैं। (1) मेसर्स राजहरा मेकेनाईज्ड माईन (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) पोस्ट दल्लीराजहरा, जिला बालोद, (2) मेसर्स महामाया दुल्की माइंस (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) पोस्ट महामाया, जिला-बालोद, (3) मेसर्स दल्ली मेकेनाईज्ड माईन (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड), पोस्ट दल्लीराजहरा, जिला-बालोद और एक लौह बेनिफिकेशन प्लांट है। यह चार माइंस चल रही हैं और जो डंपिंग होती है, जिसको लेकर ट्रक चलते हैं, वह डंपिंग के एस.ओ.पी. फ्लाई ऐश की तरह।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि आपने कितने ओव्हरलोडिंग ट्रकों के ऊपर कार्रवाई की है ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, यह पूछ रही हैं कि कितने ओव्हरलोडिंग ट्रकों के ऊपर कार्रवाई की गयी है ? बिना लाइसेंस के जो ट्रक चला रहे हैं, क्या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की गयी है ? उसके बारे में बता दीजिये। समय भी कम है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, जो ओव्हरलोड गाड़ियां रहती है, उन पर कार्रवाई करने काम ट्रांसपोर्ट विभाग के माध्यम से किया जाता है। पर्यावरण विभाग ओव्हरलोडिंग ट्रकों पर कार्रवाई नहीं

करता है। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ओव्हरलोडिंग की जितनी भी कार्रवाई हुई है, वह सारी जानकारी माननीय सदस्या को उपलब्ध करा दूंगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे जानमाल की हानि हो रही है। उनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा ? वहां माइंस की जो ट्रकें चल रहे हैं, वह माइंस से ही ओव्हरलोड होकर आ रहा है। जो माइंस चला रहा है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि गाड़ियां तो वहीं से निकलती है।

सभापति महोदय :- आपको जो पूछना है आप जल्दी पूछ लीजिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से वही जानकारी चाहती हूं कि जो एक्सीडेंट हुआ है, उनका भरण पोषण, मुआवजा कब देंगे ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, जो एक्सीडेंट की स्थितियां हैं और जो भी घटना हुई है, मैं पिछले 5-7 सालों के प्रकरण दिखवा लूंगा। मैं सदस्य महोदया से उस प्रकरण की भी जानकारी ले लूंगा, वह विशेष रूप से जिस एक्सीडेंट की बात कर रही हैं। उसमें नियम कानून के तहत जो-जो (उपलब्ध कराना है, उसको निश्तिच रूप से उपलब्ध कराया जायेगा और पिछले सालों में कितनी कार्रवाईयां हुई हैं और अभी जो कार्रवाई हो रही है, उसको भी उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त सम्माननीय सदस्या को ओव्हरलोडिंग के विषय में जो भी समस्या है, वह उसको बता दे तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से आगे भी कार्रवाई करेंगे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, ड्राईवरों की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बिना ट्रेनिंग किए हुए ड्राईवर उन गाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए, वह भारी गाड़ियां होती है।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय
12.00 बजे

जन्मदिवस की बधाई

श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य

सभापति महोदय :- आज सदन के सदस्य माननीय श्री लालजीत सिंह राठिया जी का जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ और यह कामना करता हूँ कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न बने रहें।(मेजों की थपथपाहट)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद् और साधुवाद देता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यहां केवल जन्मदिन का उल्लेख होता है। इस सत्र में 3 बार 3 लोगों के जन्मदिन का उल्लेख हो गया, लेकिन यह किसी को पता नहीं चलता कि जन्म दिन के आगे-पीछे कुछ होता है या नहीं होता है?(हंसी)

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें।

पत्रों का पटल पर रखा जाना।

समय
12.01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-1

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-1 पटल पर रखता हूँ।

(2) गुड्स एण्ड सर्विसिस टैक्स नेटवर्क (एक सरकारी उद्यम) की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार गुड्स एण्ड सर्विसिस टैक्स नेटवर्क (एक सरकारी उद्यम) की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 पटल पर रखता हूँ।

(3) वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट) पटल पर रखता हूँ।

सभापति महोदय :- एक-एक करके माननीय सदस्य बोलिए। पहले लहरिया जी बोल लीजिए।

पृच्छा

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, इस समय पूरे क्षेत्र में और पूरे बिलासपुर जिले में पानी का संकट गहराता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आम निस्तारी जिसमें आम जनता के साथ-साथ पशु पक्षी, हमारी गौ माताएं और सभी को पानी चाहिए। वहां तालाब सूख चुका है और वहां पर जल स्तर नीचे जा रहा है। इसलिए कृपया करके खूंटाघाट डेम से जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाए ताकि वहां पर आम जनता की निस्तारी की समस्या दूर हो सके।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुन्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, 28 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग के अंदर गन्ना के कारखानों के संबंध में समीक्षा की गई। जिसमें आर्थिक क्षति का नुकसान आंकलन करते हुए, उसे निजी संस्थाओं में दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके विरोध में आज गन्ना उत्पादक किसान संघ आन्दोलन पर जाने के लिए तैयार हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, जशपुर बालिका छात्रागृह में एक दुष्क्रमित पीड़िता, 14 वर्ष की बालिका ने आत्महत्या कर ली है। अगर माननीय मुख्यमंत्री के स्वयं के

गृह जिले में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, जो दुष्कर्म से पीड़ित बालिका थी उसने आत्महत्या कर ली। यहां पर आप किसकी सुरक्षा की बात करेंगे। मैं इस विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछली बार चना की खरीदी समर्थन मूल्य पर हो, इस विषय पर प्रश्न लगाया था। उस प्रश्न के जवाब में यह उत्तर आया था कि यहां मार्केट में चना का रेट ज्यादा है इसलिए समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं की जा रही है। मैं सरकार से यह निवेदन कर रही हूँ कि यहां चने का रेट 400 रूपये गिर चुका है। तो अभी चने की खरीदी समर्थन मूल्य में की जाए और यहां पर चना खरीदी का केन्द्र व्यवस्थित किया जाये।

सभापति महोदय :- मैं सबको बोलने का मौका दूंगा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे दो छोटे-छोटे विषय हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में होली पर पानी रोक दिया गया था। वहां पर किसानों के खेत बहुत ज्यादा सूख गये हैं। आज सुबह से लगातार फोन आ रहे हैं तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि तुरंत उसकी व्यवस्था करवाएं। दूसरा विषय यह है कि वहां सारी सोसायटियों में खाद रखी हुई है। वहां 31 तारीख तक बहाना बना रहे हैं और वहां पर खाद नहीं दी जा रही है। आप तुरंत उसकी व्यवस्था निर्देशित करें।

श्री संदीप साहू (कसडोल) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां भी यही पानी की समस्या है। वहां पर समोदा, गंगरेल और बलार को रोक दिया गया है। वहां के किसान परेशान हैं। दूसरी समस्या यह है कि अभी गर्मी का समय आ रही है और अभी से बिजली की लो-वोल्टेज की समस्या आने लगी है, ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं और जो लोग वनांचल में रहते हैं, अभी कसडोल का बलदाकछार एरिया तुरतुरिया में अनाप-शनाप बिल आ रहा है। जिनके यहां 600 रुपये बिल आता था, उनके यहां 3 हजार, 4 हजार रुपये बिल आने लग गया है।

श्री बालेश्वर साहू (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, होली के अवसर में जैजैपुर विधान सभा के करहीगांव में कुछ बदमाश लड़कों के द्वारा एक 17 वर्ष के लड़के को होली खेलने के दौरान उसका कपड़ा चीरकर उसको तालाब में फेंक दिया गया। वह तैरना नहीं जानता था, उसकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है। गांव में 20 से ज्यादा गवाह हैं। उसी जैजैपुर विधान सभा के वनडभरा में भी हत्या हुई है, उसकी भी अभी जांच हो रही है, लेकिन अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा में डौंडी ब्लाक में ग्राम सुडोंगर में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, ऐसा वहां जांच समिति के द्वारा कहा जा रहा है, परंतु उनके पूरे शरीर में कांट-छांट के निशान थे। मैं आपसे यह निवेदन करती हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एकतरफा कार्रवाई न हो।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। सिकासेर डेम से पानी छोड़ा जाये, जिससे पानी की समस्या से मगरलोड क्षेत्र प्रभावित न हो।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, रेत उत्खनन बहुत भयावह स्थिति में पहुंचते जा रहा है। रेत की लगातार illegal माईनिंग होती जा रही है। कल ही बात है। जिस रोड पर रेत ले जाने की ट्रेक्टर चल रहे हैं, उस रोड में रेत की इतनी बड़ी ऊपर में लेयर बन चुकी है और कल एक बहुत भयावह मोटरसाइकिल की दुर्घटना हुई है जो घिसटते-घिसटते कम से कम आधा किलोमीटर दूर गया है और आज भी उसकी स्थिति बहुत नाजुक है, वह हॉस्पिटल में है। मैं कई बार ध्यानाकर्षण के जरिये यहां लगाने की कोशिश किया हूं, अभी तक वह चर्चा में आया नहीं। आपसे निवेदन है कि उसको चर्चा के लिये जरूर जायें।

सभापति महोदय :- ठीक है। ध्यानाकर्षण की सूचना, श्री बालेश्वर साहू जी।

समय :

12:07 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत बम्हनीडीह परियोजना में रेडी टू ईट वितरण में अनियमितता की जाना।

श्री बालेश्वर साहू (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- प्रदेश के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों को पोषक तत्व प्रदाय जाना सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा बीज निगम के माध्यम से रेडी टू ईड (आर.टी.एफ.) उत्पाद का कार्य एवं वितरण किया जा रहा है, परंतु जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह परियोजना को लम्बे समय से संबंधित बीज निगम द्वारा रेडी टू ईट फूड पैकेट प्रदाय नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण संबंधित हितग्राहियों को फूड पैकेट का वितरण नहीं किया जा सका है। इसका नियमित वितरण नहीं होने से इन वर्गों में असंतोष है। प्रदेश के अन्य परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत इसी प्रकार की गड़बड़ी से इंकार नहीं किया जा सकता है। हितग्राहियों को फूड पैकेट नहीं मिलने के कारण इन वर्गों में शासन-प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय सभापति महोदय, जी हां यह कथन सही है कि 6 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों गर्भवती व शिशुवती महिलाओं एवं 14 से 18 वर्ष आयु की शाला त्यागी एवं शाला जाने वाली किशोरी बालिकाओं को (केवल आकांक्षी जिले के) छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर द्वारा रेडी टू ईट का निर्माण व प्रदाय कार्य किया जा रहा है। यह कथन सही नहीं है कि जांजगीर जिले के बम्हनीडीह परियोजना में लंबे समय से बीज

निगम द्वारा रेडी टू ईट के पैकेट का प्रदाय एवं वितरण नहीं किया गया जिसके कारण हितग्राहियों को पोषण आहार बाधित रहा।

बीज निगम द्वारा प्रतिमाह नियमित रूप से रेडी टू ईट का प्रदाय बाल विकास परियोजनाओं में किया जा रहा है। निर्माण एवं वितरण में विभाग और बीज निगम द्वारा लापरवाही नहीं की जा रही है और न ही प्रदेश के अन्य परियोजना क्षेत्र में इस प्रकार की अनियमितता हो रही है।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, दबंग दुनिया, दबंग खबर पत्राचार में लगातार छपा है । यह जो रेडी टू ईट है, छोटे बच्चे 6 माह से 6 वर्ष तक गर्भवती महिलायें, किशोरी, कुपोषित-कमजोर बच्चों को दिया जाता है और यह भण्डारण का नियम है, मान लो कि महीने में मंगलवार को इसकी शुरूआत होती है और 15 तारीख से 30 तारीख के भीतर आंगनबाड़ी में भण्डारण किया जाता है लेकिन मार्च के महीने से जब पत्राचार में आया तो मैंने कलेक्टर साहब को फोन लगाया, आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाया ।

सभापति महोदय :- सुनिये न, आप प्रश्न पूछिए ।

श्री बालेश्वर साहू :- जी । माननीय सभापति महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । यह प्रश्न ही है, मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि मंत्री महोदय को पता है कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है तो बताना तो पड़ेगा न । माननीय सभापति महोदय, खबर मिली तो माल नहीं पहुंचा था और 3 तारीख को मैंने सबको सूचना भी दी और और पेपर में भी छपा तो 4 तारीख को व्हाट्सएप के माध्यम से सब केंद्रों में पौष्टिक चीजें पहुंच गयीं और माल धीरे-धीरे पहुंचाया गया लेकिन मेरा कथन यह है कि जब माल 15 तारीख से 30 तारीख तक पहुंचाना था तो 3-4 या 5 तारीख को पेपर में छपने के बाद क्यों पहुंचाया गया और 4 तारीख मंगलवार पड़ रहा है तो उसमें वितरण क्यों नहीं किया गया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय सभापति महोदय, शासन और प्रशासन चूंकि हमारा विभाग ऐसा है कि उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं बनी हुई हैं और रही बात रेडी टू ईट की तो 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, शिशुवती महिलाओं और जो किशोरी बालिकायें हैं । लगातार जो बातें हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 4 तारीख तक यानी महीने का जो प्रथम मंगलवार होता है उसमें रेडी टू ईट पैकेट नहीं दिया गया । यह कहना सही नहीं है कि रेडी टू ईट नहीं दिया गया है । लगातार महीने के प्रथम मंगलवार को रेडी टू ईट प्रदान किया जाता है ।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी का यह कहना है कि मंगलवार, 4 तारीख को वितरण हुआ है तो बच्चों की ऑनलाईन फोटो भी खींची जाती है । मैं इस विषय में जांच की मांग करता हूं कि आप जांच कराईये और लगातार इस विभाग से शिकायतें मिल रही हैं । यहां अनेकों माननीय सदस्यों के माध्यम से भी महिला बाल विकास विभाग में प्रश्न उठाया जाता है । यह कहीं पर स्पष्ट नहीं है कि वर्षों से बैठे अधिकारियों के द्वारा चूंकि इसमें यह दोषी नहीं हैं, यह कहना सत्य नहीं

है । अगर पत्राचार में छपा है, हमको विधायक के रूप में मेसेज मिल रहा है तो कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है और मैं इसमें सुधार की भी मांग करता हूं क्योंकि यह बच्चों का सवाल है, सरकार इसमें सख्त है कि हमेशा कुपोषित और कमजोर बच्चों को या 6 महीने से 6 साल के बच्चों को रेडी टू ईट दिया जाता है तो आप इसको लगातार संज्ञान में लीजिये और मैं इसकी जांच की मांग करता हूं । यह कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है । अगर मैं 4 तारीख को पत्राचार में नहीं आता तो हो सकता है और हर महीने यह गड़बड़ी हो रही है । यदि हमको 15 से 30 तारीख तक भण्डारण करना है ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए ।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, यदि 15 से 30 तारीख तक भण्डारण करना है तो आखिर मार्च के महीने में भण्डारण क्यों हुआ ?

सभापति महोदय :- मैं आपकी बात कह देता हूं न । यह चाहते हैं कि हर मंगलवार को वहां वितरण हो तो आप सुनिश्चित करा दीजिये कि इनके क्षेत्र में सही समय पर वितरण हो और अगर कोई आगे-पीछे हो रहा है तो उसमें आप अधिकारियों को थोड़ा दिखवा लीजिये ।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं कार्रवाई और जांच की भी मांग करता हूं ।

सभापति महोदय :- मैं बोल तो रहा हूं न, आपके लिये जांच की ही मांग कर रहा हूं कि इनकी जो देरी हुई है, उसकी जांच करा देना कि क्यों देरी हुई है और यह बोल दीजिये कि अब आप सुनिश्चित करेंगे ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननी सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को और इस सदन को स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि रेडी टू ईट का जो पैकेट है वह हर मंगलवार को प्रथम और तृतीय मंगलवार को ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता । दिन सुनिश्चित है कि महीने के प्रथम मंगलवार और तृतीय मंगलवार को रेडी टू ईट पैकेट दिया ही जाता है ।

सभापति महोदय :- ठीक है, आप सुनिश्चित करा देना । चलिये, हो गया । श्री संदीप साहू ।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय मंत्री महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों में स्टॉक बचा रहता है ।

सभापति महोदय :- हो गया । उन्होंने बोल दिया न ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी..।

सभापति महोदय :- आप हर चीज में बोलेंगी तो कैसे होगा?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं संज्ञान में डालना चाहती हूं कि फरवरी माह से गर्म भोजन बंद है, उसे भी चालू कीजिए। गर्म भोजन भी चालू करवाइए, फरवरी से बंद है।

श्री बालेश्वर साहू :- सभापति महोदय..।

सभापति महोदय :- बालेश्वर जी, मैंने बोल दिया है कि आपके यहां सही समय पर आपूर्ति हो। मंत्री जी देख लेंगी और अगर कोई देरी हुई है तो किसके कारण देरी हुई है, वह उसे देख लेंगी। ठीक है। अब संदीप साहू जी पूछ लीजिए।

(2) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत स्थित औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाना।

श्री संदीप साहू (कसडोल) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है : -

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत लघु, मध्यम एवं वृहद स्तर के औद्योगिक इकाइयों में जिले मे तकनीकी शिक्षा में उच्च शिक्षित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट धारी स्थानीय बेरोजगारों को तकनीकी एवं गैर-तकनीकी के कार्यों में रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाने से स्थानीय शिक्षित युवा बेरोजगारों एवं स्थानीय जनमानस में जिले में स्थित तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा स्थापित रोजगार कार्यालय के विरूद्ध काफी रोष है।

प्रदेश के एकमात्र जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में ही अधिकांश सीमेंट संयंत्र स्थापित होते हुए भी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के स्थानीय बेरोजगारों को तकनीकी एवं गैर-तकनीकी के कार्यों में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। शासन के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा संचालित जिला रोजगार कार्यालय में विभागीय बजट अनुदानों का दुरूपयोग करते हुए प्लेसमेंट का आयोजन करके मात्र खानापूर्ति एवं बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सिर्फ छोटे स्तर के कार्यों में स्थानीय युवाओं को प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, वास्तविकता में जिले के रोजगार कार्यालय के माध्यम से जिले में स्थित लघु, मध्यम एवं वृहद स्तर के किसी भी औद्योगिक इकाइयों यथा सीमेंट संयंत्रों में तकनीकी शिक्षा में उच्च शिक्षित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट धारी स्थानीय युवा बेरोजगारों को तकनीकी एवं गैर-तकनीकी के कार्यों में प्लेसमेंट के माध्यम से किसी भी स्थानीय युवा बेरोजगार को किसी भी संवर्ग में कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षित बेरोजगार युवाओं द्वारा समय-समय पर जिला प्रशासन के समक्ष इसकी मांग रखी जाती रही है, किन्तु इस पर कोई सकारात्मक कार्यवाही अथवा निर्णय नहीं होने से स्थानीय युवा बेरोजगारों तथा नागरिकों में जिला रोजगार कार्यालय, शासन एवं प्रशासन के प्रति काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

उप मुख्यमंत्री (तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत लघु, मध्यम एवं वृहद स्तर के औद्योगिक इकाइयों में जिले में तकनीकी शिक्षा में उच्च शिक्षित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट धारी

स्थानीय बेरोजगारों को तकनीकी एवं गैर-तकनीकी के कार्यों में रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाने से स्थानीय शिक्षित युवा बेरोजगारों एवं स्थानीय जनमानस में जिले स्थित रोजगार कार्यालय के विरुद्ध काफी रोष है। अपितु वस्तुस्थिति यह है कि जिसे के वृहद स्तर के प्रतिष्ठानों यथा अल्ट्राटेक सीमेंट लि. रवान में तकनीकी योग्यताधारी जैसे-इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई. के 182 स्थानीय एवं गैर-तकनीकी योग्यताधारी के 140 स्थानीय व्यक्ति कार्यरत हैं। इसी प्रकार न्यू विस्टा लि. रिसदा में तकनीकी योग्यताधारी 141 स्थानीय एवं गैर-तकनीकी योग्यताधारी 1220 स्थानीय व्यक्ति, अल्ट्राटेक सीमेंट लि. हिरमी में तकनीकी योग्यताधारी 182 स्थानीय एवं गैर-तकनीकी योग्यताधारी के 2182 स्थानीय व्यक्ति, श्री श्याम स्पंज पावर लि. बछेरा, सिमगा में तकनीकी योग्यताधारी 53 स्थानीय एवं गैर-तकनीकी योग्यताधारी के 1063 स्थानीय व्यक्ति, अंबुजा सीमेंट रवान, बलौदाबाजार में तकनीकी योग्यताधारी 166 स्थानीय एवं गैर-तकनीकी योग्यताधारी के 1930 स्थानीय व्यक्ति कार्यरत हैं।

इसी प्रकार मध्यम स्तर के प्रतिष्ठानों जैसे इंडिया कोल बेनिफिकेशन बछेरा में गैर-तकनीकी योग्यताधारी के 4 स्थानीय व्यक्ति, कृष्णा आयरन चौरंगा में तकनीकी योग्यताधारी 2 स्थानीय एवं गैर-तकनीकी योग्यताधारी के 6 स्थानीय व्यक्ति, अर्थस्टल एण्ड लिमिटेड दुलदुला में तकनीकी योग्यताधारी 16 स्थानीय एवं गैर-तकनीकी योग्यताधारी के 10 स्थानीय व्यक्ति कार्यरत हैं तथा लघु स्तर के प्रतिष्ठान में जैन्को ब्रिक्स लिमाही, बलौदाबाजार, मोना मसाला लिमाही, बलौदाबाजार, श्रीराम पोहा उद्योग पनगांव, सत्यनारायण राईस मिल डोटोपारा, गणेश राईस मिल लाहौद में गैर-तकनीकी के 34 स्थानीय व्यक्ति कार्यरत हैं। स्पष्ट है कि जिले के वृहद, मध्यम एवं लघु स्तर के औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय व्यक्ति पर्याप्त संख्या में कार्यरत हैं।

जिला रोजगार कार्यालयों द्वारा आयोजित प्लेसमेंट कैम्प में यदि कोई भी नियोजक संस्थान यथा लघु, मध्यम अथवा वृहद् प्रकृति के, जब प्लेसमेंट कैम्प में रिक्तियों की पूर्ति के लिए उपस्थित होते हैं तो योग्य आवेदक की उपलब्धता के आधार पर रिक्तियों की पूर्ति प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से की जाती है। प्लेसमेंट कैम्प के आयोजन से उपस्थित आवेदकों को हमेशा अवगत कराया जाता है।

यह कहना सही नहीं है कि स्थानीय युवा बेरोजगारों तथा नागरिकों में जिला रोजगार कार्यालय, शासन एवं प्रशासन के प्रति काफी जनाक्रोश व्याप्त है।

श्री संदीप साहू :- सभापति महोदय, यह जो आंकड़े आए हैं । अगर हम जिले का पंजीयन देखें तो इसी वर्ष 70 हजार बेरोजगारों ने पंजीयन कराया है । लेकिन रोजगार का आंकड़ा केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का बताया गया है, जबकि बलौदाबाजार जिले में 7-7 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, जो नामी फैक्ट्रियां हैं । उसके बाद भी केवल 1200 लोगों को नौकरी देना बताया गया है । मुद्दे की बात यह है कि वहां वहां एच.आर. मैनेजर, परचेस मैनेजर, प्लांट का मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्लांट हेड, ये सब बाहरी लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को और स्थानीय लोगों को नौकरी मिली ही नहीं है । यह आंकड़ा केवल एक ही

सीमेंट फैक्ट्री और पोहा मिल में काम करने का बता रहे हैं। 6-6 सीमेंट फैक्ट्री का कोई आंकड़ा नहीं है, यहां केवल अल्ट्राटेक का आंकड़ा है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस जिले में कितने रोजगार कैम्प आयोजित किए गए और क्या उस सीमेंट फैक्ट्रियों को उसमें समाहित करके, साथ में रखकर नौकरी देने के लिए कोई दिशा निर्देश शासन प्रशासन के द्वारा दिया गया है ?

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, न्यू विस्टा कार्पोरेशन, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक इन सबके बारे में मैंने बताया, सिर्फ अल्ट्राटेक के बारे में नहीं बताया । माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं होगा । उसके बाद भी मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सीमेंट की ऐसी 6 कंपनियां हैं, प्रावधान कैसे हैं ? तो प्रावधान ऐसे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार नई औद्योगिक नीतियों में भी, वहां जिनको वहां विभिन्न अनुदान चाहिए, चाहे वह जीएसटी के संबंध का अनुदान हो या फिर स्टाम्प ड्यूटी का हो, ब्याज अनुदान हो, स्थायी पूंजी निवेश का अनुदान हो, विद्युत शुल्क हो, मंडी शुल्क हो, किसी भी प्रकार का अनुदान लेना होगा । वे सारी कंपनियां इन सारे प्रावधानों का अनुकरण करेंगी और उसमें यह है कि अकुशल 100 प्रतिशत होना जरूरी है, अर्धकुशल 70 प्रतिशत होना जरूरी है, प्रबंधकीय कर्मचारी 40 प्रतिशत होना जरूरी है, यह प्रावधान में है और इसी प्रावधान के आधार पर वहां कंपनियां काम कर रही हैं । सरकार की पूरी नज़र है, आप चाहें तो मैं कंपनीवार पूरी जानकारी आपको दे देता हूं ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट । उसी से संबंधित है।

सभापति महोदय :- अभी तो उन्हीं को पूछने दीजिए जिन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया है ।

श्री संदीप साहू :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि कितने रोजगार कैम्प लगाए गए इसकी मॉनीटरिंग सरकार के द्वारा होना चाहिए और किस किस विषय में कितने युवा आए, कितने को रोजगार मिला, न्यूनतम वेतन कितना था और अधिकतम वेतन कितना था ? ज्यादातर लोगों को वहां छोटी नौकरियां, जैसे कि गार्ड या लेबर जैसी नौकरियां दी गईं । लेकिन टारगेट बनाएं कि जो वहां तकनीकी रूप से शिक्षित हैं, उनको रोजगार मिले । मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं जितने लोगों को रोजगार दिया गया है, क्या उनका प्लेसमेंट ट्रैकिंग किया जा रहा है ? युवा केवल एक-दो महीने में नौकरी छोड़ रहे हैं और आप यहां विधान सभा में उनका रिकॉर्ड देने का कष्ट करेंगे ।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता के अनुरूप मैं सोचता हूं कि विस्तृत जानकारी सदन के समक्ष रख ही देता हूं । वह विषय ऐसा है कि न्यू विस्टा कार्पोरेशन लिमिटेड है । आज जब मैं यहां खड़े होकर बात कर रहा हूं तो अभी वहां यह स्थिति है, मैं वह कह रहा हूं । पुराने समय को जोड़कर फिर अन्य स्थितियां उत्पन्न होती हैं । प्रबंधकीय स्थिति जो न्यू विस्टा कार्पोरेशन में है, लोकल बलौदाबाजार जिले के 12 लोग हैं, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के 46 लोग हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर के भी हैं लेकिन यह 40 प्रतिशत की सीमा में है । दूसरा, श्री सीमेंट में बलौदाबजार

जिले के 31, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के 43, यह भी 40 प्रतिशत की सीमा जो कि औद्योगिक नीति के अंतर्गत है । अल्ट्राटेक सीमेंट में बलौदाबाजार जिले के 34, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के 107 लोग हैं, यह भी 40 परसेंट के अंतर्गत है । अम्बुजा सीमेंट में बलौदाबाजार जिले के 59, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के 64, वह भी 40 प्रतिशत की सीमा में है, 73 लोग और हैं । इसमें सभी कंपनियों के डिटेल हैं ।

सभापति महोदय :- आपका उत्तर तो आ गया। आप क्या पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। सीधे एक प्रश्न पूछिए।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मेरे सगे भाई के बच्चे का मामला है। श्री सीमेंट ने 15 साल से जमीन अधिग्रहण की हुई है।

सभापति महोदय :- आप इस ध्यानाकर्षण से संबंधित प्रश्न पूछिए न।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, वहीं का मामला है।

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी से मिलकर अपनी समस्या बता दीजिए।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, श्री सीमेंट ने 15 साल से जमीन अधिग्रहण की हुई है, मेरा सगा भतीजा है। वह तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होने के बाद आज भी दर-दर ठोकर खा रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या उनको श्री सीमेंट में नौकरी दी जाएगी ?

सभापति महोदय :- ये इसका विषय नहीं है, आप मंत्री जी से मिल लीजिए। उमेश जी आप पूछिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी नियम बता रहे हैं कि 40 प्रतिशत बाहरी रहेंगे, 60 प्रतिशत लोकल रहेंगे, कंपनियां उसको मान्य कर रही है। क्या आप ये बतायेंगे कि उसमें जो 60 प्रतिशत है, उसमें कितने लोग अकुशल हैं और कितने लोग कुशल हैं ? जैसे इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के पोस्ट में कितने लोकल लोग वहां काम कर रहे हैं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सदस्य ने बहुत सही प्रश्न किया। इससे पहले मैंने जो भी आंकड़े बताएं हैं, वे प्रबंधकीय स्तर के हैं, सर्वोच्च स्तर के हैं। इसके नीचे अकुशल है, वह भी मैं आपको बता देता हूं। न्यू विस्टा में बलौदाबाजार के स्थानीय 609 लोग हैं, छत्तीसगढ़ के अन्य जिले के 13 लोग हैं, राज्य के बाहर के 1 हैं। श्री सीमेंट बलौदाबाजार में स्थानीय 531 लोग हैं, छत्तीसगढ़ के अन्य जिले के 69 लोग हैं, राज्य के बाहर के 28 लोग हैं। ये अकुशल हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट बलौदाबाजार लोकल 1395 लोग हैं, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के 109 लोग हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के 131 लोग हैं। इसी तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट के दो फैक्ट्री हैं, एक रावन में हैं, एक हिरमी में हैं। अल्ट्राटेक के दूसरे यूनिट में बलौदाबाजार के 960 लोग हैं, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के 212 लोग हैं, प्रदेश के बाहर के शून्य हैं। ये अकुशल की संख्या है, मैं अब कुशल की संख्या बता देता हूं। मैंने सबसे पहले आपको प्रबंधकीय बताया था, ये कुशल के लिए है, न्यू विस्टा में बलौदाबाजार जिले के 678 लोग हैं, छत्तीसगढ़ के अन्य जिले से

48 लोग हैं और राज्य के बाहर के 136 लोग हैं। ऐसी सभी जानकारियां हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट जवाब दे दिया।

श्री उमेश पटेल :- जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रबंधकीय है, मैनेजमेंट पोस्ट है, वहां 60 प्रतिशत लोकल हैं, लोकल मतलब छत्तीसगढ़ के हैं और 40 प्रतिशत बाहरी है। आप यही कह रहे हैं जो मैं सही समझ रहा हूं।

(मंत्री जी द्वारा सिर हिलाकर सहमति दी गई)

सभापति महोदय :- आपका प्रश्न हो गया। आप बैठिए।

श्री उमेश पटेल :- सभापति जी, मैनेजमेंट पोस्ट में 60 प्रतिशत लोग लोकल छत्तीसगढ़ के हैं, मुझे नहीं लगता है।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, एक मिनट। मैंनेजमेंट पोस्ट प्रबंधकीय में 40 प्रतिशत है, अर्धकुशल में 70 प्रतिशत है और अकुशल में 100 प्रतिशत है, ये कानून है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, अभी आपने जो नई औद्योगिक नीति बनाई है उसमें 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत विभाजन किया है, वह किस आधार पर किया है ? सारे को मिलाकर किया है या उसमें प्रबंधकीय किया है।

सभापति महोदय :- उमेश जी हो गया। मंत्री जी ने बहुत विस्तृत जवाब दे दिया है।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, मैं आपकी बात समझ गया, मेरा स्पेसीफिक प्रश्न है।

श्री विजय शर्मा :- इसमें स्पष्टता है। एक मिनट मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं समझ गया।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न, उनको जवाब देने दीजिए। आप मंत्री जी को बोलने ही नहीं दे रहे हो।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, ये कुल मिलाकर नहीं कहा गया है, अकुशल 100 प्रतिशत है, अर्धकुशल 70 प्रतिशत है और प्रबंधकीय में 40 प्रतिशत है। ये अनिवार्यत: छत्तीसगढ़ के लोगों को लेना ही है।

सभापति महोदय :- चलिए आप पूछ लीजिए।

श्री सुनील सोनी :- सभापति जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की सर्वोच्च योजना कौशल विकास है। कौशल विकास के माध्यम से उस जिले के अंदर कितने लोग ट्रेंड हुए ? क्योंकि वहां पर आधा दर्जन से अधिक सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। मैं भी सांसद रहा हूं। वहां कितने लोगों को स्थाई नौकरी दी गई ? प्रश्न ये है कि उनको दो तीन महीने में नौकरी से निकाल दिया जाता है, कितने लोगों को कौशल विकास के माध्यम से नौकरी दी गई, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली, भले छोटी नौकरी हो, वहां कितने लोगों को स्थाई नौकरी दी गई अगर नहीं दी गई तो क्या आप उसकी व्यवस्था करेंगे, ये बता दीजिए ?

सभापति महोदय :- इस ध्यानाकर्षण में उसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। वे कुशल अकुशल सब बता दिए हैं। आप इनको जानकारी दे दीजिएगा। कितने लोग ट्रेनिंग लिए हैं।

श्री विजय शर्मा :- जी।

श्री संदीप साहू :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- आप आखिरी प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री सुनील सोनी :- कौशल विकास के अंतर्गत ट्रेड लोगों को।

सभापति महोदय :- वह आपको बता देंगे।

श्री संदीप साहू :- जी, आखिरी है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम जो रोजगार शिविर लगते हैं और उसमें जो नौकरी दी जाती है, उसकी जानकारी आंकड़ों में है। आपको जो भी जानकारी दी गई है, वह आंकड़ों में है। कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जो प्लेसमेंट होते हैं और जो नौकरी दी जाती है, उनकी ट्रेकिंग शासन-प्रशासन के द्वारा दिया जाये। जन सुनवाई हो। सीमेन्ट फैक्ट्री में तो जनप्रतिनिधि, जो वहां का स्थानीय विधायक है, उसको शामिल किया जाये। जो रोजगार शिविर लगे, उसमें स्थानीय विधायक को शामिल किया जाये ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो सके कि छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय लोग हैं और जो बेरोजगार हैं और जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको नौकरी मिल सके, क्योंकि जंगल, जल व जमीन हमारी है तो हमारे लोगों को नौकरी मिलनी है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता के अनुरूप 6 सीमेंट कंपनियों में से 2 के आप मुझे नाम दे दीजिए। इसका परीक्षण करवाकर व भौतिक सत्यापन करवाकर मैं आपको इसकी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री संदीप साहू :- धन्यवाद, मंत्री जी।

सभापति महोदय :- चलिये, पर्याप्त हो गया। नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं।

समय :

12.31 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

01. श्रीमती चातुरी नंद

02. श्री दलेश्वर साहू

03. श्री अटल श्रीवास्तव

04. श्रीमती कविता प्राण लहरे

05. श्री पुन्नूलाल मोहले

समय :

12.32 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का बारहवां, तेरहवां, चौदहवां एवं पन्द्रहवां प्रतिवेदन

सभापति महोदय, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (श्री अमर अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का बारहवां, तेरहवां, चौदहवां एवं पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समय :

12.33 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्य सूची में शामिल निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

01. श्रीमती गोमती साय

02. श्री लखेश्वर बघेल

03. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी

04. श्रीमती संगीता सिन्हा

05. श्री ओंकार साहू

06. श्रीमती अंबिका मरकाम

07. श्री इन्द्र कुमार साहू

08. श्री रोहित साहू

09. श्री विनायक गोयल

समय :

12.34 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई ।

सभापति महोदय :- श्री ओ.पी. चौधरी जी।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) का पुरःस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय :- श्री ओ.पी. चौधरी जी।

(2) छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई ।

सभापति महोदय :- श्री ओ.पी. चौधरी जी।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) का पुरःस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय :- शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु मैंने उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

01.	रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025)	30 मिनट
02.	छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025)	15 मिनट

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

समय

12.35 बजे

वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या	-	1	सामान्य प्रशासन
मांग संख्या	-	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	-	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (आबकारी)
मांग संख्या	-	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	16	मछली पालन
मांग संख्या	-	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	35	पुनर्वास
मांग संख्या	-	36	परिवहन
मांग संख्या	-	56	ग्रामोद्योग
मांग संख्या	-	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	65	विमानन विभाग
मांग संख्या	-	71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मांग संख्या	-	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	27	स्कूल शिक्षा
मांग संख्या	-	37	पर्यटन
मांग संख्या	-	44	उच्च शिक्षा
मांग संख्या	-	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व
मांग संख्या	-	77	सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय.

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 1 सामान्य प्रशासन के लिए- पांच सौ पच्चीस करोड़, उनतीस लाख, सोलह हजार रूपये,

मांग संख्या - 2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए- पैंतीस करोड़, चौवन लाख, अन्ठावन हजार रूपये,

मांग संख्या - 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिए- चार सौ तिरसठ करोड़, उनहत्तर लाख, चौतीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिए- तीन हजार एक सौ सतासी करोड़, पैतालीस लाख, बयासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिए- छः सौ नौ करोड़, इक्कीस लाख, चौरासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 16 मछली पालन के लिए- अन्ठानबे करोड़, सैतीस लाख, सात हजार रूपये

मांग संख्या - 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिए- नौ सौ सड़सठ करोड़, नवासी लाख, निन्यानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 32 जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिए-पांच सौ बावन करोड़, चौतीस लाख, चौरानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 35 पुनर्वास के लिए- दो करोड़, छियासी लाख, अड़तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 36 परिवहन के लिए- दो सौ सात करोड़, उन्यासी लाख, निन्यानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 56 ग्रामोद्योग के लिए- एक सौ अड़तीस करोड़, अड़तीस लाख, चौरासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए- दो सौ आठ करोड़, पचास लाख रूपये,

मांग संख्या - 65 विमानन विभाग के लिए- एक सौ अन्ठावन करोड़, तिरसठ लाख, चौसठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए- तीन सौ उन्यासी करोड़, निन्यानबे लाख, अन्ठानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिए- नब्बे करोड़, तिहत्तर लाख रूपये,

मांग संख्या - 27 स्कूल शिक्षा के लिए- दस हजार तीन सौ सैतालीस करोड़, सात लाख, निन्यानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 37 पर्यटन के लिए- दो सौ बाईस करोड़ रूपये,

मांग संख्या - 44 उच्च शिक्षा के लिए- एक हजार दो सौ चौरासी करोड़, अट्ठाइस लाख छिहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए- उनचास करोड़, तीस लाख रूपये तथा

मांग संख्या - 77 सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय के लिए- चौहत्तर करोड़, सैतीस लाख, दस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 1

सामान्य प्रशासन

1.	श्री लखेश्वर बघेल	2
2.	श्री दिलीप लहरिया	1
3.	श्री लालजीत सिंह राठिया	1
4.	श्रीमती शेषराज हरवंश	3
5.	श्री इन्द्र साव	1

मांग संख्या - 7

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (आबकारी)

1.	श्रीमती अनिला भेंडिया	1
2.	श्री दिलीप लहरिया	2
3.	श्री कुंवर सिंह निषाद	2
4.	श्री जनक ध्रुव	1
5.	श्री इन्द्र साव	1

मांग संख्या - 12

ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री दिलीप लहरिया	1
2.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1
3.	श्री जनक ध्रुव	1
4.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1
5.	श्री इन्द्र साव	1

मांग संख्या - 14

पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1
2.	श्री दिलीप लहरिया	2
3.	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा	1
4.	श्री जनक ध्रुव	1
5.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1
6.	श्री इन्द्र साव	1

मांग संख्या - 16

मछलीपालन

1.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1

मांग संख्या - 25

खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री दिलीप लहरिया	1
2.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1
3.	श्री इन्द्र साव	1
4.	श्री ब्यास कश्यप	1

मांग संख्या - 32

जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1

मांग संख्या - 35

पुनर्वास

निरंक

मांग संख्या - 36

परिवहन

1.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1
2.	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा	1
3.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1
4.	श्री जनक ध्रुव	1
5.	श्री दिलीप लहरिया	3
6.	श्री इन्द्र साव	1
7.	श्री ब्यास कश्यप	1

मांग संख्या - 56

ग्रामोद्योग

1.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1

मांग संख्या - 60

जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय

निरंक

मांग संख्या - 65

विमानन विभाग

1.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1

मांग संख्या - 71

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

निरंक

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या - 26

संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री लखेश्वर बघेल	4
2.	श्रीमती शेषराज हरवंश	2
3.	श्री दिलीप लहरिया	2

मांग संख्या - 27

स्कूल शिक्षा

1.	श्रीमती अनिला भेंडिया	4
2.	श्री लखेश्वर बघेल	11
3.	श्री दिलीप लहरिया	8
4.	श्री इन्द्र साव	4
5.	श्रीमती शेषराज हरवंश	2
6.	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा	1
7.	श्री लालजीत सिंह राठिया	3
8.	श्री कुंवर सिंह निषाद	4

मांग संख्या - 37

पर्यटन

1.	श्री दिलीप लहरिया	1
2.	श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी	1
3.	श्रीमती अंबिका मरकाम	2
4.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1

मांग संख्या - 44

उच्च शिक्षा

1.	श्रीमती अनिला भेंडिया	3
2.	श्री लखेश्वर बघेल	3
3.	श्रीमती अंबिका मरकाम	1
4.	श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी	1

5.	श्री कुंवर सिंह निषाद	2
6.	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा	1
7.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1
8.	श्री इन्द्र साव	1
9.	श्री दिलीप लहरिया	1
10.	श्री ब्याश कश्यप	1
11.	श्री लालजीत सिंह राठिया	1

मांग संख्या- 51

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य

1.	श्री दिलीप लहरिया	1
2.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1

मांग संख्या- 77

सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय

निरंक

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

सभापति महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी । श्री दलेश्वर साहू जी ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- सभापति महोदय, मैं वर्ष 2025-2026 के अनुदान मांगों की परिचर्चा में भाग लेना चाहता हूँ और आपकी अनुमति से इस बजट के विरोध के लिये खड़ा हूँ । सभापति महोदय, मांग संख्या 1, 7, 12, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 56, 60, 65, 71, 26, 27, 37, 44, 51 एवं 77 के कुछ ही विषयों पर अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूँ ।

सभापति महोदय, उर्जा विभाग में माननीय वित्त मंत्री जी ने एकलबत्ती कनेक्शन, पी.एम.कुसुम योजना, पी.एम.सूर्यघर योजना, पी.एम.सूर्यघर मॉडल सोलर, (कुछ में इंगित किया हुआ है) और मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है । सभापति महोदय, उर्जा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, हर लोगों से चाहे वह निचले बस्ती के हो, चाहे मध्यम बस्ती के हो, चाहे वह उच्च स्तर का हो, उर्जा

के बिना तो जीवन ही अधूरा है । सभापति महोदय, इस उर्जा विभाग का दायित्व हमारे मुख्यमंत्री के पास है, उर्जा विभाग विद्युत अधिनियम 2003 के छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम 2010 में संशोधन करते हुये महत्वपूर्ण 3 कंपनियों पर बांटा गया है । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इसमें तीनों का अपना-अपना एक दायित्व है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का भी बड़ा महत्वपूर्ण है । सभापति महोदय, एक कंपनी विद्युत उत्पादन करती है, दूसरा ट्रांसमिशन का होता है जिसमें सिस्टम को निचले स्तर तक फॉलो करते हैं कि कितना उच्च दाब, कितना नीचे का दाब, कितना ट्रांसफारमर, कितना सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कि कितना करेंट कहां पर जाना चाहिये, कौन से एरिया में कितना लोड की आवश्यकता है, यह अलग-अलग कंपनियों का अपना एक दायित्व है ।

समय
12:44 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, दायित्व में प्रबंधक, निदेशक, प्रबंध संचालक सहित उच्च स्तर के अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है । सभापति महोदय, हम अगर ताप विद्युत संयंत्र में जायें, हसदेव बांगों विद्युत गृह क्रमांक-1, विद्युत गृह क्रमांक-2, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप, गृह कोरबा, कोरबा पश्चिम विस्तार,

अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युतीय मड़वा, जांजगीर चांपा में है । सभापति महोदय, इन सब का अलग-अलग मैगावाट की कैपिसिटी है, जैसे 420, 420, 500, 500, 1000 मेगावाट की क्षमता है । सभापति महोदय, यह उत्पादन करता है और उच्च अधिकारी के कंट्रोल में रहता है, दूसरा जल विद्युती संयंत्र का स्थलवार विवरण है, हसदेव बांगो जल विद्युती गृह, गंगरेल जिला धमतरी विद्युत गृह, जल विद्युत सिकासेर गरियाबंद, हसदेव लघु एवं लघुत्तम विद्युत गृह कोरबा, इसका 120, 10, 7, 1.70 मेगावाट जल से हम विद्युत पैदा करते हैं । सभापति महोदय, हमने कंपनी बना दिया, संशोधन कर दिया । विद्युत विभाग अपने दायित्वों को कम्पनी के माध्यम से संचालित कर रहा है । गांव में एक दुकानदार पान ठेला चलाता है तो वह छत्तीसगढ़ के अधिनियमों के अधीन में एक पान ठेला चलाता है । अगर दुकानदार भजिया भी बेचता होगा, समोसा भी बेचता होगा तो वह भी शासन के गाईड लाईन के अधीन रहता है। एक खाद्य अधिकारी दुकान में जाता है और दुकानदार दुकान में भजिया को ढांककर नहीं रखता है तो वह खाद्य अधिकारी उसका चालान भी कर देता है । हम सॉस भी ले रहे हैं, अगर कोई हॉस्पिटल है, स्कूल है, जो भी हो, सभी हम कहीं न कहीं नियम कानून के अधीन, उनके परिपालन के साथ हम अपने जीविकोपार्जन करते हैं या किसी कम्पनी का संचालन करते हैं, पर मैंने कहा कि विद्युत जनरेशन कम्पनी हो, चाहे ट्रांसमिशन कम्पनी हो, चाहे डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी हो, जब कम्पनी को

सौंपा गया तो कम से कम नियमावली, क्रय नियम, कौन सी चीजों को हमें किस नियम के तहत खरीदना है । गारे पेलमा सेक्टर 3 कोयला खदान की उपलब्धि मतलब बिना कोयले के तो ताप विद्युत उत्पादन नहीं होगा । जब तक कोयला नहीं लाएंगे, तब तक विद्युत उत्पादन भी नहीं होगा । कोल माईनिंग का अपना नियम है कि इतने किलोमीटर से इतना परिवहन लगेगा । राजेश मूणत जी ने साल भर पहले जुलाई के सत्र में एक प्रश्न लगाया था कि आपने डबल रेट, कोई भी चीज का एबब होता है। हम किसी परिवहन की निविदा करेंगे तो चलो, ठीक है आपने 100 रूपए तय किया तो कोई 80 रूपए में तैयार हो जाता है, कोई 90 रूपए में तैयार हो जाता है । अगर नहीं होता है तो 3 प्रतिशत एबब करने की एक निविदा प्रक्रिया है, पर उसी कोयला को लाने के लिए हम अगर उस रेट का दोगुना तय करें और जवाब मांगता है कि आपने डबल पर कैसे कर दिया । छत्तीसगढ़ निविदा या जिस प्रक्रिया के तहत आपने किया है तो उच्च स्तर में जो अधिकारी बैठे हैं, चाहे वह निदेशक के रूप में हो, चाहे प्रबंध संचालक के रूप में हो, यह अपने नियम बनाते हैं और चाहे किसी व्यक्तिगत कम्पनी को ओबलाईज़ करने के लिए या किसी व्यक्ति को ओबलाईज़ करने के लिए एक निर्देश जारी करता है और उस निर्देश के तहत काम करते हैं । प्रश्न में यह भी बताया जाता है कि हम क्रय नियम बना रहे हैं । या तो आप क्रय नियम बना लेते । जैसे कम्पनी बनी, आपके पास समय था, आप 15 दिन या 1 महीने के अंदर क्रय नियम बना लेते, पर आपने नियम नहीं बनाया और सिर्फ क्रय नियम बना रहे हैं, क्रय नियम बना रहे हैं कहकर आप कुछ भी मनमानी और बेलगाम कंट्रोल करते हैं। यह कम्पनी मुख्यमंत्री जी के दायित्व में हैं, वे सीधे-साधे हैं, आदिवासी मंत्री हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कानून को दरकिनार करते हुए रेट को बढ़ाकर किसी व्यक्ति को विशेष फायदा दिलाने के लिए काम करते हैं । यह कम्पनी बेलगाम कम्पनी है ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य बेलगाम कम्पनी बोल रहे हैं । वे अपना भी ध्यान रख लेंगे कि पिछले कार्यकाल में जो माननीय मुख्यमंत्री थे, वे अपनी सगी भाभी, अपने रिलेशन को वहां पर जो एडिशनल सी.ई.ओ. लेवल की जो अधिकारी थी, उनको सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए थे । पहले अपनी पार्टी का देख लीजिए । आप गलत बोल रहे हैं, विद्युत विभाग में तीन कम्पनी बोल रहे हैं, जबकि उसमें पॉच कम्पनी हैं । आप ट्रेडिंग और होल्डिंग कम्पनी को भूल गए । पॉच कम्पनी में तीन मैनेजिंग डायरेक्टर वरिष्ठ आईएएस हैं । आप कैसे हमारे मुख्यमंत्री जी के विभाग पर आक्षेप लगा रहे हैं ।

श्री दलेश्वर साहू :- बस बैठ जा । पढ़बे, तब जानबे कि अइसने बोले से हो जही।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, निर्देश मैं दूंगा, आप निर्देश मत दीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- ठीक है न सभापति जी । आपसे अनुमति लेकर उठना चाहिए न सभापति महोदय । कोई भी उठ जाएंगे तो हम थोड़ी स्वीकार करेंगे ।

सभापति महोदय :- आप बोलिए ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैंने सप्ताह भर पहले मुख्यमंत्री जी के ऊर्जा विभाग में ट्रांसमिशन कम्पनी में प्रश्न लगाया था कि विद्युत पारेशन लाईन और उचित दाब की संरचना उपकेन्द्र के निर्माण में ट्रांसफार्मर, ब्रेकर, सीटीपीटी, आयुष्लेशन एवं उपकरण केबल वायर, मीटर्र, कम्प्यूटर, पारेषण से संबंधित सामग्री पर आपने करोड़ों रुपए खर्च किया। हमारे सीधे साधे मंत्री जी से असत्य बोलवा दिए। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ क्रय नियम बिल्कुल भी नहीं है, मैं मानता हूं, पर आपने निविदा के स्थान पर इन्क्वायरी किया। आप एकल निविदा करा लेते लेकिन इन्क्वायरी के नाम पर आपने करोड़ों रुपए की खरीदी कर ली। मैं इसी बात को कहता हूं कि जब कंपनी का निर्माण हुआ, तो आप नियम-कानून बना लेते। मैं उदाहरण के तौर पर दिया। एक पान ठेला, एक होटल चलाने वाला व्यक्ति एक नियम-कानून से चलता है, एक प्रायवेट हॉस्पिटल चलाने वाला नियम कानून से चलता है, लेकिन आप अपने नियम से बैठे हुए अधिकारी से चलायेंगे? मैं कहता हूं कि ये जो अफसर हैं, वे बेलगाम हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि आप क्रय नियम का पालन करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- दलेश्वर जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के पास 23 विभाग हैं। अब बिजली तो पूरी जल ही रही है, 24 घंटे तो दे रहे हैं, अब और कैसे करेंगे? अब आप बिजली से आगे बढ़ो।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, जो है, सत्य बोल रहा हूं, उसे तो कम से कम स्वीकार करना होगा। आपका कोई भी नियम-कानून नही है। आप जो चला रहे हैं, जो सिस्टम आपका फालो हो रहा है, जिस आदमी को फायदा दिलाना चाह रहे हो, जो अपनी मनमानी करना चाह रहे हो, करिए, कोई दिक्कत नहीं है और वह हो ही रहा है। क्रय नियम साल- दो साल तक मत बनाइए और जो आपका दिशा निर्देश है, उस निर्देश के तहत आप खरीदते रहिए। आपने एक बत्ती कनेक्शन, पी.एम.कुसुम योजना, पी.एम.सूर्यघर योजना, पी.एम.सूर्यघर मॉडल सोलर विलेज योजना के लिए पैसा रखा है। पी.एम. कुसुम योजना के लिए 362 करोड़, एकल बत्ती के लिए 500 करोड़, पी.एम.सूर्यघर योजना के लिए 200 करोड़, मुख्य मंत्री शहरी विद्युतीकरण के लिए 25 करोड़ रुपए रखा है, पर आपने 5 एच.पी. तक के कृषि पंपों का वार्षिक 7 हजार से लेकर 500 यूनिट तक की योजना को समाप्त कर दिया है। ठीक है, आपका शासन है, आपने समाप्त कर दिया। हॉफ बिजली योजना को 40 यूनिट तक को आपने समाप्त कर दिया। कृषक ज्योति योजना को आपने बंद कर दिया। मुख्य मंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण को आपने बंद कर दिया। एक रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) है। अगर आपका थोड़ा सा भी कंट्रोल हमारी कंपनियों पर या विद्युत विभाग पर होता, तो शायद इतना स्लो नहीं होता क्योंकि मैं आपको प्रतिशत बताउंगा कि 3544.38 करोड़ का रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत भारत सरकार के द्वारा पैसा पास हुआ है। सिंचाई पंप हेतु पृथक 11KV कार्यों का फीडर वितरण को अलग करना, अत्यधिक लंबाई के 11 KV फीडर को छोटा किया जाना, सिंचाई पंप हेतु

पृथक फीडर की स्थापना, धन अनुरूप नए एल.. लाईन सर्किट की स्थापना, पुराने जर्जर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को एसएमसी बॉक्स में बदलना, आपके पास सिर्फ 03 महीना बचा हुआ है। मैंने पिछले समय भी कहा था, पर उस समय मैंने मेरे राजनांदगांव को एकाग्र करके बोला था, पर आज मैं प्रदेश लेवल पर बोल रहा हूं क्योंकि रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के 3000 करोड़ रुपए सारे विधायकों के इलाके संचालित हो रहे हैं। आपके पास 11 KV लाईन 12404.82 किलोमीटर में आप 4647.47 किलोमीटर ही बना पाए हैं, 7756 किलोमीटर शेष हैं और तीन महीने आपके पास शेष हैं। 14143 नग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आप 1981 ही बना पाए हैं 12116 आपके पास शेष हैं और तीन महीने शेष हैं। आपको एल.टी. लाइन में 4,950.91 कि.मी. लाइन बिछानी है, जिसमें आपने 90.78 कि.मी. ही लाइन बिछा पायी है और 4860 कि.मी., जो आपका 3 प्रतिशत या 4 प्रतिशत के रेशियो में जा रहा है। आपके पास पैसा है। आपके पास सबकुछ है। आपने भारत सरकार से पैसा भी ला लिया है। आपने जब किसानों के हितों में काम करने के लिये बीड़ा उठाया है तो आपके पास कंट्रोल कहा है ? आपके पास समीक्षा करने का समय नहीं है। इस ढंग से अगर सोचा जाये और यदि मैं इसका पूरा विवरण दू तो आपको एल.टी. लाइन, ए.बी. केबल, 5,703.23 कि.मी बिछानी है तो आपने केवल 419.94 कि.मी. ही बिछा पायी है। आपको 11 के.व्ही. की 4,471.93 कि.मी. लाइन बिछानी है और आपने सिर्फ 1,655.61 कि.मी. लाइन बिछा पायी है। अगर इनको पूरे घटक में जो टोटल खर्चा करना है, वह 3 से 4 प्रतिशत ही है। यदि ज्यादा होगा तो मैं 10 प्रतिशत दे देता हूं। आप सिर्फ 10 प्रतिशत ही काम कर पाये हैं। इस कार्य का टेंडर जिसने लिया है, जो बॉम्बे की कंपनी है, क्या उनकी निविदा प्रपत्र के आधार पर आप उसको दंडित करेंगे ? आप उनसे कितनी वसूली करेंगे ? आपके पास समय का चक्र है, यह ठीक है। यदि वह बड़ी पार्टी होगी तो आप उसकी निविदा शर्त के आधार पर वसूल कर लेंगे। लेकिन आपने जो समय गंवाया है, जिसके कारण किसान वोल्टेज प्रॉब्लम के कारण जूझ रहे हैं। बड़े लोगों की ए.सी. जलना और यह देहातों में तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। शहर में तो एक systematic ढंग से करंट दिया जाता है और देहातों की जो प्रॉब्लम है, उससे किसान ही भुगतते हैं। आपका किसी घटक में 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत ही प्रोग्रेस है। ठेकेदार एक मनमाने ढंग से, बेलगाम ढंग से काम कर रहा है। आपके पास कंट्रोल पॉवर नहीं है। सभापति महोदय, हम चलते हैं स्मार्ट मीटर की तरफ। आपके पास स्मार्ट मीटर लगाने का भी पैसा है, जिसके लिये फण्ड के प्रावधान में केंद्रांश का 15 प्रतिशत और 85 प्रतिशत राज्यांश है। इसे एजेंसी के द्वारा स्मार्ट मीटर रीडिंग का कार्य विवरण है। सभापति महोदय, अब इनको यह कार्य, वर्ष 2026 तक पूरा करना है। यह जो मैंने बताया है, इसमें आपका समय जुलाई में खत्म हो जायेगा और इनका वर्ष 2026 में खत्म होगा, मतलब आपके पास थोड़ा समय है। इनका भी अगर प्रोग्रेस देखेंगे तो मैं सोचता हूं कि 10 से 12 प्रतिशत प्रोग्रेस है। इससे ज्यादा नहीं है। यह भी इतना स्लो है। यह योजना बना लेना, कुसुम योजना बना लेना, यह कर लेना, इसे मैं तो नहीं मानता। यह आपका प्रतिवेदन बोल रहा है, मैं

नहीं बोल रहा हूं। चलिये, हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पी.एम. जनमन, इस संबंध में कल हमारे गृहमंत्री जी बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे। भारत सरकार के जनजातीय कार्यालय मंत्रालय द्वारा 7 जनजाति, अबुझमाड़िया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरवा, कमार, शहरिया, बिरहोर जातियों के आवासों में विद्युतीकरण हेतु कार्य किया जाना है। कल गृह मंत्री जी इतनी बड़ी-बड़ी बात बोल रहे थे। हम बोलना चाह रहे थे तो हमको बैठा दिया जाता था। आपके पास इन लोगों के लिये पैसा है, no doubt। स्वीकृत हाऊस होल्ड की संख्या 7,077 है। आपको इनके घरों में बिजली की लाइन लगाकर बिजली देनी है। परंतु आपने 5,726 लोगों को ही बिजली का कनेक्शन दे पाया है आगे कार्य प्रगति पर है। कल ऐसा कह रहे थे कि आपने सब कम्प्लीट कर दिया और आपने सब राशि का यूटिलाईजेशन कर दिया। आपके पास समय नहीं है। यह ग्रीड माध्यम से है। ग्रीड माध्यम मतलब विद्युत कम्पनी। दूसरा, आपका ऑफ ग्रीड माध्यम से, मतलब सौर ऊर्जा, यह आपको क्रेडा विभाग से कराना है। ऑफग्रीड के माध्यम से 1,578 स्वीकृत हाउस होल्ड है, जिसमें से आपने सिर्फ 232 घरों में ही लगा पाया है, इतना स्लो है। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया, दिल्ली ले गये, हमने पूरे वनवासियों के नक्सल बेल्ट का उद्धार कर दिया, वह ऐसी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। यह आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है ? विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त कार्य की समयावधि दिसम्बर, 2024 निर्धारित किया गया था। दिसम्बर निकल गया, जनवरी निकल गया और आप समय पर काम नहीं कर पाये। यह आपके काम करने की तारीख है। आपका कार्य दिसम्बर में पूर्ण हो जाना चाहिए था। आपने जनवरी, फरवरी, मार्च निकल गया और आप दो साल बाद करेंगे। इसमें यह लिखा है कि दिसम्बर, 2024 में निर्धारित करने की गाईड लाईन थी। हम उन्हें क्या दण्डित करेंगे? क्या हम उनके विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? उनसे कितनी वसूली होगी? उस निविदा की शर्तों में सब नियम है सिर्फ समीक्षा करने की जरूरत है और निर्देशित करने की जरूरत है, उन पर कड़ाई करने की जरूरत है। भारत सरकार द्वारा विद्युत विहीन घरों, बसाहटों में विद्युतीकरण हेतु शायद यह 32 हजार 300 करोड़ है। दिनांक 4/10/2024 को इसमें पैसा आया हुआ है आप इसकी निविदा जारी नहीं कर पाये हो। जब आप समय पर राशि का उपयोग नहीं कर पा रहे हो और उसकी निविदा भी नहीं कर पा रहे हो। जहां पर विद्युतविहीन है, उन गरीबों के घरों में विद्युतीकरण का कार्य करना है, लेकिन आप उसकी निविदा नहीं कर पा रहे हैं। आपके विभाग का यह हाल है। यहां पर हमारे मंत्री जी GATI की बात कर रहे थे तो आपकी GATI कहां गई ? यहां अब उल्टी GATI हो रही है। इस प्रदेश की GATI दिशाविहीन हो गई है।

सभापति महोदय :- माननीय दलेश्वर साहू जी, आप 20 मिनट से ऊर्जा विभाग में चल रहे हैं। आपकी गति धीमी है। मुख्यमंत्री जी के पास बहुत से विभाग हैं, आप तेज गति से चलिये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, हम चलेंगे। इस विभाग में जहां कमियां हैं, उसी पर धावा बोलेंगे। हमारे अन्य सदस्य जो संस्कृति विभाग पर बोलेंगे और किसी दूसरे विभागों पर बोलेंगे। यहां पर हम हकीकत को बयान करने के लिए खड़े हुए हैं या बेवजह हम तारीफ कर दें।

सभापति महोदय :- मैं, आपको मना नहीं कर रहा हूँ। आज तेज गति से बोलें।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, हम उन्हीं विषयों पर बोलेंगे, जहां कमियां हैं, हम उसी की बात करेंगे। आज हमारे गृह मंत्री जी नियद नेल्ला नार योजना की बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे। केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थापित 30 सुरक्षा कैम्पों के समीप 5 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत आने वाले 115 ग्रामों में सर्वांगीण विकास हेतु चयन किया गया है। कल यहां पर हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कीं। मैं आपके विभाग का प्रोग्रेस बता रहा हूँ। ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण 8 ग्रामों में शेष और 105 आवासों को तथा ऑफ ग्रिड माध्यम से विद्युतीकरण करना है। मैं तो यह सोच रहा था कि इसमें और बजट आ गया होगा तो आपने इसे पूरा कर दिया होगा। कल यहां पर इस नियद नेल्ला नार योजना की खूब चर्चा हुई है। एक है जिसमें 8 ग्रामों का चयन, 3 सुरक्षा कैम्प के समीप 5 किलोमीटर की परिधी में सर्वांगीण विकास । आपने सिर्फ 1 हजार 1597 में 5 ही कर पाये हैं। अपग्रिड के माध्यम से 105 ग्रामों का चयन, 3 सुरक्षा कैंप के समीप 5 किलोमीटर की परिधि में सर्वांगीण विकास । 7 हजार 183 में केवल 3 ही हुए हैं। यह दुर्भाग्य है। यह हजारों में है और आपकी प्रगति 3 बताती है। यह आपके ही लिखे हुए प्रतिवेदन में है। यहां पर मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूँ। पर जो वक्ता है और अच्छा बोल लेता है इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग उनकी बातों को सुनते रहे। हम तो तथ्यात्मक बात करेंगे। जो हकीकत है और यह आपका ही प्रतिवेदन है, हम उसी पर बात करेंगे। यहां मंत्री जी जो बोल रहे होंगे, वह ठीक है या आपका प्रतिवेदन गलत होगा। अगर आपका प्रतिवेदन गलत है तो यहां मंत्री गलत बोल रहे होंगे।

माननीय सभापति महोदय, तेलंगाना राज्य के 2 पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जनवरी 2021 की अवधि में, आप उनसे पैसा वसूल नहीं कर पा रहे हैं। आपका वर्ष 2021 का पैसा बाकी है, वर्ष 2022 का पैसा बाकी है, वर्ष 2023 का पैसा बाकी है, और वर्ष 2024 का पैसा बाकी है। अगर इस प्रदेश का एक किसान आदमी दो महीने बिजली का बिल न पटाये तो उनके घर की लाईन काट देंगे। अगर वह 3 महीने तक बिजली का बिल नहीं पटायेगा तो आप पुलिस थाने में केस कर देंगे और उसको अंदर कर देंगे। जो वर्ष 2021 का पैसा बाकी है, वह पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर आपका व्रजहस्त है। यह हकीकत है और इस ऊर्जा विभाग के बारे में आपसे कुछ तथ्य बताने का प्रयास किया। अब हम शिक्षा विभाग में आते हैं। शिक्षा विभाग भी दायित्व मुख्यमंत्री जी के पास है। इसका बंटवारा कर देते तो शायद मुख्यमंत्री जी के पास इतना बोझ नहीं होता, इसका काम इतना धीमी गति से नहीं होता। हमारे अच्छे-अच्छे विधायक चुनकर आये हुए हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, उनको दायित्व दे देते। पता नहीं क्यों इतना मोह

है, क्या ऊपर से निर्देश नहीं है? एक-एक विभाग को संभालना और 20-25 विभाग की समीक्षा करना, इतने सारे विभागों का पूरा बोझ लेकर रखे हुए हैं। माननीय राजेण मूणत जी, अजय चन्द्राकर जी को देते या और किसी दूसरे को इन विभागों का दायित्व दे देते तो कम से कम विभाग की समीक्षा होती और समय पर काम होता। आप लोगों की लापरवाही के कारण आम जनता और किसान भुगत रहे हैं। शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन की प्रस्तावना में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पश्चात ही संपूर्ण राज्य में शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 06 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों हेतु प्रदेश में आवश्यकतानुसार नये विद्यालयों की स्थापना एवं संचालित विद्यालयों की उन्नत एवं विकसित किया जा रहा है। यह शिक्षा विभाग का दायित्व है। आगे बढ़ना, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना, अच्छे प्रदेश का निर्माण करना, अच्छे घरों का निर्माण शिक्षा के बिना संभव नहीं है। मैं प्रदेश के स्कूलों के भवन के बारे में बात करना चाहूंगा। 2773 प्राथमिक शाला जर्जर हैं, 782 भवनविहीन हैं। हाथा की तो मैं बात ही नहीं करता, बच्चियों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाथा का भी होना चाहिए। 947 पूर्व माध्यमिक शाला जर्जर, 255 भवनविहीन हैं। आपके पास भवन ही नहीं है। बजट को देखेंगे तो एक-दो करोड़ रुपये की व्यवस्था कर देंगे, उससे तो दो, चार, पांच स्कूलों के भवन के अलावा बनना नहीं है। 29 हाईस्कूल जर्जर, 167 भवनविहीन हैं। 76 हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन जर्जर, 93 भवनविहीन हैं। यह ला दिये, वो कर दिये, यह योजना ला रहे हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। सभापति महोदय, यह स्थिति है।

श्री सुशांत शुक्ला :- दलेश्वर भैया, माफ कीजियेगा। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में व्यापक भष्टाचार करके इनको बड़ी जल्दी स्कूलों की स्थिति याद आ गई। पिछले 5 साल तक स्कूल उन्नयन के लिये आपकी बाट जोहते रहे और उस राशि में भी बच्चों के पैसे में भ्रष्टाचार किया गया। उस समय आपकी चिंता कहां थी।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- क्या भ्रष्टाचार हुआ, उसको बताईये ?

श्री सुशांत शुक्ला :- चूना में कलर मिलाकर स्कूलों की पुताई कर दिया है। प्लास्टर के नाम पर भ्रष्टाचार किये, स्कूलों में भ्रष्टाचार किये, यह विद्युतीकरण की क्या बात करते हैं, भ्रष्टाचार के नाम पर आप लोगों ने बच्चों को नहीं छोड़ा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यह फिर पूर्ववर्ती सरकार में पहुंच गये। पूर्ववर्ती सरकार में स्कूलों के उन्नयन का काम किया है। आप लोगों राशि को वापिस ले लिया है। भवन के लिये राशि प्रदान की गई थी, उसे भी आप वापस ले लिये।

श्री मोतीलाल साहू :- रंगरोगन के लिये इतनी राशि खर्च की गई जितने में नया भवन निर्माण किया जा सकता था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने फिर से राशि वापस ले ली है।

सभापति महोदय :- मोतीलाल जी, आप बैठिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- मेरी इकलौती विधान सभा में मुख्ममंत्री स्कूल जतन योजना में 16 करोड़ रुपये का कार्य हुआ। यदि स्कूलों का उन्नयन नहीं हुआ होगा तो आप बताईये। छाती पीटने से बेजायज आरोप लगाने से काम नहीं चलता। आपको जिम्मेदारी से स्वीकार करना चाहिए। हमने स्वीकार किया है। जनता ने जनादेश दिया है और हम काम करके दिखायेंगे। 05 साल की पूतिपूर्ति सुशासन के संकल्प के साथ होगी। आप चिंता न करें।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप 05 साल से बाहर निकलेंगे या नहीं, यह पहले बता दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपके 05 साल के कार्यकाल को याद दिलाता हूं तो आपको तकलीफ क्यों होती है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सारे कार्य किये थे। जो राशि प्रदान किये थे, वह राशि को इस सरकार ने वापस ले लिया। जब स्कूल शिक्षा की बात करते हैं तो जो राशि स्कूल के लिए दी गई थी, उसको क्यों वापस लिये ?

सभापति माहेदय :- संगीता जी, आप बैठिये। मेरा सदस्यों से आग्रह है कि बहुत वक्ता हैं, पक्ष की तरफ से भी 15-16 वक्ता हैं और विपक्ष की तरफ से भी 17 वक्ता हैं। मेरा अनुरोध है कि आप अपने-अपने समय में अपनी बातों को रखें। बीच में टोकाटाकी न करें। मैं आग्रह करूंगा कि आपको बोलते हुए 25 मिनट हो गये है, 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट में समाप्त करता हूं। बाकी हमारी बहन लोग, विधायक लोग बोलेंगे। यह तो जर्जर स्कूल, भवनविहीन स्कूल, हाथा विहीन स्कूल का हो गया। मैं अभी हाथा विहीन स्कूल का उल्लेख नहीं किया। अब हम चलते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहां ?

श्री दलेश्वर साहू :- जहां एक शिक्षकीय शाला है, वहां चलेंगे। 439 शालायें शिक्षकविहीन हैं, 400 स्कूलों में एक भी गुरूजी नहीं हैं। आप वनांचल की बात करते हैं, सरगुजा की बात करते हैं, पी.एम. जनमन योजना की बात करते हैं। हमारे चन्द्राकर जी, नियद नेल्लानार योजना की बहुत तारीफ कर रहे थे। 439 शालायें शिक्षकविहीन हैं, 5912 एकल शिक्षकीय शाला हैं तो आप क्या भविष्य बनाना चाह रहे हैं ? आप बच्चों के जीवन को अंधकारमय करना चाह रहे हैं । 56,601 शाला पद रिक्त हैं, आप भर्ती नहीं कर पा रहे हैं । जो गुरूजी लगे थे उनको भी आपने बैठा दिया । शिक्षक भर्ती पर विचाराधीन, लगभग 33,000 पर आपका विचाराधीन चल रहा है । आप विचार ही करते रहिये । सीधी भर्ती वर्ष 2003 में बी.एड. अर्हता के कारण सेवा समाप्ति किये गये सहायक शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं शासन के सुझाव देने के लिये आपने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति का गठन किया था, उसका क्या हुआ ? जब किसी की नौकरी लगती है तो वह सपना देखता है

और इतने साल नौकरी करने के बाद आप उसको बैठा देते हैं, आप उनके लिये भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लेते । नौकरी में है करके बाप अपनी बेटी का वहां विवाह करता है । कोई भी आदमी सुख-चैन से जीने के लिये पढ़ाई-लिखाई करते रहता है । आपने पढ़े हुए व्यक्ति को नौकरी में लगाने के बाद बैठा दिया । अध्यक्षता के रूप में सचिव लेवल की कमेटी में कम से कम उनके लिये सहानुभूतिपूर्वक विचार करके प्रस्ताव भेज देते । वित्त विभाग के लिये कौन सी बड़ी बात है, इतनी बड़ी-बड़ी बात करते हैं तो उनके लिये भी एक व्यवस्था कर देते लेकिन उस ओर आपका ध्यान नहीं गया । माननीय वित्तमंत्री जी, महाविद्यालों के पदों की जानकारी, स्वीकृत पद 717 जिसमें 184 कार्यरत हैं और 593 रिक्त हैं । यह शैक्षणिक का है और अशैक्षणिक के 1538 पद स्वीकृत हैं जिसमें 547 कार्यरत हैं और 951 रिक्त हैं । यह हाल है । हॉयर सेकेण्डरी, हाई स्कूल के प्राचार्यों का रिक्त पद, स्वीकृत पद 4730 है, कार्यरत 876 है और 3860 रिक्त है । इतना वेरियेशन, इतना अंतर । अगर थोड़ा बहुत 2-4 परसेंट का अंतर होता तो कवर हो जाता, चलो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप कितना कवर करेंगे ? आप कर ही नहीं पायेंगे । हॉयर सेकेण्डरी स्कूलों के व्याख्याता के पद, 44,420 स्वीकृत पद हैं, 35,630 कार्यरत हैं और 8851 रिक्त हैं और आप भविष्य बनाने चले हैं । यदि आप शिक्षा के स्तर को गिराओगे, यदि आप शिक्षा के स्तर को नहीं सुधारेंगे । ठीक है कि बड़े लोग तो प्राईवेट स्कूलों में जाकर पढ़ लेते हैं लेकिन गांव के जो अंचल, आप बार-बार जिस सरगुजा और बस्तर की बात कर रहे थे, वनांचल की बात कर रहे थे तो यदि गुरूजी ही नहीं रहेंगे तो कहां से पढ़ायेंगे ? यह आपके विभाग का हाल है, आपके शासन का हाल है ।

माननीय सभापति महोदय, पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को कबाड़ियों को बेचने के दोषी । इतनी लापरवाही कि आपने जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको आपने कबाड़ में बेच दिया, यह हाल है और जब जांच हुई तो आपने सीधे ग्रेड-2 यानी एक बाबू को सस्पेण्ड करते हैं । यह लापरवाही, शिक्षा विभाग में यह दुर्गति और एक छोटे जिला शिक्षा अधिकारी सहायक ग्रेड-2 को जिम्मेदार ठहराते हुए आप उनके निलम्बन की कार्रवाई करते हैं, आप इसमें बड़े मुर्गा के ऊपर भी कार्रवाई करते।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग पर चर्चा हो रही है । यहां पर केवल एक मंत्री उपस्थित हैं और 20 मांगों पर चर्चा हो रही है लेकिन केवल 10 या 12 अधिकारी ही बैठे हुए हैं या तो लंच का टाईम है तो थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिये रोक दें और जब सब आ जायें तो हम चर्चा कर लें ।

सभापति महोदय :- माननीय वित्तमंत्री जी हैं, वे सुन रहे हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अधिकारियों की भी बात की है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, एक नीति आयोग रैंकिंग अनुसार चूंकि रैंकिंग होती है कि कौन सा स्कूल कितना प्रतिशत, प्राथमिक स्तर की रैंकिंग, माध्यमिक स्तर का रैंकिंग है, हाई स्कूल स्तर की रैंकिंग है। उस रैंकिंग में भी परसेंटेज मिलना चाहिए। जहां गुरूजी ही नहीं है, जहां

स्कूल भवन ही नहीं हैं तो रैंकिंग की क्या बात करेंगे? सभापति महोदय, 1.85, 5.3 माध्यमिक में है। हाई स्कूल में रैंकिंग का 3 प्रतिशत है। वर्ष 2023-24 में मेरे इलाके का थोड़ा सा मैं ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा। एक मचानपार बुधोभर्दा माड़ीतरई में हाई स्कूल भवन साल भर से स्वीकृत है। शिक्षा विभाग का हाई स्कूल का भवन बनना है, पर जैसे ही शासन चेंज हुआ फिर वित्त विभाग ने आपत्ति लगायी कि कोई भी काम जब तक वित्त विभाग के निर्देश में नहीं हो तो कार्य को प्रारंभ न करें। वित्त मंत्री जी थोड़ा सा प्लीज इधर सुनिए। ओ माता जी। वित्त विभाग के परमिशन के चक्कर में स्वीकृति हुए निविदा भी हो गया है, टेंडर भर खुलना था, वर्क ऑर्डर जारी होना था, आज भी साल गुजर रहा है, आज ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर जारी नहीं मिल रहा है। यह शिक्षा का भवन है, कोई विलासिता का भवन नहीं है। इस भवन के लिए भी मैं सोचता हूं। अब पी.डब्ल्यू.डी. तो आया नहीं होगा, शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठे होंगे, उस दिन चर्चा होता तो शायद हम लोग इसको बोल पाते। मैं इस सदन के माध्यम से इस परिचर्चा के माध्यम से इस भवन के बारे में कहना चाहता हूं और यह मामला आपके यहां नहीं है। राजनांदगांव, मोहला-मानपुर छात्रावास का भी मामला है। राजनांदगांव, मोहला मानपुर छात्रावास भवन के लिए 3 करोड़ 92 लाख 78 हजार रूपये की स्वीकृति है।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, समाप्त कीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- और 75 लाख 23 हजार रूपये हाई स्कूल भवन सीता नवीन गांव के लिए है। ये वन अंचल का है। मेरे क्षेत्र का तो 4-5 है। अगर आप आदिवासी अंचल की सुध लेने वाले इस ढंग से भवन नहीं बना पाओगे तो दुर्भाग्य है। बस एकाध में और बोलूंगा।

सभापति महोदय :- नहीं, समाप्त करिए। 35 मिनट से ज्यादा हो गये हैं। प्रथम वक्ता हैं, इसलिए आपने काफी बोला है।

श्री दलेश्वर साहू :- बस, 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। वाणिज्यिक कर एवं आबिकारी विभाग है। मेरे यहां विधान सभा में जब हमारा कार्यकाल था तो मैं साफ साफ बोलता था। कोई थानादार आता था तो मैं बोला कि भाई तुमको यहां रहना है तो मेरे इलाके में शराब नहीं बिकवाओगे। नंबर टू, अगर इस ढंग से करोगे तो मेरे विधान सभा में रहना अन्यथा कहीं दूसरे विधान सभा में चले जाना। हमारे शासनकाल में भी एक ठोक स्वीकृति हो गया था, एक ठोक भवन ले लिए थे, ऑर्डर हो गया था। लोग मेरे पास आए और बोले कि शराब भट्ठी खुलने दो, ये होगा। मैंने कहा कि मेरे रहते तक नहीं, मैं चुनाव हारना पसंद करूंगा। हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, बड़ा शौक से करते हैं, ऐसा नहीं कि अपने जीवनयापन को चलाने के लिए करते हैं। पर मैंने कहा कि मैं खोलने नहीं दूंगा, मैं वहीं बैठ जाऊंगा। मेरा शासनकाल है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं शराब भट्ठी खोलने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही शासन चेंज हुआ, एक नहीं चार खुल गए। ये हाल है। जहां आवक है, आप वहां पिला-पिला कर ही उनका विकास करना चाहते हैं। अभी तो और प्रस्ताव आया है। खैर यह तो मेरी विधान सभा की बात है। देशी

मदिरा के दुकान 166, कम्पोजिट मदिरा के दुकान 240, प्रीमियर विदेशी मदिरा के दुकान 29, विदेशी मदिरा के दुकान पूरा 678। अब पता नहीं दो साल में और कितनी संख्या में खुलेंगे? आप प्लेसमेंट में नौकरी रखते हो? जिस संख्या में उसको सुरक्षा की दृष्टिकोण से, जिस भी दृष्टिकोण से या संचालन की दृष्टिकोण से कर्मचारी रख रहे हो, वित्त विभाग को पता नहीं, न श्रम विभाग के नियमों को पालन किया जा रहा है, न वित्त विभाग का कंट्रोल है। अगर वित्त विभाग भी थोड़ा पत्र जारी करता तो शायद उस प्लेसमेंट में काम करने वाले शिक्षित बेरोजगार को, उसकी जो कटौती है जो भविष्य निधि की राशि है, वह कम से कम उसके खाता में जमा होता और निविदा शर्त के आधार पर उनको पेमेंट देने का अधिकार होता तो शायद उस बेरोजगार साथी को समय में पेमेंट मिलता। रेगुलर की तो बात ही नहीं सोचते । आपने जो पेमेंट तय किया है, आप शासन से पैसे ले रहे हो । मदिरा की एक दुकान में 5 कर्मचारी रखना है, वहां 2 ही कर्मचारी रख रहे हो और बाकी का पैसा, अधिकारी से मिली भगत करके, जिसने प्लेसमेंट लिया हुआ है, वे पूरे पैसे का खा रहा है ।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त कीजिए दलेश्वर जी ।

श्री दलेश्वर साहू :- कर दूं, कर दें, बैठ जाता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । जो अनुदान मांग सबसे आखिरी में है, मैं सबसे पहले उसी से अपनी बात शुरू करूंगा । सुशासन और अभिसरण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 58 नम्बर का एक नया विभाग बनाया, सुशासन और अभिसरण । सुशासन के लिए उन्होंने जो संकल्पना रखी, सोची और क्रियान्वित करने की शुरूआत की, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं । प्रतिवेदन में जो बात कही, लोगों के लिए चिंतन शिविर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आए, सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन, नई शिक्षा नीति । शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे । सुगम एप, सिंगल विंडो सिस्टम, ई-ऑफिस प्रणाली, सी.एम.पोर्टल यानी अपने ऑफिस को भी आपने ऑनलाईन किया । सुशासन विभाग के द्वारा पी.एस.सी. परीक्षा में पारदर्शिता, साइबर अपराधों की रोकथाम, अनेकानेक योजनाएं, अनेकानेक विभाग जिनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की कोशिश हुई । मुख्यमंत्री हेल्प लाईन योजना, मुख्यमंत्री जी से आप सीधे बात कर सकते हैं । यह सिर्फ एक योजना ही नहीं है, यह एक संवेदनशीलता भी है । अटल मॉनीटरिंग डेस्कबोर्ड, अनुसंधान नीति विकास अध्ययन, इस प्रदेश को आगे ले जाना है तो केवल कुछ आंकड़े ही काम नहीं कर सकते । कुछ आंकड़े हमें विभागों से मिल गए और उनके आधार पर हम नीति बना दें । खासतौर पर यह अनुसंधान नीति विकास इसलिए जरूरी हो जाता है जब देश की जनगणना दुबारा कब होगी, नहीं मालूम । हम अपने स्तर पर अपने आंकड़े जुटाकर क्षेत्रीय चीजों का अध्ययन कर कोई नीति, कोई कार्यक्रम बना सकें यह संकल्पना प्रदेश के सामने, प्रदेश की तीन करोड़

जनता की बेहतरी के लिए रखने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो वह विष्णुदेव साय जी हैं। मैं उनको बार-बार साधुवाद देता हूं । सभापति महोदय, क्षमता विकास, प्रशासन की क्षमता विकास हो, हमारी क्षमता विकास हो, हम आईआईएम में दो दिन, तीन दिन काम सीखने जा रहे हैं । आम लोगों की क्षमता विकास हो, हम एक कुशल मानव संसाधन बनते हैं, कुशल बनते हैं तो मैं सोचता हूं कि प्रदेश की सेवा ईमानदारी से, अच्छे से और नीति और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अच्छे से होगा ।

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, सुशासन के लिए । लोग आईआईएम के साथ मिलकर और जो उत्कृष्टता के संस्थान हैं, उनके साथ मिलकर काम कर सकें । यह पहला प्रतिवेदन है जिसमें अभिसरण की बात कही गई है । सुशासन आ जाएगा, मैं एक उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं । इसमें लिखा है क्षमता विकास, कौन कौन सा विभाग है जो क्षमता विकास करता है । माननीय चौधरी जी, मुझे लगता है कि सभी विभाग क्षमता विकास का काम करते हैं । यदि हम इन योजनाओं को एक अम्ब्रेला में ले आते हैं, वन विभाग भी क्षमता विकास कर रहा है, पर्यटन विभाग भी कौशल उन्न्यन कर रहा है, ग्रामीण विकास विभाग भी कौशल उन्नयन कर रहा है, शहरी विकास विभाग भी कौशल उन्नयन कर रहा है, लाइवलीहुड में तकनीकी विभाग भी कौशल उन्नयन कर रहा है, आदिम जाति विकास विभाग कौशल उन्नयन कर रहा है और उनके कितने विभाग कौशल उन्नयन कर रहे हैं, कितने लोग नियोजित हुए, कितने लोग कौन सी चीजों में दक्ष हुए, प्रशिक्षित हुए ? यह एक छोटा सा उदाहरण है । यदि हम इसे एक अम्ब्रेला के नीचे ला देते हैं तो उसका प्रभाव एक सेकेंड में दिखना शुरू हो जाएगा (मेजो की थपथपाहट) । ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं, मैं उसको आगे बोलूंगा। साहित्य अकादमी, उच्च शिक्षा विभाग में है, साहित्य अकादमी संस्कृति विभाग में है, मुझे ये समझ में नहीं आता, एक साहित्य अकादमी में 8 शोधपीठ हैं, एक साहित्य अकादमी में 3 शोधपीठ हैं, वे दोनों मिलकर क्या काम कर रहे होंगे ? ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे सड़क दुर्घटना, अभी होली के दूसरे दिन 12 लोग मर गए, परसों मेरे क्षेत्र में सड़क में चलते हुए 4 लोग मर गए, एक SUV रौंदकर चली गई। कौन जिम्मेदार हैं, इसके लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है ? मैंने उसमें 139 में चर्चा की थी। जो जिम्मेदार विभाग हैं, यदि वे अपने बजट, अपने संसाधन और को-आर्डिनेशन से काम करें तो शायद हम सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण पा सकते हैं या मृत्युदर या विकलांगता दर को कम कर सकते हैं।

सभापति महोदय, अभिसरण, मैं सोचता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी तरह के कामों की संकल्पना की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुशासन और अभिसरण की जो संकल्पना की है, मैं उनको फिर से साधुवाद देता हूं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, जब विभाग आएगा तो बधाई दूंगा। मसलन, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना। औद्योगिक नीति में पर्यटन संबंधी जो निर्माण होंगे, पर्यटन संबंधी जो निर्णय होंगे, उसके लिए छूट देना। यदि शुरू से पर्यटन उद्योग का दर्जा

हो जाता तो शायद छत्तीसगढ़ के पर्यटन का परिदृश्य कुछ दूसरा होता, हम बात करेंगे। जो ग्रीन एनर्जी है, दलेश्वर साहू जी, किधर-किधर खिसक रहे थे, किधर-किधर बहक रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उनको विद्युत का करंट ज्यादा लग गया था। वह पुराने मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र रहा है, डोंगरगढ़ में बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी, इसलिए वे बिजली से उबर नहीं पा रहे थे। थर्मल के लिए, सौर के लिए, पंप स्टोरेज के लिए नये क्षेत्रों में जो रिन्यूवल एनर्जी है, उनके लिए 3 लाख करोड़ का MOU किया, हम नये सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं, नये विषयों को स्पर्श करने जा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं ? यही चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ की जरूरत है जिसको नये ढंग से कदम उठा रहे हैं। मध्यप्रदेश से आने के बाद छत्तीसगढ़ बना तो हमने पशुपालन विभाग में देवभोग ब्रांड बनाया। आपने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एनडीडीबी से समझौता किया, हमारा जो देवभोग है वह मजबूत हो, उसकी ब्रांडिंग हो, उसका भी कौशल उन्नयन हो, उसकी भी क्षमता विकास हो। आपने राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक लिमिटेड से जो लघु वनोपज संघ मर्यादित है, आपने उसके साथ MOU किया। लहरिया जी, ये नवाचार समझने के लिए अक्ल चाहिए। आपने पूरे पांच साल में कुछ नहीं किया, आप एग्रो पर्यटन करते थे, छत्तीसगढ़ में लोग आते थे तो गोबर दिखाते थे, आप गौठान देखने चलिए बोलते थे, एग्रो पर्यटन के छोड़ छत्तीसगढ़ में पांच साल कुछ काम नहीं हुआ। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, सामान्य प्रशासन। मैं छोटी-छोटी बात करता हूं। जल्दी-जल्दी एक लाईन में बोलता हूं। 23 विभाग है, एक मिनट बोलूंगा तो 23 मिनट लगेंगे, दो मिनट बोलूंगा तो 46 मिनट लगेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग में छोटे-छोटे सुझाव, छोटे-छोटे विषय हैं, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्यों के प्रशासन के बीच में संबंध। माननीय मंत्री जी, आप यदि पत्रों के उत्तर भर दे दें, कॉलबैक कर दें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन की परिकल्पना इतने में आधी साकार हो जाएगी। यदि हम चिट्ठी लिखते हैं, यदि हम फोन करते हैं तो उसके कॉलबैक मिल जाए उसके लिए तो फुर्सत नहीं रहती, इतना ही करवा दें तो आधे लोगों का संतोष, आधे लोगों की इच्छा, आधे लोगों का काम आधा हो जाएगा। आप दो दिन बाद कॉलबैक करिए न, वाट्सएप में उत्तर दे दीजिए। आपके लिए जो चीजें प्रसारित हैं जिसके निर्देश जारी हैं, वह क्रियान्वयन हो जाए। सबके निर्देश। आप एक प्रकोष्ठ बना दीजिए। अब महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु और संवेदना संदेश का विषय है। इसी विधान सभा में षष्ठम विधान सभा में 2 बार घटना घट गई कि आपका प्रशासन उसकी बाद में सूचना दे रहा है कि Ex. MLA मर गया, उसका देह शांत हो गया। बाद में हम लोगों ने 2 बार condolences किया। यह घटना यहां पर 2 बार हो गई है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि, लोक सेवक के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है और हम इनके प्रति कितनी संवेदना रखते हैं, यह इससे झलकता है। इसके निर्देश हैं। आपके बहुत सारे कार्य हैं। मैं एक-एक को थोड़ा-थोड़ा पढ़ूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहां पर उपस्थित हैं तो मैं आपका एक विषय में ध्यान चाहूंगा कि आपने यह जो

राजनीतिकरण किया है। छत्तीसगढ़ में इतने सारे पुरस्कार हैं। अभी मैं उन पुरस्कारों पर भी बोलूंगा। वह पुरस्कार अपनी महत्ता खो चुके हैं। आपने सामान्य प्रशासन विभाग का एक और पुरस्कार जोड़ दिया है। आप उप नेता हैं, आप इसके बारे में बतायेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे पुरस्कार की छत्तीसगढ़ को जरूरत नहीं है। किस स्तर पर यह पुरस्कार दिया जाएगा और किसको दिया जाएगा, इसके संबंध में आपको कोई जानकारी होगी तो मुझे मालूम नहीं है। उपरोक्त पुरस्कारों में आप सामान्य प्रशासन विभाग से 3 पुरस्कार देते हैं। रविशंकर शुक्ल जी, यतियतन लाल जी और महाराजा अग्रसेन जी पुरस्कार और आप चौथा पुरस्कार देंगे। उपरोक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त विभाग द्वारा इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक सदभावना सामाजिक सौहार्द्र पुरस्कार प्रतिवर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समारोह पर दिया जाना प्रावधानित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगले साल जब यह प्रतिवेदन प्रिंट होगा तो यह लाइन प्रिंट हो कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र में इंदिरा गांधी जी का कोई योगदान नहीं था। इतनी बड़ी मॉबलिंचिंग हुई, जो आजाद भारत की सबसे बड़ी मॉबलिंचिंग थी।

माननीय सभापति महोदय, आप बिल्डिंग व सड़क का नामकरण करते हैं। मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा है कि भौगोलिक नाम में परिवर्तन शासकीय भवनों का नामकरण। मैंने आपके विभाग में नामकरण के संबंध में 2 प्रश्न लगाये थे। भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 साल में छत्तीसगढ़ में, माननीय वित्त मंत्री जी, यदि इनको देखे, जो मैं बोलने जा रहा हूं तो बाहर का आदमी आएगा, उसको ऐसा लगेगा कि इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण शायद कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम लोगों ने 15 साल तक बैठकर कुछ नहीं किया और यह 20वां-22वां साल शुरू कर रहे हैं, तब भी हमने कुछ नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सर्कुलर आपके यहां लागू है, उस सर्कुलर का उल्लंघन करके किसी को जिला स्तर पर, किसी को बिना सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के 5 साल में उन्होंने 1054 संस्थाओं, सड़कों व कॉलोनियों के नाम परिवर्तन किये हैं। गलत नियम से नाम रखे हैं, किसी को legislation से परिवर्तित किया, किसी को जबरदस्ती परिवर्तित कर दिया और आपने नाम परिवर्तन की यह गलत परंपरा डाली। क्या आपने और कुछ किया ? बताने के लिए तो कुछ नहीं था। कोई आये तो उसको दिखा दो कि इसको हमने बनाया है। मैं नाम नहीं लेता। [xx] की हद होती है। एक व्यक्ति के नाम में 10-10 हैं। मैं आपको इतना बड़ा फोल्डर दे दूंगा। उसको आप लोगों का मौन समर्थन था। क्या आज उस पर बोलने से कोई फर्क पड़ेगा ? जिस समय नियम टूट रहे थे, परंपरा टूट रही थी, उस समय के आपके मौन को यह प्रदेश माफ नहीं करेगा। (मेजों की थपथपाहट) माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इसमें एक कमेटी बने, जो इस बात की समीक्षा करे कि गलत नामकरण हुए हैं और परंपरा से हटकर हुए हैं, इसलिए वह यथास्थिति में लाये जायें। छत्तीसगढ़ के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का कोई योगदान नहीं है। अटल जी को छोड़कर कोई दूसरा आदमी यदि कहे तो वह सही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं संस्कृति विभाग में कुछ लाइनें बोल देता हूं। मैं इस विभाग में रहा हूं और यह मेरे सबसे प्रिय विषयों में से एक है। यदि मैं इसमें बोलूंगा तो मेरे बोलने का पूरा समय इसी में चला जाएगा। इसलिए मैं इसको केवल स्पर्श करते हुए आगे बढ़ूंगा। मैंने पिछले 5 साल में इसमें कई अशासकीय संकल्प लाये। भूपेश बघेल जी ने एक अशासकीय संकल्प में उत्तर दिया। उनके तत्कालीन संस्कृति मंत्री अमरजीत जी यहां पर बैठते थे। उन्होंने कहा कि आप इसको वापस ले लीजिए। हम संस्कृति परिषद बनाएंगे। आयोजन करना और संरक्षण देना, ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। माननीय केदार जी, मैंने भरथरी का आयोजन किया। मैं भरथरी सीखना चाहता हूं और सिखाने के लिए यह संस्था है, इन दोनों में अंतर है। दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान के सबसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कोई प्रदेश होगा तो छत्तीसगढ़ है, यह मैं साबित कर सकता हूं। लेकिन उसके साथ यह दुर्भाग्य भी जुड़ा है कि उसके सरंक्षण के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए कोई संस्था काम नहीं कर रही है। अब माननीय विष्णु देव साय जी ने जब यह संकल्प व्यक्त किया है और वह उस समृद्ध संस्कृति से चुनकर आते हैं, तो मैं यह अपेक्षा जरूर करूंगा कि आपने जो सुशासन की अवधारणा प्रस्तुत की है, उस सुशासन में कोई प्रदेश जाना जाता है तो अपनी समृद्ध संस्कृति परम्पराओं से ही जाना जाता है। छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध परम्पराओं से पर्यटन को भी प्रभावित करेगा, प्रशासन को भी प्रभावित करेगा, आय भी अर्जित करेगा और देश-दुनिया में नाम भी कमायेगा। आप बस्तर पण्डुम करते हैं। यदि यह बस्तर पण्डुम दिल्ली में करते तो कितनी बड़ी बात होती, उसका क्या एक्सपोजर होता, उसको सोचिये। अब यह सन् 2020 में बना। इसके अन्तर्गत क्या-क्या रहेगा, उसको सुनिये। साहित्य अकादमी, पन्ना लाल पदुम लाल बक्शी सृजन पीठ, श्रीकांत वर्मा पीठ, गुरूघासीदास पीठ, कला अकादमी, आदिवासी एवं लोककला अकादमी, नाचा केन्द्र, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी, ये सब इसके अंदर रहेंगे। और क्या लिखा है, वह मैं पढ़ देता हूं। परम्परागत कला संस्कृति एवं साहित्य पर शोध एवं अध्ययन होंगे। इसका सेटअप नहीं दिखा, पूरे प्रतिवेदन में कोई सेटअप नहीं दिखा। यदि इतना महत्वपूर्ण काम दिया गया है लेकिन इस प्रतिवेदन का उसका सेटअप नहीं है। उसके अध्यक्ष कौन होंगे, उसके उपाध्यक्ष कौन होंगे, उसके सचिव कौन होंगे, उसका कार्यकारी परिषद् क्या होगी, बैठक कैसे होगा, नियम कैसा होगा, कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के कला, संस्कृति और साहित्य की कौन से दौर की बात करेंगे ? उत्तर पाषाण काल की बात करेंगे, मध्य पाषाण काल की बात करेंगे या पूर्व पाषाण काल की बात करेंगे ? इतिहास के हर दौर में, हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का योगदान प्रमाणित रहा है। लेकिन सवाल यह है कि उसका दस्तावेजीकरण नहीं है, जो आगे आयेगा। आप मजाक कर रहे थे।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। 12 पुरस्कार एवं सम्मान देते हैं। देवदास बंजारे स्मृति में दो पुरस्कार देते हैं। छत्तीसगढ़ में इतने सारे लोक नृत्य हैं कि एक पुरस्कार सिर्फ पंथी नृत्य के लिए दे रहे हैं, एक पुरस्कार लोक कला के क्षेत्र में दे रहे हैं।

लोक कला, ललित कला कितना अधिक व्यापक है। उसमें तो आप एक-एक में पुरस्कार दे सकते थे। तो ये दो पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ संतुष्टिकरण के लिए दे रहे हैं। देवदास जी ख्यातिनाम कलाकार था, उन्होंने भारत महोत्सव तक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। आपको इसमें जाने की जरूरत है। हम लोगों ने एक संस्था पुरखौती मुक्तांगन बनाई थी। पुरखौती मुक्तांगन दो सौ एकड़ में था। मैं भी इस विभाग में कुछ दिनों तक मंत्री था। ट्रिपल आई.टी. खुली तो बोले कि 25 एकड़ दे दीजिये और 25 एकड़ हम दे देंगे। वह वन विभाग का जमीन उससे लगा हुआ है, वन विभाग की जमीन दे देगा। 25 एकड़ तो नहीं मिला। ट्राइबल म्यूजियम के लिए 15 एकड़ ले लिया गया। शहीद वीर नारायण स्टेडियम के लिए 10 एकड़ जमीन ले ली गई। 200 एकड़ में बना, उसमें अब डेढ़ सौ एकड़ जमीन बचा है। भोपाल का ओपन म्यूजियम, खुला मानव संग्रहालय से बड़ा बनाने की संकल्पना करते थे। हमने वन विभाग से ज्यादा जमीन मांगी थी, 25 एकड़ जमीन दिया है, आप 50 एकड़ जमीन दीजिये। आज सांस्कृतिक परम्पराओं के सरंक्षण और पुनर्जीवन के लिए भोपाल के मानव संग्रहालय में शोध होता है। हम लोगों ने इसको उससे बड़ा बनाने की संकल्पना रखी थी लेकिन यहां जमीन घटते जा रही है। जमीन घटते जा रही है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने पुरखौती मुक्तांगन में लिखा है कि क्या-क्या बनायेंगे। उसको बनाने के बाद कितनी जमीन बचेगी, उसको देखियेगा। रायपुर में गुरूघासीदास जी के नाम पर संग्रहालय शोध पीठ संस्थान बनाये जायेंगे, कबीरधाम जिले के भोरमदेव के पास आदिवासी पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय में रिक्त भूमि पर भारत भवन निर्माण किया जाएगा, पुरखौती मुक्तांगन भूमि पर अभिलेखागार निर्माण किया जाएगा, पुरखौती मुक्तांगन में मानव संग्रहालय भवन निर्माण किया जाएगा। भूपेश बघेल जी ने सभी रिक्त भूमि में इतना सारा निर्माण का संकल्प लिया कि खुला मानव संग्रहालय, पुरखौती मुक्तांगन कहां पर है, उसको हम लोगों को खोजने जाना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक चीज के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप छत्तीसगढ़ के बारे में जितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में शोध नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश है, जहां अभी तक अभिलेखागार नहीं है। आप तीन साल से हर साल एक करोड़ रूपये दे रहे हैं, लेकिन वह अभी तक क्यों नहीं बन रहे हैं, यह मुझे नहीं मालूम। जब अभिलेखागार बनेगा तो मैं बोलता हूं कि सी.पी. बरार से ऊपर भोसले शाही तक के रिकॉर्ड को छत्तीसगढ़ में लाना चाहिए, चाहे जो भी चीजें छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदश के कुछ रिकॉर्ड आ गये हैं। यदि वह अभिलेखागार बनता है तो छत्तीसगढ़ के बारे में शोध होगा, छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान बनेगी। यह छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जिसके संग्रहालय में डायरेक्ट्रेट लगता है। हमारा जो गुरू घासीदास संग्रहालय है, उसमें पुरातत्व विभाग, संस्कृति विभाग और भी विभागों के डायरेक्ट्रेट लगते हैं, वहीं प्रदर्शन के लिए भी एम्फीथियेटर है, वहीं कला दीर्घा है, जिसे चित्रकारी व अन्य चीजों के लिए किराये में देते हैं। मैंने एक सुझाव दिया था, एक चीफ सेक्रेटरी थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरा सुझाव नहीं माना। छत्तीसगढ़ में जो पुलिस भवन है, वहां सारा डायरेक्ट्रेट ला दीजिये।

वहां पार्किंग की व्यवस्था है, वहां एम्फीथियेटर बनाईये, वहां अभिलेखागार रहेगा। रायपुर में सारे लोगों के मनोरंजन के लिए वह हृदयस्थल में एक सबसे अच्छी जगह होगी। मुझे नहीं मालूम कि आज तक उसमें क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ। पुलिस विभाग नये रायपुर में जाने के बाद उस बिल्डिंग को क्यों छोड़ना नहीं चाहता है, यह मुझे समझ में नहीं आया? उससे अच्छी जगह रायपुर में नहीं है, जहां आप दीर्घा भी बनवा लें, आप प्रदर्शन भी करवा लें, आप वहां आकार भी लगवा लें, वहां पार्किंग लगवा लें, भवन भी बनवा लें और वहां डायरेक्ट्रेट के लिए बना हुआ बिल्डिंग भी है, लेकिन मैं यह सोचता हूं कि अब एक संस्कृति प्रेमी मुख्यमंत्री आने के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जो भी संस्कृति के लोग हैं, वह थोड़ा सा सुन लें। कुलेश्वर मंदिर, नवागांव, जिला-धमतरी, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मंदिर है। आपने प्रतिवेदन में एक जगह लिखा है कुलेश्वर मंदिर, राजिम, जिला-गरियाबंद। भैया, उसको सुधरवा लीजिये। इसी प्रतिवेदन में लिखा हुआ है। वह कुरूद, नवागांव, धमतरी जिला है। मुख्यमंत्री जी, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए मैंने आपको बधाई दी। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं कि जो आपका बाहर का पर्यटन सूचना केन्द्र है, वह पूरी तरह से बंद हैं। आपने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है तो छत्तीसगढ़ की विविधताएं देश और दुनिया के सामने जानी चाहिए। पर्यटन केन्द्र कम चलायें, एक चलायें, लेकिन आप इस प्रतिवेदन के पेज क्र. 5 में देखेंगे, यदि कोई अधिकारी लोग होंगे तो देख लें कि जो 24 पर्यटन सूचना केन्द्र है, वहां पूरे के पूरे रिक्त पद भरे हुए हैं। जो छत्तीसगढ़ हॉटल है, हम आज के दौर में हॉटल चलायेंगे, यह कुछ समझ में नहीं आता है। आप सुशासन के अग्रदूत हैं। आप निजीकरण करिए, इसको लीज में दीजिए। वह हम लोगों के अर्थात् अधिकारी, नेता, यह सब वहां जाकर चाय पी लें और जितने फ्री लॉसिंग हो सकता है, वह उसी को काम देता है, वहां पर्यटन संबंधी कुछ काम नहीं होता है। आपको इस बात के लिए बधाई कि घुमरा रास आया। आपको इसलिए बधाई कि यूनेस्कों की टीम में अस्थाई तौर पर कांगेर घाटी भी शामिल हो गई है। सभापति महोदय, मैं एक किताब पढ़ रहा था, जो भी पर्यटन के अधिकारी होंगे, एक नई विधा जो कि हम लिखते हैं कि जितने भी प्रकार के पर्यटन, उसके अतिरिक्त एक पर्यटन उभर रहा है, वह है वेब पर्यटन । सभापति महोदय, न्यूजीलैंड की ओटेमो क्यू, इटली की ब्लू ग्रोटोक्यू, उत्तराखंड देहरादुन में रावर्ट केव, हमारे यहां भी तो जोरदार वाला केव है, कांगेर घाटी में ही है ? दुनिया में केवल पर्यटन उभर रहा है, हमारे यहां इतना बड़ा केव है, हम लोग उसका उपयोग करें, उसको प्रचारित करें । सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं थोड़े दिन के लिये पर्यटन मंत्री था, यह पुरातन संस्कृति थी । सिरपुर में 10 साल से कोई काम नहीं हो रहा है, जो 58 टीले हैं, साडा बनाई और साडा आप देखते हैं, यहां पूरे पद रिक्त हैं, कभी उसकी बैठक नहीं हुई है, सिरपुर यूनेस्को की धरोहर बनेगा । सभापति महोदय, सिरपुर में क्या नहीं हुआ है, औदान शतक एक किताब है, उसको पढ़ें । अरूण शर्मा जी जब जिंदा थे तो बोलते थे कि यह बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध आये थे। सभापति महोदय, उसी सिरपुर में 3000 से ज्यादा आचार्य और 10,000 से

ज्यादा विद्यार्थी रहते थे, मैं व्हेनसांग की किताब में इतना देखता हूँ, यह स्थापित है। महायान शाख की शून्यवाद सिरपुर की भूमि से ही निकला, हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म सारी चीजों को स्थापित कर सकते हैं । आप उसको व्यक्तिगत रूचि लेकर देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, जो अधिकारी लोग होंगे, फिर इसमें सुधार लेना । सभापति महोदय, धमतरी के पर्यटन में कुलेश्वर महादेव का फिर नाम नहीं है, अब एक लाईन में इस विभाग को खत्म करता हूँ । सभापति महोदय, इंस्टिट्यूट ऑफ हॉटल मैनेजमेंट, इतनी बड़ी संस्थान स्वाद, आतिथ्य, हॉस्पिटिलिटी दुनिया का सबसे उभरता उद्योग है । भारत सरकार के सहयोग से यह संस्था बनी, अब इसके अम्बलगहन साहब अध्यक्ष हैं । मैं इसको पढ़ रहा हूँ भई, इसका नाम नहीं ले रहा हूँ ? विवेक आचार्य जी प्राचार्य हैं, अब पेशेवर लोग आयें । छत्तीसगढ़ में आतिथ्य के सबसे तेजी से उभरते सेक्टर में मेनपॉवर तैयार हो, स्वाद में मेनपॉवर तैयार हो, स्वाद क्या है पर्यटन विभाग में होगा । सभापति महोदय, मैंने छत्तीसगढ़ की रेसिपी बनवाई थी, बस्तर तक पहुंचने के पहले सरकार चली गई, अवधिया परिवार ने काम लिया था तो उसका भुगतान नहीं किया । छत्तीसगढ़ की स्वाद भी अद्भूत है, बस्तर का लांदा खाकर देखिये, केदार कभी सब को लांदा खिलाईये । सभापति महोदय, सारे व्यंजन की रेसिपी छत्तीसगढ़ की भी बने, इसी संस्थान को दे दीजिए । छत्तीसगढ़ में लोग ठेठरी खुरमी इतना ही बस जानते हैं और अइरसा बोलेंगे, तीन चीज बोलेंगे ? एक पेशेवर संस्थान बने, उत्कृष्टता का संस्थान बने, देश के टॉप संस्थानों में से एक बने, आप इसके लिये काम करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। सभापति महोदय, धर्मस्य में बिना खोले आगे बढ़ता हूँ, कुछ मंदिरों में सेवादारों की सेवा यह है, मैंने प्रश्न किया था । छत्तीसगढ़ में जितने ट्रस्ट हैं, उसका दस्तावेजीकरण नहीं है, उस सरकार के मंत्री ने यही कहा कि मैं संचालक बनाऊंगा और संचालक और डिप्टी डायरेक्टर उन्होंने बना दिये । पैसे कैसे खर्च करेंगे, उसके निर्देश क्या है, पैसे का दुरूपयोग हुआ तो उसकी जांच कैसे होगी, समझ लीजिए कि यह हमारा वैचारिक क्षेत्र भी है । इस वैचारिक क्षेत्र में यदि ट्रस्ट के पैसे का दुरूपयोग होता है, एक जैतूसाव मठ में 50 लाख रूपये निकाले गये, मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कहा कि इसको जनहित में खर्च किया गया है और जनहित में क्या खर्च किया है, यह नहीं बता सके हैं ? जांच करवायेंगे तो उसका अध्यक्ष कांग्रेस का एक बड़ा नेता है । मुझे कहा कि मैं जांच नहीं करवा सकता, जाने दो 50 लाख रूपया को । मैंने चार-पांच मंदिर के नाम बताये कि इसमें ट्रस्ट है, इसमें पैसे हैं, इसमें गांव मे, त्यौहार में खर्च कर सकें, इसके लिये दिशानिर्देश इस धर्मस्व विभाग को बनाना चाहिये । सभापति महोदय, मेरी फिर बधाई ले लीजिए कि आप रामलाल के दर्शन का संकल्प लिये हैं, आप कौन सी भूमिका में हैं, आपने बंद योजना को शुरू किया, उसके लिए मेरी बधाई स्वीकार कर लीजिए । इस कार्यकाल का हमारा दूसरा बजट आ गया । माननीय वित्तमंत्री जी, आप संयोग से उपस्थित हैं । जो पॉच शक्तिपीठ को जोड़ने की बात है, उसका डीपीआर बने । कोई अच्छी संस्था उसका

डीपीआर बनाएं । आप कितना काम हाथ में लेंगे ? जब अगली बार हम भाषण दें तो लगे कि हमारे प्रदेश की पॉच शक्तिपीठों के लिए अब यह सरकार आगे बढ़कर काम कर रही है।

सभापति महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग । माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी योजनाएं, उपलब्धियां सब चीज ठीक है । लोगों ने आपके नेवता भोज को हाथों-हाथ लिया । 10 हजार से ज्यादा नेवता भोज हो चुके । सभी योजनाएं चल रही हैं । जो चिंताजनक स्थिति है, उसको मैं बता देता हूं । आपने सुशासन का संकल्प लिया है इसलिए मैं इसको बता देता हूं । आज के समय में 20 प्रतिशत से ज्यादा शाला त्यागी बच्चे हैं । जो अधिकारी समग्र शिक्षा देखते हैं, मैं बोलने के पहले उस अधिकारी को फोन किया था कि एस.सी., एस.टी. के कितने बच्चे हैं और बस्तर के कितने बच्चे हैं और सरगुजा या जशपुर के कितने बच्चे हैं, यह जानना जरूरी है । दूसरी एक चिंताजनक बात है कि सरकारी स्कूलों में दर्ज संख्या निरंतर कम हो रही है । तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, माननीय मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हम 33000 भर्ती करेंगे । फिर आपका एक वक्तव्य आया कि हम युक्तियुक्तकरण करेंगे। फिर वह युक्तियुक्तकरण निकल गया । दर्ज संख्या कम हो रही है, स्कूल शिक्षाविहीन है । अब इसमें आप क्या कदम उठाएंगे कि यह संतुलित हो जाये कि 33,000 पदों की जरूरत नहीं है, युक्तियुक्तकरण से हो जाएगा तो युक्तियुक्तकरण एक टाईम बीइंग प्रोग्राम बन जाए । इसका विरोध कौन करता है । छोटा सा छत्तीसगढ़ हो गया, यदि छत्तीसगढ़ के बच्चे सरगुजा में नौकरी करना नहीं चाहते तो मैं तो बोलता हूं कि उनको नौकरी मिलनी भी नहीं चाहिए । यदि मध्यप्रदेश होता तो निमाड़ में गए हैं, ग्वालियर में गए हैं, चम्बल में गए हैं तो यह बात प्रभावित होती, पर शिक्षक संघ से यदि युक्तियुक्तकरण का विरोध हो रहा है तो तुरंत हटा देना चाहिए । दूसरी जो बात है, वह कैरिकुलम की है । आपने पहली से तीसरी और छठवीं कक्षा एनसीईआरटी की किताबों को स्वीकार किया है । राष्ट्रीय संस्कृति के पुनरोदय का काल है । एससीईआरटी को ब्यूरोक्रेसी से हटाकर हम किसी शिक्षाविद को क्यों नहीं सौंप सकते? अब यह निर्णय लेने का समय आ गया है कि छत्तीसगढ़ के क्या पढ़ाया जाये, छत्तीसगढ़ के समकालीन दौर में योगदान क्या थे, आज देश में क्या योगदान हैं ? यदि छत्तीसगढ़ के बच्चों से आज बात करेंगे तो आधा बच्चे छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं बोल पाएंगे । एक किताब ऐसा नहीं है, जो छत्तीसगढ़ के बारे में एससीईआरटी ने तैयार किया हो या छत्तीसगढ़ की इतिहास, संस्कृति, परम्परा, भूगोल से लेकर जितनी चीजें हैं, उसको वह किताब बता सके । एनसीईआरटी में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शिक्षाविद रहे हैं । मैं तो कहूंगा कि आप इस विषय में विचार करें । आप मुख्यमंत्री जी हैं । आपसे मांग नहीं कर सकता, आपको सारे विषय मालूम हैं । मैं तो अनुदान मांगों की औपचारिकता को पूरा कर रहा हूं । छोटे-छोटे विषय को ध्यान में लाने की कोशिश कर रहा हूं । मैं राईट टू एजुकेशन के बारे में कह देता हूं ।

सभापति महोदय :- अजय जी, आपको बोलते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो एक-एक लाईन पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा हूं । मैं तो स्कूल शिक्षा में

तीन घंटे बोल दूंगा। नई शिक्षा नीति । मध्यप्रदेश को श्रेय मिला कि उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में हम नई शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं, पर आपने बताया है कि कुल टास्क 997 हैं, जिसमें 44 टास्क केन्द्रीय संस्थानों से संबंधित हैं, भारत सरकार से संबंधित हैं । आपने 70 टास्क पूरे किये हैं, आपने 33 टास्क को प्रारंभ किया है और 150 टास्क प्रक्रियाधीन हैं । अर्थात् हमारी जो स्कूल शिक्षा है, जो बेसिक शिक्षा है, वह छत्तीसगढ़ के लिए बेस बनेगी, नई शिक्षा नीति को स्वीकार करने के बाद इसमें तेजी से काम करने की जरुरत है। अब आपका इशारा हो गया, इसलिए मैं बाकी विषयों को छोड़ देता हूं। नई शिक्षा नीति में तेजी से काम करने की जरुरत है चाहे वह प्रशिक्षण हो, केरीकुलम हो, भर्ती हो या जिस तरह की भी चीजें हों। उसमें टास्क पूरे तय हैं, मुझे उसे दोहराने की जरुरत नही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा विभाग में कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, हम जब सरकार में आए तो क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या से जूझ रहे थे। यूनिवर्सिटी, कालेज, आईटीआई, तकनीकी संस्थान खोलना है, इस तरह की चीज़ों में आ रहे थे लेकिन अब रजत जयंती वर्ष में हम क्षेत्रीय असंतुलन से दूर हो चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ उस दौर में पहुंच चुका है, जहां क्वालिटी एजुकेशन की जरुरत है और मैं सोचता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे। हमारा जीईआर 19-20% है, जबकि विकसित राष्ट्रों का 50% से ऊपर है। देश का औसत 25-26% है। यदि मोदी जी ने 2047 का लक्ष्य रखा है, तो आप भी एक लक्ष्य रखिए कि जैसा जिला स्तर पर आप जीडीपी की परिकल्पना किए हैं, छत्तीसगढ़ में इस जीईआर को भी जिला स्तर पर नापा जाए, इसलिए नापा जाए क्योंकि सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जशपुर, सूरजपुर में कितना है, ये अगल-अलग जानना जरुरी है। सिर्फ दुर्ग, भिलाई, रायपुर इसका प्रतिनिधित्व नहीं करते। जहां पर असली जरुरत है, वहां पर उस लेवल पर नापा जाना चाहिए कि यहां जीईआर कितना है। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो समस्या है, वह रिक्त पदों की है। उच्च शिक्षा विभाग में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सब मिलाकर लगभग 8 हजार पद रिक्त हैं। उसमें प्रशासनिक पद भी हैं और शैक्षणिक पद भी हैं। ये एक चिन्ता है। कुलपति की नियुक्ति, इसका सिस्टम, चार विश्वविद्यालय से अब शायद दो विश्वविद्यालय बाकी है, लेकिन कुलपति की नियुक्ति कैसे हो? स्कूल शिक्षा में मैंने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बारे में बात की, उच्च शिक्षा में भी लगभग वही स्थिति है। इसमें रिक्त पदों की स्थिति तो आपने शिक्षा विभाग की बताई है, यू.टी.डी. का यदि प्रतिवेदन में देखेंगे तो बाकी पदों को यदि छोड़ दें, तो आधे से ज्यादा शैक्षणिक पद खाली हैं।

सभापति महोदय, अब दो छोटे-छोटे विषय आपके ध्यान में लाकर मैं आगे बढ़ता हूं। खैरागढ़ विश्वविद्यालय पर हम गर्व करते थे कि कला और संगीत का एशिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है। इसकी तो आप एक बार व्यक्तिगत तौर पर समीक्षा कीजिए। केदार जी, मैं आपको अभी से बता देता हूं, मैं अगली बार एक संकल्प लाऊंगा कि जो उच्च विशेषज्ञता के पद हैं, उसमें भारत सरकार रिजर्वेशन को

समाप्त करे। एस.सी. वर्ग से आप तबला वादक कहां से लायेंगे यदि नहीं है तो? बांसुरी वादक आप एस.टी. वर्ग से कहां से ले आओगे, यदि नहीं है तो? हारमोनियम वादक ओ.बी.सी. वर्ग से आप कहां से ले आओगे, यदि नही है तो? तो क्या इन पदों को रिक्त करके हम आगे बढ़ जाएं? ये तो नैसर्गिक चीज़ें हैं। संगीत तो भगवान की पूजा कही जाती है। ललित कला देवों के प्रदत्त गुण माने जाते हैं इसलिए इन उच्च विशेषज्ञता के पदों को आरक्षण से मुक्त रखा जाए और इनके पद शत-प्रतिशत भरे जाएं, इसके लिए आप कोशिश करेंगे।

माननीय मुख्य मंत्री जी, एक हिन्दी ग्रंथ अकादमी है। यह पहली अकादमी है, जो रमन सिंह जी की भाजपा शासनकाल में बनी। पांच साल भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया बोलते रहे। छत्तीसगढ़ के लोग लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रकाशन कैसे होगा? छत्तीसगढ़ का जो पुरा साहित्य है, आज उसकी पाण्डुलिपियां हैं, उसको खोजने का काम कौन करेगा? यदि पाण्डुलिपियां उपलब्ध हैं, तो उन्हें छापकर नि:शुल्क या कम दरों में लाईब्रेरी में लोगों तक कौन पहुंचाएगा? 5 साल से इसमें ताला लग गया। यह भूपेश बघेल जी के छत्तीसगढ़ियावाद की मरने की स्मारक है, मजाक की स्मारक है। वह मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, यदि वह सुनते तो मैं इसमें 5 मिनट और बोलता।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, असल में आज सुनिता विलियम्स वापस आयी हैं। आप लोगों को मालूम है या नहीं ? यह सब उसका जश्न मनाने गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने अभिसरण में बोलते समय कहा था कि इसमें भी साहित्य अकादमी है। इन्होंने साहित्य अकादमी में दो पीठ को डाल दिया है। यह कितनी साहित्य अकादमी है ? पीठ और साहित्य अकादमी, दोनों अलग विषय है। भूपेश बघेल जी ने कुछ करने के चक्कर में सब गुड़गोबर कर दिया।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप तो 15 साल तक थे। आपने क्यों कुछ नहीं किया ? अब आप 5 साल के लिये बोल रहे हैं। आप 15 साल तक संस्कृति मंत्री थे, पर्यटन मंत्री थे। आपने क्या किया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं एक सेकंड में उत्तर देता हूं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप केवल 5 साल की बुराई करते हैं। आप आने वाले 5 सालों में भी वही करेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ कल्चर को उजागर करने का काम किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं एक सेकंड में उत्तर देता हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने क्या किया है ?(व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आपने 15 सालों में क्या किया ? (व्यवधान)

श्री संदीप साहू :- आप लोग 5 साल में राजभाषा आयोग का अध्यक्ष नहीं बना पाये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति ही खत्म कर दी है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आज कम से कम सब यह कहते तो हैं कि यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। पर आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कहां पहुंचाया है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको बता देता हूं। अटल जी विद्वान आदमी हैं। मैं इसको रख देता हूं क्योंकि जल्दी-जल्दी बोलना है। मैंने कहा कि वह दौर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का दौर था। रजत जयंती के बाद अब छत्तीसगढ़ भूमिका निभाने के लिये तैयार है। क्षेत्रीय असंतुलन हर क्षेत्र में दूर हो गया है।

सभापति महोदय, ऊर्जा विभाग में तो बहुत भाषण हो गया है लेकिन मैं एक-आत चीज को बोल देता हूं, जिसको पहले बोल चुका हूं। आपने 3100 मेगावॉट बिजली के लिये परमाणु, थर्मल, सौर पंप, स्टोरेज, सभी के लिये जो नये क्षेत्र को स्पर्श किया है, उसके लिये मैं आपको बधाई और साधुवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार देश के ताप विद्युत गृहों का औसत, प्लांट लोड फैक्टर 69.01 प्रतिशत है । छत्तीसगढ़ में यह 74.32 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। (मेजों की थपथपाहट) यह मैनेजमेंट है। भोला जी को बोलिये कि आधा गिलास खाली है, यह मत देखिये, आधा गिलास भरा है, यह देखिये। साहब, छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों पर गर्व करना सीखिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आप बहुत बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। आपने बिजली बिल हॉफ की बात की थी, मतलब इस सरकार ने हमारा समर्थन किया था। लेकिन समर्थन हुआ और बिजली बिल में बढ़ोत्तरी हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ में 19,609 आबाद ग्राम हैं, जिसमें 18,728 ग्रिड से और 881 ग्राम ऑफग्रिड से विद्युतीकृत हैं, अर्थात 100 प्रतिशत वृद्धि है। (मेजों की थपथपाहट) चलिये, 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के लिये ताली बजाईये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप पहले गरीब जनता को तो देखिये। बड़ी-बड़ी बात करने से पहले गरीब जनता की समस्या को तो हल करिये।

श्री विक्रम मण्डावी :- भैया, आज पूरा प्रदेश लो वोल्टेज में है। पूरा प्रदेश लो वोल्टेज में मर रहा है। बिजली कटौती हो रही है। किसान परेशान हैं। आप कहां हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बेचारे गरीब व्यक्ति की कमाई ज्यादा लिये हैं। उनका 4 हजार और 5 हजार रूपये बिजली बिल आ रहा है। बड़ी-बड़ी बात करने से पहले वह समस्या तो हल कीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मेरी बड़ी-बड़ी बात हो या छोटी-छोटी बात हो। क्या आप असहमत हैं ? यदि आप असहमत हैं तो बोलिये कि मैं असहमत हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं पूरी तरह से असहमत हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके बच्चे नई शिक्षा नीति में नहीं पढ़ेंगे। है ना ? ठीक है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, यह शिक्षा की बात कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले पेपर में आया था कि शिक्षक लोग 5वीं कक्षा के बच्चों को नकल करवाकर परीक्षा दिलवा रहे हैं। यह है आपकी शिक्षा नीति।

सभापति महोदय :- संगीता जी, प्लीज बैठिये। आप अपने समय में बात रखियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, बिजली में जो जल कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसान हो, घरेलू उपभोक्ता हो, यह सारी छूट और जो चीजें मिलती थी, बजट में वह सब के सब हैं, उसके लिये बजट प्रावधान है। अभी नेता प्रतिपक्ष जी नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। लखेश्वर जी भी गायब है। आप लोग बिजली की उपलब्धता के लिये मेज थपथपाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिये।

सभापति महादय, एक विमानन विभाग है, जिसमें मुझको कुछ बोलना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी बढ़े। रायपुर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विमान स्थल बने और बिलासपुर, जगदलपुर, दोनों से अन्य बड़े शहर जुड़े और कनेक्टिविटी बने। आप उसके लिये प्रयास करेंगे। अभी सदन में माननीय पुन्नूलाल जी नहीं हैं क्या ? मैं हमेशा माननीय पुन्नूलाल जी से मजाक करता हूँ कि आपके विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में सब चीज बन चुका है और केवल एक हवाई अड्डा बनना बाकी है। वहां सड़क आ गई है, रेल आ रही है अब केवल हवाई अड्डा बनना बाकी है। आप अपने पड़ोसी को यह बता दीजिएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- वहां पर हेलीपेड है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वहां पर हेलीपेड है।

माननीय सभापति महोदय, व्यापारियों के द्वारा कार्गो की मांग होती है। आप कार्गो हब के बारे में बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है। उन्होंने अपने भाषण में नीली क्रांति के बारे में कहा। उन्होंने मतस्य संपदा लागू की। यह कृषि का Allied Sector है, जो उन्होंने किसान की इंकम को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। हम पोस्टल एरिया में नहीं हैं, लेकिन हमारे पास इतना जल क्षेत्र है कि हम नीली क्रांति, मतस्य संपदा के भागीदार बन सकते हैं और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो कह रहा हूँ । अभी मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है। मैंने माननीय भूपेश बघेल जी की मत्स्य नीति का बहुत विरोध किया था। उन्होंने मछुआरा परिवार, मत्स्य कृषक को हटाकर निजी क्षेत्र के लोग भी बांध को ले सकते हैं, वह Sublet कर सकते हैं यह उन्होंने मत्स्य नीति में रखा था। यदि आज भी वह मौजूद है तो वह डिलिट होना चाहिए। यदि पहला अधिकार जल क्षेत्र में किसी का है तो वह परम्परागत निषादों का है, परम्परागत केवटों का है और छत्तीसगढ़ की ओ.बी.सी. आबादी में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर आबादी होगी तो निषाद और केवटों की होगी। उनको यह अधिकार मिले। उनकी

सोसायटी जितनी विवादग्रस्त है, उनको एक अभियान चलाकर, ठीक किया जाये। उसके बाद उनको 5 सालों में कोई भी उपकरण जाल मिलना बंद हो गया। उनको प्रशिक्षण, उनका Exposure Visit, उनको Equipment देना, उसके सशक्तिकरण के लिए योजना बनाना, यह प्रदेश आपसे अपेक्षा करता है। यह Allied Sector है इसमें आप किसानों की आय दोगुनी करने में जरूर रूचि लेंगे, ऐसी अपेक्षा है। मैंने, आपसे पशु पालन के बारे में एक लाईन कही और आपका अभिनंदन किया। आपने राष्ट्रीय डेयरी डेवलप बोर्ड से एन.डी.डी.वी. से समझौता करके, देवभोग को आगे ले जाने का काम किया, सशक्तीकरण का काम किया। इसमें छूट भी है। आपने निरंतरता में छूट भी घोषित की है, लेकिन इसको प्राथमिकता देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि माननीय मोदी जी जो किसानों की इंकम को दोगुना करने की बात करते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण घटक पशु पालन विभाग हो सकता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि माननीय मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी होगी। हमारे प्रदेश में जो किसान मित्रों की राशि है, मतलब 4 साल, 5 सालों से रूकी हुई है। कम से कम 9 हजार किसान मित्रों की राशि को देने की कृपा करें। यह मोदी जी की गारण्टी में है और यह आपके भी है। किसान मित्रों की राशि डेढ़, दो सालों से रूकी हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपके पास आबकारी विभाग है। मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैंने आपके आबकारी सचिव से एक मांग की है कि जो प्रदेश में 671 शराब दुकानें खोल रहे हैं उसमें वहां कुरूद में एक दारू भट्टी और खोलवा दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप यह बोलिए कि वहां पर क्वालिटी-क्वालिटी की शराब मिले।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, दूसरा जब मैं दुग्ध विभाग में बोल रहा था तो आपने पिछले साल जो स्वीकृत किये हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने मिल्क रूड और चिलिंग सेन्टर दिया है, उनकी आज तक प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई है। मैं कुरूद के बारे में नहीं बोलता हूँ। मैंने यह चलते-चलते बोल दिया। यहां पर ग्रामोद्योग में बहुत संभावनाएं हैं। मैं हथकरगा पर कहना चाहूंगा। इसमें जितनी चीजें चल रही हैं वह पर्याप्त हैं, लेकिन ग्रामोद्योग में एक चीज की जरूरत है। यदि हम हस्तशिल्प, रेशम पर हैं तो छत्तीसगढ़ के लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए ऋण नीति बने और उनका प्रशिक्षण हो। उसके लिए ऋण नीति भी हो। स्टेट गारण्टी में एक बेल मेटल बनाने वाले को एक कणरा, एक कुम्हार को भी ऋण मिल सके। उसके लिए मिट्टी, कच्चा माल और लोहा आरक्षित हो, उसके लिए एक सुस्पष्ट कुटीर उद्योग नीति बनाने की जरूरत है। वह आपके सुशासन का अंग बनेगा, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है। पंचायतों तक जल्दी नेट पहुंच जायेगा, connectivity बन जायेगी। पर मैं एक आरोप लगाया था, मेडम संगीता सिन्हा जी, आपकी सरकार ने 200 करोड़ रुपये की पेनाल्टी भारत नेट परियोजना में माफ कर दी थी। और कैसे

माफ की, क्या माफ की, यह जांच का विषय है। अब मैं जांच की मांग तो नहीं करूंगा, आपके ध्यान में ला देता हूं। बस्तर नेट की परियोजना है, बस्तर में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह समय में पूरा हो। बस्तर में जो परिवर्तन आप ला रहे हैं, उसमें यह विभाग मददगार विभाग बनेगा।

परिवहन विभाग में आपको इलेक्ट्रिक वाहन मिले है। लेकिन मैं परिवहन विभाग में एक ही लाईन बोलूंगा, ओवरलोडेड गाड़ी पर, दूसरे राज्यों से परिवहन पर, स्थानीय संस्थायें यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखती हैं, यदि परिवहन विभाग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं देखता तो आपने अभिसरण किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मंहगा है। उसमें रायपुर, बिलासपुर या बड़े शहरों के लिये स्थानीय शासन, परिवहन विभाग मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे सस्ता कर सकते हैं, कैसे सुचारू रूप से लागू कर सकते हैं। आपको जो ई-बस मिली है, उसके अतिरिक्त उनके पास भी पुरानी बस रखी है जो नहीं चल रही है। मैं आपसे ऐसी अपेक्षा करता हूं कि यह एक संयोजन और इंटीग्रेटेड कर देंगे तो शायद परिणाममूलक हो जायेगा। यह तो सिर्फ हमको राजस्व देगा।

सभापति महोदय, जनसंपर्क विभाग में तो जोरदार है, जनसंपर्क में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस जितने आपके विभाग हैं, उसकी छवि अच्छी बने। कई बार हम लोग छवि के मामले में, प्रचार के मामले में पीछे हो जाते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो भी हम प्रचार के मामले में पीछे हो जाते हैं। इन लोगों टाइप नहीं होता कि असत्य को सच बना दें। राम वनगमन पथ के बारे में ऐसा करके बहुत चिल्लाये। उसमें भी अपना निकाल दिये। इन लोगों ने घोषणा की पत्रकार सुरक्षा कानून बनायेंगे। मैं सोचता हूं कि संगीता सिन्हा जी बहुत खड़ी होती हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून उनकी सरकार ने बनाया है या नहीं बनाया है, उस पर जरूर बात करेंगी। यदि नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाये थे। उनकी सुरक्षा के लिए नीति भी बनाये थे। पूर्ववर्ती सरकार में माननीय चन्द्राकर जी सबसे ज्यादा स्पीच आबकारी विभाग में किये थे। इस बार आबकारी वाले में एक लाईन बोलकर बंद कर दिये। मैं चाहती हूं कि वह आबकारी विभाग में बोलें।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि अभी आबकारी विभाग ईमानदारी से चल रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं चाहती हूं कि चन्द्राकर जी आबकारी विभाग में बोलें, उसमें चर्चा करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आबकारी विभाग में जेल के अंदर कोई नहीं जा रहे हैं और न कोई फरार है। अब न डबल काउंटर लग रहे हैं, न नकली होलोग्राम लग रहे हैं तो मैं इसमें क्या भाषण दूंगा ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, डबल हो रहा है, डबल बन रहा है, आपका ट्रांसफर कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी नई जेल बनवा रहे हैं, विजय शर्मा जी चले गये। वह बोले हैं कि 90 बैरक नई बन रही हैं। कोढ़ी मे सर्वसुविधायुक्त नई जेल बन रही है। खनिज संसाधन में आपने पहली बार लीथियम खोजा है। खनिज विभाग में भी कौशल उन्नयन है। मेरे को समझ में नहीं आता कि यह क्या कौशल उन्नयन करते हैं ? क्या खनिज विभाग वाले रेट माइनर्स तैयार करते हैं ? रेट माईनिंग होती है, उस तरह का तैयार करते हैं। खैर जो भी हो, सरकार को सर्वाधिक राजस्व देने वाले में से एक विभाग है। इस विभाग में जितनी पारदर्शिता रहेगी, आप ई-ऑक्शन कर रहे हैं, सबका ई-ऑक्शन हो तो अच्छा हो। इसमें एक छोटी सी मांग है कि ये रेत का अवैध परिवहन, अवैध खदान जरूर बंद हो। मैंने एक कलेक्टर को फोन किया तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। तो मैं डॉयरेक्टर और सेकेटरी को बोला, तब बंद हुआ है। अभी फिर से चालू हो गया है, मेरे को नहीं मालूम। वहां पर दारू की भी दुकान है, नाश्ते, चखना की भी दुकान है, सारी दुकानों में लाईट लगी हैं, सब लगे हैं और रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। वह विभाग को मैंने बता दिया था। सभापति महोदय, मैं आपके निर्देशानुसार सभी विभागों में एक-एक लाईन बोला, ज्यादा देर नहीं बोला, रूका नहीं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि भगवान ने आपको सामाजिक क्षेत्रों के बहुत सारे विभाग दिये हैं जिसमें खासतौर से पर्यटन, संस्कृति ताकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति का संरक्षण हो।

छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण के बारे में हमने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है । स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा यह सामाजिक क्षेत्र के विषय हैं, बहुत दैनंदनीय की जो आवश्यकताएं हैं, आपके पास बिजली विभाग है । अभी से गांव में लो-वोल्टेज आ गया है । गांव से लो-वोल्टेज जाये, मैं रायपुर शहर के बारे में हमेशा बोलता हूं कि यहां की बिजली व्यवस्था राजधानी के लायक नहीं है । मैं 5-10 सालों से इस बात को जब भी डिमाण्ड मांग या जब भी मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैं बोलता हूं कि एक आंधी आयी और रायपुर में लाईट गोल हो जाती है । किसानों को बिजली मिले, अभी संकट का समय है । जलस्तर नीचे जा रहा है और बिजली ही रबी फसल के किसानों के प्राण बचायेगी । मैं धमतरी जिले से आता हूं जहां रबी फसल सबसे ज्यादा लगती है ।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा विभाग में जो तकनीकी शिक्षा है तथा और भी विश्वविद्यालय हैं । जो आपके पास है वह केवल 9 राजकीय विश्वविद्यालय के हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में और भी तरह के विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, कामधेनु विश्वविद्यालय हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है । अलग-अलग नेचर की, सारे विषयों की यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में हैं लेकिन यू.टी.डी. की स्थिति बहुत गंभीर है, उसको आप ठीक करेंगे ताकि यहां का जो मेन पॉवर निकलेगा । इंजीनियरिंग का भी वही, विवेकानंद का भी वही, नये सब्जेक्ट हांलाकि उच्च शिक्षा विभाग वालों ने बोर्ड ऑफ स्टडीज बनायी है लेकिन बोर्ड ऑफ स्टडीज में कोर्स बनाने के लिये कितनी विशेषज्ञता है, आज बिल्डिंग-भवन की जरूरत नहीं है । हमारे जो कोर्स हैं और एजुकेशन का हमारा जो वार्षिक

कैलेण्डर है वह अखिल भारतीय परीक्षाओं के बराबर रहे । हमारा जो कैरिकुलम है वह अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के बराबर रहे तब छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी सक्सेसफुल होंगे । इसके बाद मैं जिसके लिये हमेशा लड़ता रहा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में चूंकि राम वनगमन पथ में सोशल ऑडिट की विधानसभा में घोषणा है । मैं अटल जी को लक्षित करके नहीं बोलता, मैं हमेशा जानता हूं कि वह निगम के अध्यक्ष थे लेकिन वह एक पोस्टर ब्वॉय भर थे, उसके पीछे के खिलाड़ी कोई और थे । मैं नहीं जानता कि छत्तीसगढ़ को छोड़कर भगवान के नाम पर करप्शन हिंदुस्तान के 32-33 राज्यों में और कहीं हुआ होगा ।

श्री राजेश मूणत :- आप अटल जी के नाम का उल्लेख कर रहे हैं, आप पहले यह क्लियर कर दें कि वह कौन हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपसे एक अपेक्षा है कि उस विषय में जांच हो और दूसरी बात कि आप मंदिर में जो मूर्ति लगा रहे हैं वह ऐसी लगे कि जो भगवान राम की तरह दिखें । मैंने उदाहरण भी दिया था, वहीं से चुनकर आते हैं रामटेकरी में, भगवान राम की रतनपुर में अवाक्ष प्रतिमा है, अजानबाहू प्रतीमा है, उसी अजानबाहू प्रतिमा को छत्तीसगढ़ का प्रतीक बनाकर आपको मूर्ति लगाने का शौक है, वहीं लगा दीजिये लेकिन जो लगाये हैं वह भगवान जैसे तो दिखें। क्या पर्यटकों को यह बताना पड़ेगा कि यह भगवान राम की मूर्ति है तो उसमें देरी क्यों हो रही है ? आपसे यह मेरा विनम्र आग्रह है ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय । भैया, प्रणाम ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी बैठिये । आप बाहर थे तब तक बहुत अच्छे से चल रहा था । (हंसी) आप आ गये हैं, अब आप बार-बार खड़े होंगे, अभी उन्हें समाप्त करने दीजिये ।

श्री रामकुमार यादव :- एक मिनट । माननीय सभापति महोदय, मैंने इसीलिये आपसे आज्ञा ली है । मैं यह जान रहा हूं कि यह महाज्ञानी हैं, ये पूरा प्रदेश ला घोर के पी डारे है लेकिन ज्ञानी जी मैं यह कहना चाहत हंओं कि भगवान ला मन के भावना से पूजा किये जाथे, मन के अंतर्आत्मा से पूजा किये जाथे ।

श्री अजय चंद्राकर :- भगवान राम मन के भावना मा का पैसा खाय से आथे? तें हा बईठ के बात करत हस ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी बैठिए ।

श्री रामकुमार यादव :- मन के भावना से पूजा किये जाथे, अइसनहे नइ किये जाये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अंत में आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ चहुंमुखी विकास करेगा । (मेजों की थपथपाहट) आपके पास जो विभाग है वह छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा विभाग बनेगा, आपके लिये यह शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात

समाप्त करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये जो समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से आग्रह है कि प्रथम दोनों वक्ताओं ने अभी विस्तृत बात रखी है । अभी 30 वक्ताओं को और बोलना है, वे 10-10 मिनट भी बोलेंगे तो 5 घंटे से ज्यादा समय लगेगा, मेरा आग्रह है कि अब संक्षेप में अपनी बातों को रखेंगे । श्री अटल श्रीवास्तव ।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामान्य प्रशासन, वाणिज्यिक कर, ऊर्जा विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन, खनिज विभाग, जनसंपर्क, ऐसे तमाम 20 अनुदान मांगों के विरोध में यहां पर खड़ा हुआ हूं। चूंकि बहुत सारे विषयों पर बात हो चुकी है, हमारे छत्तीसगढ़ बनने की अवधारणा यह थी कि हमारा छत्तीसगढ़ धान के कटोरे के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। हमारा छत्तीसगढ़ वन संपदा के नाम से देश में ज्यादा जाता है, जहां छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत वन संपदा है। हमारे छत्तीसगढ़ को खनिज संसाधनों के नाम से जाना जाता है, जो देश का 22 प्रतिशत दूसरा खनिज उत्पादक प्रदेश है और छत्तीसगढ़ को आदिवासी संस्कृति के नाम पर जाना जाता है। यहां पर 33 प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं और उनकी संस्कृति के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। संस्कृति की बात हो रही थी, हमारे छत्तीसगढ़ की इतनी समृद्धशाली संस्कृति है, जिसके लिए बहुत सारे काम करने की जरूरत है। माननीय हमारे सदस्य महोदय ने एक मुक्तांगन की बात की, पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए कभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव शुरू किया था, आप चाहे भले ही उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव करिए, पर जो छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति की पहचान पूरे देश में हो रही थी, जहां पर 22 देशों के और 9 विदेशों के नृत्यक दल यहां आए थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझा था, उस आयोजन को आप बंद मत कीजिए, क्योंकि किसी भी प्रदेश की पहचान उसकी वहां की संस्कृति से होती है और पिछले तीन सालों में जब यह आयोजन हुआ था तो छत्तीसगढ़ की पहचान बनी थी कि छत्तीसगढ़ का आदिवासी नृत्य हमेशा लोगों के और पर्यटकों के सामने आया था। जिस तरीके की बात हुई। भोपाल में भारत भवन बना, पर वैसा ही भवन छत्तीसगढ़ में बनना चाहिए था। मैं इस बात का विरोधी हूं कि हर चीज केवल रायपुर में सेंट्रलाइज न हो। बस्तर है, सरगुजा संभाग है, मेरे बिलासपुर के पास अमरकंटक का क्षेत्र है, जहां पर आदिवासी बाहुल्य लोग रहते हैं तो जो आदिवासी मानव संग्रहालय बने, उसको डीसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। केवल रायपुर में हर चीज को केंद्रित करने से काम नहीं होगा। अगर छत्तीसगढ़ में लोगों को घुमाना है, छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान बनानी है तो आपको विकेंद्रीयकरण करना होगा। केवल हर चीज नया रायपुर में लाने की कोशिश करने से काम नहीं चलेगा।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, आप बस्तर के लिए कुछ किए हो तो एकाध कुछ विषय बताइए न। एकाध संस्थान वहां खोले हो?

श्री अटल श्रीवास्तव :- साहब, आप तो 17 साल से थे। अभी भी बस्तर के लोग चिल्ला रहे हैं। आपने 17 साल में क्या किया?

श्री केदार कश्यप :- हमारे 17 साल में मेडिकल कॉलेज बना, हमारे 17 साल में यूनिवर्सिटी बना, अब 17 साल में वह जिला बना। (मेजों की थपथपाहट) समझ रहे हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- तो मैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात कर रहा था। ये भारत भवन जैसा भवन बनना चाहिए, जिसमे सभी विधाओं की एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए। माननीय चंद्राकर जी कह रहे थे कि दो चीजें होती हैं, एक आयोजन करना और उस विधा को सीखना। जब तक हम भारत भवन जैसा भवन का निर्माण नहीं करेंगे तब तक छत्तीसगढ़ की लोक कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम नहीं हो पाएगा। हमारे यहां दो बड़े महोत्सव होते हैं, एक चक्रधर महोत्सव होता हैं, एक भोरमदेव महोत्सव होता है। बाकी बहुत सारे छोटे महोत्सव होते हैं। पर उन उन आयोजनों को करने के पीछे कारण यह है कि देश विदेश के लोग आकर समझें कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कितनी समृद्धशाली है। पर्यटन क्षेत्र में बात हो रही थी। आदरणीय चंद्राकर जी ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ की बात की। हमारी तो सोच थी कि भगवान राम जो पुराण कहता है, कहते हैं कि भगवान राम जब 14 साल के वनवास में अयोध्या से निकले थे तो उन्होंने अपना लगभग 10 साल छत्तीसगढ़ में बिताया था। ये किंवदंतियां हैं। ये लिखे हुए परिणाम हैं कि हमारे कोरिया के सीतामढ़ी से लेकर सुकमा के रामा राम तक 2260 किलोमीटर का राम वन गमन परिपथ बनाया गया था। उसके कुछ क्षेत्रों को डेवलप किया गया था। समय कम था, हमने चित्रों को डेवलप किया। हम यह मानते हैं कि एक मूर्तिकार ने एक मूर्ति गलत बनाई थी। हम उसको स्वीकार करते हैं कि वह मूर्ति गलत बनी थी। आप उस मूर्ति को बदल दीजिए, क्योंकि उस मूर्ति को देखने के बाद हमने भी कहा था कि उस मूर्ति को बदला जाना चाहिए। अगर मूर्ति के कलाकार ने मूर्ति का शेप ठीक नहीं दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा intension गलत था। हम चाहते हैं कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ को बनाया जाए, वह जो 2260 किलोमीटर का एरिया है वहां पर।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, आग्रह है। हमारे अटल जी छत्तीसगढ़ सरकार में पर्यटन मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और इन्हीं की विधान सभा में रतनपुर और रामटेकरी पड़ती थी। ये जो पर्यटन परिपथ की बहुत व्याख्या कर रहे हैं, उसमें एक बार पलटकर देखना भी चाहिए कि छत्तीसगढ़ की पुरातन राजधानी को उस क्षेत्र से वंचित क्यों किया गया, ये भी आज इनको सदन को बताना चाहिए।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, इनको बोलने दीजिए। अटल जी, आप बोलिए

श्री अटल श्रीवास्तव :- सिरपुर की बात हुई, हमारी सरकार ने बौद्ध सर्किट में लाने के लिए केंद्र सरकार को लगातार पत्र लिखा कि हमारे सिरपुर को पूरे देश के बौद्ध सर्किट में लाया जाए, पर अभी तक वह लेटर पेंडिंग है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पर्यटन मंत्री की हैसियत से सिरपुर को बौद्ध सर्किट में लाया जाए। सभापति महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग की बात हो रही थी । मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि अजय चन्द्राकर जी के क्षेत्र में 67 शराब की दुकानें खुल गईं और जो आत्मानंद स्कूलें चल रही थीं, स्कूलों की बिल्डिंग बननी थी, नई स्कूलों की घोषणाएं करनी थी, वे घोषणाएं नहीं हुईं । मैं मानता हूं कि आपने फिजियोथेरेपी कॉलेज की घोषणा की, आपने नर्सिंग कॉलेज की घोषणा की लेकिन हमारे गांवों में जिस स्कूली शिक्षा की जरूरत पड़ती है, आपने उसमें कोई काम नहीं किया । आप केवल 67 शराब की दुकानें बनाएंगे ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, दुकान खोल रहे हैं, फर्जी काउंटर नहीं लगा रहे हैं । पिछली सरकार में जो दो-दो काउंटर का खेल था । (व्यवधान) छत्तीसगढ़ की अस्मिता को तार-तार करके मुगलिया सल्तनत के लोगों के द्वारा जो वसूली की जाती थी वह तो छत्तीसगढ़ में बंद है । यह उल्लेखनीय है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आपका तो एक काउंटर दिल्ली में खुला हुआ है । पूरा परसेंटेज तो दिल्ली वाला काउंटर ले जा रहा है, जो डायरेक्ट कंपनी से परसेंटेज ले रहा है, आपको क्या मिल रहा है । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- ये आत्मानंद की बात करते हैं, आत्मानंद में इन्होंने किया ही क्या है । चलते स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर दिया । इधर की ईंट उधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा । न बजट, न कोई सेटअप, न कोई बिल्डिंग, न कोई स्थायी व्यवस्था और आज ये आत्मानंद की दुहाई देते हैं । स्वामी आत्मानंद जी के नाम को इन्होंने सिर्फ उपयोग किया है ।

सभापति महोदय :- सुशांत जी अपने समय में बात रखिएगा ।

श्री सुशांत शुक्ला :- चलते स्कूलों को बंद किया और आज दुहाई दे रहे हैं आत्मानंद स्कूल, आत्मानंद सकूल ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप तो बस्तर में नियद नेल्लानार की बात कर रहे हैं 400 स्कूलों का आपने बंद कर दिया था, उसका जवाब देंगे क्या ? जहां तक आबकारी नीति की बात आ रही है जो 30-35 परसेंट दिल्ली वाले ले जा रहे हैं उसका क्या होगा ? डायरेक्ट कंपनी से पैसा जा रहा है (शेम शेम की आवाज) । वहां जो काउंटर खुला हुआ है उसका क्या होगा ?

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यह आपत्तिजनक है । एक आदमी पर आरोप लगता है तो पूरी कांग्रेस एक हो जाती है और एक आदिवासी पर आरोप लगता है तो कोई कांग्रेसी एक नहीं होता, तब जवाब देना पड़ता है कि ये किसके हितचिंतक हैं ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके सम्मान में खड़ी है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बोलिए ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मैं मिडिल सकूल, प्रायमरी स्कूल, हाईस्कूल, आत्मानंद और पीएमश्री स्कूल । मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल का सेटअप सबसे बड़ा है और हमारे जितने विधायक हैं सबकी शिकायत रहती है और आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कोई टीचर शराब पीकर स्कूल पहुंच गया । बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अपने स्कूल में जाते ही नहीं । सात दिन में एक बार अटेंडेंस लगाते हैं और वापस हो जाते हैं । सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इन स्कूलों के डायरेक्टोरेट को तीन टुकड़ों में बांट दिया जाना चाहिए । जो आपका मैन पावर का कंट्रोल है, वह स्कूल शिक्षा में हो जाना चाहिए । सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि विमानन विभाग के अंतर्गत बिलासा दाई केंवटीन एयरपोर्ट है । मैं चाहता हूं कि उस एयरपोर्ट का उद्धार किया जाए, इस बजट में उसके लिए कोई भी राशि नहीं दी गई है । नाइट लैंडिंग का पैसा रखा हुआ है लेकिन अभी तक नाइट लैंडिंग शुरू नहीं हुई है । बिलासपुर से हैदराबाद, बिलासपुर से कोलकाता, कोलकाता की सेवा तो शुरू हो चुकी है किंतु बिलासपुर से हैदराबाद, बिलासपुर से मुंबई, ये सेवाएं शुरू होनी चाहिए ताकि बिलासपुर दूसरा बड़ा शहर है, जहां पर हाईकोर्ट है, जहां पर एसईसीएल का मुख्यालय है, जहां पर साऊथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है, जहां पर एनटीपीसी है वहां के एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए इस बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया है, जबकि डबल इंजन की सरकार होने के बाद यह प्रावधान किया जाना चाहिए । बिलासपुर के हमेशा कुठाराघात होता है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अनुपूरक बजट में बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए कुछ पैसा दिया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय, बात खनिज विभाग की हो रही थी । अंत में मैं खनिज विभाग पर ही बोलना चाहूंगा कि हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान खनिज संसाधनों से भी है । हिंदुस्तान का 22 परसेंट खनिज संसाधन हम छत्तीसगढ़ के लोग प्रोवाइड करते हैं । हमने हसदेव क्षेत्र में क्या किया ? राजस्थान सरकार को एक खदान मिली, जिसमें राजस्थान सरकार की खदानों के लिए 15 सालों का कोयला डिपॉजिट है । राजस्थान ने अपने कोयले के खनन का काम किसी प्रायवेट कंपनी को दिया, उसके बाद आज वहां यह स्थिति है कि देश का सबसे घनत्व वाला इलाका, देश का सबसे घनत्व वाले वन को बर्बाद किया जा रहा है । उद्योगपति को देने के लिए वहां 3-3, 4-4 खदानें दे दी जा रही है, हमारा हसदेव एरिया अगर उजड़ जाएगा, वहां का वन उजड़ जाएगा, वहां के वन्यप्राणी उजड़ जाएंगे, जो हसदेव बांगो डैम है जिसमें पूरे सरगुजा क्षेत्र का पानी आता है, अगर उस डैम पर पानी आना बंद हो जाएगा तो जांजगीर जिले के किसानों की क्या हालत होगी ? माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपना पदभार संभाला तो हम लोग खुश थे कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। जल, जंगल, जमीन की बात होगी, आदिवासी संस्कृति की बात होगी, पेड़ों की कटाई रोकने की बात होगी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़

रहा है कि जिस तरीके का काम हसदेव बांगों एरिया में हो रहा है, एक व्यापारी को, एक उद्योगपति को हजारों साल पुर्खों के लगाए हुए जंगल दे दिए जा रहे हैं, जंगल में कटाई हो रही है, एक दिन में एक-एक लाख पेड़ कांट दिए जा रहे हैं, आपको सोचना होगा, यहां जितने लोग बैठे हैं, सबको अपनी आने वाली पीढ़ी को जवाब देना होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अटल जी, वह आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में है। वहां जोड़ दिया गया है कि दो आदमी के खिलाफ जहां पर अवसर मिले वहां सबको बोलना ही है। आप उन कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं जो आपको एक परिवार से निर्देश मिला है।

श्री विक्रम मंडावी :- सभापति महोदय, जहां गलत हो रहा है, वहां बोलेंगे। दो आदमी नहीं, सबके लिए बोलेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, एक मिनट। महाज्ञानी बैठे हे, मैं ओला कहना चाहत हौं, 20 लाख पेड़ ला कांट दिहा, अउ हमन ला मां के नाम पेड़ लगाए बर कहत हो। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत हे, काखरो साबर ला चोरी कर लेवो अउ सूजी के दान दे देवा। इही ला कहे गे हे, साबर के चोरी अउ सूजी के दान। 20 लाख पेड़ कांट के 1 पेड़ मां के नाम लगात हो। बाप के नाम में घलो लगाबो लेकिन 20 लाख पेड़ कैसे में लगही।

श्री अजय चंद्राकर :- गिनत ले तोर चार जन्म निकल जही। ते हा 20 लाख हे कीही के कब गिन के आए हस।

श्री रामकुमार यादव :- आही, मौका आही। छापा पड़ही, जेन ला बने बनवात रेहेव, तुहीच मन जइहा। अभी बड़ अकन घोटाला करत हव।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, एक मिनट। उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तैं रेहे कहां तेला बता। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- ओ हा 20 लाख पेड़ गिने ला गे रिहिस हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- तैं हा तीन घंटा ले गायब हस। मुझे किसी ने बताया कि सुनीता विलियम्स से मिलने गया था।(हंसी)

श्री सुशांत शुक्ला :- अटल भैया, अटल जी को जब हम अटल जी बोलते हैं तो गौरव की अनुभूति होती है। बात पे ही नहीं लिखा पा रहे हैं, बस यही अंतर है। परंतु एक विषय है मैं आज आपको बोलना चाहता हूं। मैं एक आग्रह कर रहा हूं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मैं भी अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि इतने बड़े देश के नेता का नाम मेरे नाम से है।

सभापति महोदय :- बहुत सारे वक्ता हैं, आप लोग समय को जाया न करें।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, जब हसदेव पर प्रश्न उठता है तो ये पूछना लॉजिमी है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे, वे किस बात के लिए रायपुर आए थे, ये भी बताईए। मैं पूछना चाहता हूं, हसदेव के पूरे प्रकरण पर हस्ताक्षर करके किसने अधिसूचना जारी की, ये भी बताईए। किस-किस के कहने पर आपने जारी करवाया था, ये भी बताईए।

श्री रामकुमार यादव :- कैंसल करा दीजिए, कैंसल करा दीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, इसी विधान सभा में अशासकीय संकल्प पारित हुआ था, उसके बाद जंगल कट रहा है। माननीय धर्मजीत भैया ने अशासकीय संकल्प लगाया था और सर्व सम्मति से पास हुआ था। अगर उसके बाद भी कटाई हो रही है तो ये दुर्भाग्यजनक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग अटल जी को बोलने दीजिए, वे बिलासपुर की बात कर रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं। बिलासपुर की हवाई जहाज की मांग कर रहे है, आप उनको मांग तो करने दीजिए, आप लोग खुद डिस्टर्ब कर देते हो।

सभापति महोदय :- निषाद जी, आप सब पुराने सदस्य हैं, आप लोग इस तरह से बहस करेंगे तो ये उचित नहीं है। अटल जी, जल्दी समाप्त करिए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, मैं आपका 10 मिनट बस और लूंगा।

सभापति महोदय :- नहीं 10 मिनट मत लीजिए, जल्दी समाप्त करिए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, बस्तर की विकास की बात कर रहे थे, बस्तर में नियद नेल्लानार खुल रहा है, बस्तर के कई सुदूर इलाकों में सड़कों का निर्माण हो रहा है, बस्तर की बहुत सारी बातें हो रही थी। जब से ये सरकार बनी है, हमने देखा है कि इस देश के गृहमंत्री बस्तर में आकर दो दिन डेरा डालते हैं, मुझे तो इस बात का दुख है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली जाते हैं तो केवल पेपर में छपा हुआ है कि बस्तर के विकास का रोडमैप है। मैं खुश हूं कि बस्तर का विकास होना चाहिए, पर मुझे मुख्यमंत्री जी से ये आशा थी कि मुख्यमंत्री जी वहां छत्तीसगढ़ का रोडमैप रखेंगे। आखिर बस्तर से इतना प्रेम क्यों ? आखिर बस्तर की इतनी बात क्यों ? इसके पीछे कहीं न कहीं कोई कारण है, ऐसा तो नहीं है कि आंख मिचौली हो रही है, हमारी आंखों में विकास का धूल झोका जा रहा है, हमारे बस्तर के लोगों के आंख में धूल झोंककर बस्तर की खनिज संपदा को बेचने का काम किया जा रहा है। (शेम शेम की आवाज)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, बस्तर जल रहा था, ये असम में चुनावी पर्यटन कर रहे थे, बस्तर जल रहा था, ये उत्तरप्रदेश में चुनावी पर्यटन कर रहे थे। जवाब तो देना पड़ेगा, बेगानी शादी में अबदुल्ला दीवाना। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जोर से चिल्लाकर बात करने से आप अपनी बात को नहीं बदल सकते। आप जोर से चिल्लाकर बात करके अपनी बात को सही साबित नहीं कर सकते हैं। सभापति महोदय, आप इसकी जांच करवाइये। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- आप सच्चाई को सुन क्यों नहीं रहे हैं ? आप सच्चाई को सुनिये। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप बस्तर ला बेचिहो झन। हमन ला ए बात के डर हे कि आपमन बस्तर ला बेच झन दीहु, काबर कि आपमन जम्मो ला बेच डारे हो। छत्तीसगढ़ के हमर सोना के चिड़िया, हमर हृदय बस्तर ला आपमन बेच देहुं, ए बात के हमला डर हे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यदि आप तेज आवाज से बात करेंगे तो आप सत्य से मुकर नहीं सकते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ते पानी पी के आ जा।

सभापति महोदय :- मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है। संगीता जी, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। समय की मर्यादा है और आज बहुत ज्यादा वक्ता हैं। यदि आप लोग इस तरह से आपस में बहस करेंगे तो यह उचित नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, दो मिनट। आप बोल लीजिएगा। मैं 2 दिन से आपकी बात सुन रहा हूं। हर बात में आप प्रश्नवाचक उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को बस्तर से इतना प्रेम क्यों है? इनको बस्तर से इसलिए प्रेम है कि वहां पर 20 साल से नक्सली हिंसा से ग्रस्त लोग हैं। कोई बेघर-बार हुआ है, किसी के लोग बिछड़ गये हैं, टूट गये, मर गये हैं, जवान शहीद हो गये हैं। यदि वह उनसे प्रेम कर रहे हैं तो इसमें आपको क्यों कोई शंका दिख रही है ? इसमें कोई शंका नहीं है। आप चिंता मत करिये। यदि आप ऐसा बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बस्तर से प्यार नहीं करेंगे तो क्या रायबरेली से प्यार करेंगे? क्या वह अमेठी से प्यार करेंगे?

श्री रामकुमार यादव :- नहीं-नहीं। तुमन मिल के खावो। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी, बैठिये। धर्मजीत जी। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, हम आपको थोड़ी न बोल रहे हैं कि आप दिल्ली से प्यार करें, मद्रास से प्यार करें, गुजरात से प्यार करें। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अगर आप बस्तर के बारे में बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- यह कांग्रेस पार्टी है। तुमन ओला बेचहु तो हमन अपन जान में लड़ देबा, लेकिन ओला रोक के रहिबो। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- विक्रम जी, रामकुमार जी, बैठिये। निषाद जी, आप अपने समय में बात रखियेगा। बार-बार बातों का जवाब देना उचित नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, जब बात आती है तो बोलना पड़ेगा। आज भोले-भाले आदिवासियों को जिस हिसाब से नक्सली के नाम से बस्तर में मारा जा रहा है। आप नक्सली मारेंगे तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिन निरीह आदिवासियों को मारा जा रहा है, उसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है।

सभापति महोदय :- निषाद जी, आप अपने समय में अपनी बात रखियेगा। अटल जी, आप समाप्त करिये। अन्य सदस्य बोलेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी गये हैं तो वह गिल्ली-डंडा और भावरा की बात करने के लिए नहीं गये हैं। वह बस्तर के विकास की बात करने के लिए गये हैं। यह गिल्ली-डंडा, भावना, कबड्डी ये सब आप लोग ही करो। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, वह फोटो में अच्छा दिखता है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- निषाद जी, आप फिर से खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। आज ही पेपर में आया है कि छत्तीसगढ़ की 44 खनिजों की ई-नीलामी की गई है। जिसमें 14 लौह अयस्क की खनिज हैं, 9 बाक्साइट की हैं, 11 स्वर्ण की हैं, 3 निकिल की हैं, क्रोमियम की 7 हैं, ग्रफाइट की 2 हैं, ग्लोनाइट की 3 और लिथियम की 1 खनिज की कल सुबह यहां ई के माध्यम नीलामी हो चुकी है। मेरा यह कहना है कि जिस तरीके से बस्तर को लेकर हमारी भावनाओं को जगाया जा रहा है, कहीं उसके पीछे कोई खेल तो नहीं है? एक साइड सरगुजा उजड़ रहा है, एक साइड बस्तर उजाड़ा जाएगा। आखिर इसके पीछे कौन उद्योगपति हैं, जो छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटना चाहते हैं ? (शेम-शेम की आवाज) मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। यहां इतने सारे लागे बैठे हैं। इस छत्तीसगढ़ में स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा जी, स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी, अरविंद नेताम जी जैसे नेता पैदा हुए। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर को संरक्षित किया। आज हम सब 90 लोग बैठे हैं। कल हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे कि आने वाले इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ की संपदा को बेच दिया गया और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खराब कर दिया गया।

श्री राजेश मूणत :- अटल जी, एक मिनट। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। पर्यटन विकास निगम में आप भी रहे हैं और उस समय की सरकार के आप सहयोगी भी रहे हैं। आप आपकी पुरानी उद्योग नीति को स्वयं पढ़ लीजिए। बस्तर के अंदर आपने जो उद्योग नीति बनाई, आपने उसमें किन-किन चीजों की छूट दी? आप जरा उसका विश्लेषण पहले स्वयं कर लीजिए। सरगुजा के अंदर आपने किन-किन चीजों की छूट दी और उस समय की आपकी तत्कालीन सरकार ने किन-किन चीजों पर NOC दी?

जरा आप उसका विश्लेषण कर लीजिए। भाषण अच्छे लगते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करते समय कहीं न कहीं हमको भी उस पर आत्म चिंतन करना चाहिए। उंगली उठाने के पहले 3 उंगली अपनी तरफ भी आती हैं। यदि आप उस पर डिबेट चाहेंगे तो मैं लंबी डिबेट के लिए भी तैयार हूं।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- मूणत जी, आप बैठिये। विक्रम जी, प्लीज। अटल जी, आप अनुदान मांगों पर बात रखिये और समाप्त करिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- हां, अंतिम है। माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय राजेश मूणत जी के लिए एक शेर कहना चाहता हूं।

नशे मन के लूट जाने का ही गम होता तो क्या गम होता,

यहां तो बेचने वालों ने पूरा गुलशन बेच दिया है।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके की बातें बस्तर में हो रही हैं। हम सब लोग इस सदन के सदस्य हैं। आपका यह जो 5 साल का कार्यकाल है, कहीं यह छत्तीसगढ़ के लिए काला धब्बा न हो कि बस्तर उजड़ जाये, बस्तर की खनिज संपदा उजड़ जाये, बस्तर की संस्कृति उजड़ जाये, इस पर ध्यान देना होगा। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे ? जिस तरीके की साजिशें हो रही हैं। यहां पर बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं, जिनकी छत्तीसगढ़ को लेकर सोच है। माननीय अजय चंद्राकर जी 5 बार के विधायक हैं, परंतु मंत्री किसको बनाया गया है, जो कठपुतलियां बनकर नाचे और जो कठपुतलियां बनकर छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को बेचने का काम करे। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आप जैसे लोग कभी छत्तीसगढ़ को बिकने नहीं देंगे। परन्तु जो लोग सामने बैठे हैं, उनको यह सोचना होगा कि आने वाले समय में जवाब देना होगा। इतने सीनियर-सीनियर विधायक बैठे हैं, हमारे पुन्नू लाल मोहले जी बैठे हैं, उन लोगों को मंत्री बनाया गया, जो खनिज सम्पादा को बेचने के लिए उन उद्योगपतियों का साथ दे रहे हैं। इस तरीके से खनिज सम्पदा बेची जा रही है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, बेवफा, वफा की बात कर रहा है। यह बड़ा आश्चर्य का विषय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अटल जी, जो 5 साल का काला धब्बा था, छत्तीसगढ़ की जनता ने नजर उतारकर सीधा कर दिया। वह धब्बा नजर नहीं आयेगा। नजर उतारकर जंगल में चढ़ा दिया गया है।

सभापति महोदय :- अटल जी, समाप्त करिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अंतिम शेर आपको समर्पित कर देता हूं :-

'जमीन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे,

कलम सिपाही अगर सो गये तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे।'

आप लोग छत्तीसगढ़ को मत बेचो। धन्यवाद जय हिन्द।

सभापति महोदय :- श्री धरम लाल कौशिक जी।

श्री सुशांत शुक्ला:- सभापति महोदय, 2 मिनट। अटल जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता एक डेढ़ साल पहले कहने लगी थी कि

'तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में,

चुनरी तक का रंग उड़ गया, फागुन के त्यौहार में।'

आप अपने कार्यकाल को याद रखो कि आज बेवफा, वफा की मांग कर रहे हैं। यही सुशासन के संकल्प की प्रतिपूर्ति है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, एक मिनट बोलूंगा। अटल जी, यहां कोई गगन नहीं बेचने वाले हैं। 2जी स्पेक्ट्रम आपके ही कांग्रेस सरकार के केन्द्रीय मंत्री लोग बेचे थे।

श्री अटल श्रीवास्तव :- उसका क्या हुआ ? 10 साल आपकी सरकार रही, कोई निर्णय आया क्या ? सब छूट गये, बाइज्जत बरी हो गए। 2जी स्पेक्ट्रम में बरी हो गए, कोल घोटाला में बाइज्जत बरी हो गए। बस आपका काम आरोप लगाना है, आपका काम बेचना है।

सभापति महोदय :- धरम लाल जी, आप अपनी बात शुरू करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- पंडित के यहां 3 करोड़ 71 लाख नकदी बरामद हुआ।

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार जी, एक मिनट। फिर आप बोल लेना। हमारे मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ाने के लिए दूसरे प्रदेश में पैसा नहीं भेजना है। असम में चुनाव लड़ाने के लिए पैसा नहीं भेजना है, उत्तर प्रदेश में नहीं भेजना है, कर्नाटक में नहीं भेजना है। वहां जैसे ही पैसा भेजना शुरू होता था तो दारू की दुकान में तीन-तीन रैक और लग जाता था, बिना इसके बिल बेचो, बिना नंबर के बेचो।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आपकी सरकार को तो हम दो हमारे दो को पैसा भेजना है। हम दो तो केन्द्र में बैठे हैं, हमारे दो तो अडानी और अंबानी हैं। इस छत्तीसगढ़ को आप लोग उनके हाथों बेचना चाहते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- यहां से नेता और नेत्री को यहां से पैसा नहीं भेजते हैं। पहले तो यह सब आप लोगों की मजबूरी थी। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप लोग सीधा दिल्ली भेजते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महतारी वंदन योजना में नेत्री को मुम्बई पैसा गया है। आप मुम्बई में पैसा भेज रहे हैं। आप ऐसा बात मत करिये, आपके यहां छत्तीसगढ़ में करीना कपूर आ रही है।

सभापति महोदय :- धरम लाल, आप अपनी बात शुरू करिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सन्नी लियोनी को पैसा भेजे हैं, पैसा सन्नी लियोनी के खाते में पैसा जा रहा है।

श्री राजेश मूणत :- नेत्री कौन है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सन्नी लियोनी के खाते में पैसा भेज रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- कौन नेत्री है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग सन्नी लियोनी के खाते में पैसा डाल रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूं। उन्होंने जिस व्यक्ति की बात की, उनसे पूछिये। उन्होंने किस नेत्री की बात की है ?

श्री धरम लाल कौशिक :- जिनके लिए गुलाब की पुखड़िया बिछाई गई थी, उस नेत्री की बात कर रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह तो राज नेत्री है, आप तो अभिनेत्री के खाते में पैसा डाल रहे हैं।

सभापति महोदय :- संगीता जी, रामकुमार जी बैठिये। राम कुमार जी हर बात में बोलने के लिए खड़े होते हैं, यह उचित नहीं है। आप हर बार खड़े होते हैं।

श्री राम कुमार यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट।

सभापति महोदय :- एक मिनट नहीं, कई बार एक मिनट हो गया है।

श्री राम कुमार यादव :- कौशिक भईया, हमन ला एखर खातिर शंका हे। छत्तीसगढ़ी मा कहावत - जे हा दूध मा जरे रहथे, मही ला फूंक के पीथे। तुमन ट्रेन ला बेच द हा, तो हमन ला शक हे छत्तीसगढ़ के बस्तर ला झन बेच देहा, कहकर हमन ला शक ए।

श्री सुशांत शुक्ला :- ये दूध पीकर जहर बोलथे।

सभापति महोदय :- मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि अनुदान मांगों पर गंभीर चर्चा है। आप लोग अनावश्यक एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं। यह सदन की परम्परा में उचित नहीं है। आप लोग इस बात को ध्यान रखें।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, अनावश्यक विषयों में चर्चा नहीं करेंगे, आवश्यक विषयों में जरूर करेंगे। आप अनुमति दे दीजियेगा।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अनुदान मांग रखा गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि सवा साल इस कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को जिस ऊंचाई में ले जाना चाहिए था, छत्तीसगढ़ के किसानों की जो चिंता करना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की चिंता करनी चाहिए थी, छत्तीसगढ़ में हमारे श्रमिक बन्धुओं की चिंता करनी चाहिए थी और हमारा उद्योग नीति कैसा हो, उन सारी बातों को लेकर सवा साल में जो कार्य किया गया है, उसके कारण आज छत्तीसगढ़ का परिदृश्य बदला हुआ दिखाई दे रहा है। मैं निश्चित रूप से इसके मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जी के बहुत सारे विभाग हैं और उन बहुत सारे विभागों में अजय चन्द्राकर जी ने बहुत सारे विषयों को रख लिया है इसलिए उसको

दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ बातों को रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के द्वारा सामान्य प्रशासन को लेकर पारदर्शिता के साथ प्रयास किया गया है, उस प्रयास में सब विभागों की बात अलग है, लेकिन उनका जो स्वयं का ऑफिस है, उसको भी उन्होंने ई-ऑफिस बनाने के लिए प्रयास किया है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा 21 अगस्त, 2024 को ई-ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, इससे निश्चित रूप से न केवल मुख्यमंत्री जी की ऑफिस की पारदर्शिता दिखाई देगी, बल्कि अलग-अलग विभागों के जो सारे ऑफिस हैं, उनमें भी पारदर्शिता दिखाई देगी, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के लोग यह जाने कि मुख्यमंत्री जी कैसे काम कर रहे हैं, काम के साथ में उनके काम करने का जो तरीके हैं, उसके साथ में उनको छत्तीसगढ़ की जनता का जो प्रेम मिला है, उसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता उनसे कैसे मिल सकते हैं, इस बात को लेकर प्रयास हुआ है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं, मैंने इस बात को पिछले समय भी रखा था कि जिस प्रकार से सामान्य प्रशासन को लेकर पारदर्शिता की बात करते हैं तो खासकर हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों की जो अपेक्षाएं रहती हैं, उन अपेक्षाओं में कितना काम होगा, कितना काम नहीं होगा, वह अलग बात है, लेकिन उनसे बातचीत हो जाये और उनसे बातचीत के साथ हम समय-समय पर जो पत्र लिखते हैं, उसका जवाब भी आ जाये, यह हमें अपेक्षा रहती है। उन जनप्रतिनिधियों की यह अपेक्षाएं भी पूरी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। इन सवा सालों में यह डबल इंजन की सरकार ही नहीं, पहले हमारे मुख्यमंत्री जी, उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार Repeat हुई और उसके बाद में हमारी कथनी और करनी में जो समानता रही है कि हमने चुनाव के समय लोगों को वादा किया था, वह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही वादा नहीं किया था, बल्कि हम लागों ने उस वादा को निभाया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस वादा को निभाया। यह केवल डबल इंजन की सरकार ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार लगा दी है, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) इसके साथ ही साथ में आबकारी विभाग में बहुत ज्यादा बोलने का विषय नहीं है। अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि एक दुकान खोल दीजिये तो इधर से लोग हंसी उड़ा रहे थे। मैं इस बात को फिर से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में दुकान खोलने की बात अलग है, लेकिन जिस प्रकार से पिछली पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा शराब नीति को लेकर दुरूपयोग किया गया। उनके द्वारा दुरूपयोग करने कारण, इसी विधान सभा में जब हम इधर बैठते थे तब हम लोग अनेक बार प्रश्न उठाते थे कि एक दुकान में दो पेटी रखी जाती है, उसमें से एक पेटी सरकार की और दूसरी पेटी स्वयं की, वह सिस्टम बंद होनी चाहिए। लेकिन यह सरकार चली गई और यह लोग उस सिस्टम को बंद नहीं किये, जिसके कारण यहां की जनता को सरकार बदलनी पड़ी। आज सरकार आने के बाद में वह सारे सिस्टम चेंज हो गये, लेकिन उसके बाद में मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि उनके समय से जो कोचिया सिस्टम लाया गया है ..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मतलब जनता ने आपको कहा है कि दारू के दुकान को डबल करो तो उसको रखेंगे। यह सिस्टम है? दारू दुकान डबल हो रहा है, वह सिस्टम है?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सरकार आय के बाद 67 नया दारू भट्ठी खुल गय हावय, सिस्टम वहीं से हो रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- दारू दुकान डबल करना सिस्टम नहीं है। एक दुकान में दो पेटी रखा जाता है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जहां पर दारू दुकान नहीं था, वहां पर आप लागों ने दारू भट्ठी खोल रखा है। आप लोगों ने वहां पर बैठने की व्यवस्था कर रखी है, वहां पर लोग दारू पीयें और रोज एक्सीडेंट हो। आजकल महिलाएं भी दारू पीना शुरू कर दिये हैं।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, छत्तीसगढ़ के मन ला दारू पीयावौ, दारू भट्ठी खोला, तेखर बर तुमन सरकार म बईठे हौ। तुमन दारू भट्ठी ए.सी. रूम बनावत हौ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, एक दुकान में दो पेटी रखी जाती है, उसमें से एक पेटी सरकार की और दूसरी पेटी स्वयं की होती है, यह सिस्टम बंद होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश में पिछली सकरार द्वारा कोचिया सिस्टम लाई गई थी।(सत्तापक्षा के सदस्यों द्वारा शेम-शेम की आवाज) उस कोचिया सिस्टम के कारण आज गांवों में लोग परेशान हैं। अभी भी वह कोचिया सिस्टम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोचिया सिस्टम के बजाय यदि आवश्यक लगता है कि वहां पर शराब दुकान खोलने की आवश्यकता है तो वह दुकान खुल जानी चाहिए, लेकिन कोचिया सिस्टम में पूर्ण रूप से ब्रेक लगनी चाहिए, जिससे जो अवैध तरीके अपनाये गये थे, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होनी चाहिए और कोचिया सिस्टम समाप्त होनी चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, कहीं पर अवैध सिस्टम बंद नहीं होगा, वह लगातार चालू रहेगा क्योंकि आप राजस्व बढ़ाने के लिए, अपना आवक बढ़ाने के लिए दारू को बढ़ावा दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप लोग अपने समय में बात रख दीजियेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, हम प्रदेश में आबकारी विभाग को राजस्व का एक हिस्सा जरूर मानते हैं, लेकिन इस विभाग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता मुख्यमंत्री जी को भी नहीं है । इस विभाग को इंकम का जरिया न मानें, बल्कि इस विभाग में लोगों के माध्यम से कितना जागरूकरता फैला सकते हैं, हम जागरूकता लाकर यह न देखें कि उसमें हमारी इंकम जनरेट हो रही है, हमारी इंकम बढ़ रही है, इसके बजाय लोग शराब पीना कैसे कम करें, उस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है और उससे छत्तीसगढ़ का भला होगा । सभापति महोदय, आबकारी विभाग के राजस्व से

छत्तीसगढ़ का कोई भला होने वाला नहीं है । जब हम उर्जा विभाग की बात करते हैं तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, जहां वर्ष 2000 में 73 हजार पम्प के कनेक्शन थे, आज छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक पम्प कनेक्शन हुये हैं । मैं इसके लिये मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, हमारे कृषि में पम्पों को उर्जीकृत करने का काम सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर किये गये । हम लोगों ने पिछले समय देखा था, हम लोग बार-बार प्रश्न लगाते थे, इस बात को बार-बार कहते थे कि किसानों के पम्प कनेक्शन क्यों नहीं लग रहे हैं ? सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में यह पम्प के कनेक्शन लगने फिर से प्रारंभ हो गये हैं । माननीय सभापति महोदय, यदि उपभोक्ता के द्वारा बिजली के डिमांड बढ़ रही है तो यह कहा जाता है कि वह प्रदेश उन्नत दिशा में जा रहा है, जब उनकी आवश्यकता होगी तो डिमांड करेंगे । मुझे आज इस बात की खुशी है कि जहां हमारे 30 हजार जो उत्पादन क्षमता है और लोगों की मांग है, वह 2200 यूनिट प्रति माह की जो डिमांड आ रही है, हम कह सकते हैं कि यह प्रदेश निश्चित रूप से उन्नति की दिशा में जा रही है । माननीय सभापति महोदय, इसके लिये एकलबत्ती कनेक्शन में प्रावधान किये गये हैं, 15 लाख से ऊपर परिवार हैं उसका लाभ ले रहे हैं । उसके बाद 44 लाख 92 हजार परिवारों को बिजली बिल हॉफ का लाभ मिल रहा है और इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सूर्यघर की जो कल्पना की गई है, इसमें योजना बनाई गई है, 1 करोड़ लोगों के घरों में सूर्यघर के माध्यम से जो मुफ्त बिजली पहुंचाई जा रही है, उसमें लक्ष्य की दिशा में सरकार ने कार्य प्रारंभ कर दिया है, इसका फायदा करोड़ों लोगों को मिलेगा । माननीय सभापति महोदय, अविद्युतीकृत मजरे-टोले हैं, वहां भी लोग वंचित न हो, इसके लिये वहां पर विद्युत लाई का विस्तार आने वाले समय में हो और दूसरे माध्यमों से वहां बिजली पहुंचा सकें, यह व्यवस्था भी सरकार के द्वारा इस बजट में की गई है और उर्जा के क्षेत्र में प्रदेश की एक बड़ी प्रगति हुई है । सभापति महोदय, जहां पर 33/11 KVA सब स्टेशन का हो, उसके बाद 132 KVA का हो, 220 KVA का हो, 400 KVA का हो, जो नये-नये सब स्टेशन बना रहे हैं, इसके माध्यम से जो लो-वोल्टेज की समस्या रही है, उसको समाप्त करने का काम सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है । सभापति महोदय, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहां छत्तीसगढ़ में जो डोमेस्टिक कनेक्शन है, हमारे पम्प कनेक्शन अलग नहीं हुये हैं, इसके कारण से जब पम्प कनेक्शन की आपूर्ति बंद करते हैं तो डोमेस्टिक कनेक्शन की भी आपूर्ति बंद हो जाती है । आपूर्ति बंद होने के कारण जो गांव में पानी की व्यवस्था है, वह हमारे बिजली से जुड़ा हुआ है, नल-जल योजना हो, अन्य जो योजना हो, जब लाईट रहेगी तो आपको पानी मिलेगा और लाईट नहीं रहेगी तो पानी नहीं मिलेगा । यह जो दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों को दूर करने के लिये हम कितना जल्दी उसको सेप्रेट कर सकते हैं, जब तक नहीं हुये हैं, तब तक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी कि पानी का समस्या न हो, इतना सुबह-शाम वहां पर्याप्त बिजली मिले, जिससे लोगों को दिक्कत न आये ।

समय :-

3:00 बजे

माननीय सभापति महोदय, लोग अभी रबी फसल में काफी मात्रा में धान बोए हुए हैं। जैसे लोग खरीफ सीजन में धान की फसल लेते हैं, वैसे ही लोग रबी के धान का फसल ले रहे हैं । पिछले वर्ष गर्मी में धान के फसल का रेट अच्छा मिल गया था, जिसके कारण इस वर्ष धान बोने के रकबे में फिर वृद्धि हो गई । रकबे में वृद्धि हुई तो जिसने धान का रबी फसल लिया है तो उसके कारण वाटल लेवल लगातार डाऊन हो रहा है और वाटल लेवल डाऊन होने के कारण गांव में पीने के पानी का संकट आ रहा है और धान बोने के कारण वाटल लेवल डाऊन हुआ है । मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इस ओर विचार करने की आवश्यकता है कि हम वाटल लेवल को मेन्टेन कैसे करें । इसलिए अभी हम गर्मी के समय में पर्याप्त पानी की व्यवस्था की दृष्टि से लोगों को बिजली उपलब्ध कराएं ।

माननीय सभापति महोदय, खनिज विभाग की भी बहुत सारी चर्चा हो रही थी। खनिज के दृष्टिकोण से भगवान ने दोनों हाथों से छत्तीसगढ़ को परोसा है । हम यहां पर वन संपदा की बात करें, श्रम संपदा की बात करें, जल संपदा की बात करें । हम माईनिंग की बात करें तो उसमें कोयला और बाक्साइड आता है । आज हम देख रहे हैं कि खनिज के रूप में आय का जो साधन प्रदेश के लिए है, उसमें मुझे लगता है कि इस प्रदेश को 9000 करोड़ से ऊपर की राशि केवल खनिज संपदा के माध्यम से, रायल्टी के माध्यम से आय अर्जित हो रही है, जो विकास के कार्य में लगे हुए हैं । मैं रेत उत्खनन की अनुमति के बारे में देख रहा था कि 134 निविदा में से 92 खदान पर्यावरण सहमति प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाधीन है । अब लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं कि वह खदान खुला है या नहीं खुला है । इसके कारण रेत के अवैध खदानों का खनन हो रहा है, जो अवैध परिवहन हो रहा है । इस दिशा में मुझे लगता है कि हम अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन कैसे रोक सकते हैं । समाचार-पत्रों में, इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से यह बात लगातार उठती रहती है कि अवैध उत्खनन के कारण कई जगह बच्चियों की मृत्यु भी हुई है और बिलासपुर में बिजली के खम्बे के जो टॉवर हैं, वहां पर जो अवैध उत्खनन हुआ । हमारे गांव में अवैध खनन के कारण मृत्यु हुई तो जो अवैध उत्खनन को रोकने की आवश्यकता है । अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हम इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे दिन देखेंगे तो फिर से धड़ल्ले के साथ में अवैध उत्खनन जारी रहता है । खनिज विभाग में सरकार के द्वारा पारदर्शिता के साथ में काम किए जा रहे हैं, उसके कारण ई टेण्डरिंग के द्वारा जो एलॉटमेंट होता है तो मैं समझता हूं कि उसमें काफी पारदर्शिता आई है । मैं इसमें खनिज निधि की बात करूंगा, हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा बार-बार खनिज निधि की बात उठाई जाती है।

सभापति महोदय, मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में कहना चाहूंगा । जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में यहां बैठते थे तो मैंने इंगित करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री जी, आप जो स्वामी

आत्मानंद स्कूल खोल रहे हैं तो आप इसका सेटअप क्यों नहीं बना रहे हैं, आप इसकी नयी बिल्डिंग क्यों नहीं बना रहे हैं ? आप केवल रंग-रोगन कर रहे हैं। पुराने बिल्डिंग में जितना खर्च किया गया है, उससे कम खर्च में नया बिल्डिंग बना देते और सेट-अप कहीं नहीं बनाया गया । आज स्वामी आत्मानंद स्कूल की स्थिति क्या है ? उसे कलेक्टर के प्रसाद पर्यन्त छोड़ दिया गया और कलेक्टर के प्रसाद पर्यन्त छोड़ने के कारण में जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, वे कहते हैं कि हमारे यहां शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक की व्यवस्था की जाये । यदि इन सारी बातों को सोचकर स्कूल खोले होते तो शायद यह दिक्कत नहीं आती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें विचार कर रहे हैं कि जो स्कूल खोल दिए गए हैं, उसको हम ठीक प्रकार से संचालित कर सकें । साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें डीएमएफ में कैसे [xx] हुआ है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज डीएमएफ की राशि का जो [xx] हुआ है इसके कारण कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोग बेल में हैं । आज ये हमें खनिज नीति के बारे में बताएंगे? इन्होंने खनिज नीति और डीएमएफ का खुलकर दुरूपयोग किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी उस व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जनसंपर्क विभाग में हमारे यहां जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं हैं और उनका क्रियान्वयन है, ताकि उसे हम लोगों तक कैसे पहुंचा सकें, इसके लिए हम प्रयास करते हैं।

सभापति महोदय, पर्यटन एवं संस्कृति के मामले में भी हम देखते हैं कि इस दिशा में काम हो रहा है और उन कामों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसके साथ ही इस बजट में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कराने का जो प्रावधान किया गया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि गुजरात में यह कार्यक्रम चलता रहता है। छत्तीसगढ़ में इस दिशा में यह बहुत अच्छा प्रयास है। जब ये कार्यक्रम होंगे, तो न केवल वे निवेश करेंगे बल्कि निवेश के लिए अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने का काम भी उनके द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार के काम से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। महोदय, पिछले कार्यकाल में मीडिया पर अघोषित आपातकाल लगाया गया था। कई पत्रकारों को जेल भेजने का कार्य किया गया और इसी परिसर में बंदिश भी लगायी गयी कि आप क्यों दिखाते हैं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया आज स्वतंत्रता से कार्य कर रहा है और सरकार की अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है और सरकार की कमियों को भी उजागर कर रहा हैं, लेकिन हमारी सरकार से वह कभी भी भयभीत नहीं हैं जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार में वह दिखाई देते थे। आज उन्हें काम करने की आजादी मिली हुई है।

माननीय सभापति महोदय, परिवहन विभाग में प्रश्न और अन्य माध्यमों से बहुत चर्चा हुई है। आजकल परिवहन में हम राखड़ की ढुलाई या माल की ढुलाई में 18 चक्का और 22 चक्का गाड़ियों की बात करते हैं। इनके कारण आज लगातार एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं और मौतों की संख्या बढ़ रही है। इसमें

परिवहन विभाग द्वारा कैसे शिकंजा कसा जाए। हम देखते हैं कि गाड़ियों को किनारे खड़ा कर दिये हैं, लेकिन पीछे में जो स्टीगर लगना चाहिए, वह आपको नहीं दिखेगा और जिसके कारण पीछे से जाकर लोग टकरा रहे हैं। साथ ही साथ गाड़ियां बड़े ही रफ्तार से चल रही हैं और बिना नियमों का पालन किए चल रही हैं। इसके लिए वर्ष 2025-26 में जिला परिवहन कार्यालयों में automated computerized driving test e track की स्थापना की घोषणा हुई है, ताकि वे कितना प्रशिक्षित हैं और किस प्रकार से उनको प्रशिक्षित करके गाड़ियां चलाई जा सकें, उन्हें हम कैसे लाईसेंस जारी करें, इस पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से सारी बातों को देखते हुए इन कार्यालयों में automated computerized driving test e track की स्थापना की घोषणा हुई है। मैं समझता हूं कि इससे एक्सीडेन्ट्स की समस्या में कमी आएगी और जो लगातार मौतें हो रही हैं, उसमें भी कमी आएगी।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में ग्रामोद्योग में अपार संभावनाएं हैं। चाहे सूक्ष्म, लघु या मध्यम क्षेत्र हो, यहां पर हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे हम बस्तर के काष्ठ शिल्प की बात करें, अंबिकापुर के कालीन बुनाई की बात करें, बैगनडीह सारंगढ़ की बात करें तथा इसी प्रकार से हम चांपा की बात कर सकते हैं। कोंडागांव की बात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य जो हमारे हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उस क्षेत्र में उनको बाजार की उपलब्धता कराना, उनके माल को बेचने की व्यवस्था करना और सरकार के द्वारा उनको सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उनको नवीन बुनाई प्रशिक्षण देना और उपकरण प्रदान करने के लिए भी बजट में राशि की व्यवस्था की गयी है। उसके लिये समय के साथ परिवर्तन किया गया है। आज के समय में जो उनके उत्पाद की मांग है, उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है और उसके अनुरूप सरकार के द्वारा उनको चिन्हांकित किया जाना और चिन्हांकित करके काम करना। मैं इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उनके कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण की व्यवस्था की ताकि हम समय के साथ उसमें सुधार कर सके और समय के साथ उनके माल के उत्पादन की बाजारों में बिक्री हो सके। इसके लिये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी और सराकर के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हम यह कह सकते हैं कि जो ग्राम स्वराज की कल्पना की गयी है, वह उस ग्राम स्वराज की सही मायने में प्राप्ति करना है। ऐसे जो हमारे आधारभूत है। मैं सूक्ष्म और लघु कुटीर उद्योग की बात करता हूं। यदि इसको बढ़ावा देंगे तो गांव में आर्थिक समृद्धि आयेगी और जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, केवल उनको ही नहीं बल्कि उससे गांव में भी विकास बढ़ेगा और गांव में समृद्धि आयेगी।

सभापति महोदय :- धरमलाल जी, थोड़ा संक्षेप करिये।

श्री धमरलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं बस 5-10 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, विमानन की जो बात आयी है, वह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्रयास है। चाहे जगदलपुर की बात करें, चाहे अंबिकापुर की बात करें या चाहे बिलासपुर की बात करें। बिलासपुर का एक मामला अटका हुआ है। वह मामला यह है कि आप वहां पर बड़े प्लेन उड़ाने की स्थिति में नहीं है। वह तब तक संभव नहीं होगा, जब तक जमीन का अधिग्रहण न किया जाये। यदि जमीन का अधिग्रहरण करना है तो वहां सेना के पास 1200 एकड़ जमीन है। सेना ने उस जमीन को पहले अपने लिये अधिग्रहित करायी थी लेकिन उनके नाम में जाने के बाद उनका कार्यक्रम बंद हो गया। आज वह जमीन वहां पर खाली पड़ी हुई है। वह जमीन एयरपोर्ट से लगी हुई है। यदि उसमें से 300-400 एकड़ जमीन ले ली जाये, जो एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम वहां पर बड़े प्लेन उड़ा सकते हैं। यदि हम वहां की एयर स्ट्रिप को बढ़ाना चाहते हैं तो वहां आज अलग जमीन नहीं है, तब तक हम सेना की जमीन को उनसे नहीं लेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आज यदि हम रायपुर की पैसेंजर फ्लाइट्स की बात करें, तो उसमें 40 प्रतिशत बिलासपुर संभाग के लोगों की भागीदारी है, जो रायपुर आकर यहां से विभिन्न प्रदेशों में जाते हैं। बिलासपुर एयरपोर्ट प्रारंभ हो तो गया है और वहां से हमारी कुछ फ्लाइट्स भी चल रही है। जैसे दिल्ली के लिये, प्रयागराज के लिये, जबलपुर के लिये, कोलकाता के लिये और उसके साथ अलग-अलग स्थानों के लिये फ्लाइट्स चल रही है। एक तो इसकी नियमितता रहे, फ्लाइट रेगुलर चले। मैंने उसके साथ ही साथ कहा कि यदि आपको बोइंग विमान चलाना है तो उसके लिये आपको एयर स्ट्रिप को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके अंबिकापुर में भी ट्रायल चल रहा है, आपने उसको प्रारंभ किया। हमारे जगदलपुर में प्लेन की सेवाएं लोगों को मिल रही है और वहां से विशाखापट्टनम और रायपुर के लिये भी प्लेन की सुविधा है। यह एक बहुत अच्छा प्रयास है और इस प्रयास में थोड़ा सा और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों को भी इससे एक बड़ी सुविधा मिलेगी। माननीयम मुख्यमंत्री जी, मुझे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जिस प्रकार से बस्तर और सरगुजा जिले में मोबाईल कनेक्टिविटी वृद्धि के लिये नेटवर्क क्रांति योजना प्रारंभ की गयी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री टॉवर योजना के लिये भी बजट में प्रावधान किया गया है। आज जो बीजापुर के बच्चे आये हैं, मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। वे अलग-अलग पंचायतों से आये हैं। कल विजय शर्मा जी बता रहे थे। आज हम लोगों ने उनसे पूछा कि 1 साल पहले तक कितने लोगों ने इस उम्र में टी.व्ही. नहीं देखी है ? उसमें लगभग 95 प्रतिशत जो बच्चे हैं, उन्होंने बताया कि हमने टी.व्ही. नहीं देखी है। उन्होंने मोबाईल का उपयोग नहीं किया है। आप यह बताईये कि जहां हम एक तरफ सूचना क्रांति की बात करते हैं और तरफ सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, हम दूरस्थ अंचलों को नेटवर्किंग से कनेक्ट करने की बात करते हैं। हमारे प्रदेश में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन क्षेत्रों में नियल नेल्ला नार योजना के अंतर्गत गांवों का समुचित रूप से कैसे विकास हो,

उसके लिए जो प्रयास किये गये। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उस दिशा में यह कारगर कदम साबित होगा। आने वाले समय में हम सूचना क्रांति की बात करते हैं तो अभी तक जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ में उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है और वहां जो इससे दूर रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको जोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। हम समुचित विकास की बात कहते हैं तो केवल हम किसी एक क्षेत्र के विकास की बात नहीं कहते हैं, बल्कि हमारे प्रदेश का समुचित रूप से कैसे विकास हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं संस्कृति विभाग पर कहना चाहूंगा। हमारे प्रदेश की जो विरासत और संस्कृति है, हमारी सरकार के द्वारा इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा गोड़ी और हल्बी भाषा के विकास हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो भारत भवन के निर्माण की बात आयी है निश्चित रूप से भारत भवन का निर्माण होने से हमारे जो छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने, कला को निखारने के लिए एक मंच मिलेगा। इससे वह हमारी संस्कृति और कला क्षेत्र से जुड़ेंगे। यहां के कलाकार एक बड़े मंच के माध्यम से प्रस्तुति देंगे । उसे हम न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए भारत भवन के निर्माण का प्रस्ताव लाये हैं निश्चित रूप से इससे हमारी संस्कृति को उजागर करने में काफी लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जब यहां स्कूल शिक्षा पर बात आयी है। इस विषय में बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन हमारी नई शिक्षा नीति के तहत छत्तीसगढ़ को जोड़ने का प्रयास करना और यहां पर नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात है। इतना ही नहीं बल्कि उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विकसित की जाये। उसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। यहां पर नई शिक्षा नीति के तहत लगभग 16 भाषाओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने की योजना बनायी गयी है। निश्चित रूप से उस योजना के अंतर्गत जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, बोली हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। हमारे स्कूलों में 4 अन्तर्राज्यीय भाषा में पुस्तकें, पाठ्यक्रम संचालित की जा रही हैं। ऐसे ही यहां अब दो बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। हमारे जो विद्यार्थी हैं और पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको परीक्षाओं का बोझ न हो, उसके लिए यह प्रयास किये गये हैं और उसके साथ ही साथ 5 वीं और 8 वीं कक्षा की जो बोर्ड परीक्षा लेने की तैयारी की गई है। हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके, विकास कैसे कर सकें, हम उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दे सकें, उसके लिए इस दिशा में प्रयास किये गये हैं। मैं हमारी नई व्यवसायिक शिक्षा पर कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक है। यहां पर हमारी सरकार के द्वारा 692 शालाओं में व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है। इसमें मुख्य रूप से टूरिज्म और उसके साथ में Hospitality, पॉवर, अपलेयर, हेल्थ केयर, रिटेल और टेलीकॉम इसी तरह की 15 विधाओं में प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके प्रथम चरण में 10 लाख असाक्षरों को साक्षर किये जाने का लक्ष्य है । वर्ष 2030 तक प्रदेश को शत प्रतिशत साक्षर करने की योजना बनायी

गयी है। इस बजट में अनेक स्कूलों को अपग्रेड करने का काम किया गया है। इस पर समय-समय पर जनप्रतिनिधियों की मांग भी आती है, उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास स्कूल शिक्षा विभाग भी है, इन सब को दृष्टिगत रखते हुए, चाहे वह 5 वीं से आठवी कक्षा हो या आठवीं से दसवीं कक्षा हो या दसवीं से बारहवीं कक्षा हो। इस बजट के माध्यम से अपग्रेड करने का काम किया गया है। इसमें क्षेत्र की मांग के अनुसार उनको लाभ भी मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जब हम पर्यटन विभाग की बात करते हैं तो पर्यटन के दृष्टिकोण से चाहे मैनपाट , चित्रकूट, कोटमसर गुफा, बड़े गणेश जी की बात करें, ऐसे हमारे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर पर्यटन के दृष्टिकोण से काम करने की अपार संभावनायें हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म की बात करें, जहां पर केवल कुछ सुविधायें मुहैया कराने की बात है। यदि आपको पर्यटन को बढ़ावा देना है तो सुविधाओं में वृद्धि करनी होगी। उसके बाद पर्यटकों के रूकने के लिए रेस्ट हाउस, होटल की व्यवस्था हो, वहां पर बहुत अच्छी सड़कें हों, सुरक्षा व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो। एक पर्यटक चाहता है कि पर्यटन क्षेत्र में अपने परिवार, मित्रों के साथ जाऊं तो जो बुनियादी सुविधायें हैं, वह बुनियादी सुविधायें देने से हमारे पास में पर्यटन की अपार संभावनायें हैं जिससे पर्यटन के दृष्टिकोण से यहां पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। न केवल देश के बल्कि हम विदेशी पर्यटकों को भी खींचकर के ला सकते हैं। यह आकर्षण पैदा करने की स्थिति छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम जितना काम पर्यटन के क्षेत्र में करेंगे, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने और हम कैसे पर्यटन के माध्यम से उद्योग के दृष्टिकोण से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। उससे यहां पर नये रोजगारों का सृजन होगा, लोगों को छोटे काम करने का भी अवसर मिलेगा, केवल उतना ही बल्कि हमारे उत्पादों की बिक्री भी होगी और आर्थिक रूप से समृद्धि भी मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत काम करने की संभावनायें हैं।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्रयास हमारे माननीय मुख्ममंत्री जी और अधिकारियों के द्वारा किया गया है, अब ई-लर्निंग और स्मार्ट क्लासरूम का दौर आ गया है। ऐसे में हम महाविद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से कितना लैस कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ center of excellence की अहम भूमिका रहेगी। इस दृष्टिाकोण से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह गति के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से जो हमारे काम प्रारंभ हुए हैं तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। रायगढ़ में भी एक नवीन संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अभी तक हम केवल खैरागढ़ संगीत महाविद्यालय की बात करते थे। संगीत के क्षेत्र में एक नवीन महाविद्यालय का उदय हो रहा है। क्योंकि रायगढ़ घराने की अलग से पहचान है और वहां यदि संगीत महाविद्यालय ला रहे हैं तो निश्चित रूप से उस विधा में लोगों को जुड़ने का, समझने का लाभ मिलेगा और उस दिशा में काम होंगे।

माननीय सभापति महोदय, 25 जिलों में एक महाविद्यालय को center of excellence के रूप

में भी विकसित करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा किया गया है। उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। निश्चित रूप से यह सबकी जो अपेक्षा रहती है, उन अपेक्षाओं में हमारी सरकार खरा उतर रही है।

सभापति महोदय :- धरमलाल जी, आपको बोलने हुए आधा घंटा से ज्यादा हो गये। कृपया समाप्त करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। मैं कुछ को ऐसे ही बता देता हूं। जिस प्रकार से पशुपालन, दुग्ध, डेयरी के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है, डेयरी के क्षेत्र में भी अपार संभावनायें हैं। यहां नदियां हैं, नदियों में एनीकट बना हुआ है, एनीकट में बारहमासी पानी है। यदि हम उनको डेयरी के क्षेत्र में जोड़ते हैं। आज भी छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि डेयरी में काम करने की अधिक संभावनाये हैं। डेयरी केवल दूध बेचने का साधन नहीं है, बल्कि डेयरी हमारे किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। डेयरी के माध्यम से पशुओं को सुरक्षित रखने का भी मामला है। डेयरी के माध्यम से हमारे पशुओं को सुरक्षित रखने का भी मामला है और डेयरी में जो सब्सिडी दी जा रही है, उस सब्सिडी के माध्यम से हम अधिकाधिक कैसे उसको लिंक करके जोड़ सकते हैं और लिंक करके जोड़कर इस डेयरी के क्षेत्र में अनेक काम करने की संभावना है । इसके साथ ही साथ हमारी नदियों में जो पानी है उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं ? हमारे एनीकट बने हुए हैं, उस जल का उपयोग हम डेयरी के क्षेत्र में भी कर सकते हैं । मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अवार्ड भी मिला है चूंकि मत्स्य पालन के क्षेत्र में हमारा देश में जो स्थान है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे काम हुए हैं और मत्स्य पालन के क्षेत्र में अभी और काम करने की संभावनाएं हैं इसलिये अभी-अभी नये जिलों में नये हैचरी के भी काम प्रारंभ हुए हैं इसके साथ ही साथ हमारे जो पुराने हैचरी हैं उनको और मजबूत करने का काम और इसके साथ ही मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो जन्म से काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और जब हम उनको प्रोत्साहित करेंगे तो उनका जो पैदाईशी जीविकोपार्जन का साधन है, हमारे जो डेम हैं, हमारे जो बड़े तालाब हैं, आजकल जो उसकी नीलामी होती है उस नीलामी में हम उनको कितनी प्राथमिकता दे सकते हैं और प्राथमिकता के साथ में यदि उस नीलामी में मत्स्य पालन के लिये हम उसको देंगे तो निश्चित रूप से वह समाज आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे और जो मत्स्य के क्षेत्र में बचपन से काम करते आ रहे हैं उनको एक नया काम भी मिलेगा और काम के साथ-साथ वह ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में उत्पादन करने में सफल होंगे तो मैं इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मत्स्य पालन करने वाला समाज चाहे हम केंवट समाज की बात करें । केंवट समाज में ऐसे बहुत सारे समाज हैं जो उस मछली के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सारे समाजों को प्राथमिकता के आधार पर हम उसको कैसे दे सकें इसके लिये प्रयास आवश्यक है ।

माननीय सभापति महोदय, हमारा धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग है जिसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों के लिये व्यवस्था की गयी है । लगातार अयोध्या में रामलला दर्शन योजना । हम लोग भी उन्हें छोड़ने के लिये स्टेशन जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उन्हें ट्रेन में बैठाते हैं और आने के बाद में जब हम उनसे पूछते हैं कि आपकी यात्रा कैसी रही तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह रामलला दर्शन योजना चलायी जा रही है तो यदि वे अपना खर्च करके भी जायेंगे तो भी उनको उतने आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, उतनी सुविधा नहीं मिलेगी जितना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो रामलला का दर्शन कराया जा रहा है इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । (मेजों की थपथपाहट) नियमित रूप से हमारी ट्रेन और गाड़ियां चल रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों की तो यह अपेक्षा है कि उसमें और वृद्धि की जाये । अब आप उसको देखिये, उसको बजट में बढ़ाईये । अभी तक हमने 22,000 लोगों को रामलला दर्शन कराया है लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें लोग आकर यह बोलते हैं कि साहब हमारा कोटा बढ़वाईये और कोटा बढ़ाकर जयादा से ज्यादा लोगों को रामलला दर्शन करने का अवसर मिले । माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस दिशा में एक बहुत अच्छा काम प्रारंभ किया गया है ।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर भाषण ला सुन के महाज्ञानी जी सुत भुलईस ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ हम लोग बहुत समय से मांग कर रहे थे कि जैसे बहुत सारे लोग बाबाधाम जाते हैं, जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिये जाते हैं इसी प्रकार से हमारे जो अन्य धार्मिक स्थल हैं, वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उनके रूकने के लिये व्यवस्था की जाये इस हेतु वहां पर धर्मशाला बनाये जायें, यह हम लोग समय-समय पर मांग कर रहे थे लेकिन उसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहल की गयी है और प्रारंभिक रूप से वहां जमीन खरीदी के लिये 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है कि हम जमीन खरीदकर वहां बड़े-बड़े धर्मशाला बनायेंगे । (मेजों की थपथपाहट) हम न केवल उनको प्रदेश में सुविधा देंगे बल्कि प्रदेश के बाहर भी हमारे यात्रियों को सुविधा मिले सके इसके लिये सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, मैं इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को बधाई देना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, सुशासन की बात आयी है तो हम लोग इस बात को कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी का सुशासन । यह केवल कहने का नहीं है बल्कि इस दिशा में हमारी नीति और नीयत । हम दोनों में अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, इसके लिए जनता का भरोसा भी जीतने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। माननीय सभापति महोदय, ई-ऑफिस नवाचार की बात आई है। निश्चित रूप से इसमें हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे सुधार की यहां पर आवश्यकता है और मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, उसके लिए वे काम रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे जो वर्क कल्चर में बदलाव आए। एक बार अजय जी के द्वारा

यहां से इस बात को रखा गया था कि डी.एन.ए. बदल गए हैं। वे मेरी बात को सुन रहे है, वे अभी उठ जायेंगे। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- ओहा, ब्रह्मनींद में लीन होगे हे। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- अजय चंद्राकर जी के द्वारा ये बात रखी गई थी कि वर्क कल्चर हमारे डी.एन.ए. बदल गए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे सारे अधिकारियों ने सकारात्मक दिशा में सोच और सकारात्मक दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, इससे हमारा प्रदेश विकास की दिशा में बढ़ रहा है। रामकुमार पिछली सरकार में आपको मालूम है, आप भी थे कि अधिकारियों से कैसे काम कराते थे? कैसे काम कराते थे, वह बताने की जरूरत नहीं है। यह उनके काम का परिणाम है कि आज वे जेल में हैं और आज भी बेल में हैं, उसको बदलने की आवश्यकता थी और हमारी सरकार ने उसको बदलने का काम किया है।

श्री रामकुमार यादव :- भैया..।

सभापति महोदय :- आप बैठिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने सरकार चलाया था। अभी हम सरकार चला रहे हैं और इस प्रदेश में सकारात्मक सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, ए अधिकारी के चक्कर में मत रहिया, ए अधिकारी के चक्कर में रहिया न तो ए मन टोपी पहना देथे, भौंरा में मत रहियौ।

श्री धरमलाल कौशिक :- रामकुमार, ते ठीक बोलत हस। मुख्यमंत्री हा तुम्हर नहीं सुनत रहिसे। ओ केवल अधिकारी के सुनत रहिस हावै और न केवल तुमन ला टोपी पहनाइस, बल्कि मुख्यमंत्री जी ला भी टोपी पहना दिस। (हंसी) ते बहुत बढिया बात बोलत हस। लेकिन हमर मुख्यमंत्री जी ये चक्कर में नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी की सोच, उनके खुद के विचार और जनता के हित में क्या क्रियान्वयन कराना है, ये उनके विचार के साथ में वे काम कराते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों की जो चर्चा हो रही है और उस चर्चा में सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हम छत्तीसगढ़ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, छत्तीसगढ़ की जो हमारी पुरानी पहचान थी, वह पहचान बने और उसके साथ में निरंतर प्रगति के पथ पर छत्तीसगढ़ आगे चले, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके जीवन में खुशहाली आये, छत्तीसगढ़ के किसान सुखी रहें, छत्तीसगढ़ में माताओं का वंदन होता रहे और महिला समृद्धि की दिशा में जो काम हो रहे हैं और उसके साथ में हमारा छत्तीसगढ़ चहुंमुखी विकास की दिशा में अग्रसर हो, मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए अपनी बात को करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं मांग संख्या 1, 12, 25, 32 और 27 में बोलने के लिए खड़ी हूं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे विभाग हैं।

श्री राम विचार नेताम :- जो भी बोलेंगी सही बोलेंगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जो भी बोलूंगी सही ही बोलूंगी।

श्री रामविचार नेताम :- सही-सही ही बोलेंगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं शुरूआत ही वहीं से करना चाहती हूं, जो महोदय जी ने बोला। पिछले 5 साल पूर्ववर्ती सरकार में आप लोग यहां बैठे थे, हम वहां थे। उस समय जितनी भी विभागीय चर्चा होती थी, उसमें सबसे ज्यादा जिस विभाग में हल्ला करते थे, आवाज उठाते थे, वह सबसे ज्यादा दारू पर था। बाकी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन दारू पर अवश्य चर्चा होती था। दिन में एक बार..।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीया जी, इतने सारे विभाग में आपको दारू ही मिला? शुरुआत करने के लिए और कोई विभाग नहीं मिला?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं मुद्दे पर आ रही हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- इससे देखिए, दारू में कितनी लोकप्रियता है, वह समझ में आ रहा है। (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं बता रही हूं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कलार समाज के व्यवसाय शराब है।

श्री अजय चंद्राकर :- दारू से ओखर मन के ऐतिहासिक संबंध है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- ओही ला तो कहाथ हो गा।

श्री अजय चंद्राकर :- है न। हवय कि नहीं हे?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हावय। हमारा वंशज है।

श्री रामकुमार यादव :- दोहा पारव दोहा।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा भाषण में बता तो मंतरपी काला कहिथे तेला।

श्री रामकुमार यादव :- मैं दारू बर दोहा पार दूंहूं।

श्री अजय चंद्राकर :- बइठ।

श्री रामकुमार यादव :- अतका बेर ले सुतत रहे अभी बइठ कथे । तू गहरा नींद में हे, सरकार के जब भी तारीफ होथे तो तोला नींद आथे, एखर सेती तोला बनाके रखे हे बीच में ।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार तुम कितना भी खड़े हो, पिछले शासन की प्रशंसा कर लो, तुमको तो झलक ही मिली है, अंदर तो आया नहीं है ।

श्री रामकुमार यादव :- तू अभी सिर्फ मूकदर्शक बनके बइठे रहियो, हमन तोला मंत्री बनही काहत रहेन । तू कइसे मंत्री बनत हो तेला बताओ ।

समय
3.35 बजे

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेंडी) पीठासीन हुईं)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं दोहे से शुरूआत करूंगी । सामने बैठे लोगों से अपेक्षा करूंगी कि वाह वाह जरूर बोलेंगे । राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी । विष्णु राज में दारू मिले, खुले आम पी । सभापति महोदय, मैं दारू की बात करूं तो ये हमेशा पूर्ववर्ती सरकार की बात करते हैं । अभी मैं बोल रही हूं कि हमेशा यहां पर चंद्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मन्तरपी का होते तेखर बारे में तो बता ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं बताहूं ना, आगे चलके बताहूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी बता ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, दारू बंद करो कहते हुए यहां से कई बार निलंबित हुए और बाहर भी जा चुके हैं । लगातार दारू बंद करने के लिए शासन पर हमेशा दबाव बनाया गया । आज क्या हो रहा है ? अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो सभी जगह नई नई दारू भट्ठियां खुल रही हैं । पंचायत में फोन जाता है और दबाव बनाया जाता है कि यहां दारू भट्ठी खुले । अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो गुरूर में दूसरी दारू भट्ठी खुल चुकी है, करहीभदर में खुल चुकी है और बालोद में भी खुल चुकी है और अभी अरमरीकला सहित बहुत सी पंचायतों में डिमांड आ गई है । सभापति महोदय, यही चंद्राकर जी हैं जो बहुत चिल्लाते थे, आवाज देते थे, इन्हीं चंद्राकर जी का एक बाइट आया था क्वालिटी क्वालिटी की दारू मिलेगी । आए रिहिस के नइ आए रिहिस ? आप ही का बयान है। सभापति जी, छत्तीसगढ़ राज्य की जनता का ऐसे में क्या होगा ? अभी तक तो पुरूष पी रहे थे, अब महिलाएं भी पीना शुरू कर देंगी और होली में हमने देखा भी है आपने दारू सस्ती की तो महिलाओं और बच्चों ने भी पीना शुरू कर दिया । स्थिति यह है कि बच्चे तक नशा कर रहे हैं । आजकल छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं और दारू भट्ठी जाकर दारू पी रहे हैं । सभापति महोदय, सरकार के पास राजस्व बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं । आप दूसरे काम कीजिए लेकिन दारू पर काम मत कीजिए । दारू को छोड़ दीजिए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- पिछली सरकार में डबल काउंटर, कोचिया की व्यवस्था और उससे इनका निजी राजस्व बढ़ता था । ये उससे वंचित हो गए, अब उसकी पीड़ा यहां झलका रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन दारू भट्ठी खोले के ठेका ले हौ । सरकार चलाए के ठेका ले हौ के दारू भट्ठी खोले के महाराज । महाराज हो कम से कम तू तो एमा सम्मिलित मत हो ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, हरिभूमि देखो, दैनिक भास्कर देखो, नवभारत देखो तो पहली लाईन रहती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तैं साफ साफ बता, एती तेती के बात मत कर । बेचारा हमर दोस्त कवासी लखमा कहां चल दे हे, कहां गे हे अउ काबर गे हे ?

श्री रामकुमार यादव :- ओला तुमन जबरदस्ती भेजे हौ । छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज देखत हे, तूमन बेमतलब के जेल भेजे हौ । प्रदेश के आदिवासी समाज देखत हे, 32 परसेंट आदिवासी समाज ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, 15 साल इनकी सरकार थी 44 हजार करोड़ का घोटाला आबकारी में किया था । उसको अगर गिनें तो ?

श्री सुशांत शुक्ला :- कौन सा घोटोला हुआ था, तथ्य दें ? यह सम्मानित सदन है यहां सीधा सीधा झूठ बोला जा रहा है, यह अच्छी बात नहीं है । कोचिया और वसूलीबाज लोग थे आपकी सरकार में ।

सभापति महोदय :- आप बैठ जाएं, उनको अपना वक्तव्य पूरा करने दें ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- रायपुर में 10 करोड़ की राशि (व्यवधान) अगर आवक की बात करूं 2025-26 में नई दुकानों की बात करूं तो 67 नई दुकानें खुल रही हैं, दारू भट्ठी में 10 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है । वहां पर काउंटर लगाकर पिलाने का भी काम कर रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है । यहां दारू की खपत में 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है । आप लोग शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र को छोड़कर सीधा पिलाने का काम कर रहे हैं, ताकि राजस्व बढ़े, राजस्व दुगुना हुआ है, यह आपके प्रतिवेदन में दिया है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, इस बात को सिद्ध करता है कि पूर्ववर्ती सरकार में जो दो हजार करोड़ रूपए इनके माता दरबार में चढ़ावे के रूप में चढ़ा दिया गया। एकपक्षीय परिवार (व्यवधान) मेरी साथी सदस्या इस बात को सिद्ध कर रही है कि पूर्ववर्ती सरकार में 2 हजार करोड़ रूपए की ज्यादा की लूट एक परिवार के चरणवंदना में समर्पित कर दिया गया। इस बात से सिद्ध हो रही है कि छत्तीसगढ़ में राजस्व बढ़ा है। वह राजस्व पिछली सरकार में कहां थी ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी बैठ जाईए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं प्रतिवेदन की ही बात कर रही हूं। इस प्रतिवेदन में दिया है।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगए ला दरूहा बनात हो। दारू ला तुमन बेचत हो, भट्ठी तुमन खोलत हा। (व्यवधान) चखना दुकान खोलत हो। दारू भट्ठी में बैठावत हो। (व्यवधान) तुमन ला ऐखरे बर बनाय हन कि दारू बेचो करके। तुमन ला अउ कुछु काम नई मिलत हे। महराज, कम से कम तुमन दारू झन बेचव। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी, रामकुमार जी बैठ जाईए। आप लोग बीच-बीच में खड़े मत होइए, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं राजस्व की बात करूं तो आबकारी विभाग में राजस्व दुगुना हुआ है। ये प्रतिवेदन में ही दिया है। वर्ष 2020-21 में 4636 करोड़ की राशि थी, ये राशि धीरे-धीरे बढ़ते हुए वर्ष 2022 में 5510 करोड़ हुआ, अगर मैं वर्ष 2023-24 की बात करूं तो 8430 करोड़ रूपए की बढ़ोत्तरी हुई है, राजस्व दुगुना हुआ है। आप छत्तीसगढ़ को पीछे धकेल रहे हैं, 10 साल आगे की बात करते हैं, आप क्या करेंगे ? आपने बच्चों को बैठकार दारू पिलाना शुरू कर दिया, बैठाकर दारू पिलाना शुरू कर दिया, महिलाओं को पिलाना शुरू कर दिया। आप एक तरफ महतारी वंदन देते हैं, दूसरी तरफ दारू पिला रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, हमारी वरिष्ठ साथी हैं, मैं पूछना चाहता हूं अगर राजस्व बढ़ा है तो पूर्ववर्ती सरकार में वह राजस्व किसके जेब में गया? वे कौन लोग हैं जो जेल में हैं ? ये बताईए। (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- दारू आप लोग पिलाते हैं, आप लोगों ने कोरोनाकाल में ऑनलाईन दारू बेचने की शुरूआत की थी। आप लोगों ने घर पर दारू पहुंचाया था। लज्जा करिए।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- अभी तो आप लोग पिला रहे हो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, अगर इसको शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करें तो ज्यादा उचित होगा। अगर इसमें उनको ज्यादा परेशानी है तो मैं आगे बढ़ रही हूं। सभापति महोदय, मैं ऊर्जा विभाग में अपनी बात रखना चाहती हूं। बिजली बिल हाफ योजना। यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने बिजली बिल हाफ किया। हमारे गरीब किसान बहुत खुश हुए।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपने बिजली बिल हाफ नहीं बिजली बिल साफ कर दिया।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आप बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- बिजली गायब हो गई, बिजली गोल रहने लगा। गांव में पूरी बिजली साफ हो गई थी, बिजली आती ही नहीं थी। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी गांव में जाकर देखिए, किसान बिजली के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, आप क्या जानोगे। आपकी सरकार में अभी महासमुंद में आत्महत्या हुई, आपको मालूम है। अभी महासमुंद में पूरण निषाद जी ने आत्महत्या की, केवल बिजली के कारण आत्महत्या की है।

सभापति महोदय :- निषाद जी, प्लीज आप बैठ जाईए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, सरकार ने बिजली बिल हाफ का समर्थन किया। हमने यहां से बधाई दी। एक ऐसी योजना है जिसका इस सरकार ने समर्थन किया। आज आप गांव में जाकर देखिए, 200-300 रूपए बिजली बिल आता था, अभी किसान भाईयों का हजार रूपए बिजली बिल आ रहा है। जो गरीब तपके के लोग हैं, 200-300 रूपए रोजी कमाते हैं, वे हजार रूपये बिजली बिल पटाते हैं, आपने बिजली बिल में बढ़ोत्तरी की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करती हूं कि इस ओर विशेष रूप

से ध्यान दें, क्योंकि यह गरीबों का मामला है, जनहित का मामला है। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, मैं बता रही हूं, जो मीटर रिडिंग करते हैं, वे लोग गांव के लोगों के बीच गये, गांव वालों ने कहा कि बिजली बिल बहुत आता है, उन्होंने कहा कि कम कर देंगे, हमको थोड़ी सी राशि दीजिए, हम आपकी बिजली बिल कम कर देंगे, आपकी मीटर की रिडिंग कम आएगी और बिजली बिल कम आएगा। वे लोग बिजली मीटर लेकर अपने घर गए, पता नहीं, उसमें क्या किए, उसको लाकर लगाए, जब उनके घर छापा पड़ा वे बड़े लोग नहीं थे, वे गरीब लोग ही थे, वे 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख की पेनाल्टी भरे हैं। उनके भाईयों से हमने कहा कि आप रिपोर्ट करवाईए तो FIR दर्ज हुआ ही नहीं, जब विभाग वाले वहां रिपोर्ट करने गए तो उनके द्वारा भी वहां FIR दर्ज नहीं हुई। ये बहुत ही संगीन मामला है, गंभीर मामला है, मीटर रिडिंग करने वालों ने गड़बड़ी की है, सरकारी आदमी मीटर को खराब कर रहे हैं और जो किसान भाई हैं, जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, वे 2-2 लाख, 5-5 लाख रूपए पेनाल्टी भर रहे हैं। मैं इस विषय पर विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कम से कम मीटर रीडर उन पर कार्रवाई करें। आज तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे पैसे की वसूली की जानी चाहिए। यह विशेष तौर पर संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र की बात है। मैं आपको नाम सहित इसकी जानकारी दे दूंगी। आदरणीय सभापति महोदया जी, पिछले 1 वर्ष से अघोषित बिजली कटौती बहुत हो रही है। लो वोल्टेज की बहुत समस्या है। थोड़ी सी हवा चली नहीं कि बिजली बंद हो जाती है। 8-8 घंटे तक लाइट बंद रहती है। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप इस पर विशेष ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदया, मैं जन संपर्क विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में चर्चा करना चाहूंगी। जो इसकी वेबसाइट होती है, यदि आप उस वेबसाइट को खोलकर देखेंगे तो उसमें वर्ष 2019-2020 की ही रिकॉर्डिंग दिखाती है। आज तक का कुछ भी ऑनलाइन नहीं दिखता है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में चौथे नंबर में लोक प्राधिकारियों की बाध्यता में स्पष्ट लिखा है कि कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों का संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से ऐसे अभिलेख की पहुंच को सुगम बनाया जाये। मतलब, वह डायरेक्ट दिखना चाहिए। आज हमारे शासन के लोग बात करते हैं कि हम गति की ओर जा रहे हैं और बहुत बड़ी-बड़ी बात करते हैं। वह कम्प्यूटर के जमाने की बात करते हैं। मेरा यह कहना है कि आज भी मुल्लेगुड़ा में कहीं पर मोबाइल टॉवर नहीं है। पिछली बार जब ऑनलाइन परीक्षा होनी थी तो बच्चे मोबाइल टॉवर की वजह से परीक्षा नहीं दिला पाये। मैं आपसे विशेष तौर पर निवेदन करती हूं कि मोबाइल टॉवर के ऊपर ध्यान दिया जाये।

श्री गजेन्द्र यादव :- एक मिनट, दीदी। माननीय सभापति महोदया, आपने मोबाइल की बात कही है। आप पिछले कोरोनाकाल की बात कर रही हैं। पिछले समय जब हमारे डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी और हमने जब नि:शुल्क मोबाइल वितरण किया था तो उस समय मोबाइल घोटाला के नाम से उसका

सबसे ज्यादा विरोध इन्हीं लोगों ने किया था। मुझे गर्व होता है कि पूरे कोरोनाकाल में जो शिक्षा व्यवस्था बची और गांव व शहर के गरीब बच्चों ने जो भी पढ़ाई की तो डॉ. रमन सिंह जी ने जिस मोबाइल का वितरण किया था, उसी मोबाइल के बदौलत ही वह बच्चे अपनी शिक्षा का अध्ययन कर पाये। आप उसकी बात कर रही हैं तो मैं इस विषय को आपके संज्ञान में ला रहा हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदया जी, मैं खनिज विभाग की बात करूंगी। रेत का अवैध खनन व परिवहन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रेत का खनन व परिवन होता है तो यदि उसको अधिकारी पकड़ लेते हैं तो शमन शुल्क लेकर उसको छोड़ दिया जाता है और उसको छोड़ते हैं तो सीधे ट्रक सहित छोड़ते हैं।

सभापति महोदया :- संगीता जी, आपको 15 हो गये हैं। थोड़ा जल्दी कीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी, सभापति महोदया। शमन शुल्क छोटी सी राशि होती है। यदि एक चोर चोरी करता है और सोना-चांदी के साथ पकड़ाता है तो सोना-चांदी को रख लेते हैं और उसको जेल में डालते हैं। यहां तो यदि चोर पकड़ता भी है तो चोर को चोरी के माल के साथ छोड़ दिया जाता है। यह स्थिति है। अभी हमने देखा कि यहां मोहला-मानपुर के आदरणीय विधायक जी बैठे हैं। उनके यहां से अभी तुरंत सुबह ही खबर आई कि जंगल में पेड़ को काटा जा रहा है और जो बैलगाड़ी से ले जाते हैं, उनसे पैनाल्टी वसूला जाता है और जो ट्रक से ले जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। यह वहां के अधिकारियों की मिलीभगत है। इस पर तुरंत के तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप इस विषय को संज्ञान में लीजिए। यह तुरंत की खबर है। यह त्वरित खबर है। इसको संज्ञान में लेते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।

माननीय सभापति महोदया जी, मैं शिक्षा विभाग के बारे में बात करना चाहूंगी। शिक्षा विभाग में जो कार्य पूर्ववर्ती सरकार ने किये हैं। उसकी यह बहुत बुरी तरीके से बुराई करते हैं। पूर्ववर्ती सरकार व माननीय भूपेश बघेल जी ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला ताकि उसमें गरीब के बच्चे भी पढ़ें। यदि गरीब के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है?

श्री सुशांत शुक्ला :- कहां हो रहा है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपको तकलीफ होती है। माननीय सभापति महोदय, यदि वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिये जाते हैं तो उनको 2 लाख रूपये लगते हैं। जो महिलाएं खेत जाती हैं, उनके बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं। मैं इस बात को आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि जब हम एक राउण्ड में गये थे तो वहां एक गरीब बच्चा बैठा था। मैं उस बच्चे से पूछी कि बेटा, मम्मी कहां है? तो उस बच्चे ने कहा कि मम्मी रोजी में खेत गयी है। माननीय सभापति महोदया

जी, यदि रोजी करने वाले का बेटा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय सभापति महोदया, इन लोगों ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से छोटे-छोटे मासूम बच्चों में बहुत भेदभाव कर दिया है। वहीं पर स्कूल बनाया, उसी आधे स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप अलग बिल्डिंग बनाते, आप उसके लिए अलग व्यवस्था क्यों नहीं दिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। आप क्षेत्र में जाकर पता कीजिये, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में पता कर लीजिये कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। आदरणीय सभापति महोदय, उनको मर्ज किया जा रहा था।

श्री मोती लाल साहू :- आप वहीं उसी स्कूल में आधे बच्चों को हिन्दी मीडियम से और आधे बच्चों को इग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं। आपने भेदभाव पैदा कर दिया है। आप बच्चों के मन में घृणा पैदा कर दिया है। हम स्कूल जाते हैं, हमको पता है।

सभापति महोदय :- मोती लाल जी, बैठिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- जिस योजना का न कोई सेटअप, न वित्तीय प्रावधान हो।

श्री रामकुमार यादव :- गरीब के बेटा इंग्लिश पढ़त हे, अउ पढ़ा लेवा न।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आप बैठ जाईये।

श्री मोती लाल साहू :- योग्यता का मापदण्ड भाषा नहीं है।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, मोती लाल जी, राम कुमार जी, आप लोग बैठ जाईये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, जब डी.एम.एफ. फण्ड के पैसे से मेडिकल कालेज बनवा सकते हो उसी डी.एम.एफ. के पैसे से आत्मानंद स्कूल का उन्नयन हुआ था, आपको क्यों तकलीफ हो रही है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय,

सभापति महोदय :- गजेन्द्र जी, आप बैठ जाईये। माननीय सदस्य को अपनी बात बोलने दीजिये।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, आपने आत्मानंद स्कूल खोला है, उसका स्वागत है। लेकिन आपने उसमें क्या किया ? भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति लाई, उसमें अनिवार्य था डी.एड, बी.एड. किए हुए लोगों को शिक्षक बनाना था। आपने किसी को भी उठाकर, अपने परिवार के लोगों शिक्षक बना दिया।

सभापति महोदय :- गजेन्द्र जी, आप बैठ जाईये।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, दूसरा, जब आपने स्कूल बनाया तो स्कूल का संचालन राज्य शासन करता है। आपने उसको कलेक्टर के भरोसे छोड़ दिया है। किसी प्रकार का स्टेटस नहीं है, उन शिक्षकों को पेमेन्ट नहीं मिल रहा है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कलेक्टर कौन होता है ? प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ही संचालित होता है क्या ?

सभापति महोदय :- आप लोग आपस में डिस्कशन मत करिये, बैठ जाईये। निषाद जी, आप बैठिये।

श्री कुवर सिंह निषाद :- पहले तकनीकी जानकारी रखिये, उसके बाद बात करें।

श्री गजेन्द्र यादव :- मुझे पूरी तकनीकी जानकारी है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कोई तकनीकी जानकारी नहीं है। न अंक बढ़ने वाला है न मंत्री बनने वाले हो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बनही, बनही, चिंता मत कर। मंत्री बनबे। आदरणीय सभापति महोदय जी, ठीक है, मैं सब मानने को तैयार हूं।

श्री रामकुमार यादव :- सब कहथे तो ईश्वर भइया मंत्री बनही।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं मानती हूं कि चलो पूववर्ती सरकार में आत्मानंद स्कूल में भ्रष्टाचार हुआ है, मोती भइया, मैं आपकी यह बात भी मानती हूं कि (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) मेरी पूरी बात सुनो तो।

सभापति महोदय :- आप उस तरफ मत देखिये, आप आसंदी की ओर देखकर बोलिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ है, आधे लोग हिन्दी मीडियम में पढ़ रहे हैं आधे लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। अब तो आपकी सरकार है, आप कीजिये न। आप आत्मानंद स्कूल के पूरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाईये न। मैं बोल रही हूं, मैं चैलेंज कर रही हूं पूरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम से शिक्षा दीजिये। हमको गर्व होगा कि यह सरकार इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रही है।

श्री मोती लाल साहू :- माननीय सभापति महोदय, आखिर आप इंग्लिश मीडियम के पीछे क्यों भाग रही हैं ? भाषा किसी योग्यता का मापदण्ड नहीं होता। भाषा किसी योग्यता का मापदण्ड नहीं होता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जब आप कम्प्यूटर युग की बात करते हो तो इंग्लिश मीडियम की बात करनी चाहिए। कम्प्यूटर हिन्दी मीडियम से नहीं चलता, इंग्लिश मीडियम से चलता है। (व्यवधान)

श्री मोती लाल साहू :- हिन्दी हमारी मातृ भाषा है। जगह-जगह लिखते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आनलाईन की बात करते हैं, तो इंग्लिश मीडियम की क्यों नहीं बात करते ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपने 5वीं, 8वीं खत्म किया है, यह आपकी शिक्षा नीति है।

सभापति महोदय :- देखिये, आप लोग इस तरीके से खड़े होंगे, यह उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों पर चर्चा हो रही है। संगीता जी 15-17 मिनट से ज्यादा समय हो रहा है, कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, आप सबको इंग्लिश मीडियम में जरूर पढ़ाये, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूं।

सभापति महोदय :- मोती लाल जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिये। आप बैठ जाईये, यह ठीक नहीं है।

श्री मोती लाल साहू :- सबको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने की बात कर रही हैं। वह सदन को भ्रम में डाल रही हैं।

सभापति महोदय :- मोती लाल जी, आप बैठ जाईये।

श्री मोती लाल साहू :- हम लोगों की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। आप बोलते हैं कि सबको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाईये, यह कहां तक उचित है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मानीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लाख नौकरी की बात की थी। यहां पर जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने यहां सदन में कहा था कि 33 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी।

श्री मोती लाल साहू :- आप यहां क्या कहना चाहती हैं ? हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- 19 भाषाओं में शिक्षा दी जा रही है, बता दे कि कौन कौन सी 19 भाषाएं हैं, जिसमें पढ़ाई हो रही है ? कौन से 19 भाषाओं में शिक्षा दी जा रही है ?

सभापति महोदय :- यह प्रक्रिया ठीक नहीं है कि आप लोग बीच में खड़े होकर वाद विवाद करें। बैठ जाईये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, अभी तो महोदय जी सांसद बन गये हैं। उन्होंने कहा था कि 33 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी। लेकिन आज तक एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। यहां तक डी.एड., बी.एड. वाले बच्चे दो साल शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे, उनको निकाल दिया गया और वे बच्चे परेशान हैं।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी, यह कोर्ट के निर्णय पर बात हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। यह कोर्ट के डिसीजन की बात है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था का मामला नहीं है। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, चार इंजन की सरकार है। आप चाहे तो कर सकते हैं।

श्री राम कुमार यादव :- आप कोर्ट के बहाना माकर पल्ला नहीं झाड़ सकव महाराज।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, ठीक है। यह लोग बोलते हैं कि कोर्ट का मामला है। आज सचिव लोग हड़ताल पर बैठे हैं। आपके घोषणा-पत्र में मोदी जी की गारंटी है, उसक बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी सरकार ने सचिव लोगों का शासकीयकरण क्यों नहीं किया?

श्री सुशांत शुक्ला :- पांच साल तक गंगाजल की सौगंध खाकर जनता को ठगने वाले लोग चिल्ला रहे हैं। आप लोग छत्तीसगढ़ के महिलाओं को पांच साल तक 500 रूपये नहीं दे पाये और आप लोग न्याय की बात करते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने लोगों ने शासकीयकरण की बात की है। आज जब हम शासकीयकरण की बात कर रहे हैं तो आप लोग शासकीयकरण क्यों नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, बार-बार खड़े होना ठीक नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह मोदी जी की गारंटी है। आपकी चार इंजन की सरकार है। सभापति महोदय, उन्होंने मुझसे पूछा इसलिए मैंने उनको बोला।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आपको बोलते 20 मिनट से ऊपर हो रहे हैं। आप जल्दी अपनी बात खत्म करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपकी चार इंजन की सरकार है। आप शासकीयकरण कर दीजिये, सचिवों का उद्धार हो जाएगा। आदरणीय सभापति महोदय जी, अभी आप कल का समाचार पत्र में देख लीजिये। वे शिक्षा की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आपको 20 मिनट से ऊपर हो रहे हैं। आप जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी। सभापति महोदय जी, पांचवीं और आठवीं कक्षा के बच्चों की परीक्षा थी, वहां खुलेआम शिक्षक लोग नकल करवाये हैं। शिक्षा विभाग कहां है? बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। मैं कहना चाहती हूं कि बड़ी-बड़ी बातें करने से पहले आप लोग धरातल में उतरें, जमीन में उतरें, गरीबों के बीच उतरें और उनके पास जाकर चर्चा करें।

सभापति महोदय :- आपको आधे घंटे होने जा रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, जल्दी समाप्त कर रही हूं। मैं स्कूल के विषय में बात करूं तो जो बच्चियां रायपुर के स्कूल में पढ़ने जाती हैं, वह पांच रूपये पैसा देकर सुलभ शौचालय जाती हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं आप स्कूल का स्तर सुधारें। घोषणा के बाद मेरे ही

विधान सभा क्षेत्र में दो-तीन स्कूल गये थे, उन स्कूलों की निविदा हो गई थी, उसको आप वापस ले लिये।

सभापति महोदय :- समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, वहां सिर्फ कांग्रेस पार्टी की विधायक है इसलिए सरकार ने वहां के बच्चों के साथ अन्याय किया है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आपको जो स्कूल पास हो चुका है, उसमें आप पैसा दीजिये। आपने उस स्कूल को क्यों लाया है? ठीक है, वहां कांग्रेस पार्टी की विधायक है, लेकिन बच्चों ने आपके साथ अन्याय नहीं किया है।

सभापति महोदय :- आपने अपनी बात कह दी। अब समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। मेरी बात के समय थोड़ी सी बहस जरूर हुई। मैं इन अनुदान मांगों की घोर निंदा करते हुए, विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री राजेश मूणत।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- सम्माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी के विभागों की अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं।

सभापति महोदय, बहन संगीता जी ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन वह बोलते-बोलते यह भूल गईं कि आप इस सदन के पूर्व सदस्य हैं। उंगली उठाने के पहले तीन उंगली अपनी तरफ भी आती है। सबको कुछ करने का अवसर मिला, उसे करने के लिए इच्छाशक्ति चाहिए, क्रियान्वयन करने के लिए शक्ति चाहिए। आपने अपनी बात आत्मानंद स्कूल से प्रारंभ किया तो मैं भी शिक्षा विभाग से ही अपनी बात प्रारंभ करता हूं। यदि आप पांच साल के कार्यकाल का विवरण उठाकर देखें कि पांच साल में आपकी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है? पांच साल में जितने ट्रांसफर व पोस्टिंग हुई हैं, मेरे ख्याल से 15 सालों में शिक्षा विभाग में उतने ट्रांसफर नहीं हुए होंगे, यह समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा शेम-शेम की आवाज) यह मैं नहीं कह रहा हूं ..।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, 15 सालों में 1200 स्कूल बंद हुए थे।

श्री राजेश मूणत :- आप सुन तो लीजिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप यह भी भूल गये क्या कि 15 सालों में 1200 स्कूल बंद हुये थे, उन स्कूलों कि अगर किसी ने खोलने का काम किया है तो वह हमारी सरकार ने किया है।

श्री रामकुमार यादव :- ओमा साहब के ही दस्तखत रिहीस हावय।

श्री राजेश मूणत :- यादव महाराज।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, मूणत जी, एक मिनट।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन हेतु 4 बजे का समय निर्धारित है। चूंकि अभी अनुदान की मांगों पर चर्चा जारी है। अत: मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, हम शिक्षा क्रांति की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल का स्तर सुधरना चाहिए, हम चाहते हैं कि शिक्षा में क्रांति आनी चाहिए और सरकारी स्कूल के बच्चों का स्तर सुधरना चाहिए। चाहे वह पढ़ाई का स्तर हो, चाहे स्कूल की बिल्डिंग की व्यवस्था हो या हमारे शहरों के स्कूल हो या गांवों के स्कूल हो, उन सभी के ऊपर हमें काम करना चाहिए। अभी आपने आत्मानंद स्कूल की बातचीत की। मैं आपसे ही एक प्रश्न और सुझाव के साथ में, दोनों सकारात्मक बात करूंगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में पाठ्य पुस्तक निगम का गठन हुआ। पहली बार पूरे प्रदेश के अंदर संपूर्ण समाज, जाति, वर्ग को ऊपर उठकर चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राईवेट स्कूल हो, हर बच्चे को किताबें मुफ्त में दिये तो वह डॉ.रमन सिंह की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है । उस समय कान्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे को भी, जब वह मल्टी कलर का किताब देखता था, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा किताब देखता था तब तोते का कलर काला होता था । प्रायवेट स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूलों में, पढ़ने वाले बच्चे का कलर ए फॉर एप्पल मल्टी कलर होता था, हमने एक स्तर लेकर आये और सरकार ने पहली बार मल्टी कलर की किताबों को छापकर वितरण का काम प्रारंभ किया । चाहे वह सरकारी स्कूल हो या प्रायवेट स्कूल हो, अगर आपने आत्मानंद स्कूल खोला तो आपकी सोच होना चाहिये, आपकी कल्पना होना चाहिये, आत्मानंद स्कूल का सेट-अप कैसे स्वीकृत करें, किसके भरोसे आत्मानंद स्कूल चलेगा ? सभापति महोदय, मैं रायपुर के कई आत्मानंद स्कूलों का उदाहरण दे दूँगा, आप जिसको बहुत अच्छा आत्मानंद सकूल मानकर चलते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि चलिये मैं आपको आत्मानंद स्कूल दिखाता हूँ । आपने बिल्डिंग के सामने पुताई कर दी, लेकिन अंदर की व्यवस्था कौन दुरूस्त करेगा ? सभापति महोदय, स्कूल में बैठने के लिये फर्नीचर नहीं है, अगर हम राजधानी के अंदर बैठकर बातचीत करते हैं, राजधानी के अंदर जो बिल्डिंग का काम किया है, आत्मानंद स्कूल की छत गिर जाती है, कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं है । आपने इसे कलेक्टर के माध्यम से छोड़ दिया है, स्मार्ट सिटी के पैसे से काम करा लीजिए । न कोई सेट-अप, न कोई व्यवस्था । हम बच्चों के भविष्य बनाने की बातचीत कर रहे हैं, उर्दू

टीचर की भर्ती हमने की है,इसे हमारे कार्यकाल में की है, शिक्षक की भर्ती हमने की है । गर्व होता है कि 5 साल में हमने कितनी भर्ती की है, जरा इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा । सभापति महोदय, शिक्षा क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन क्रांति कहां अपने घर में नहीं, बल्कि पड़ोस के घर में आना चाहिये । आप, हम सभी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिये चिंता का विषय यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिये निचले स्तर तक हमें सख्त चिंतन करना पड़ेगा । सभापति महोदय, मैंने अपने विधान सभा में विधायक निधि का 4 करोड़ रूपये एक अच्छी सोच के साथ स्कूल को दे दिया । सभापति महोदय, सरकार के साधन सीमित है, हमें भी तो सरकार ने विधायक निधि दी है, क्यों न हम उन स्कूलों के ऊपर खर्च करे, उन स्कूलों का स्तर सुधारें, लेकिन हम वह काम करते हैं जो नहीं होना चाहिये । सभापति महोदय, जिन स्कूलों में लाईट नहीं है, वहां कम्पयूटर सप्लाई करते हैं, जहां लैब नहीं है वहां लैब का सामान खरीदते हैं ? हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुनकर आये हैं, हमें जनता ने जिस चीज के साथ विश्वास करके भेजा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जैसा कि अभी संगीता सिन्हा जी ने कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी की विधायक हूँ, आप कांग्रेस पार्टी की विधायक नहीं है, आप जनप्रतिनिधि हैं और हमारे प्रदेश की सम्मानीय विधायिका हैं। राजनीति नहीं करते, लेकिन अगर वहां किये तो विष्णु देव साय सरकार में इस बात को मानकर चले कि आपकी मांग की पूर्ति कोई कर सकता है तो विष्णु देव साय की सरकार कर सकता है । (मेजों की थपथपाहट) मैं क्लियर कह रहा हूँ, मैंने तो यह बहुत नजदीक से देखा है, मैं कई विषयों पर कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब व्यवस्था को दुरूस्त करना हो, व्यवस्था के अंदर बातचीत करते हैं, यह जिम्मेदारी आपकी और हम सब की है । हम लोग टाईम टेबल का मैनेजमेंट करने के लिये अपने स्कूलों के अंदर, गुजरात के अंदर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि सेट-अप बना हुआ है, उसकी व्यवस्था बनी हुई है । सभापति महोदय, अप्रैल से लेकर मई तक, जनपद से लेकर जिला पंचायत तक, हमारा कोई बच्चा स्कूल से ड्राप नहीं होना चाहिये, 100 परशेंट बच्चा स्कूल जाये, उसके लिये जनप्रतिनिधि खुद मैदान में जाते हैं और बच्चों से आग्रह करते हैं कि स्कूल जाईये । सभापति महोदय, व्यवस्था क्यों नही हो सकती, साल में कैलेण्डर क्यों नहीं बन सकता है, हम बच्चों को ड्रेस देते हैं और हम इसी काम में लगे रहते हैं कि कौन ड्रेस सप्लाई करे ? यदि ड्रेस की चिंता करना है तो ग्रामोद्योग विभाग कपड़े का निर्माण करता है, जब ग्रामोद्योग विभाग द्वारा इतनी बड़ी क्वांटिटी में ड्रेस सप्लाई करनी है तो हमारे पास पहले से धागा लूम वालों को देकर रखना पड़ेगा और इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी । जब आप उनको डिपाजिट देंगे, तब कहीं जाकर वह कपड़ा तैयार करेंगे और कपड़ा तैयार करने में समूह की बहिनें उसको सिलाई करके रखेगी, ताकि अप्रैल के बाद में जब शिक्षण सत्र प्रारंभ हो तो उन बच्चों को ड्रेस मिल सके । अगर हम पहले से व्यवस्था करके नहीं चलेंगे तो यह व्यवस्था खड़ी नहीं हो सकती ।

सभापति महोदया, पाठ्य पुस्तक निगम समाचार-पत्रों की सुर्खिया बना । यह सामान्य व्यवस्था

है कि जब स्कूल की दर्ज संख्या आती है, स्कूल में कितने बच्चों ने प्रवेश लिया ? वह जानकारी संकुल में आती है, संकुल से ब्लाक में आती है, ब्लाक से जिला मुख्यालय में आती है, उसके आधार पर 10 प्रतिशत किताबें छपती हैं । पूर्व सरकार के कार्यकाल की किताबें ट्रकों के ट्रकों में छपती थी, कोविड कॉल में कितने प्रतिशत किताबें नहीं बटी, कोविड काल में स्कूल नहीं लगा और आपने करोड़ों किताबें छाप दीं । वह किताबें कहां गईं, किसने छपवाई थी ? आज आप आकर बोलने लग गए कि किताबें पकड़ाईं । पाठ्य पुस्तक निगम ने किताब छापने का आर्डर दिया, जो वहां बैठकर काम करते थे, उनसे पूछिए कि आपने किसकी डिमांड पर किताबें छापीं? कुल कितने विद्यार्थियों ने दाखिला लिया, कौन-कौन सी क्लास में कितने विद्यार्थी थे और कितनी किताबें छापनी चाहिए । यह कोई चिन्ता का विषय नहीं है ? आखिर में हर व्यक्ति अपना पल्ला झाड़कर चुप हो गया । अगर वयवस्था में परिवर्तन चाहिए तो एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा । यही सबसे बड़ी चीज है, जब पहली बार बच्चों को मुफ्त में किताबें मिल रही थीं तो हम छपाई करने वालों के साथ ही भिड़ गए। शिक्षा विभाग के संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पाठ्य पुस्तक निगम कोई छोटा-मोटा स्कैण्डल नहीं है । पाठ्य पुस्तक निगम में पेपर खरीदी से लेकर जितनी किताबों की डिमांड है और उस डिमांड में आपने उससे ज्यादा किताबें छापी हैं और कोविड काल में अगर स्कूल बंद था तो किताबें छपवाने की जरूरत क्यों पड़ गई ? जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट आ चुकी है, उस रिपोर्ट पर कार्रवाई हो और भविष्य में एक अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करूंगा, शिक्षा विभाग के प्रति भी आभार व्यक्त करूंगा कि आने वाले समय में जो किताबें छपेगी, उसमें कोड नम्बर डलेगा। किताबों का सिलेबश चेंज नहीं होता है । बच्चों के पढ़ने वाली किताबें फिक्स हैं । उस किताब में 2024 का कवर है तो अगले साल उसमें 2025 का कवर लग जाएगा। हम उस जमाने के स्कूलों में पढ़े हैं, जब किताबें खरीदकर नहीं लाते थे तो भाई की किताबें लेकर पढ़ लेते थे । खाली कवर चेंज करने के लिए पूरी किताब को रद्दी कर देना कहां की नाइंसाफी है । ये चिंता का विषय है । इसीलिए जिन लोगों ने यह कर्म किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए ।

सभापति महोदया, मैं आत्मानंद स्कूल के संबंध में आग्रह करूंगा । राजधानी में जरूर इतने आत्मानंद स्कूल खोल दिए गए हैं । हिन्दी मीडियम में सरकारी स्कूल में गरीब परिवार के बच्चे ही पढ़ते थे, उनकी जगह आपने उसको आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिया । अब जो गरीब बच्चा है, उसके लिए स्कूल ही नहीं बचा। अब वह कहां जाए ? आत्मानंद स्कूल के नाम पर आपने बिल्डिंग में कब्जा कर लिया। अब किसी स्कूल में बच्चों की संख्या 2000 है, किसी स्कूल में 1500 बच्चे हैं और उसमें आपने मेरिट का क्राईटेरिया कर दिया तो बच्चा कहां से आएगा । इसलिए उसका सेट-अप, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित हो, मैं यह आग्रह करना चाहूंगा । उन बच्चों को समय पर ड्रेस मिल जाये और इसके लिए पहले से प्लानिंग हो जाये। मैं यह इसलिए आग्रह करना चाहता हूं कि जब कोई अच्छी सोच के

साथ में काम करता है तो धन्यवाद भी देना चाहिए संगीता जी । खाली विरोध करने के लिए कहना है तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कहना है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- देखिए मूणत भाई साहब, अगर बच्चे नकल करके पास हो रहे हैं, उसमें आप बोलें कि सरकार को धन्यवाद दो, तो मैं तो नहीं दे सकती। क्योंकि शिक्षा विभाग तो चरमरा रहा है ना। शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है और उनकी कमी है। हमारे कैमेस्ट्री के बच्चे प्रेक्टिकल के लिए तरश जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक प्रेक्टिकल रूम नहीं है। आप संसाधन तो उपलब्ध कराइए।

श्री राजेश मूणत :- सरकार से डिमांड करना आपका अधिकार है। पहले धैर्य से बात सुन लीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- प्रतिवेदन में आंकड़े आते हैं और आपके धरातल पर कुछ नहीं है। बॉयो के बच्चे हैं, वे प्रेक्टिकल नहीं करते, लेकिन पास हो जाते हैं। एक प्रेक्टिकल नहीं होता और वे पास हो जाते हैं, ये शिक्षा विभाग का हाल है।

श्री राजेश मूणत :- संगीता जी बहुत सीनियर विधायक हैं, यहॉ जितने बैठे हैं सब जानते हैं और वे अच्छा बोलती भी हैं। पांच साल आप लोग भी सरकार में रहे, मैंने कहा ना कि उंगली उठाने पर तीन अपनी ओर आएगी कि हमने क्या किया। आपको अवसर जनता ने दिया था, नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, हो सकता है, उस समय अपनी नहीं चलती होगी। कोई बात नहीं। मैंने पहले ही कह दिया कि आपकी डिमांड्स को माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं सुन रहे हैं और उसे वे गंभीरता के साथ ले रहे हैं। आप बोल रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें जो परिवर्तन चाहिए, उसे हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। व्यवस्था में कुछ कमी है, उसे ठीक करना आपका और मेरा कर्तव्य है।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस विधान सभा सत्र में हमें नेता प्रतिपक्ष टाईप तो आप ही लग रही हैं। दो-चार कुर्सी छोड़कर थोड़ा आगे बैठ जाइए ना।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, अब कहानी तो इतनी लंबी है कि कितनी कहानी कहां तक चले। वर्ष 2018 में जब आपकी सरकार रही तो खनिज रायल्टी कितनी मिलती थी और इन पांच सालों में खनिज रायल्टी कितनी आती है, एक बार उसका भी अध्ययन कर लेना। हम एक तरफ टेक्नालॉजी की बात करते हैं, हम एक तरफ नेट की बात करते हैं, पूर्व सरकार ने खनिज के नाम पर जो खेल खेला है वह कोई आम जनता से छिपा हुआ है या आपसे छिपा हुआ है? रायल्टी की परमीशन, ट्रांसपोर्टिंग की परमीशन अगर चाहिए, तो आप कलेक्टर के पास जाओ, कलेक्टर कहेगा कि फलाने से मिलकर आओ। फलाना लिखकर के देगा, उसके बाद जो ऑनलाईन परमीशन थी, उसे आप लोगों ने ऑफलाईन कर दिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- कलेक्टर के यहां नहीं जाना पड़ता था।

श्री राजेश मूणत :- कहां जाना पड़ता था?

श्री धर्मजीत सिंह :- कलेक्टर ऑफिस के सामने में पान ठेला में 40 रुपए वाला, कम वाला मिलता था। कहां कलेक्टर आदि के पास? इनकी सरकार इतना कष्ट नहीं देती थी। पान ठेला से 40 रुपए का कूपन लो और ले जाओ। इसी में तो सब गए हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे विधान सभा में किसी-किसी पान ठेला में कोड वर्ड चलता है कि 30 रुपए का पान, 25 रुपए का पान, 50 रुपए का पान। आप जाओगे तो आपको गांजा की पुड़िया मिलेगी। मैं अभी आपको लेकर चलता हूं, अगर आप लेना चाहें।

सभापति महोदया :- निषाद जी, आपकी बारी आएगी, उस समय बोलिएगा।

श्री राजेश मूणत :- भाई, अभी अवसर आएगा, हम लोग गांजे पर भी बात करेंगे, क्या तकलीफ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- पान तो आप कभी खाते हो नहीं, सुनी-सुनाई बात पर बात कर रहे हो। पान ठेले में आप जाओगे क्यों?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं खाता नहीं हूं, अलग बात है, लेकिन जानता हूं कि कहां-कहां पर मिलता है, कहां-कहां पर सप्लाई होता है। इतना तो जानता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- निषाद साहब, पान ठेले में जाना नहीं चाहिए। पान ठेले में जाओगे तो वह थोड़ा आपके दर्जे के खिलाफ हो जाएगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं जाता भी नहीं हूं और खाता भी नहीं हूं लेकिन इतनी जानकारी जरूर रखता हूं कि वहां पर क्या-क्या मिलता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हॉ, मैं वही तो बोला कि बिना जाए आप कह रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- क्या अपनी आदत पड़ गई तांक-झांक करने की?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- तांक-झांक नहीं करता, तांकने-झांकने का काम उधर से होता है। मैं झांकने वाला नहीं, मैं सीधा-सीधा स्टेट फारवर्ड बात करता हूं।

श्री राजेश मूणत :- चल भाई, मैं तेरे साथ हूं, चिन्ता मत कर। आपकी बॉर्डर उड़ीसा से लगी हुई है, उसे ठीक कर लो, बस।

सम्माननीय सभापति महोदय, पारदर्शिता के साथ यहां की सरकार ने एक सबसे बड़ा फैसला किया और ऑनलाईन को जिन लोगों ने ऑफलाईन किया था, ये इस प्रदेश का सबसे बड़ा स्कैंडल निकलकर आया है और जिसमें कई लोग प्रेम-मोहब्बत से कृष्ण भगवान का जहां जन्म हुआ, वहां चले गए। सरकार के संज्ञान में आया और पारदर्शिता के साथ एक लाइन के अंदर, एक चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने घोषणा कर दी कि ऑफलाइन को ऑनलाइन किया जाता है। यह सरकार की पारदर्शिता है, यह सोच है और यह कल्पना है। (मेजों की थपथपाहट) आपको ऑफलाइन करने की क्या जरूरत पड़ गयी थी ? मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता

कि हाउस में किसी का नाम आये। मुझे जैसे ही वर्ष 2020 को मालूम हुआ, मैंने कलेक्टर, कोरबा को फोन लगाया। यदि उनके नाम का उल्लेख करने को कहेंगे तो वह भी कर दूंगा, वह अभी अंदर है। मैंने उनसे कहा कि क्या ऐसा हो गया है ? उन्होंने कहा कि नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहां से पर्ची आयेगी तो मैं कर दूंगी। मुझे इस मामले में क्या करना है। विमान में बैठाकर सब विधायकों को दिल्ली किसने ले गया था ? और अपने करंट अकाउण्ट से चेक से प्लेन का किराया दिया था, वह कौन है ? यह रिश्ता क्या कहलाता है ? आप जाकर पूछियेगा। वह अंदर है। 12 लाख रूपये का चेक दिया गया था कि समर्थन में दिल्ली चलो। मैं और क्या बोलूं ? जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो एक ही श्लोक गाता हूं

"कर्म किये जा फल की इच्छा मत कर ऐ नादान

जैसा कर्म करेगा, वैसा फल देगा भगवान"।

और जैसे कर्म किये हैं, वैसा फल मिलेगा। संगीता जी, आपको जानकारी चाहिए होगी तो मैं डिटेल दे दूंगा। आगे मत कहियेगा कि यही है गीता का ज्ञान।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हमको इसकी जानकारी तो नहीं है। प्लीज, इस विषय में चर्चा न करें तो अच्छी बात होगी। आप प्रतिवेदन की चर्चा कीजिये।

श्री राजेश मूणत :- वह प्रतिवेदन का ही हिस्सा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हमको भी पता है कि मेय फेयर में क्या हुआ था। लेकिन हम उस बात को नहीं ला रहे हैं। मैं मेय फेयर की बात करूं तो आपके सरकार की भी पोल पट्टी खुलेगी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- (व्यवधान) अभी तक ढूंढ रहे हैं कि वह तीनों कौन हैं ? वह तीनों कौन है जो मेय फेयर की राशि अपने पास रखे हैं और अभी तक जमा नहीं किये हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मूणत जी आपसे यह पूछ रहे हैं कि।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं भी पूछ रही हूं कि मेय फेयर में क्या हुआ था ?

श्री राजेश मूणत :- वही हुआ जो रोज होता है। हम दोनों खाना खाने गये थे। आपने बिल का पेमेंट किया और उमेश जी मेरे साथ थे। आप और बोलिये ?

श्री धर्मजीत सिंह :- हम बता रहे हैं कि मेय फेयर एक फाईव स्टार होटल है। वह जनता के लिये बना है। हम गये थे, अभी भी जायेंगे और आगे भी जाते रहेंगे। आपको क्या कहना है ? आप यह बताईये कि आप टी.एस. बाबा साहब के खिलाफ दिल्ली गये थे या नहीं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम नहीं गये थे। हमने तो अपना जवाब दिया और हम आपसे भी जवाब चाहते हैं।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैंने तो कहा कि 12 लाख रूपये का चेक दिया गया। मैं आंकड़ा दे रहा हूं। इंडिगो को पेमेंट हुआ और स्पेशल प्लेन गया। आपको और डिटेल चाहिए तो वह भी दे दूंगा।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- प्लेन में बैठने वालों को भी कुछ मिला या नहीं ?

श्री राजेश मूणत :- वह तो नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी के हिसाब से मिला होगा। मैं उस विषय में ज्यादा नहीं जाता। लेकिन मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि जो भी बात संज्ञान में आयी, माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार ने उनके ऊपर बहुत पारदर्शिता के साथ कार्य किया। डी.एम.एफ. फण्ड का उपयोग कैसे होता था, यह बात किसी से छिपी हुई तो नहीं है। एक पारदर्शिता के साथ 25 कि.मी. के परिक्षेत्र के अंदर खनिज संसाधन के पैसे की जो रॉयल्टी आ रही है, उसका सदुपयोग हो, उसकी पॉलिसी बनाकर फैसला करना, यह अपने आप में इस प्रदेश की विष्णु देव साय जी की सरकार ही कर सकती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सरकार की पारदर्शिता और सोच है। उस सोच को गति देने के लिये खनिज के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। आप रेत की बात करते हैं। अब मैं रेत के बारे में किससे कहूं और क्या कहूं ? इसी सदन में कई बार आरोप, प्रत्यारोप लगे। पेपरों की सुर्खियां बनी। उत्तर प्रदेश के कौन प्रभारी जी रेत की खदान चलाते थे ? यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह पेपर की सुर्खियां बनी और हाऊस में प्रश्न उठा था। यह हाऊस के रिकॉर्ड में है। कम से कम वह रेत माफिया अब तो नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जहां से भी रेत निकलती है, जैसे पहले पंचायत के माध्यम से रेत का संचालन होता था, वहां उसकी रॉयल्टी मिलती थी, उसके ग्रांट से पंचायत के अंदर विकास होता था। रेत के ऊपर एक पॉलिसी बननी चाहिए ताकि रेत निकले और सरकार के राजस्व का सदुपयोग हो। मैं इस विषय में एक और आग्रह करूंगा । जहां-जहां रेत और गिट्टी की खदानें चल रही हैं वहां पर ओव्हर लोडिंग की भरपूर शिकायतें हैं। वहां ग्रामीण मार्ग बने हुए हैं वह मार्ग की क्षमता 40 टन की गाड़ी लेकर चलने की नहीं है, लेकिन वहां से जो ओव्हर लोडिंग गाड़ियां निकल रही हैं और उसके कारण सड़कें खराब हो रही हैं, वहां से शिकायतें आ रही हैं यह भी हमारी प्राथमिकता में आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर खनिज विभाग पर भी बहुत सी बातें कही हैं। माननीय धरम जी, अजय चन्द्राकर जी ने इस विषय में कहा है। मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैंने खुद सबसे आग्रह किया है कि हम थोड़ा-थोड़ा बोलकर, जल्दी कर लें। मैं भी किसी को उसका ज्यादा पार्ट नहीं बनाऊंगा। आपने आबकारी विभाग में जो बात की है। यह जनजागरण का विषय है। प्रदेश की जनता जागृत हो और शराब का कम सेवन करे। मुझे यह याद है कि पूर्व की सरकार के पहले हमारी सरकार थी। हमने 2500 की आबादी में धीरे-धीरे शराब दुकानें बंद कर दी थी,

लेकिन उस समय राजस्व की वृद्धि उतनी ही थी। जब आपकी सरकार आयी तब से राजस्व के रिकॉर्ड में जो गिरावट आयी है...।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय राजेश भईया, अभी आपकी सरकार है। इसके पूर्व 5 सालों तक हमारी सरकार थी।

श्री राजेश मूणत :- इसलिये तो मैं गिना रहा हूँ। मैं तो वही कह रहा हूँ। हॉ, यादव महाराज, हम दूध बांटने वाले हैं हमें शराब से क्या लेना-देना है ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। आप बहुत अच्छा बोलत रहेव में बाहिर में सुनत रहेव। आप बार-बार मोदी जी, मोदी जी कहात रहेव। ता मोदी जी के बात करत हौ तो आप 15 लाख के भी याद रखिहौ। दूसरा, ये दारू भट्टी ला मत खोलव। हमर प्रदेश में स्कूल खोलव, गुरू जी के भर्ती करव, सुरक्षित करव । साहब, आप दारू ला पियाकर मतवार बनात हौ, ए अच्छा नइ लागए। आप ला ए शोभा नइ देवत हावए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, हम तो दूध बांटने वाले हैं। हमारा दूर-दूर तक शराब से कोई लेना-देना ही नहीं है, लेकिन पूर्व में जिनका धंधा दारू के नाम पर चल रहा था। उस समय अगर उनको इस बात का ज्ञान दे दिया होता तो प्रदेश में यह स्थिति नहीं आती। राघवेन्द्र भाई, मैं माननीय संगीता जी से इसलिए कह रहा हूँ । संगीता जी ने वंशज की बात कही। वह सिंह समाज के हैं, उनका चलता है, करार समाज है, यह तो उनका अपना काम चला होगा, उससे इनका क्या लेना-देना है, पर वह बहन अपने भाषण में जितना शराब पर बोलीं । मुझे आश्चर्य लग रहा था कि कहीं न कहीं उस समय का कुछ शेयर गलती से इधर भी जाता होगा तो अब वह बंद हो गया। उसके कारण कहीं दर्द तो नहीं झलक रहा है।

सभापति महोदय :- आपको 20 मिनट से अधिक हो गये। अब आप जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने शराब के विषय पर इसलिए कहा क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में सदन में हमेशा रहती थी। अगर उस समय 8 घण्टे का सदन चलता था तो इस सदन में 4 घण्टे या 5 घण्टे केवल शराब की बात होती थी। आज भी वहीं पर अटके हैं। मैंने यह देखा । यहां पर माननीय चन्द्राकर जी और बहुत सारे लोगों ने साथियों ने अपना भाषण दिया। यहां किसी ने आबकारी विभाग में बात नहीं की। सिर्फ यहां मैं ही एक सदस्य हूँ जिसने शराब के विषय में कहा क्योंकि मुझे दर्द होता है। जिस सरकार ने हमेशा शराब बंदी की बात की है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय संगीता जी फिर उसी विषय पर कह रही हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, शराब बंदी पर नहीं, पूर्व में आपने यह बात कही है कि इस प्रदेश में शराब बंदी होनी चाहिए। पिछली बार आप लोगों ने पूरे विधायकों के घर का घेराव किया था।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- दीदी, मोर बात सुन तो ले।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आप लोगों ने सभी विधायकों के घरों का घेराव किया था कि यहां पर शराब बंद होनी चाहिए। आज यह लोग कहां गये? आज इनका यह न्याय कहां है ? आज वह जनता कहां है? आप सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और आप सब वोट के लिए बात करते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, शायद माननीय सदस्या भूल रही हैं कि पिछली सरकार में हमारे जो सदस्य रहे होंगे, वह उधर बैठते थे और पिछली बार की विधायक, माननीय सदस्या इस तरफ बैठती थी। शायद वह भूल रही हैं कि जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लागू किया था, उसमें यह कहा था कि प्रदेश में हम शराब बंदी करेंगे। इनके घोषणा पत्र में यह बात लिखी हुई थी। यहां उसी पर 4 घण्टे चर्चा होती थी। शायद माननीय सदस्या भूल रही हैं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, ठीक है। मैं यह मान रही हूँ, लेकिन आपके यह घोषणा पत्र में यह बात है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, हमारे घोषणा पत्र में यह बात नहीं है। आप हमें यह दिखा देना और लेकर आना। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह दिखा दूंगी। मेरे पास प्रूफ है। इसे मैं पटल पर रखूंगी। मेरे पास मोदी की गारण्टी की प्रति है। आपके, हमारे जो सांसद विजय बघेल जी का बयान है, आपकी मोदी की गारंटी का, मैं सबको पटल पर रख दूंगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- पहली बात तो यह है कि हमारे मोदी जी शराब के बारे में बात ही करते, आप समझ गई न। शराब के बारे में आप कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए जिसमें आप लोगो ने गंगाजल उठाकर कसम खाई थी, press conference में गंगा जल को हाथ में उठाकर कसम खानी पड़ी थी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैंने सचिव के शासकीयकरण की बात की है जो मोदी की गारंटी में है।

श्री रामकुमार यादव :- यह गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, अगर कसम हुई थी, कर्ज माफी को लेकर गंगाजल उठाकर कसम खाई थी, सदन में यह बार-बार असत्य बोला जाता है कि गंगाजल को लेकर शराबबंदी की कसम खाई थी, यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप मन दारू भट्ठी खोलव हव, छत्तीसगढ़ की जनता दारू भट्ठी खोलने वाला मन ला माफ नई करय। यह याद रखिहा। हमन दारू भट्ठी ला खोले नई रहन, ओला कम करय के प्रयास करे रहेन, आप मन दारू भट्ठी ला बढ़ाये के कम करत हव।

सभापति महोदया :- आप लोग बैठ जाईये। संगीता जी, आप बैठ जाईये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, यह सचिव लोगों का है, आपकी मोदी की गारंटी मे है। मैं इसको रखी हूं, आप बोलेंगे तो मैं पटल पर रख दूंगी।

श्री राजेश मूणत :- हम बात कर लेंगे न, आपका क्या तकलीफ है? अपने को इतना कष्ट भी क्यों करना ?

सभापति महोदया :- मूणत जी, आपको 25 मिनट होने जा रहे हैं। आप लोग आपस में चर्चा न करें।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदया, मेरा 15 मिनट तो यही ले लिये। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, वह मेरी तरफ देखते हैं, मैं क्या करूं ? दारू को लेकर के सबके मन में प्रयत्न है, कोशिश है, लेकिन दारू की आड़ में गलत धंधा करना, एक दुकान में दो तरह की दारू बेचना, प्राइवेट के अंदर पैसा अलग वसूल करना। हम सब लोग बैठ करके बहुत बात करते हैं। जब देखो तब बात होती है। आज संगीता जी बिल्कुल फुलफार्म में हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जी नहीं हैं। भगवान करे कि आप नेता प्रतिपक्ष बन जाईये। मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम मैं आपसे यह बात कह रहा हूं कि हमारे आदिवासियों की बात करने वाले शुभचिंतक सब लोग बात करते हैं, कवासी भाई से मिलने तो एक आदमी नहीं गया। एक विधायक, एक नेता कवासी भाई से मिलने नहीं गया, क्योकि वह आदिवासी हैं।

श्री विक्रम मंडावी :- राजेश भैया, मैं दो बार मिलने गया हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, सभी लोग मिलने गये हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी मिलने गये हैं, हम लोग भी गये हैं। आप जांच करवा लीजिए। आप लिस्ट निकलवा दीजिए, हम सब गये हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हम उनसे मिलने जायेंगे तो आपको बताकर थोडी जायेंगे ? आप चाहते हैं कि हमको बताकर इनसे मिलने जायें। हम यदि अपने परिवार के सदस्य से मिलने जायेंगे तो आपको बताकर थोड़ी जायेंगे।

श्री राजेश मूणत :- अच्छा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अच्छा, आप मत जाना। आप ईमानदारी से यह बताईये कि लगभग 20 दिन से यह सदन चल रहा है, आप लोग एक भी स्थगन कवासी लखमा जी की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाये हो ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- इस सदन में कितनी बार चर्चा हुई है।

श्री धर्मजीत सिंह :- जब पूर्व मुख्यमंत्री जी के यहां रेड पड़ी तो पूरा आसमान उठा लिये थे, पूरी विधान सभा को खाली कर दिये थे।

श्री राजेश मूणत :- पूरा कुनबा चल दिये थे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उनकी गिरफ्तारी के संबंध में लगातार इसी सदन में चर्चा हुई है। आप रिकॉर्ड निकलवा कर देख लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसमें कार्रवाई नही चल रही है। आप लीगली बात करिये, मैं विधान सभा की प्रोसीडिंग की बात कह रहा हूं। आपने एक भी कोई गिरफ्तारी के खिलाफ यहां कोई कवासी लखमा जी के बारे में आवाज उठाई ? भूतपूर्व मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग पूरा आसमान हिलाकर रख दिये थे। कोई कुछ एक शब्द नहीं बोला। वह बेचारा तो छोटा था। उनके बारे में आप लोग बोलते न।

सभापति महोदय :- मूणत जी, समाप्त करेंगे।

श्री राजेश मूणत :- वह बेचारा नहीं था, अपना भाई था।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह बेचारा था। यह जो ई.डी की कार्रवाई हुई है, प्रदेश की सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोग कम से कम एक शब्द तो बोलते। आप लोग तो नहीं बोले। वह तो टिकट नहीं दे पाता। जो टिकट देने वाले हैं, आप उनकी बात कर रहे थे।

श्री राजेश मूणत :- वह तो पूरा कुनबा उठकर चल दिया था। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से सरकार ने पारदर्शिता के साथ में आबकारी नीति के ऊपर कार्य करना प्रारंभ किया, जिस प्रकार से बाहर की दारू आ करके यहां पर मंहगे रेट में बिकी, एफ.एल. 10 काहे का लाईसेंस बोलते हैं, वह मेरे को पता नहीं। धर्मजीत भैया, एफ. 10 या एफ.एल.10 क्या होता है ? विदेश की कौन सी दारू चलेगी, किसकी चलेगी, जिसका निर्धारकर्ता उसका सिंडिकेट बन करके...।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह premium shop थी।

श्री राजेश मूणत :- हां, premium shop।

श्री धर्मजीत सिंह :- उच्च कोटि की शराब मिलने का स्थान को premium shop बोलते थे। यह लोग तो गोवा तक देखे हैं।

श्री विक्रम मण्डावी :- राजेश भैया, आपका तो दारू से दूर-दूर का नाता नहीं है लेकिन आप दो दिन से दारू के पीछे पड़े हैं ।

श्री राजेश मूणत :- नहीं-नहीं, मेरा कोई लेना-देना नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका नहीं है लेकिन जनता का तो है भई, उससे कई लोगों का है न तो कम से कम उसको तो बंद मत कराओ । (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- नहीं-नहीं । वह क्या है कि राजेश पास में पहुंच गया तो वहां पर बैठकर बोल रहे हैं । (हंसी) माननीय सभापति महोदय, जो अच्छा काम किये उसकी मैं तारीफ करता हूं कि आने वाले समय में राजस्व का ही केवल साधन न बने, जन-जागरण करके और जिस प्रकार से पहले भारतमाता वाहिनी जो जन-जागरण करती थी और जनता इस व्यसन से दूर रहे, वापस इसमें गांव में भारतमाता वाहिनी के माध्यम से जन-जागरण प्रारंभ करना चाहिए । मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जो 5 साल तक बंद हो गया था उसको वापस चालू करना चाहिए ।

सभापति महोदय :- जल्दी समाप्त करेंगे ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदया, मैं बस दो छोटी-छोटी सी बातें कहना चाहता हूं । मैं बस इतना ही कहूंगा कि परिवहन विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन परिवहन विभाग में जो पूर्व में फिटनस को लेकर धंधे की दुकान खोलकर चले गये, एक छोटे से टैबलेट के अंदर दिन में 150-200 गाड़ियां, प्राईवेट सेक्टर वाला कैसे फिटनेस कर देता है यह समझ के बाहर है और इसीलिये जो एजेंसिया बांटकर चले गये, जो अपने लोगों को बैठाकर चले गये, उनका यह जो गोरखधंधा बन गया, जरा एक-बार इस पर जरूर विचार करना चाहिए । धीरे-धीरे परिवहन आम जनता की पहुंच वाला कुछ सुविधायें आपने पहुंचा दी हैं, जहां सर्विस है वहां से आराम से आपको लाईसेंस बन जाता है लेकिन जिस प्रकार से लोगों को यह दुकानें पहले एलाटमेंट हुई हैं, पूर्व सरकार ने जिस प्रकार से एक कागस बनाकर के, योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोगों को स्थापित करके चले गये, उनके बारे में एक-बार जरूर विचार करना चाहिए ताकि इनविशियेंस वेल्यू इस प्रदेश से खत्म हो । मैं ग्रामोद्योग के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, एक छोटा विभाग है लेकिन मुझे इसलिये इस विभाग पर कहना है कि ग्रामोद्योग एक बहुत अच्छा खासकर के जांजगीर-चांपा, खैरागढ़ यह पट्टी के अंदर बुनकर लोगों के लिये बहुत महत्वपूर्ण विभाग भी है । जो कोसा सिल्क का निर्माण भी करते हैं, खादी के कपड़ों का भी निर्माण करते हैं और वहीं हमारे बस्तर आर्ट के निर्माण के अंदर भी इनका बहुत बड़ा योगदान है इसलिये इसको कुटीर उद्योग के रूप में इनके लोन की व्यवस्था से लेकर इनको मार्केट उपलब्ध हो जाये और सरकारी अस्पतालों में सुनिश्चित हो जाए, जितने भी सरकारी अस्पताल हों या सरकार की जितनी भी चीजें हैं उसमें टेबलक्लॉथ-चद्दर से लेकर तकिया तक अस्पताल में खादी के लगें तो इससे उनको एक रोजगार मिल जायेगा तो कालातीत में जो कई सोसायटियां चली गयी थीं उनके लिये एक बहुत मार्केट खड़ा हो जायेगा । मैं आपके माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूं, मैं केवल दो लाईन कहूंगा ।

माननी सभापति महोदय, खासकर अब छत्तीसगढ़ रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन बन चुका है । हमारे यहां पर वित्तमंत्री जी ने एक फैसला कर दिया और उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद दूंगा । छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय बहुत बढ़ चुका है लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार न के बराबर मिलता है । बाहर के लोग आते हैं, टेंडर डालते हैं और

काम लेकर चले जाते हैं और वही काम यहां के लोगों को सबलेट कर देते हैं । अब जो व्यक्ति लाखों-करोड़ों रूपये लगाकर चूंकि छोटा-मोटा काम भी गांव-देहात से लेकर आज सब जगह होता है, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उनको लोकल काम मिल जाये और खासकर के यह संवाद के माध्यम से होता है । मेरा आग्रह है कि छोटे लोगों को भी जिला मुख्यालय में उनका रजिस्ट्रेशन करके वहां के लोगों को रोजगार मिल जाये, यह बड़े-बड़े इवेंट की कंपनियां यहां आकर जो काम करती हैं, काम उन्हीं लोगों से करवाती है लेकिन उनको वह पैसा नहीं मिलता, उनका वह ट्रांजेक्शन नहीं होता है । मेरा आग्रह है कि इनको जिला स्तर पर जहां भी इस प्रकार का काम होता है, इनका रजिस्ट्रेशन कर उनको रोजगार दें। आज मुख्यमंत्री जी के अन्य कई विभाग हैं, सब लोगों ने विषय रखा है। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए संगीता जी आपको पहले धन्यवाद क्योंकि इसलिए कि अब वहां विपक्ष के कोई साथी लोग नहीं हैं, आप दोनों ही बैठे हैं और दोनों के प्रति आभार और मैं तो यह चाहूंगा कि ध्वनिमत से पारित करिए और झमेला खत्म करिए। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करिए कि हम सब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके अनुमोदन कर दें। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद।

श्री राजेश मूणत :- भाई कुंवर, जो बोला हूं, वही बोलना।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- जी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग की अनुदान मांग संख्या 1, 2, 7, 12, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 56, 60, 65, 71, 26, 27, 37, 44, 51, 77 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं। अभी सुशासन पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुईं। बजट को लेकर बातें आईं। माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2024-25 के बजट के भाषण में कहा था कि सहज, सरल मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का कुशल नेतृत्व हमारी ताकत है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि या तो माननीय वित्त मंत्री जी को कुशल राजा के कर्त्तव्य का ज्ञान नहीं है या फिर आपकी सरकार के कुशल राज पिछले सवा साल में अपने कुशल दायित्व का या तो फिर निर्वाहन नहीं कर पाए हैं। जब भी सदन में बातें आती हैं तो पिछला एक वर्ष में केवल बदले की भावना से राजनीति करने में व्यतीत हो गया। केवल पूर्व की सरकार ने क्या किया? पूर्व की सरकार ने वह किया, आपकी सरकार को सवा साल हो गए, आपकी सरकार ने क्या किया? ये आपके प्रशासकीय प्रतिवेदन में है, वे बातें आपको यहां पढ़ना चाहिए। मैं तो यही पूछना चाहूंगा, बड़े-बड़े विकास की बातें करते हैं, आधारशिला की, नींव की, बुनियाद की बात करते हैं, एकाध बता दें किसी काम के लिए, उस बुनियाद के लिए अगर इन्होंने एक ईंट रखी है तो बता दें। कानून व्यवस्था से लेकर डेवलपमेंट की बात करते हैं। पूरा प्रदेश की जनता देख रही है कि पूरे प्रदेश में क्या हालात है? बड़ी-बड़ी बातें हुईं। माननीय वित्त मंत्री जी ने पहले बजट भाषण में कहा था। पहले बजट भाषण का आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु ज्ञान था। उन्होंने नेल्सन मंडेला जी का एक वाक्य पढ़ा था कि किसी देश को तबाह करने के लिए उसकी शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर देना और

परीक्षाओं में भ्रष्टाचार ही किसी देश को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है। ये शिक्षा की बड़ी- बड़ी बात करते हैं, लेकिन आज धरातल पर देखें तो जिस शिक्षा की बुनियाद को लेकर हम चिंता करते हैं, आने वाली पीढ़ी का, उनके भविष्य का शिक्षा एक आधार होता है एक बेस होता है कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसे मानसिक रूप से मजबूत कर सकें ताकि वह अपने घर, परिवार, समाज, प्रदेश, देश के लिए सोच सकें। शिक्षा एक मजबूत आधार होता है। लेकिन आज प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा की जो बुनियाद होती है, जो नींव होती है पांचवीं, आठवीं और दसवीं होती है। जो बोर्ड परीक्षा थी और बच्चों में एक डर होता था। आज आपकी शिक्षा नीति ने क्या कर दिया है? एक पंगु और लाचार बना दिया है। आपने बोर्ड को खत्म कर दिया है। बच्चों में भय खत्म है। आप यदि छठवीं, सातवीं, आठवीं के बच्चों को पूछें तो वे न ही essay लिख पाते हैं, न कोई application लिख पाते हैं, न ही 15 से 20 तक की गिनती बोल पाते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग छात्र हुआ करते थे, तीसरी में थे तो 20 तक की गिनती हमको याद रहती थी, क्योंकि उस समय एक अनुशासन होता था और उस समय के शिक्षकों में सेवा भाव होता था । लेकिन आज स्कूलों में अनुशासन नहीं दिखता है, यह उसका मूल कारण है । राजनीतिक विचारधारा से हटकर हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि शिक्षा की बुनियाद कैसे मजबूत हो ? हम लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि इस सरकार ने क्या किया, उस सरकार ने क्या किया ? अगर हममे साहस होता, हमारी सोच अच्छी होती तो पिछली सरकार ने जो 3000 स्कूलों को बंद किया था, वे बंद नहीं होते । जिनको खुलवाने का काम हमारी सरकार ने किया । मैं इस आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि आने वाली हम आने वाली पीढ़ी के लिए जो सपने संजोकर रखे हैं, वह बुनियाद कैसे मजबूत हो, उसका धरातल कैसे मजबूत हो, यह हम सबकी सोच होनी चाहिए । हमारी सरकार ने स्कूल जतन योजना के माध्यम से स्कूलों को रिन्यूवेशन करने का काम किया, जीर्णोद्धार करने का काम किया लेकिन उसमें भी आपको भ्रष्टाचार दिखता है । जिन स्कूलों को बने 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गए थे उन स्कूलों को हमने स्कूल जतन योजना के माध्यम से संवारने का काम किया था । आपके पिछले साल की प्रवीण्य सूची देखें तो जितने दसवीं और बारहवीं के मेधावी छात्रों की सूची में आए, सबसे ज्यादा 60 से 70 प्रतिशत छात्र स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र थे । सभापति महोदय, युक्तियुक्तकरण के माध्यम से इस प्रदेश में बड़ा खेल होने वाला था । एक साल पहले इसी पवित्र सदन से 34000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी । आज वे मंत्री जी हमारे बीच नहीं हैं, उच्च सदन में चले गए हैं । लेकिन उनकी घोषणाओं पर अमल करने का प्रयास इस सरकार ने कभी नहीं किया । अगर इनकी नीयत अच्छी होती, सोच अच्छी होती तो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते, कम से कम वेकेंसी तो निकालते । लेकिन युक्तियुक्तकरण के नाम से बड़ा खेल लगभग 50 हजार शिक्षक अतिशेष दिखाकर क्या करना चाह रहे थे ? जो हजारों छात्र डीएड, बीएड करके बैठे हैं उनके जीवन में आपने उजियारा करने के बजाय अंधियारा करने की कोशिश की है । उनका क्या दोष, जिन्होंने डीएड

किया, बीएड किया, अन्य योग्यता लेकर नौकरी की चाह में अपना पूरा समय लगाया । सभापति महोदय, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए कि हम ऐसा प्लान बनाएं, ऐसा विजन बनाएं ताकि जो शिक्षा के मंदिर, ये हमारी स्कूलें हैं, हमारी पाठशालाएं हैं उन्हें हम पुराना स्वरूप दे सकें और वहां से निकलने वाले छात्र अभाव में रहकर पढ़ाई करते हैं लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षा की बात आती है तो बहुत से बच्चे गांव के भी शामिल होते हैं लेकिन पर्याप्त सुविधा और पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण उस परीक्षा में नीचे की लाईन में खड़े हो जाते हैं । सरकार की बच्चों के प्रति जो सोच होनी चाहिए, चाहे वह प्रयास स्कूल के माध्यम से हो, चाहे एकलव्य स्कूल के माध्यम से हो या अन्य संस्थान के माध्यम से हम कोचिंग संचालित करते हैं तो हमारा विज़न भी स्पष्ट होना चाहिए । उदाहरण के तौर पर मैं अपने दुर्ग संभाग के प्रयास स्कूल की बात करूं तो पाटन, दुर्ग और बालोद का संयुक्त रूप से दुर्ग में संचालित हो रहा है वहां 500 सीटर के छात्रावास में 1000 बच्चे हैं । अब कल्पना कीजिए कि 500 सीटर के छात्रावास में 1000 बच्चे कैसे रहते होंगे और किस अवस्था में रहते होंगे ? जब बच्चे कलेक्टर तक अपनी बात रखने जाते हैं तो बच्चों को डराकर वापस भेज दिया जाता है कि आपको रहना है तो रहो, पढ़ाई करना है तो करो, तो उनके मन में क्या बीतती होगी यह समझिए ? यदि आज तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात करते हैं और जब तक हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो दिल्ली में हम कितने ही बड़े संस्थान खोल लें, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा । पहले हम अपने बेस को मजबूत करें । जब हमारी बुनियाद मजबूत होगी तब हमारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे, आई.आई.टी. करेंगे, जे.ई.ई. करेंगे, PMT परीक्षा की तैयारी करेंगे हो सकता है जिनका किस्मत हो वे IAS IPS भी बनेंगे। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, ये प्रयास संस्था कब चालू हुई और किसने चालू की ? जरा उस पर भी कुछ बता दीजिए। आपने कोई नई चीज प्रारंभ की है उसके बारे में बताईए न।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जो नई खोले हैं उसके बारे में बता रहा हूं।

श्री राजेश मूणत :- सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में चालू किया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नई जगह और खुली हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं।

श्री राजेश मूणत :- भाई, पहले कब चालू हुई, किसने चालू की, दंतेवाड़ा के अंदर जाकर देखिए, प्रयास संस्था वहां से प्रारंभ हुई है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैंने वहां जाकर देखा है, मैंने वहां छू लो आसमान भी देखा है।

सभापति महोदय :- आपस में वाद-विवाद न करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैंने उनको देखा है। हम तो ये कह रहे हैं कि उनको कितना अच्छा कर लें, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, ये मेरा आग्रह है, ये मेरा निवेदन है कि हम उसको

कितना अच्छा कर सकते हैं। हम अपनी बुनियाद कितनी अच्छी मजबूत कर सकते हैं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आप लोगों ने पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व पर बड़ी-बड़ी बातें की। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का पर्यटन, निश्चित ही बस्तर से लेकर सरगुजा तक अपनी एक अलग पहचान है। जितने भी सुदूर अंचल हैं, चाहे बस्तर दशहरा की बात करें या सरगुजा की बात करें, चाहे हम रतनपुर की बात करें या सिरपुर की बात करें या रायगढ़ कला महोत्सव की बात करें, डोंगरगढ़ की बात करें, चंद्रहासिनी की बात करें, सबका अपना-अपना महत्व है और समय के आधार पर उनका एक अलग महत्व होता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में वनांचल के साथ-साथ मैदानी क्षेत्रों की कला संस्कृति की भी एक अलग पहचान है। विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का काम पूर्व में हमारी सरकार ने की थी। एक अवसर मिलता था, विश्व के ऐसे बहुत से देश जिनकी संस्कृति को देखने का, जानने का अवसर मिलता था। इस परंपरा को हम राजनीतिक सोच से हटकर आगे बढ़ाएं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, आप आदिवासी संस्कृति की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के चेहरों पर कालिख पोतने का काम भी आप लोगों ने ही चालू की थी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप कौन सी बात कह रहे हैं बता दीजिए। क्या हुआ था ?

श्री केदार कश्यप :- कालिख पोलने का काम हुआ था।

सभापति महोदय :- बाहर इस विषय पर चर्चा कर लीजिए, अभी विषय पर रहें।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, रायपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर आदिवासी समाज का सम्मेलन हुआ था, यही उनके मुंह पर कालिख पोते थे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप लोग ज्यादा जानते हैं।

श्री राजेश मूणत :- आपकी पार्टी के लोगों ने कालिख पोता था।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में बात करना उचित नहीं समझूंगा। मुझे जितनी जानकारी है, मैं उसके बारे में बात करूंगा।

श्री राजेश मूणत :- मतलब जितना पढ़ा हूं उतना ही बोलूंगा, उसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। ये असत्य नहीं, सत्य है। ये रायपुर शहर में मेडिकल कॉलेज के अंदर सर्व आदिवासी समाज की मीटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने घूस करके आदिवासियों का मुंह काला किया था, ये कोई और नहीं आपकी ही पार्टी के नेता लोग थे, इसलिए आदिवासियों की संस्कृति की बात न करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जितना पढ़ा हूं वह बात अलग है। जितना बोल सकता हूं, उतना बोलूंगा। मैं असत्य बोलने का काम नहीं करता। मैं जितना जानता हूं, उसके बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में नहीं जानता, मैं उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक नहीं समझता। हमने भी देखा है कि आपकी पार्टी ने सार्वजनिक मंच में आदिवासी संस्कृति का कितना सम्मान किया था, उसको भी देखा है। विश्व आदिवासी

दिवस के समय आपकी पार्टी के कितने नेता वहां पर उपस्थित हुए और कैसे उनका सम्मान किए, ये भी हमने देखा है। माननीय सभापति महोदय, अगर हम संस्कृति में देखें, मैदानी और वनांचल को लेकर बात करें ।

(माननीय सदस्य श्री अजय चंद्राकर जी सदन में प्रवेश करने पर)

श्री राजेश मूणत :- अजय जी आ गए। आप संस्कृति में बात कर लीजिए। वे आ गए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, वे संस्कृति से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ की परंपरा से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, पर्यटन से जुड़े हैं।

श्री राजेश मूणत :- कौन से पर्यटन से जुड़े हैं ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभी पर्यटन से जुड़े हुए हैं। आप लोग जितना जानते हैं उससे ज्यादा जुड़े हुए हैं। सुवा, कर्मा, ददरिया, पंथी, पंडवानी, रहस, रैला, सैला, जितनी भी विधाएं हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- लेकिन भूपेश बघेल जी ने देवदास बंजारे जी के नाम से ईनाम दिया, वह सिर्फ पंथी के लिए दिया। आप उस प्रतिवेदन को पढ़ लीजिए। आप बैठे-बैठे क्या कर रहे थे? जब आप इतनी लंबी-लंबी बात कर रहे हैं तो उस समय मौन क्यों थे?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं उसमें भी आ रहा हूं। आप लोगों ने 15 सालों में क्या किया, यह भी दिख जाता है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- क्या आप भावरा-बाटी को भूल गये ?

श्री अजय चंद्राकर :- हमने 15 सालों में एक पंथी भर के लिए ईनाम नहीं दिया था।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप किसमें-किसमें ईनाम दिये थे, वह भी बता दीजिए। माननीय सभापति महोदया, यदि हम बात करे।

श्री राजेश मूणत :- मोहले जी, गिल्ली-डंडा में ईनाम मिला था न ? (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को एक स्थान मिले, उन कलाकारों को सम्मान मिले और भारत भवन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी एक संस्था बननी चाहिए, क्योंकि यहां भी ऐसे बड़े-बड़े नामचीन कलाकार हैं, जो छत्तीसगढ़ की लोक विधाओं और लोक संस्कृति में पारंगत हैं। इससे उन्हें उनकी कला के लिए सम्मान मिलेगा, पर्याप्त पारिश्रमिक मिलेगी, उन विधाओं को सिखाने के लिए वह वहां पर जाएंगे तो उनका जीवन भी सुसज्जित हो जायेगा। इससे आने वाली पीढ़ी को हम हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी दे सकेंगे। माननीय सभापति महोदया, यदि हम हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी विधा की बात करे तो वह नाचा है।

सभापति महोदया :- आप जल्दी समाप्त करेंगे। आपको 15 मिनट हो गये हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदया, अभी तो ले-देकर 5 मिनट हुए हैं।

सभापति महोदया :- आपको 15 मिनट से ऊपर हो गये हैं। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदया, अभी मैंने केवल एक ही पृष्ठ की बात रखी है, बाकी सारे पृष्ठ शेष हैं। माननीय सभापति महोदया, नाचा का जो स्वरूप था, उसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नाम और प्रसिद्धी दिलाने का काम किसी ने किया है तो स्वर्गीय हबीब तनवीर जी ने किया है। दाऊ मदन मंदराजी, झुमुक जी, न्यायिक दास जी, डोमार सिंह कुंवर जी, दाऊ महान सिंह चंद्राकर जी, रामचंद्र देशमुख जी, खुमान लाल साव जी, सुकुमार दीपक जी, मिथलेश साहू जी, दीपक चंद्राकर जी, भुलवाराम जी, किस्मत बाई जी, माला बाई जी, फिदा बाई जी, दीपक विराट जी, गोविंद मानिकपुरी जी ने छत्तीसगढ़ की नाचा शैली विधा को राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई। ऐसे लोगों के बारे में जब भारत भवन की तर्ज पर कोई थियेटर बनेगा तो वहां हमारी संस्कृति के लिए उनके द्वारा किये हुए कार्यों को लोग जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग भी भारत भवन गये हैं। हमें गर्व होता था कि वहां हमारे छत्तीसगढ़ की विधाओं की फोटो लगी होती थी, छत्तीसगढ़ के कलाकारों की फोटो लगी रहती थी और मंचीय प्रस्तुति होती थी। उसको देखने से हमको आनंद का अनुभव होता था। उसकी तर्ज पर वह हो। पंडवानी में पद्म श्री, पद्म विभूषण तीजन बाई जी, पद्म श्री पुनाराम निषाद जी, पद्म श्री आदरणीय झाड़ूराम देवांगन जी, ऋतु वर्मा जी और ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कलाकार हुए। जैसे अभी माननीय अजय भैया ने कहा कि पद्म श्री देवदास बंजारे जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंथी को पहचान दिलाई। सभापति महोदया, मैं आपसे एक बड़ी बात कहना चाहूंगा कि आज हम लोग संस्कृति विभाग से जो कार्यक्रम गांव-गांव में अपने रिकमेण्ड से कराते हैं, उसके नियम में कुछ बदलाव होने चाहिए। जो ग्रडेशन की बात आई है तो ग्रेडेशन का मापदण्ड कैसे हुआ, किसने तय किया, कौन इसकी समिति में है और उसका आधार क्या रहा? तो इसमें थोड़ी विसंगति है। एक विधान सभा स्तरीय समिति बननी चाहिए। जो इस विधा को जानते हैं, उन कलाकारों और विधायकों को उसमें शामिल करना चाहिए।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदया, ग्रेडेशन भी इन्होंने तय किया, गलत तय किया और यह उसी को सुधारने के लिए बोल रहे हैं। यदि आप उसको अपने समय में सुधारते तो आज आपको इस विषय में बोलना नहीं पड़ता।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदया, मैं इसमें गलत वाली बात नहीं कर रहा हूं। इसमें गलत नहीं हुआ है। मैं यह कह रहा हूं कि यदि इसमें कुछ और विसंगति है तो उसको हम कितना अच्छा और बेहतर कर सके, इसके बारे में एक प्रयास होना चाहिए। एक समिति बने। उसमें विधायक भी रहें और उन विधाओं में पारंगत लोग भी रहें, तब उन कलाकारों को सम्मान मिल सकेगा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब सब साय-साय होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अनुज भाई, वह तो मैं देख रहा हूं कि कितना साय-साय हो रहा है। मैं कलाकार हूं, इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है और इसलिए मैं ये बातें इस सदन में कह रहा हूं कि पहले क्या होता था और अभी क्या हो रहा है।

श्री राजेश मूणत :- वह भी तो कलाकार हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हां, मैं जानता हूं। मैं उनसे सीनियर हूं। आप अनुज जी से पूछ लीजिए। मैं उनसे 10 साल सीनियर हूं।

श्री राजेश मूणत :- आप उनसे किस चीज में सीनियर हैं ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं उनसे सभी विधाओं में सीनियर हूं। आप उनसे पूछ लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- अच्छा, आप विधाओं में सीनियर हैं। ok.

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं सन् 1991 से मंचीय कलाकार हूं और वह सन् 2001 से कर रहे हैं।

श्री अनुज शर्मा :- आज आपको सब असत्य माफ है, जैसे 3 हजार स्कूल बंद कराये थे, वह भी माफ है।

श्री केदार कश्यप :- विधा में नहीं, दुविधा में सीनियर हो।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं सन् 1991 से मंचीय कार्य कर रहा हूं, वह 2001 से कर रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- कुंवर जी, आप विधा में नहीं, दुविधा में सीनियर हो।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं विधाओं में बोल रहा हूं। मैं विधाओं में सीनियर हूं। अगर किसी को सीखना है तो वे आये और सीख लें।

श्री अनुज शर्मा :- मोहले जी आपसे सीखेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं, उनसे सीखूंगा।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- कौन-कौन सी विधा है, बता तो।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं उनसे सीखूंगा। वह जिसमें पारंगत हैं, मैं उसमें पारंगत नहीं हूं, मैं उनसे सीखूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अगर पर्यटन की बात करें तो मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे पर्यटन स्थल हैं, चाहे वह गौरया मेला का हो, जोगी मठ का हो, कबीर घाट का हो, नर्मदा धाम तुलसी का हो, बाबा मोहंदीपाठ का हो, देव दशहरा का हो, डेंगरा पाट का हो, भुईफोड़ का हो कमरौद का हनुमान मंदिर का हो, पर्यटन स्थल में शामिल है। लेकिन आज भी वहां सुविधाएं नहीं मिल रही है। मैंने पूर्व की सरकार के माध्यम से इन संस्थाओं को अनुदान राशि के रूप में दो-दो लाख रूपये दिलाने का प्रयास किया था और सरकार दे रही थी। लेकिन वर्तमान सरकार अभी तक लगभग दो साल हो रहे हैं, दूसरा मेला निकल गया, लेकिन अभी तक अनुदान के रूप में वहां एक रूपए की राशि नहीं मिला है। क्योंकि बाकी चीजों को 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक दे रहे हैं। अगर कोई गौरयामेला

पर्यटन स्थल गया होगा, मेरे ख्याल से यहां अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए अधिकारी होंगे, वे शायद गये होंगे और देखें भी होंगे। जैसे आपके सिरपुर का है, अन्य जगहों का है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा कलचुरी वंश का गौरया मेला का निकला हुआ मूर्ति है, वहां जमीन के अंदर से निकला हुआ मूर्ति है, उसके सरंक्षण की बात है, उसके संग्रहालय की बात है। लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रयास नहीं हुआ है। मैं इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में देव दशहरा डेंगरापार होता है। वहां मन्नत के घोड़े चढ़ाये जाते हैं। साल में एक बार होता है। वहां एक साल में सैकड़ो घोड़े चढ़ते हैं। जब वहां का मेला इतना बड़ा विशाल स्वरूप लेता है तो कहीं न कहीं मान्यता होगी। वहां साल में हजारो घोड़े चढ़ते हैं और हजारों की संख्या में भीड़ होती है। वहां एक साल में एक बार, एक दिन मेला लगता है। वहां आदिवासी संस्कृति को दिखाने का एक बड़ा सौभाग्य मिलता है। मैंने उस मेले को पर्यटन स्थल में रखने की बात कही थी, लेकिन अभी तक न तो उसे पर्यटन स्थल में शामिल किया गया है और न ही उसको सरंक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वह देव दशहरा आदिवासी संस्कृति का पर्याय है, उसको भी सरंक्षण मिले, उसको शासन से अनुदान मिले ताकि बढ़िया आयोजन कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं उस समाज से हूं, मैं उस वर्ग से हूं जहां हमारा पारंपरिक और पुश्तैनी व्यवसाय मछली पालन रहा है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जा रही है, पूर्व में जो योजना बनी थीं, उसके माध्यम से हम लोगों, मस्तय कृषक को भी लगातार मत्स्य कृषक का एक बढिया दर्जा मिला था, के.सी.सी. की तरह ऋण लेने का बहुत सी सुविधाओं का पारंपरिक तौर पर शुरूआत किया था। लेकिन अभी पिछले साल से, इसी सरकार के कार्यकाल में राजनांदगांव और बालोद जिले में केज कल्चर के रूप में बड़ा धांधली उजागर हुआ था, विधान सभा में मामला आया था, एक के ऊपर एफ.आई.आर. होता है और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी विसंगति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यह व्यवसाय करने वाले आज केवल निषाद समाज के लोग नहीं है, अन्य वर्ग के लोग भी यह व्यववसाय कर रहे हैं। वह करें, लेकिन जिस पर हमारा पुश्तैनी और एकाधिकार है, उससे हमको वंचित करके स्वयं इस क्षेत्र में आ जाते हैं और अपना व्यवसाय करने लग जाते हैं तो फिर हमारा क्या होगा ? योजनाएं हमारी लिए बनती है। लेकिन काम कोई और करता है। वहां पर हमारे लोग केवल मजदूरी का काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बालोद जिले में जो केज कल्चर में धांधली हुई थी, उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उस पर जरूर कार्रवाई करें, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मछली मारने की परम्परा को भी तकनीकी रूप से सरंक्षित करना जरूरी है। बिलकुल आधुनिक तकनीक से मछली पालन करें। लेकिन जो पुरानी पद्धत्ति है, जिसमें

छोटे-छोटे मछुआरे हैं, जिनके पास न तालाब है, न बांध है, न अन्य संसाधन है, वह तो नरवा, डबरी, पोखर से, इन छोटी-छोटी जगहों पर मछली मारकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। लेकिन आजकल नाला में मछली का बीज नहीं छोड़ा जा रहा है। जिसको ग्रामीण स्तर पर जिसे छोटे-छोटे नरवा बोलते हैं, उसमें भी मछली बीज नहीं डाल रहे हैं, डबरी में भी मछली बीज नहीं डाल रहे हैं। नाला में भी मछली बीज नहीं डाल रहे हैं। बड़े-बड़े बांध और तालाबों में मछली बीज डाल रहे हैं तो वहां भी मछली बीज डाले ताकि जो छोटे-छोटे मछुआरे हैं, वे केवल वहीं से 2-4 किलो मछली निकालकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उसमें भी हमारी बात होनी चाहिए। लगभग जो देशी प्रजाति है हैं, वह लगभग विलुप्त हो गये हैं। अगर मैं उस प्रजाति की बात करूं तो आजकल बाम्बी मछली देखने को नहीं मिलता, यह कुछ-कुछ जगहों में मिलेगा। ऐसे ही रूदनी, सरांगी, डड़ाई, टेंगना, सिंघी, मोंगरी व कोतरी हो गया, इन सभी प्रजातियों का संरक्षण करने की जरूरत है।

समय :

5:00 बजे

श्री अनुज शर्मा :- अब तैं हर असली विषय में आय हस।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आय हौं न। तैं हर महाराज हो के बात मत कर। सब महाराज मन मछली खाथे, लेकिन मैं हर तोर बारे म उजागर नई करवं। (हंसी)

सभापति महोदय :- आपको 25 मिनट से ऊपर हो गये हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जो देशी प्रजाति की मछलियां हैं, उसके सरंक्षण के लिए शासन के तरफ से कोई योजना बननी चाहिए, ताकि हम जिस मछली का व्यवसाय करते हैं, उसका संरक्षण हो सकें। एक बड़ी बात की मत्स्य वानिकी महाविद्यालय में मछुआरा समाज को पढ़ने के लिए जो आरक्षण मिला है, उसमें सिर्फ पांच से दस सीटों पर आरक्षण है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उनके लिए लगभग 20 से 25 प्रतिशत सीट का आरक्षण हो, ताकि हमारे मछुआरे समाज के जो पढ़ने वाले होनहार हैं, जो गरीब मछुआरे परिवार हैं, अगर वे वहां एडमिशन लें तो कम से कम उनके लिए एक रोजगार के अवसर प्रदान हो सकें। एस.डी.आर.एफ. की भर्ती होती है। आप देखते हैं कि जब नदी, तालाब व बांध की बात आती है तो बेखौफ रूप से, बगैर सेफ्टी जैकेट, बगैर सेफ्टी गार्ड के अगर कोई पार करता है तो वह मछुआरे परिवार के लोग हैं। अगर एस.डी.आर.एफ. की भर्ती होती है, उसमें कम से कम जो पढ़े-लिखे मछुआरे परिवार हैं, उनके बच्चों को अवसर मिलेगा तो निश्चित ही उनको रोजगार में लाभ होगा। हमने इसका उदाहरण देखा है। जब कुछ व्यक्ति शिवनाथ नदी के बाढ़ में डूबे हुये थे तो एस.डी.आर.एफ. की टीम उन्हें दो-दो दिन तक ढूंढ नहीं पाई थी, लेकिन मछुआरों ने कहा कि हमें सिर्फ 2 घंटे का समय दीजिये और उन्होंने 2 घंटे में ही उन लोगों को पूरे कार सहित ढूंढ निकाला था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी

गणेशखपरी में जब एक बालक डूब गया था तो एस.डी.आर.एफ. की टीम उसको 24 घंटे तक नहीं निकाल पाई, लेकिन मछुआरे गये और उन्होंने उसको 2 घंटे में निकाल दिया। उनको ज्ञान होता है कि कहां पर कितना गहरा है, पानी का ठहराव कितना है, पानी का वेग कितना है, यह काम मछुआरा करता है। इसलिए जो एस.डी.आर.एफ. की भर्ती होती है, उसमें मछुआरों के परिवार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय :- समाप्त करेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरकारी हेचरी है, उसमें हम देखते हैं कि चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती में कोई न कोई व्यक्ति की भर्ती होती है, लेकिन यदि उसमें मछुआरों के परिवार के लोगों को भर्ती कर दिया जाये तो मछली को कैसे संरक्षित करना है, कैसे मछली को रखना है, इसकी उनको पूरी जानकारी रहती है। इसलिए चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज मछलीपालन विभाग जिस रूप से जूझ रहा है, अगर मछलीपालन विभाग में 851 पद स्वीकृत हैं, लेकिन उसमें कार्यरत सिर्फ 487 हैं। 364 पदों में कार्यरत नहीं है तो हम कैसे पूरा काम कैसे कर सकते हैं? वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ है, जिसमें 115 पद स्वीकृत हैं, उसमें केवल 37 पदों पर ही कार्य कर रहे हैं, फिर उसमें कैसे अच्छे काम की बात कर सकते हैं? उसमें 78 पद रिक्त हैं। मछुआरों के कल्याण के लिए जो एक मछुआ कल्याण बोर्ड बना हुआ है, लेकिन हम उसमें देखते हैं कि उसमें केवल एक पद पर हैं, उसमें भी चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी काम कर रहे हैं। उसके लिए 12 पद सृजित हैं, लेकित एक ही कर्मचारी काम कर रहे हैं और 11 पद रिक्त हैं तो हम वहां पर कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं? इसलिए इसमें भी गंभीरता से सोचने की बात है। अगर मैं पशुधन विकास विभाग की बात करूं तो ..।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, बस दो मिनट और बालूंगा। गौमाता के ऊपर बात आई है इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आज उनकी जो हालात हैं, अगर उसका कोई जिम्मेदार है तो वह भा.ज.पा की सरकार है। मैं सीधे स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि आज उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी सदन में गौ अभ्यारण्य की बड़ी-बड़ी बातें हुई थी। वह कहीं पर चालू हुआ है तो आप बता दीजिये। लेकिन गौठान के माध्यम से जो सुचारू रूप से संचालित हो रहे थे तो बड़ी-बड़ी बातें हुई थी कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हमको तो व्यवस्था करने में समय लगता है, किसी चीज को बनाने में समय लगता है कि कितना अच्छा से हम उसको बेहतर कर सकें। सबका प्रयास होना चाहिए और हमने देखा है कि आज ..।

श्री राजेश मूणत :- भाई निषाद जी, आप गौठान की बात कर रहे हैं। आप हाऊस छूटने के बाद हम साथ में चलते हैं। मैं अटारी लेकर चलता हूं, मैं आपको राजधानी के बीच का गौठान बताता हूं कि पिछले पांच साल के गौठान की क्या स्थिति है? (सत्तापक्ष के सदस्यों के द्वारा शेम-शेम की आवाज) हम दोनों यहीं से साथ चलेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप मेरे विधान सभा क्षेत्र चलिये।

श्री राजेश मूणत :- उस समय तुम्हारी सरकार थी, तुमने करवा लिया, बचे हुये के साथ क्या किया, राजधानी भी तो अपनी थी ? गौठान का संचालन..। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आज भी राजधानी में सड़क में गाय बैठी है, अब उसको देखने वाला कोई नहीं है । आपके गौ-रक्षक कहां हैं, जो उस समय गाय को लेकर सड़क पर निकलते थे, आज बोलने वाले कोई नहीं है....।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदया, गौ-रक्षकों ने जितना काम किया है, उसे 7 जनम में नहीं कर सकते । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कुछ नहीं किया है, गौ-तस्करी करने का काम भी वही किये हैं । छत्तीसगढ़ को कत्लखाना बना दिये थे । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जो आपके तथाकथित गौ-रक्षक हैं, वह राजनांदगांव के गार्डन में पकड़े गये हैं । आपके तथाकथित गौ-रक्षक राजनांदगांव के बार्डर में गौ-तस्करी करते हुये पकड़े गये हैं । यह भी भूल गये हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदया :- समाप्त करेंगे । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदया, आप गलत बात कर रहे हो । यह बार-बार गलत आरोप लगाते हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदया :- आप लोग आपस में बातचीत न करें ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, गौशाला के माध्यम से आपकी सरकार में करोड़ों रूपये के जो अनियमितता हुई थी...। (व्यवधान) सैकड़ों गाय मर गई थी, उसके खाल का, उसकी हड्डी का आपने व्यापार किया । (व्यवधान) मछली खाने के लिये तालाब में डाल दिये थे । यह हमने देखा है । बड़ी-बड़ी बात करते हैं, गौर रक्षा की बात करते हैं, गौ-संरक्षण की बात करते हैं । सभापति महोदय, आज भी जो किसान बकरी शेड, पशु शेड के लिये आवेदन भरे हैं, वह तरस रहे हैं, जनपद के चक्कर लगा रहे हैं...।

सभापति महोदया :- निषाद जी, आधे घंटे से ऊपर हो गये हैं । कृपया समाप्त करें ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदया, मैं शराब में दो मिनट बोलना चाहूँगा कि आज भी गांवों में अवैध शराब बिक रहे हैं । मेरे साथ चुपके से एक-दो विधायक जाने चाहें तो कहां-कहां पर अवैध रूप से शराब अवैध रूप से बिक रहे हैं और किसके संरक्षण से बिक रहा है ?

श्री राजेश मूणत :- चुपके से क्यों जायेगा ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मेरे साथ चलिये, मैं सार्वजनिक करूँगा ।

श्री राजेश मूणत :- आपके साथ जाने में डर थोड़ी है ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- डर नहीं बोल रहा हूँ, आपको विधायक है ऐसा जान जायेंगे तो आपको क्यों शराब देंगे ? (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- आप लोगों को सब अड्डा तो पता ही है ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदया, मेरे साथ चलें और जो बेचने वाले हैं, वह सब आपके पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो आज जिम्मेदार पद पर हैं । मेरे यहां अर्जुन्दा में दारू बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं ।

सभापति महोदय :- निषाद जी, समाप्त करेंगे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदया, मैं यह बता रहा हूँ कि बड़ी-बड़ी बात करते हैं । महिलायें जब विरोध करती हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। मोंहदीपाठ और भरतपुर की पीड़ित महिलायें कलेक्टर तक पहुंची थी और उन्होंने मांग की थी शराब भट्ठी खुलना चाहिये । एक तरफ बंद की मांग किये हैं और एक तरफ खोलने की बात करते हैं । वहां पर अवैध रूप से शराब आ रही है और महाराष्ट्र से शराब आ रही है, क्योंकि राजनांदगांव जिला सीधा आता है और अर्जुन्दा सीधा पहुंच जाता है । सभापति महोदय, यह व्यवस्था सरकार ने की है, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदया :- श्री नीलकंठ टेकाम जी, समय का ध्यान रखिये, अभी 12 सदस्यों को और कहना है ।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदया, इस 10 मिनट में ही बस्तर के बारे में बोल दूँ । खासकर जो चर्चित विषय है, इसको लेकर पूरा सदन और पत्रकारगण, छत्तीसगढ़ से लेकर देश की राजधानी तक, नक्सलवाद की चर्चा होती है और जिस पर आखिरी कील ठोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, जो कि इतिहास के सुनहरे पन्ने पर लिखा जायेगा ।(मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदया, बस्तर में जब नक्सलवाद 1990 के दशक में आया था तो गांव से लोग शौक के तौर पर जाया करते थे कि नक्सलवादी होते कैसे हैं ? उनकी बखान होती थी, फलाना फारेस्ट गार्ड ने साप्ताहिक भुगतान नहीं किया तो उसको चीटीं चबाने का काम नक्सलाईट करते हैं, लाल सलाम जिंदाबाद बोलते थे। अगर कहीं पर मजदूरी नहीं बंट रहा था तो वहां के सब-इंजिनियर, ओव्हरसियर को

उन लोग पकड़कर मजदूरी दिलाते थे और उनका जय-जयकार होता था, लेकिन देश के आजादी के 35 साल तक जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बस्तर को केवल लूटने का और अपनी राजनीति चमकाने का काम किया था । माननीय सभापति महोदया, उसी का नतीजा है कि नक्सलवाद को पिछले 45 सालों से झेलते आ रहे हैं और आज हम सब बड़े उम्मीद के साथ उस सुनहरे दिन का, उस सुनहरे समय का इंतजार कर रहे हैं, जब नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होने जा रहा है और एक नये युग की शुरूआत बस्तरवासियों के लिये, देशवासियों के लिये और पूरे छत्तीसगढ़वासियों के लिये बनने जा रहा है । सभापति महोदया, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि नक्सलवाद के बाद हमारा क्या होने वाला है ? बस्तर की आबादी 40 लाख के आसपास है । उस 40 लाख की आबादी के लिए, आने वाले नौजवानों के लिए, माताओं के लिए, किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, उसका एक बड़ा ही सुन्दर बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ज्ञान के तहत और गति के माध्यम से देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है । मैं समझता हूं कि आज तक के इतिहास में इससे अच्छा दूर दृष्टि रखने वाला कोई भी बजट अभी तक देखने को नहीं मिला है, पढ़ने को भी नहीं मिला है । मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमारे बस्तर में उपलब्ध संसाधन हैं, हमारे पास जंगल है, हमारे पास नदी-नाले हैं, हमारे पास औषधियां हैं और हमारे पास मेन पावर है । हम इन तमाम संसाधनों को किस प्रकार से व्यवस्थित करके एक आर्थिक उन्नति के उपाय में तब्दील कर पाएंगे, वह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है ।

सभापति महोदया, पर्यटन के बारे में लगातार बातें हो रही हैं । बस्तर में कण-कण में पर्यटन है । जब आदमी केशकाल के घाट में चढ़ता है और जब सांस लेता है तो उसको जो महसूस होता है, उसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है । इतना स्वच्छ वातावरण, इतनी गहराई, इतनी सुन्दरता, इतनी हरियाली है और ऐसे में माननीय गृहमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही सुझाव रहेगा कि उन तमाम जगहों पर जहां पर नक्सलवादियों के साथ हमारी लड़ाईयां हुई हैं, उसकी भी एक शौर्य गाथा बनाई जाए, वहां पर स्मारक बनाई जाए, ताकि लोग उन जगहों पर जाकर वहां पर घूमें, उनको देखें कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कैसे यहां पर शहादत हुई और नक्सलियों का समापन कैसे किया गया, वह भी हमारे लिए पर्यटन का काम कर सकता है । इस समय हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती कनेक्टिविटी को लेकर है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री टावर योजना, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है । मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें जितनी तेजी हो सके, उतनी जल्दी से जल्दी ये टावर लगाने का काम होना चाहिए, ताकि वहां के लोगों को कनेक्टिविटी मिल सके ।

सभापति महोदया, इस समय हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि इंद्रावती नदी पूरी तरीके से सूख गई है । हमको पता ही नहीं चला कि हमारे हिस्से का पानी उड़ीसा वालों ने कोलाब नाला के माध्यम से कब जोरा नाला से छीनकर अपने हिस्से में ले लिए । इसको लेकर पूरा बस्तर इस समय फिर से एक

बार झूलसा हुआ है। वहां से हमारे विधायक जी भी आते हैं, इस बात को लेकर उन्हें भी बहुत चिन्ता है । इस पर शीघ्रतिशीघ्र विधायक दल का गठन किया जाना चाहिए, स्थल का निरीक्षण किया जाना चाहिए और बस्तर के हिस्से का पानी तत्काल बस्तरवासियों को मिलना चाहिए। इसलिए लिए उड़ीसा में भी हमारी ही पार्टी की सरकार है । उनके साथ मिल-जुलकर व्यवस्था बनाने की कोशिश करनी चाहिए ।

सभापति महोदया, माईनिंग के माध्यम से 6 हजार करोड़ से ज्यादा की रायल्टी एनएमडीसी के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य और केन्द्र सरकार को प्राप्त होता है । उसके एवज में आज भी जगदलपुर से लेकर रायपुर तक आने वाले किसी व्यक्ति को बस में 600 रूपए किराया देकर आना होता है । हम अभी भी रेल्वे की सुविधा नहीं ला सके । जब अंग्रेजों ने वहां का झाड़ काटकर विश्रामपुरी तक रेल्वे लाईन बिछाकर वहां के पूरे वनोंपज को लूटने का काम किया, जब बैलाडीला के खदान से लोहा निकालने की बात आई तो वहां तक रेल्वे लाईन बिछा दी गई, लेकिन बस्तरवासियों की सुविधा के लिए जगदलपुर से, बीजापुर से, हैदराबाद से हमारी कनेक्टिविटी किस दिन होगी, यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उस पर हमें काम करने की आवश्यकता भी है ।

सभापति महोदया, शिक्षा के बारे में बात हो रही थी, अलग-अलग प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप भी हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था जापान का जो मॉडल है, हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है, जहां पर बच्चे पढ़ते-पढ़ते, सीखते भी हैं और उनका कौशल उन्नयन भी होता है और जिस दिन वे हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा पास करते है, उस दिन उनके हाथ में उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक जरिया रहता है। हमें भी कुछ इसी प्रकार की दिशा में आगे बढ़ना होगा। बहुत बार हमारे साथी बोलते हैं कि हमने तीन हजार स्कूल खुलवा दिए, लेकिन कम से कम ये तो बताएं कि उन स्कूलों को जिन्हें आप लोगों ने खुलवाया, में पढ़ाने का काम नक्सलाईटों ने किया, जिसकी वजह से हम आज भी नक्सलवाद की चपेट में फंसे हुए हैं। हमारा जो प्रतिवेदन है, उसके हिसाब से हम विद्यार्थी और शिक्षक के रेशियो में देश में सबसे अच्छी स्थिति में हैं लेकिन उसका युक्तियुक्तकरण सही ढ़ंग से नहीं हो पाने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। इस पर शीघ्रातिशीघ्र विचार कर इसका निराकरण करने की आवश्यकता है। हमारे राज्य में बस्तर को लेकर जो चिन्ता है, उस चिन्ता में सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि हमारे पास जो संसाधन हैं, पर्यटन है, वहां की संस्कृति है, उसे हम कैसे आर्थिक आय का स्रोत बना सकते हैं। इसके लिए लगातार हमारी सरकार की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में काम चल रहा है। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बस्तर ओलंपिक जैसे एक बहुत ही सुंदर अभियान को चालू किया, जिसके माध्यम से 1 लाख 65 हजार लोग ऐसे क्षेत्रों से निकलकर बाहर आए, जो कि कभी नक्सलवाद की चपेट में था और उनके अंदर के कौशल, टैलेंट, एनर्जी को लोगों ने देखा है। उसी की तर्ज पर एक बार फिर से बस्तर पंडुम के नाम से बस्तर की संस्कृति , बस्तर की मौलिकता, वहां का

रहन-सहन, वहां का रेला, पाटा, वहां की ढोल, वहां की मांदरी और वहां की तमाम् कलाकृतियों को एक बार फिर बाहर निकालकर लाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे एक वरिष्ठ विधायक जी बता रहे थे कि अगर ये बस्तर पंडुम का आयोजन बस्तर के बजाय अगर एकाध बार दिल्ली में कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर पूरे देशवासियों को बस्तर के बारे में, बस्तर के कल्चर के बारे में जानकारी हो सकती है, तब जाकर हमारे बस्तर की संस्कृति को विश्वस्तरीय लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 144 साल बाद जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, वहां पर छत्तीसगढ़ पैवेलियन बनाया था, जहां पर 75000 लोगों ने जाकर व्यवस्था प्राप्त की। उस धार्मिक पर्यटन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 8 हजार करोड़ रुपए खर्च किये थे, लेकिन उससे उन्होंने उस राज्य की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंचा दी। उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी ऐसे अनेक स्थान हैं, जहां पर हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, धार्मिक क्षेत्र हैं, वनों से आच्छादित पर्यटन क्षेत्र हैं, राज्य के व्यंजन हैं, बस्तर के पेय पदार्थ हैं, हमें भी उन सबको एक तरह से नई टेक्नीक के माध्यम से उसका आर्थिक उन्नति में उपयोग करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं।

सभापति महोदय, पुन: मेरा यही कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है कि विधान सभा, लोक सभा, नगर सरकार और ग्राम सरकार इन सभी जगहों पर काम करने के लिए अधिकृत करने का प्रमाण पत्र जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इससे बड़ा प्रमाण पत्र कुछ नहीं हो सकता है और हमारा जो सुशासन है, उसका परिणाम अब दिखने लगा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की मांगों में ऐसी एक भी कोई निगेटिविटी नहीं है, जिस पर कोई बहस करने या कटौती पर विचार करने की आवश्यकता हो। मैं तमाम मांगों पर अपना समर्थन व्यक्त करते हुए, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तुरी) :- माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग संख्या 1, 2, 7, 12, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 56, 60, 65, 71, 26, 27, 37, 44, 51 और 77 के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदया, मैं स्कूल शिक्षा विभाग से अपनी बात की शुरूआत करना चाह रहा हूं। चूंकि अच्छी शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो गरीबी, अंध:विश्वास और असामनता को मिटा सकती है। ज्ञान में किया गया निवेश बहुत ही उत्तम होता है।

"एक शिक्षित व्यक्ति अपनी जिंदगी खुद संवार सकता है

लेकिन एक शिक्षित राज्य पूरे प्रदेश को आगे बढ़ा सकता है"।

माननीय सभापति महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग एक सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इसका कार्य विभिन्न योजनओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना है। स्कूली शिक्षा में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुण का विकास होता है। शिक्षा विभाग द्वारा 6 से 18 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए प्रदेश में आवश्यकतानुसार नये विद्यालय की स्थापना एवं संचालित विद्यालय को उन्नत एवं विकसित किया जाता है। चूंकि इस तरह का कोई प्रावधान इस अनुदान मांग में नहीं किया गया है इसलिए मैं इसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। जिसमें नवीन प्राथमिक शाला शिक्षा का वह प्रारंभिक चरण है, जिसमें बच्चे की सीखने की यात्रा की नींव रखी जाती है। यह एक महत्वपूर्ण अवधि है, जिसमें बच्चे मौलिक कौशल विकसित करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने समग्र विकास को आकार देते हैं। एक हवा है और उज्जवल भविष्य की ओर शुरूआत भी होती है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है कि प्रदेश में एक भी नवीन प्राथमिक शाला खोलने का कोई प्रावधान कोई उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। इसलिए मैं इस अनुदान मांग के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं।

समय:

5.23 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- तोला समर्थन करे बर कौन बोलिस हे ? तै विरोध करत हन तो तोर मर्जी हे।

श्री दिलीप लहरिया :- बहुत सही है। लेकिन आपको अपने समय में बोलना चाहिए कि जो इस देश के नींव है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए एक भी प्राईमरी स्कूल का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें आपकी भी चिंता होनी चाहिए और हमें भी चिंता करनी चाहिए। आपकी इस ओर कोई चिंता नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- लहरिया जी, हमारे भांचा उधर रहते तो जरूर चिंता करते। यह गलती हो गया कि वह इधर है।

श्री दिलीप लहरिया :- मैं माननीय अजय जी का भाषण सुन रहा था। वह विद्वान हैं। उनका भाषण सब सुनते हैं। लेकिन उन्हें यह कहना चाहिए था कि बजट में एक भी नवीन प्राईमरी स्कूल, प्रारंभिक स्कूल का उल्लेख नहीं होना चिंता का विषय है। जिसमें 67 नयी शराब दुकान खोलने का उल्लेख है और एक भी नवीन स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है। (शेम-शेम की आवाज) यह तो गलत बात है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसमें हाई स्कूल के भी उन्नयन का उल्लेख नहीं है। माननीय चंद्राकर साहब जी, पिछले सत्र में एकाध स्कूल का उल्लेख था। लेकिन इस बार

एक भी हाई स्कूल के उन्नयन का उल्लेख नहीं है। मस्तुरी क्षेत्र में एक भी जगह स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि यह द्वेष भावना है या क्या है यह मैं नहीं जानता।

श्री अजय चन्द्राकर :- लहरिया जी, सुनिये। आप यह पढ़ाई-लिखाई, स्कूल की बात को छोड़िये। आप संस्कृति में बोलिये, पर्यटन में बोलिये और नाचते हुए बोलिये। आप कुछ गाते नाचते हुए बोलिये।

श्री दिलीप लहरिया :- ऐसा है कि मैं बहुत नचवा चुका हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- तें गाके तो बता।

सभापति महोदय :- माननीय अजय जी, उनको बोलने दीजिए।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय जी, यह लोग नहीं चाहते कि इस प्रदेश के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। हमें इनकी सोच समझ आ रही है। मस्तूरी क्षेत्र में कक्षा दसवीं तक पढ़ाई करने के बाद, वहां के बच्चे लम्बी दूरी तय करने की समस्या से जूझ रहे हैं और वहां पर लम्बी दूरे होने के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उनको बीच में ही अपनी पढ़ाई को बंद करना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई भी बाधित होती है और उस क्षेत्र के बच्चे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत इटवा, ग्राम पंचायत रांख, ग्राम पंचायत भरारी, ग्राम पंचायत धनगंवा, ग्राम पंचायत कुरकुरदीगेरा में जहां पर हाई स्कूल है, लेकिन इनका हायर सेकेण्डरी में उन्नयन होना अति आवश्यक है। इसमें एक भी स्कूल के उन्नयन के प्रावधान होने का उल्लेख नहीं है। जो भौगोलिक दृष्टि से बच्चे कहीं दूर भी होते हैं और आजकल जहां कहीं पर भी आप लोग शराब की दुकानें खोल रहे हैं तो इसलिए बच्चियां, बेटियां दूर स्कूल नहीं जा पातीं। इसलिए वहां पर हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन होना, नितांत आवश्यक है, लेकिन इस सरकार में एक भी जगह स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जबकि यहां पर नये स्कूल खोलने का उल्लेख होना चाहिए। इस प्रदेश में चाहे आपकी सरकार रही हो या हमारी सरकार रही हो। यहां स्कूलों का उन्नयन होता है, प्रायमरी से मिडिल, मिडिल से हाईस्कूल और हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन होता है, लेकिन इस सरकार की सोच, विचार अच्छे नहीं है कि इस प्रदेश के बच्चे पढ़े और आगे बढ़ें। इसलिए मैं यह चाहूंगा। इसके साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम स्वामी आत्मानंद स्कूल है इसमें निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ी भाषा में जो पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। यह निर्धारित होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूँ। मैं हमारे अजय चन्द्राकर जी को पीछे भी देख लेता हूँ।

सभापति महोदय :- आपको उनका संरक्षण है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर इन्होंने 19 भाषाओं की बात की है और इनको 5 भाषाओं की भी जानकारी नहीं है। आपको छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में बोलना था कि यहां इंग्लिश मीडियम स्वामी आत्मानंद स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई हो। हम जो अरपा, पैरी मैया की छत्तीसगढ़ी में स्तुति करते हैं और जो अन्य राज्यों में वह लोग अपनी भाषा को समझते हैं कि यह

हमारा मूल अधिकार है, जिस पर उनको गर्व होता है। हमें भी हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा पर गर्व है। निश्चित तौर पर इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये। यहां पर इंग्लिश मीडियम स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी इसे अनिवार्य रूप से शामिल किया जाये। हमारे मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत स्कूल सामुदायिक भवन, पंचायत भवनों और अन्य जगहों में संचालित हैं। वहां के स्कूल अत्यंत जर्जर और खण्डर स्थिति में हैं। इसमें जर्जर भवन की जगह नवीन भवन बनाने का उल्लेख नहीं है। इसलिए मैं आपकी इन अनुदान मांगों के विरोध में खड़ा हुआ हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तें कई बार बोलत हस कि में खड़े हो तो तोला कोन बोलत हे कि तें बईठे हस कहिके। तें तो खड़ेच हस।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है ?

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

वित्तीय वर्ष 2025 - 2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। यहां कहीं पर स्कूल है तो वहां पर शिक्षक नहीं हैं और जहां पर शिक्षक हैं वहां पर स्कूल भवन नहीं है। वहां सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे स्कूल, संस्था चल रहा है। अब जैसे किसी स्कूल में 100 बच्चे है। आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 23 विभाग हैं, आप संख्या पढेंगे तो 20 निकलेगी। आप स्कूल से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- मेरी स्कूल में इसलिए प्राथमिकता है कि डॉ. भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का कहना है कि शिक्षित बनोगे तभी सब ठीक होगा, अन्यथा नहीं होगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भैया, 23 विभाग ला रखै बर कौन कहिस हे, मंत्री ला बना दो न। दो झन ला बांट डालो। 6-6 विभाग बांट दो, 12 ठन विभाग ऐसे ही कम हो जाही।

सभापति महोदय :- निषाद जी, आप काफी लंबा बोले हैं। आप बैठिये। लहरिया जी, थोड़ा सा संक्षेप करेंगे, 12 मिनट से ज्यादा हो गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- थोड़ा बहुत मन मा वोहां भी गोठिया ना यार।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमारे भांजा की रणनीति है।

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिए न, उनका समय खराब हो रहा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं। चूंकि शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण विभाग है। इस सरकार में शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा अव्यवस्था है। हमारे सदस्य ध्यानाकर्षित करा रहे हैं तो आप सदन का ध्यान बांटने के लिए ऐसा मत कीजिए न।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह उच्च शिक्षा में नहीं बोल रहे हैं, वह जब से बोल रहे हैं स्कूल शिक्षा में अटके हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- मैं उसी में फिर से आ रहा हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उन्होंने अभी तक जो बात बोले हैं, एक बात गलत बोले हैं तो आप बता दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, द्वारिकाधीश जी पूरे यंग दिख रहे हैं, पेंट, शर्ट में आये हैं।

सभापति महोदय :- लहरिया जी, संक्षेप करिये।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं कविता पढ़ रहा हूं-

हर किसी को अपने ज्ञान का अभिमान होता है,

असली ज्ञान वह नहीं, जिसे अपने अभिमान का ज्ञान होता है।

वह ज्ञान नहीं है जिसे अभिमान का ज्ञान हो। यदि एक शिक्षक के भरोसे संस्था चले।

श्री धर्मजीत सिंह :- तोर समय पूरा मिलही। सभाति महोदय, ये बहुत ही अच्छे कवि, गायक, कलाकार भी हैं। जब इनके आगे में डांस होते रहता है तो यह एक बहुत बढ़िया गाना गाते हैं- "कटनी का चूना है, सोच-समझकर छूना है।"

श्री दिलीप लहरिया :- सर, अब मैं उसको होली में सुना चुका हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ के एकमात्र कलाकार रहे हैं जिनके कार्यक्रम में दंगा होता है। इनके कार्यक्रम में मारपीट, लड़ाई, झगड़ा सब कुछ होता है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी, उनकी गाड़ी भी हमेशा मंच से लगी हुई तैयार रहती है।

सभापति महोदय :- अनुज जी, आप बैठिये।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, वह दौर समाप्त हो चुका है। यह लोग मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक समय था, वो दौर था। बच्चों का समय अंधकारमय है इसलिए मैं चाहता हूं कि जो शिक्षकों की कमी है, रिक्त पद हैं, शासकीय स्कूलों में शिक्षकों के 56,601 रिक्त पद हैं, आप लोगों ने 70,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था और आप ही की सरकार के एक मंत्री जिनको आप लोग बाहर भेज दिये, उन्होंने 33,000 शिक्षकों की भर्ती का एलान भी किया था। लेकिन आज तक इन

शिक्षकों की भर्ती करने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादाखिलाफी का काम की है, जनता को धोखा देने का काम किये हैं, शिक्षकों, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का काम किये हैं। यह गलत रणनीति है। शिक्षकों की भर्ती कब तक होनी चाहिए, इसके निश्चित निराकरण के लिए एक समय सीमा तय होनी चाहिए। आज 100, 200 बच्चे हैं और मात्र एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 56,101 शिक्षकों के रिक्त पद में जल्दी से भर्ती की जाये। प्रदेश में बेरोजगार डी.एड., बी.एड. डिग्रीधारी युवाओं के लिए भी एक निश्चित जगह बनाई जाये जिससे वह वंचित हो चुके हैं।

सभापति महोदय :- लहरिया जी, समाप्त करिये। आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात जल्दी-जल्दी बोलना चाहता हूं। इसी में मैं और बोलना चाहता हूं कि जो 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारी 14-15 वर्षों से कार्यरत हैं और इनके कार्य करने का समय 02 घंटे निर्धारित है। लेकिन इन सफाई कर्मचारियों से स्कूल में पूरे समय कार्य लिया जाता है और इनका 3 हजार रुपये प्रति महीने मानदेय है। इनके मानदेय को भी बढ़ाने का उल्लेख आपके द्वारा नहीं किया गया है। जबकि सफाई कर्मचारी के भरोसे में बच्चों को छोड़ दिया जाता है, चूंकि शिक्षकों की कमी है । माननीय सभापति महोदय, मोदी जी की गारंटी में जो 50 प्रतिशत राशि वृद्धि किये जाने की घोषणा की गयी थी यह कब तक पूरा होगा ? यह सरकार में निश्चित होना चाहिए । माननीय सभापति महोदय, जो 2900 बी.एड. डिग्रीधारी सहायक शिक्षक हैं, जिनका समायोजन करने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यह गलत नीति है । हमारे बी.एड. डिग्रीधारी जो सहायक शिक्षक हैं, उन साथियों के साथ अन्याय हो रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं उच्च शिक्षा में आ रहा हूं जिसमें जो छत्तीसगढ़ी भाषा में रूचि रखते हैं । हमारे प्रदेश के युवा जो छत्तीसगढ़ी भाषा में रूचि रखते हैं, छत्तीसगढ़ी में दक्षता हासिल करना चाहते हैं उनके लिये छत्तीसगढ़ी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई की व्यवस्था बनायी गयी है । वर्ष 2013 से एम.ए. छत्तीसगढ़ी का पाठ्यक्रम खोला गया था ताकि छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति शिक्षा जगत में स्थापित हो सके लेकिन जिसके लिये हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब ने अनिवार्य भी किया था और आज सरकार में इसके लिये किसी प्रकार की रोजगार की व्यवस्था नहीं की गयी है । जबकि छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारे जो मास्टर डिग्रीधारी युवक हैं इनके लिये कहीं भी नौकरी का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके लिये व्यवस्था नहीं की गयी है । पिछले उसमें हमारी घोषणा भी हुई थी लेकिन आप लोग उसमें कोई पहल नहीं कर पा रहे हैं ।

सभापति महोदय :- लहरिया जी समाप्त करिये । मैं दूसरे को अवसर दूंगा, आप दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा । मेरा पूरा समय तो चंद्राकर जी ने ले लिया इसलिये मैं थोड़ा सा और बोलना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं । अभी और बहुत सारे वक्ता हैं ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, नवीन महाविद्यालय । मैं अब संक्षिप्त कर रहा हूं कि हमारे मस्तूरी क्षेत्र में चूंकि एक सोनसोनसरी में नवीन महाविद्यालय खोला जाये और एक सीपत बेल्ट में जेवरा में नवीन महाविद्यालय भौगोलिक दृष्टि से भी अतिआवश्यक है लेकिन आपके इस अनुदान मांग में मस्तूरी क्षेत्र के लिये नवीन महाविद्यालय खोलने के लिये प्रावधान नहीं है । जो पर्यटक स्थल है जिसमें हमारे मस्तूरी क्षेत्र में दो बड़ी जगह हैं एक लुतराशरीफ और एक मल्हार है और एक खोंदरा है । इनको कहीं भी विकसित करने का और इनको आगे बढ़ाने संबंधी कोई प्रावधान आपके इसमें नहीं है इसलिये मैं इसके विरोध में खड़ा हुआ हूं । माननी सभापति महोदय, हमारे मल्हार, लुतरा और खोंदरा को पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जाये और जिसमें कुटेलाधाम है और इटवापाली को भी पर्यटक स्थल बनाया जाये । माननीय सभापति महोदय, इस समय हमारे क्षेत्र में एक गंभीर विषय है, वह पूरे प्रदेश में है, यह ओवरलोडिंग का विषय है । ओवरलोडिंग के माध्यम से सीपत एन.टी.पी.सी. में राखड़ परिवहन हर महीने करोड़ों का जहां भ्रष्टाचार भी हो रहा है और लगभग 1500 गाड़ियां चल रही हैं जिसमें 600 गाड़ियां ओवरलोड राखड़ परिवहन प्रतिदिन होता है । 55 टन राखड़ का परिवहन करना, 75 से 80 टन लेकर जा रही है और जिसमें ये लोग क्या करते हैं जो कि बड़े दुख की बात है कि लगातार एक्सीडेंट भी हो रहा है और ट्रक में 2 फीट का अलग से एक बढ़ाकर वे लोग अपने ट्रक में बना लिये हैं और ओवरलोडिंग के चलते एन.टी.पी.सी. के राखड़ की वजह से पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है और लगातार अप्रिय घटनायें हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें । लहरिया जी समाप्त करिये ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट ।

सभापति महोदय :- समाप्त करिये, आपने हाईस्कूल पास करने में बहुत समय लगा दिया ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि सांस्कृतिक कला की बात आ चुकी है और चूंकि मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूं इसलिये हमारे प्रदेश में जो कलाकार हैं, हजारों कलाकार हैं जिनकी अनुशंसा से हम लोग सांस्कृतिक कला का आनंद भी लेते हैं और कार्यक्रम भी होता है । जब कलाकार जाते हैं तभी कार्यक्रम बहुत अच्छे से, मजबूती से संपन्न होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आपकी इस सरकार में किसी भी प्रकार का इन कलाकारों के लिए कोई सिस्टम नहीं है और साल भर हो गए, जो पूर्व में कार्यक्रम किये थे, अभी तक इनका कोई पेमेंट भी नहीं हुआ है। लाखों हजारों कलाकार भटक रहे हैं, जिनका प्रोग्राम देने के बाद आज तक इनका पेमेंट नहीं हुआ है। मैं अभी एक ताजा घटना बता रहा हूं। मल्हार महोत्सव का 5 लाख रूपये था। आप ही की सरकार ने उधर बिलासपुर जाकर अभी

घोषणा की है कि मल्हार महोत्सव के लिए 5 लाख रूपये को बढ़ाकर 20 लाख रूपये दिया जायेगा। उस समय क्षेत्र में बहुत खुशी हुई कि बढ़ाए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तो 4 दिन बचे हैं। आखिर आपको महोत्सव को करने से किसने रोका? कौन रोका? वह रुक गया। अब वह पैसा लैप्स हो जाएगा। आप इस प्रकार का जनता के साथ असत्य वादा कर रहे हैं, [xx] कर रहे हैं। 20 लाख रूपये दिया करके उस दिन पेपर में छप गया। बड़ी-बड़ी फोटो भी छपी तो खुशी हुई, लेकिन कहां चला गया? धरातल में कहां है? इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। कलेक्ट्रेट में पैसा जा चुका है, लेकिन कैसे अनुमति नहीं दी गयी और इस चीज को किसने रोका? आप करवा सकते थे। आप घोषणा किये हैं, आपको 31 मार्च के पहले होना था । ये जो कलाकारों के प्रति आपके मन में जो एक द्वेष है, उनका पेमेंट नहीं होना, उनको पुरस्कृत नहीं करना, हमारे समय में तो जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बघेल साहब जी थे तो रामायण के कार्यक्रम का आयोजन होता था। हमारे बघेल साहब ने कलाकारों को बढ़ावा दिया है। आप लोग भी दीजिए, आप लोगों को कौन रोक रहा है? लेकिन आपके पेमेंट नहीं हो पाना, एक महोत्सव नहीं हो पाना और कलाकारों के प्रति जो आप लोगों की सोच है, अभी मैं देख रहा था कि मोहले जी कुछ बोलने वाले हैं।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, ये छत्तीसगढ़ के कलाकार मन बर नहीं हे। श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और सलमान खान बर एमन करा पैसा हे।

श्री दिलीप लहरिया :- अंत में ये जो अवैध खनन जो हो रहा है। ये चिंता का विषय है, जिसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में अलग से एक माहौल है। आपकी सरकार में लगातार सरकार की संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे हमारे क्षेत्र में कौड़िया है, गतोरा में है, जो चिल्ली मुरूम है, उसका अवैध खनन हो रहा है और अधिकारियों का वहां संरक्षण है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से चले और आपको चलाना चाहिए।

सभापति महोदय :- लहरिया जी, समाप्त करिए। आपके 25 मिनट हो गये। समाप्त करिए। माननीय अनुज शर्मा।

श्री दिलीप लहरिया :- जी-जी, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति जी, बहुत-बहुत आभार। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों के अनुदान मांग संख्या..।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, तुम्हर माइक ला चालू कर लेवव।

श्री अनुज शर्मा :- चालू हे।

श्री रामकुमार यादव :- तुम्हर बंद ही हे। (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- चालू हे, तहूं हा मोला सुने ला बुलात हस।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- बंद हे।

श्री अनुज शर्मा :- चालू हे ग।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, हीरो मन ला लेके ठेठवा देहे। ओ छत्तीसगढ़ के हीरो ला ओती भा.ज.पा. में लेके तुमन जीरो बना देहव।

श्री अनुज शर्मा :- मांग संख्या 1, 2, 7, 12, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 56, 60, 65, 71, 26, 27, 37, 44, 51 और 77 के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए यहां खड़ा हूं। इस बजट में एक बहुत खूबसूरत बात हुई। जब माननीय वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण को पढ़ रहे थे तो जब विभिन्न विभागों के विषय में उन्होंने बात शुरू की तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के इतिहास में ऐसा पहला बजट होगा, जिसमें विभिन्न विभागों की चर्चा में शुरुआत संस्कृति विभाग से हुई होगी। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की पूरे विश्व में पहचान है और इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो शुरुआत की, वह संस्कृति से की, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ की असल पहचान को बजट में इतना महत्व देते हुए उन्होंने वहां से शुरुआत की। माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा विभाग में इस बार बजट में 56.67 करोड़ रूपए आवंटित किये गये हैं । ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सशक्त बनाने में उपयोगी होगा । यह वो राजभाषा आयोग है जिसमें पिछली सरकार पांच सालों में राजभाषा आयोग का अध्यक्ष नहीं बना पाई । पांच सालों में छत्तीसगढ़ी राजभाषा का ख्याल नहीं आया था । पांच साल में किसी एक अच्छे सहित्यकार को, किसी एक गुणी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता। सभापति जी, पूरी दुनिया के जितने विकसित देश हैं चाहे वह चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे रूस हो इन सभी ने एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान अपनी मातृभाषा के जरिये बनाई । उनके लिए अंग्रेजी कोई मजबूरी नहीं रही, इन देशों ने पूरी दुनिया में अपना परचम अपनी मातृभाषा के साथ फ़हराया है । इसी मातृभाषा को प्राथमिकता देते हुए बजट में गोंडी और हल्बी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़, 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है ताकि गोंडी और हल्बी के संरक्षण और संवर्धन के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण शिविर एवं कार्यशालाएं, शब्दकोष, पाण्डुलिपि आलेखों का प्रकाशन आदि किय जा सके । ये हमारे छत्तीसगढ़ की अलग-अलग बोलियों और भाषाओं को बचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक महोदय ।

सभापति महोदय :- आप उनको बोलने दीजिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक सेकेंड ।

सभापति महोदय :- आप हर बार एक सेकेंड करते हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मेरा नाम ही नहीं आया है तो थोड़ा तो बोलने दीजिए।

सभापति महोदय :- आप उनको बोलने दीजिए फिर आप बात करियेगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय विधायक जी, 1 लाख, 60 हजार करोड़ के बजट में केवल 2 करोड़ में गोंडी भाषा से लेकर सारी प्रगति हो जाएगी, सब हो जाएगा, 2 करोड़ में यह हो जाएगा ? आप मंच और सदन में बोलने की भाषा बोल रहे हो, धरातल पर इसका कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, छत्तीसगढ़ के प्रशंसा करत हौ अउ हिंदी मा बोलत हौ । छत्तीसगढ़ी मा गोठियाावव महाराज । छत्तीसगढ़ी के हीरो हव, छत्तीसगढ़ी मा गोठियाावव ।

श्री अनुज शर्मा :- गोठियाहं, गोठियाहूं मोला आथे ।

श्री रामकुमार यादव :- हिंदी के प्रशंसा मत करव, छत्तीसगढ़ी मा गोठियाावव ।

श्री अनुज शर्मा :- तोर कहे ले नइ गोठियाव । इफ़्तदाए इश्क़ है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आगे आगे वही होगा, नकल मारके पास होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में ज़ीरो होंगे, कुछ काम नहीं होगा ।

श्री अनुज शर्मा :- धीर मा खीर हे । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार भारत भवन का निर्माण करने जा रही है । मेरे एक साथी माननीय विधायक जी कह रहे थे कि भारत भवन की मांग होनी चाहिए, शायद उन्होंने बजट को ठीक से पढ़ा नहीं । उनकी जानकारी को दुरूस्त करते हुए मैं बता दूं कि प्रदेश में कलाकारों को एक मंच दिलाने के लिए संस्कृति एवं ललित कलाओं के विकास को गति देने के लिए सरकार भारत भवन का निर्माण करेगी । यह कलाकारों की बहुप्रतीक्षित मांग थी कि एक ऐसा संस्थान हो, जहां विभिन्न कलाओं के लोग, जो कलाकार हैं, चाहे वह फ़ाइन आर्ट के हों, चाहे नृत्य के हों, संगीत के हों, ड्रामा के हों ऐसे कलाकारों को एक ऐसा केन्द्र मिना चाहिए जहां उनकी कला का संवर्धन हो सके, जहां उनका प्रशिक्षण हो सके, जहां उनका प्रदर्शन हो सके । ऐसे भारत भवन का निर्माण हमारी सरकार करने जा रही है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत् करता हूं, उनका वंदन करता हूं । सम्माननीय सभापति जी, छत्तीगढ़ की कुज़ीन की अलग पहचान है इसलिए समस्त जिलों में और पर्यटन स्थलों में गढ़ कलेवा की स्थापना की घोषणा की गई है । न सिर्फ छत्तीसगढ़ के खान-पान को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास है बल्कि इससे रोज़गार का भी सृजन होगा, नए लोगों को रोज़गार का अवसर प्राप्त होगा । सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, आज का दौर है और भविष्य में आज के दौर को कैसे याद किया जाए इसके लिए इतिहास लिखा जाता है । इसलिए संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा के अंतर्गत गजेटियरों का लेखन कार्य प्रकाशन और डिजीटलाईजेशन किया जाएगा। इसका मतलब अभी जो बातें हो रही हैं, आज के सामाजिक परिवेश को आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार करने की पूरी जवाबदारी से काम करने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठा

रखा है। मैं इसके लिए भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बस्तर दशहरा दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला उत्सव है, उसके लिए 40 लाख रूपए का बजट स्वीकृत किया गया है। पर्यटन के इस वैश्विक मानचित्र में बस्तर का दशहरा अपनी अलग पहचान बना रहा है। सन् 1965 में पहली फिल्म कही देबे संदेश आई थी और सन् 1970 में दूसरी फिल्म घर द्वार आई थी। इन फिल्मों में मोहम्मद रफी, मीनू पुरूषोत्तम, महंत कपूर, मन्ना डे जैसे बड़े-बड़े कलाकारों ने काम किया था और उन्होंने अपनी आवाज दी थी। उसके बाद सन् 2000 में फिल्म मोर छईहां भुंईया के साथ फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ, एक बहुत बड़ा वर्ग सिनेमा के रोजगार से जुड़ा। हम फिल्म वाले हैं, क्योंकि मैं फिल्म फर्टिलिटी से भी आता हूं, हम बहुत दिनों से ये मांग कर रहे थे कि एक फिल्म सिटी का निर्माण हो, इस मांग को पूरा करने का काम विष्णुदेव साय जी की साय-साय सरकार ने किया है और जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। (मेजों की थपथपाहट) मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पहले जो लोक कलाकार हुआ करते थे, जब वे अपने कार्यक्रमों से रिटायर हुआ करते थे, उनके लिए उचित पेंशन की योजना नहीं थी।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, एक मिनट। अनुज जी, फिल्म सिटी की पहली फिल्म आप ही बनाओगे न ?

श्री अनुज शर्मा :- जी।

श्री राजेश मूणत :- इस हाउस में कुछ कलाकार लोग हैं। आप उनको कौन-कौन सा किरदार दोगे बता दीजिए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- हमर पास भी कलाकार हे, ऐला लेना हे।

श्री राजेश मूणत :- खुशवंत सिंह जी हीरो बन सकते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- उसमें विलेन का रोल कौन होगा, मैं उसको जानता हूं। (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- रामकुमार यादव जी होंगे।

श्री राजेश मूणत :- दादा कोटके की जगह है।

श्री रामकुमार यादव :- राजेश अग्रवाल जी, आप उसमें क्या रोल करोगे। आलू गुंडा का रोल करोगे। (हंसी)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- ये ठगवा फिल्म 2019 में फिर रिलीज होए रिहिस का। ओमन ओखर बारे में ज्यादा जानथे।

श्री अनुज शर्मा :- जी-जी। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों की पेंशन की राशि बढ़ाने का काम किया है। एक समय था, मैं एक कलाकार होने के नाते बहुत दुख के साथ यह बात कह रहा हूं, 15 सालों तक सम्माननीय डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी लेकिन कभी किसी कलाकार के साथ पार्टीगत दृष्टिकोण से भेदभाव नहीं किया गया। मैं बहुत दुख के साथ बहुत भारी मन

से कह रहा हूं, पिछली सरकार ने कलाकारों को छांटने, बांटने और निमारने का काम किया था और कलाकारों को बांटने का जो कुत्सित प्रयास किया था, अब उससे हमारी सरकार आगे चलेगी और सभी कलाकारों के लिए नये ग्रेडेशन पॉलिसी लाएगी और ऐसे दो सदस्य जो कला के विशेषज्ञ होंगे, उनको ग्रेडेशन समिति में सदस्य बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है ताकि किसी भी कलाकार के साथ भेदभाव न हो सके। उनका जो मानदेय है, उसमें कोई भेदभाव न हो सके, इसके लिए निष्पक्ष तरीके से एक कमेटी का गठन किया है और उसमें दो ऐसे विषय विशेषज्ञ लोग होंगे जो कलाकारों का ग्रेडेशन करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- अनुज जी, ये घोषणा विधान सभा में की थी ?

श्री अनुज शर्मा :- नहीं-नहीं, मैं बता देता हूं।

श्री उमेश पटेल :- मैं इसलिए बोल रहा हूं कि विधान सभा में ट्रेजरी बेंच कुछ और ही घोषणा करता है और बाहर जाकर कुछ और कर देता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, बालीवुड में ही कम्प्लेन हुआ था और दूसरी जगह कोई भेदभाव नहीं हुआ था।

श्री अनुज शर्मा :- मैं आपको जवाब दे रहा हूं।

सभापति महोदय :- संगीता जी, उनको बोलने दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ी में एक कहावत हे, एक हाथ खीरा के 12 हाथ बीज। अउ वइसने लमा लमा के गोठयात हो।

श्री अनुज शर्मा :- हव ठीक हे। अउ तैं लमा-लमा के खींच। (हंसी) अब मोर बात ला सुन ले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो अशासकीय सदस्यों को ग्रेडेशन कमेटी में जोड़ने की घोषणा राज्योत्सव में की थी। अब उसको हमारी सरकार लागू करेगी, नया ग्रेडेशन होगा ताकि किसी भी कलाकार के साथ अन्याय न हो सके।

श्री उमेश पटेल :- क्योंकि इनका घोषणा वाला ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- भाई, राज्योत्सव में कौन आवत हे, तेला पहली ले बता दे रहा।

श्री अनुज शर्मा :- मैं बता देहूं। माननीय सभापति महोदय...।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन अइसने गोठयाहू त कइसे बनही, मैं हमर धान ला बेच के तोर फिलिम ला देखे रेहेव। मैं ओला वापस लेहुं। मैं ओला नहीं जानो। मैं तोला हीरो ए करके बने जाने रहे हव। जब ले आप भाजपा में गेहो, तब ले मोदी के गोठ ला गोठियात हो।

श्री अनुज शर्मा :- मैं कहे हव न कि धीर ला खीर मिलही। ते धीर रख भैया।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बार-बार अनावश्यक रूप से डिसटर्ब न करें। (व्यवधान)

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अब मोला समझ में अइस कि ऐखर बिहाव काबर नहीं होए। ए अतका कोचकोचहा हे ता ऐखर से कोन बिहाव करही। (हंसी) ए हा कखरो बात ला सुनबे नहीं करे। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- ते सही नहीं जानत हस। ओखर बिहाव नहीं होए के कारण अलग हे। तै मोला अलग से मिलबे, तब मैं तोला बताहुं। (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- ठीक है।

श्री रामकुमार यादव :- आपमन दू-दू ठन बिहाव करे हव, तेखर का कारण हे?

सभापति महोदय :- अनुज जी, आप अपनी बात कहिये। ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री अनुज शर्मा :- जी। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने एक पवित्र योजना को बंद करने का पाप किया था। तीर्थ यात्रा योजना को बंद करने का पाप पिछली सरकार ने किया था और जिसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ा और छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको सरकार से बेदखल करने का काम किया। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने तीर्थयात्रा योजना को फिर से शुरू करने का पुण्य का काम किया है। ऐसी सरकार और ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने तीर्थयात्रा योजना को फिर से प्रारंभ करने का काम किया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, पाप शब्द को विलोपित किया जाये। आप गलत शब्दों का चयन कर रहे हैं। हमने कोई पाप नहीं किया है। कई योजनाओं को आपने भी बंद किया है तो क्या आपने भी पाप किया है ? आप सही शब्द का चयन कीजिए। आप अभिनंदन कीजिए। आप सही हैं, लेकिन आप इस शब्द का उपयोग मत कीजिए। आपने भी कई योजनाओं को बंद कर दिया है। क्या आपने स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करके पाप नहीं किया? आपने स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद किया है तो आपने कौन सा पाप किया है? आपने महापाप किया है। उस स्कूल में गरीब के बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते थे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप भी पाप कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आपने उस स्कूल को बंद करके महापाप किया है और बच्चों के साथ अन्याय किया है। (व्यवधान)

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस योजना के अंतर्गत ढाई लाख से अधिक हितग्राही थे। उसके द्वारा उन्होंने हरिद्वार, पुरी, द्वारिकाधीश, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, सबरीमाला, वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर इत्यादि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की यात्रा की थी। पिछले बजट में इस योजना को पुन: प्रारंभ किया गया था और इस बजट में इसके लिए 15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, अनुज जी, एक मिनट। क्या है कि बैठेंगे तो बोलेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, वह आपकी भी नहीं सुन रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, एक साथ 3-4 लोग खड़े होते हैं तो यह कैसे बोलेंगे ?

सभापति महोदय :- अनुज जी बोल रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- आप असली हीरो हरो या नकली हीरो हरो, तेखर आज परीक्षा हे। ओ फिलिम में तो अइसे करके कई झन ला मारे रहे हव, लेकिन ए हा रियल हे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है तो क्या इन्होंने पाप नहीं किया है ? क्या आपको आपकी पत्नी श्राप नहीं देती होगी ? (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- ओ 3 ठन राखकर के ते पुण्य करे हस का ? (हंसी)

सभापति महोदय :- मोहले जी, आप बैठिये।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, का हे कि जब हमर गांव में गम्मत होथे न तो जोक्कर हा बीच-बीच में कभू भी बुलक देथे तो ओखर बर दूध-भात हे। माननीय सभापति महोदय, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का महत्वपूर्ण काम किया है और उसका आप नतीजा देखिये कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में छत्तीसगढ़ का घुड़मारास गांव श्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जगह बना रहा है। उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। कांगेर घाटी भी उसमें जल्दी से शामिल हो जायेगा। उसके संकेत मिल रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर मड़ई, बस्तर मैराथान, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आयोजित होने वाले मड़ई, मेले के लिए भी इस बजट में 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय :- अनुप जी, आप संक्षेप करियेगा। 15 मिनट हो गये हैं।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय,

अभी तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी,

लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे

और ये भी पूछेंगे कि तुम इतने हैरान क्यों हो, तनहा क्यों हो।

माननीय सभापति महोदय, यह छत्तीसगढ़ के भाचा राम की धरती है। राम लला दर्शन योजना के अंतर्गत अभी तक 26 स्पेशल ट्रेनों से 22 हजार छत्तीसगढ़ निवासियों ने रामलला के दर्शन किये हैं। यह पुण्य का हिस्सा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। उनको हर दर्शनार्थी का आशीर्वाद मिलेगा, जिन्होंने इतनी पवित्र योजना की शुरूआत की है। इस योजना के लिए बजट में 36 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह हमारी सरकार के सनातन एवं भारतीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का बेहतरीन उदाहरण है। मैं छत्तीसगढ़ के समृद्ध इतिहास की बात करूं तो जब बख्तियार खिल्जी ने

नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगाई थी तो वह आग 3 महीने तक जल रही थी। उसमें से कुछ किताबों को बचाने का काम जिसने किया था, वह हेनसांग सिरपुर (श्रीपुर) के वैभव को देखकर अचंभित रह गया था। श्रीपुर जो जैन, शैव और बौद्ध इन तीनों धर्मों का एक बड़ा केन्द्र है, वहां एक बेहतरीन काम करने का प्रयास हमारी सरकार करने वाली है और वहां के पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षण देने का काम करने वाली है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक और विषय में कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में फिल्मी पर्यटन चल रहा था। बहुत सारी भाषा की फिल्में ऐसी रहीं हैं, जो छत्तीसगढ़ में बनती रहीं हैं। जिनमें से ऑस्कर के लिए नामिनेटेड फिल्म न्यूटन भी एक है। इन सब फिल्मों का निर्माण छत्तीसगढ़ की धरा पर हुआ है। उनके लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम हमारी सरकार करने जा रही है।

समय
6.01 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, मैं, आपका एक और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि डोंगरगढ़ में परिक्रमा पथ के लिए 59 करोड़ रूपए और बम्लेश्वरी मंदिर के सामने Y शेप पुल 21 करोड़ हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है। मैं इसके लिए भी अभिनंदन करता हूं कि यह एक बड़ी आस्था का केन्द्र है। माता बम्लेश्वरी का दरबार, वहां न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश के हजारों-लाखों श्रद्धालु आते हैं। वहां हमारी सरकार एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है। धार्मिक न्यास के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 49.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है और यह पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार एक और महत्वपूर्ण योजना शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों के लिए इस वर्ष बजट में 5 करोड़ रूपए की एक नई योजना छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना प्रारंभ की जा रही है। सरकार अन्य राज्यों में भूमि क्रय करेगी। जो धार्मिक श्रद्धालु तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं, हमारी सरकार उनके लिए धर्मशाला की व्यवस्था कर सके, उनके रूकने-खाने की व्यवस्था कर सके, इसके लिए हमारी सरकार चिंतित है। उसके लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस बार पूरे महाकुंभ छत्तीसगढ़ राज्य का पैवेलियन बना था वहां सवा लाख लोगों ने भोजन और विश्राम किया है। उन सभी का पुण्य छत्तीसगढ़ की सरकार को मिला है। कहीं न कहीं इस बात की चिंता हमारी सरकार ने की है। राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा विभाग के विषय में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। स्कूली शिक्षा को दुरूस्त और मजबूत करने के लिए बजट में 22,473 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। हम स्कूली शिक्षा के अधोसंरचना को मजबूत कर रहे हैं और गुणवत्ता भी ध्यान दे रहे हैं।

इसके लिए वर्ष 2024-25 के बजट में भी 21,603.96 करोड़ रूपए का प्रावधान था। इस साल इसको बढ़ाया गया है। जिसमें 4.02 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बच्चों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने के लिए 144.5 करोड़ रूपए, छात्रवृत्ति के लिए 248.05 करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के लिए 690 करोड़ 70 लाख रूपए, नि:शुल्क साइकल प्रदाय करने के लिए 50 करोड़, नि:गणवेश प्रदान करने के लिए 65 करोड़ रूपए, अशासकीय शालाओं में शिक्षण के लिए 121.20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। यह सारा प्रावधान कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए किया गया है।

श्री राम कुमार यादव :- दारू भट्ठी कै ठो खोला था महाराज ?

सभापति महोदय :- राम कुमार जी, बैठिये। बोलने दीजिये न। आप थोड़ा संक्षिप्त कर लीजिये।

श्री अनुज शर्मा :- जी। माननीय सभपति महोदय, मैं संक्षिप्त कर देता हूं। माननीय सभापति महोदय, बोलने के लिए बहुत सारा विषय है।

सभापति महोदय :- नहीं, आपसे से सहयोग चाहिए, दोनों तरफ से बहुत से वक्ता हैं। आप कृपा करके सहयोग करिये।

श्री अनुज शर्मा :- जी। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी कुछ विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। पहली बात यह कि छत्तीसगढ़ सरकार ने फिल्म पॉलिसी लाई है। इस पॉलिसी को लागू करने, उसको मूर्त रूप देने का, उसको जमीन में उतारने का समय है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि अब फिल्म पॉलिसी को छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए, उस पर कार्य किया जाए, उसमें जमीनी स्तर पर काम दिखे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और उन्होंने इस पर घोषणा भी कर दी है कि कलाकारों का फिर से ग्रेडेशन किया जायेगा। मेरा एक और आग्रह है कि यहां जो स्थानीय कलाकार हैं, उनके भुगतान का भी वही सिस्टम बनाया जाये जो बाहर से आने वाले कलाकारों को जिस तरह से भुगतान किया जाता है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ स्थानीय कलाकारों के भुगतान की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में बोहरहीधाम एक पर्यटन स्थल है। उसके विकास के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां पर कोई एक बड़ी योजना लेकर आये, वहां बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ ग्राम बेन्दरी के शासकीय प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन करने के लिए और ग्राम ताड़ा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन कार्य के लिए और वैसे ही ग्राम धनेली में माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन कार्य के लिए, ग्राम कुम्हारी में शासकीय हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन कार्य, ग्राम कुकेरा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन कार्य, ग्राम पड़रभट्ठा में शासकीय हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन कार्य, ग्राम परसतराई में शासकीय प्राथमिक शाला भांठापारा का पूर्व

माध्यमिक शाला में उन्नयन कार्य, नवीन महाविद्यालय स्थापना कार्य सिलयारी, सद्गुरू कबीर मोनी बाबा वात्सल्य धाम ग्राम माठ के परिसर में अहाता एवं मंगल निर्माण कार्य, माठ शासकीय महाविद्यालय, खरोरा में मैदान समतलीकरण का कार्य हैं। माननीय सभापति महोदय, कुछ और बातें हैं, मैं थोड़ा समय लूंगा। एक महत्वपूर्ण विषय है कि जिस ग्राम बरौदा में विधान सभा परिसर है। शासकीय हाई स्कूल बरौदा में अहाता निर्माण हेतु विगत सत्र में मैंने याचिका प्रस्तुत किया था। शाला अवधि के पश्चात् वहां हमेशा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। अत: मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस बजट में उक्त कार्य को भी सम्मिलित करने का कष्ट करेंगे। सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं इन सभी मांगों को समर्थन करते हुए बस यही कहूंगा कि -

पीछे मत देख, न शामिल हो गुनहगारों में।
सामने देख कि मंजिल है तेरी तारों पे।
बात बनती है अगर दिल में इरादें हो अटल।
चल मेरी साथी चल, चल मेरी साथी चल। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्रीमती अंबिका मरकाम।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों की अनुदान मांग संख्या 1, 2, 7, 12, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 56, 60, 65, 71, 26, 27, 37, 44, 51 एवं 77 के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री का सुशासन, श्री विष्णु देव साय का सुशासन के सामान्य प्रशासन विभाग के बारे में बोलना चाहती हूं। अभी प्रदेश में जो सरकार चल रही है, वह संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भरोसे चल रही है। आप न नियुक्ति कर पा रहे हैं, न अभी नई नियुक्तियां नहीं हो रही है। जब कोई संविदा कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, उन लोगों को पुन: संविदा में नियुक्ति की जाती है, जिसके नये लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही है। जब नये लोगों की भर्ती नहीं होगी तो संविदा के भरोसे ही सरकार चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। आज बैकलॉक पदों की भर्ती नहीं हो पा रही है। एस.सी. व एस.टी. लोगों के लिए जो बैकलॉग पद होता था, उसकी भर्ती बंद है। कर्मचारियों का प्रमोशन भी बंद है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आज बहुत दिनों से उनका प्रमोशन रूका हुआ है। जिनको अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलेगा और वे रिटायर हो जायेंगे, उससे अधिकारी-कर्मचारियों को नुकसान है। इस ओर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। मैं खनिज विभाग के बारे में बोलना चाहती हूं। हमारे और भी सदस्यों ने इस विभाग में बहुत बोला है। निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश नदी-नालों से घिरा हुआ है। यहां प्राकृतिक चीजों का दोहन हो रहा है, रेता का उत्खनन हो रहा है, गिट्टी का उत्खनन हो रहा है। रेत के उत्खनन से पूरी नदियों की सुंदरता समाप्त होती जा रही है। वहां रेत उत्खनन कर हजारों गाड़ियां निकल रही हैं और वह दूसरे प्रदेश

को स्थानांतरित हो रही है, इससे पूरी नदियों की सुंदरता समाप्त हो जा रही है। पहले निदयों में झरिया खोद कर पानी निकाला जाता था, लेकिन आज नदी से रेतों का इतना अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है कि रेत तो समाप्त हो गया है, अब वहां मिट्टी ही नजर आ रही है। इस तरह से नदियों की स्थिति हो गई है। हमारा क्षेत्र जंगल, झाड़ी का क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र बांधों से घिरा हुआ है। बांध के किनारे में जो पहाड़ हैं, उसको तोड़ कर ठेकेदारों द्वारा गिट्टी की सप्लाई की जा रही है। वहांपर बांध असुरक्षित सा हो गया है। यह अवैध रूप से उत्खनन पर रोक लगाया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हजारों टन गिट्टियां निकल जा रही है, जंगल कट जा रहे हैं, जंगल के अंदर से सड़क बना दिया जा रहा है, यह बहुत चिंता का विषय है । हम यदि उसे नहीं रोकते हैं तो पर्यावरण भी दूषित होगा, उसका दोहन ज्यादा होगा, नदी-नाले समाप्त हो जायेंगे, हमारे क्षेत्र में जो बांध है, जिस बांध से पूरे प्रदेश को सिंचाई मिलता है, उस बांध को नुकसान होगा । सभापति महोदय, मैं दुधावा बांध का बताना चाहती हूँ कि वह पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसके किनारे में गिट्टी का उत्खनन हो रहा है, उससे बांध को नुकसान हो रहा है, जहां से भिलाई इस्पॉत संयंत्र को सुविधा मिलती है, इस पर रोक लगाया जाना चाहिये ।सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इतना आगे बढ़ चुका है लेकिन आज भी हम पीछे हैं, जो बी.एस.एन.एल. का टॉवर होता है, वह कई दिनों से बंद पड़ा है । जंगल क्षेत्र में रहने वालों को मोबाईल टॉवर नहीं मिलता है । डबल इंजिन की सरकार है, आपकी सेंट्रल की योजना है, आपको ध्यान देने की जरूरत है, जहां पर अन्य कंपनियां काम कर रही है, वहां पर बी.एस.एन.एल. को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करके जो टॉवर से वंचित हैं, जो मोबाईल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आज इंटरनेट का जमाना है, वहां इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है,इलेक्ट्रानिक सूचना प्रौद्योगिकी है, उसमें इसको लिया जाना चाहिये, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है । सभापति महोदय, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो शिकायत करते हैं कि हमारा टॉवर नहीं चल रहा है, जब इतना टॉवर हो गया है तो क्यों नहीं चल रहा है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है । सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में मुरूमडीह, पालवाड़ी, जंगल क्षेत्र है, जहां से कोई भी टॉवर काम नहीं करता है । वहां पर कई वर्षों से बी.एस.एन.एल. का टॉवर गड़ा हुआ है, मैंने अधिकारियों से बात भी किया, लेकिन वहां पर अभी तक काम चालू नहीं हुआ है । माननीय सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण चीज है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आज खादी ग्रामोद्योग में उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा है, धागे नहीं मिल रहे हैं, हमारे राजेश भईया बोल रहे थे ना कि ड्रेस जो है खादी ग्रामोद्योग से बनाकर चलाया जाता था, लेकिन जब तक आप उसकी व्यवस्था बनायेंगे नहीं तो वह कैसे चलेगा? आज कई समूह के लोग खाली बैठे हैं, बल्कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के समय महिला समूहों को काम मिला था, चाहे वह किसी भी रूप में हो, लेकिन आज महिला समूह के लोग खाली बैठे हैं, सिर्फ महतारी वंदन उनको मिल रहा है, रोजगार से प्रभावित हो रहे हैं । सभापति महोदय, मैं उर्जा के बारे में कहना चाहूँगी कि विद्युत की

सप्लाई बहुत कम हो रही है, विद्युत विभाग के द्वारा लो-वोल्टेज का प्राब्लम बहुत आ रहा है । मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपके कांकेर जिले से विद्युत आता है, धमतरी जिले से आता है, इधर राजिम और कुरूद क्षेत्र से आता है, लो-वोल्टेज की इतनी ज्यादा प्राब्लम है, वहां पर लोगों को वोल्टेज नहीं मिल रहा है, किसानों का धान सूख रहा है, बच्चों के परीक्षा का समय है, उनको पढ़ाई के लिये दिक्कत हो रही है । सभापति महोदय, सौर उर्जा की बात करूँ तो जल जीवन मिशन से कई जगहों पर टंकी बनाया गया है, वहां मोटर को चलाकर टंकी भरकर पानी सप्लाई करना है , लेकिन वहां पर सौर ऊर्जा काम ही नहीं कर रही है । जब सौर ऊर्जा वालों से बात करो तो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है तो इस ओर भी फंड देने की जरूरत है । आखिर विभाग खाली बैठा रहेगा क्या ? जब तक आप विभाग को फंड नहीं देंगे तो वह काम कैसे करेगा । मेरा सिहावा विधान सभा क्षेत्र बहुत घने जंगल क्षेत्र में है, जहां पर आप विद्युत की व्यवस्था नहीं दे सकते क्योंकि वह अभ्यारण्य क्षेत्र है । वहां पर सौर ऊर्जा से ही आप दे पाएंगे तो सौर ऊर्जा को उसको बढ़ाना पड़ेगा ।

सभापति महोदय :- आपको बोलते हुए लगभग साढ़े नौ मिनट हो गए हैं ।

श्रीमती अम्बिका मरकाम :- अभी तो मैंने भाषण शुरू किया है ।

सभापति महोदय :- सबका ख्याल रखना पड़ेगा न ।

श्रीमती अम्बिका मरकाम :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि वहां पर लो वोल्टेज की जो समस्या है, उसको दूर करे और बिजली बिल की जो समस्या है, अभी जो नया डिजीटल मीटर लग रहा है, उसमें इतना अधिक बिजली बिल आ रहा है कि वे लोग पुराने बिजली बिल को नहीं देखते और अटंडम बिजली बिल भेज रहे हैं । ये किस तरह की व्यवस्था है, यह समझ से परे है इसलिए मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहती हूं ।

सभापति महोदय, मैं सौर ऊर्जा के बारे में कह रही थी । मेरा क्षेत्र अभ्यारण्य क्षेत्र है, वहां बिजली नहीं पहुंच पा रही है । वह सौर ऊर्जा से चलता है, लेकिन सौर ऊर्जा बंद पड़ी है । सौर ऊर्जा को चालू किया जाना चाहिए । वहां पूरे आदिवासी रहते हैं, उनको न बिजली मिल रही है, न उनके लिए पुल है, न रास्ते हैं, न किसी तरह की सुविधा है तो उनकी सुविधा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि यदि वहां अभ्यारण्य क्षेत्र है तो कुछ नियमों को शिथिल करके उनके लिए वहां पर काम करना चाहिए । कई जगह पर ट्रांसफार्मर खराब हैं । जहां ट्रांसफार्मर खराब हैं तो उसके लिए भी किसान बार-बार बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर को बदल नहीं पा रहे हैं तो मैं इस ओर आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहती हूं ।

सभापति महोदय, मैं धार्मिक न्यास और पर्यटन के संबंध में बोलना चाहूंगी । मेरा क्षेत्र भी धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और महानदी का उद्गम स्थल है, वहां पर श्रृंगी ऋषि महाराज जी की मूर्ति स्थापित है, जिनके आशीर्वाद से श्री राम जी का जन्म हुआ । उस किनारे में मेला लगता है, जहां

पर बहुत बड़ा पुरातात्विक मंदिर है। जैसे राजिम में है, वैसा मंदिर है । इस ओर भी विकास करने की जरूरत है । वहां पर महानदी का उद्गम स्थल है, महानदी निकली हुई है, वहां पर एनीकट का निर्माण कराया जाना चाहिए । मेरे क्षेत्र में मोहेरा ग्राम है, वहां पर पहाड़ पर निरई माता है, जो कि साल में एक बार ही वहां का मंदिर खुलता है और साल में एक बार वहां हजारों बलि चढ़ती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, अभी शाम को जो नाश्ते की व्यवस्था है, वह कौन से विभाग की ओर से है ।

सभापति महोदय :- मैं पढ़ देता हूं । श्री टंक राम वर्मा, राजस्व मंत्री जी की ओर से...

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, टंक राम वर्मा जी को अभिनंदन पत्र देना है, उनको कैसे दिया जाए ।

सभापति महोदय :- एक मिनट, मैं पूरा पढ़ देता हूं, फिर आप बोलिएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी धीरे-धीरे लग रहा है, लोग लाईन में खड़े हैं। मस्त वाला है, सस्ता वाला । सस्ता, सुन्दर टिकाऊ है ।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- श्री टंक राम वर्मा, राजस्व मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए स्वलपाहार की व्यवस्था लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार स्वलपाहार ग्रहण करें ।

वित्तीय वर्ष 2025 - 2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आसंदी से राजस्व विभाग की प्रशंसा होनी चाहिए । जो व्यवस्था है, वह अत्यधिक शानदार है ।

सभापति महोदय :- अम्बिका जी, अब आप समाप्त करिए क्योंकि अभी 10 सदस्य बाकी हैं ।

श्रीमती अम्बिका मरकाम :- सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है, थोड़ा सा ही बोली हूं ।

सभापति महोदय :- आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गए हैं, यहां टाईम नोट होता है ।

श्रीमती अम्बिका मरकाम :- सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए । मैं पर्यटन के क्षेत्र में कह रही थी, जो कि निरई माता का मंदिर है, जहां साल में एक बार मेला लगता है, वहां पर चैत्र नवरात्रि में जो भी रविवार पहला दिन पड़ता है, उसमें मेला लगता है इसलिए वहां का विकास कराया जाना चाहिए ।

मेरे क्षेत्र में कुकरेल के पास एक नरहरा धाम है, उस नरहरा धाम का विकास होना चाहिए। वहां पर जो सौर उर्जा की लाईट है, वह बंद पड़ी हुई है। वहां पर सौर उर्जा की लाईट को चालू किया जाना चाहिए। वहां पर रोड नहीं है। वहां पर रोड बनना चाहिए और उस नरहरा धान का विकास होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगी। शिक्षा के बारे में हमारे सदस्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं। कक्षा पहली से दसवीं तक छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करने का प्रावधान है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा मनमानी करते हुए प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी के बिना मांग पत्र के, दर्ज संख्या की बिना जानकारी के मांग से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की गईं तथा उसे वितरण नहीं कर थोक के भाव कबाड़ी के पास बिक्री किया गया और बाकी गोदामों में छोड़ दिया गया। इससे शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति हुई है। इसमें जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही होना चाहिए। महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की मांग रखूंगी।

सभापति महोदय :- जरा जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- सभापति महोदय, प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत गिर रहा है। युवाओं का पढ़ाई करने के बावजूद आज की परिस्थिति के अनुरूप उनका डेव्हलपमेंट नहीं हो पा रहा है। जो स्कूल हैं, उनका उन्नयन कराया जाना चाहिए। आप अप्रैल, 2024 हाईस्कूल परीक्षा का रिजल्ट देखिए कि 38405 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं, जिसमें से कुल...।

सभापति महोदय :- अंबिका जी, आप तो सीधे-सीधे मांग पर आ जाईए ना।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- सभापति महोदय, मैं जब से खड़ी हूं, तब से आप मुझे संरक्षण नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत से वक्ता हैं और रात हो जाएगी। आप कृपा करके इतना सहयोग करिए, अपने क्षेत्र की मांग रख लीजिए।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में निम्नलिखित पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में उन्नयन करने की मांग है :- पूर्व माध्यमिक शाला रतावा, पूर्व माध्यमिक शाला कोटरवाही, पूर्व माध्यमिक शाला कपालफोड़ी, पूर्व माध्यमिक शाला खिसोरा, पूर्व माध्यमिक शाला परसट्टी इन सभी का हाईस्कूल में उन्नयन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से हाई स्कूल का हॉयर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु निम्न हैं :- शासकीय हाई स्कूल तुमड़ीबहार, शासकीय हाई स्कूल घटला, शासकीय हाई स्कूल शुक्लाभांठा, शासकीय हाई स्कूल नवागांव, शासकीय हाई स्कूल करइया, शासकीय हाई स्कूल भोथापारा, शासकीय हाई स्कूल उमरगांव, शासकीय हाई स्कूल भैंसामुड़ा। इन मांगों को बजट में सम्मिलित किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के सभी विभागों की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं आज अपनी बात रखना चाहूंगा। गत वर्ष, वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत हुआ था और उसमें भी ऐसी चर्चा हुई थी और बजट के बाद जो कार्य एक साल में हुआ, उसका जनता ने अभिनंदन किया, आशिर्वाद दिया है। चाहे वह लोक सभा चुनाव हो, बीच के चुनाव हों, नगरीय निकाय या पंचायत के चुनाव हों। उस समय भी हमारे विपक्षी साथी बजट का इसी प्रकार से विरोध किए थे लेकिन ये माननीय विष्णु देव साय जी का सुशासन और मोदी जी की गारंटी है कि जो भी बजट में लाते हैं, उसे हम धरातल पर उतारते हैं।

सभापति महोदय, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जो व्यक्ति के जीवन के साथ-साथ उसके सामाजिक, आर्थिक विकास और पूरे देश के सर्वांगीण विकास की दिशा तय करता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा के लिए जो 22473 करोड़ का बजट प्रावधान लाया है, वह राज्य के कुल बजट का 12% है और इसके इर्द-गिर्द किसी भी विभाग का बजट छू तक नहीं पाया है । यह इस बात का द्योतक है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा के प्रति, हमारे बच्चों के भविष्य के प्रति और छत्तीसगढ़ राज्य के भविष्य के प्रति कितने चिंतनशील है। मानीय सभापति महोदय, हमको विभिन्न अवसरों में शालाओं में जाने का अवसर मिलता है, चाहे वह शाला प्रवेश उत्सव का अवसर हो, या फिर वार्षिक उत्सव का अवसर हो। जब इस बार शासकीय स्कूलों में हमारा जाना हुआ तो उन स्कूलों का जो रिर्पोट कार्ड है, वह बहुत ही प्रशंसनीय रहा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हर जगह एक उत्साह का वातावरण बना है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, क्या एक शिक्षकीय शाला में भी प्रसन्नता का विषय है ? हजारों स्कूल ऐस हैं, जो एक शिक्षकीय है और रिकॉर्ड के मुताबिक व्यवस्था में भी एक शिक्षक है। इस प्रदेश में शिक्षकविहीन स्कूल भी हैं। आप एकदम से ऐसे मत बोलिये। आप बच्चों के हित में बोलिये।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री राजेश मूणत :- द्वारिकाधीश भाई, आपकी सरकार में कितनी भर्ती की गयी, यह बता दीजिये ?

सभापति महोदय :- आप बैठिये। मोतीलाल जी, आप बोलिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हमारी सरकार में जितनी भी भर्ती हुई, लेकिन आपकी पार्टी के सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबसे वरिष्ठ नेता जिस शपथ कर रहे थे। उन्होंने उस दिन इस बात की घोषणा की थी कि 36 हजार शिक्षकों की भर्ती की जायेगी। 36 हजार में से एक भी भर्ती हुई होगी तो बता दीजिये ?

सभापति महोदय :- आप इधर मेरी तरफ देखिये। मैं आपसे बोल रहा हूं। बहुत मुश्किल है।

श्री राजेश मूणत :- यदि आपने भर्ती की है तो बता दीजिये ?

सभापति महोदय :- मूणत जी, आप बैठिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपने 36 हजार की घोषणा की थी, उसमें से कितनी भर्ती की, यह बता दीजिये ?

सभापति महोदय :- आप बैठिये। मोतीलाल जी, आप बोलिये।

श्री मोतीलाल साहू :- सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में जो शासकीय स्कूल संचालित हो रहे हैं, यदि माननीय सदस्य चाहे तो मैं उनको अपने साथ ले जाकर उनको मेरी बातों की पुष्टि करा सकता हूं।

सभापति महोदय :- आप उधर मत बोलिये। आप अपनी बात करिये। आप उनको पुष्टि मत कराईये। आप सीधे अपनी बात करिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप मेरे क्षेत्र में साथ में चलियेगा।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं।

श्री मोतीलाल साहू :- सभापति महोदय, ऐसे कई स्कूल हैं, जहां बच्चे बहुत ही प्रतिभावान हैं, जहां बच्चों ने मेरिट में अपना स्थान सुनिश्चित किया है और अन्य गतिविधियों, चाहे वह खेल हो या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अपनी प्रविण्यता को और अपनी दक्षता को साबित किया है।

समय:
6.27 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, यहां ऐसे स्कूल भी हैं, जहां पर प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और जब प्रवेश का समय आया, तो इस बार मेरे पास बहुत से ऐसे पालकों का भी आवेदन आया, जिनका कहना था कि हम स्कूलों में भर्ती तो चाहते हैं परंतु उस स्कूल की सीट, वहां की जो व्यवस्था है, वह पूरी हो जाने के कारण हम बच्चों को प्रवेश नहीं करा पा रहे हैं। आज मेरे क्षेत्र में शासकीय स्कूलों में ऐसी स्थिति भी निर्मित हुई है। निश्चित तौर पर शासकीय स्कूलों के प्रति पालकों का और बच्चों का जो अध्ययन करने की एक इच्छा और आस्था है, वह अब बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि वहां का परिणाम और वहां की पढ़ाई का जो स्तर है, निश्चित तौर पर वह अब ऊपर उठते जा रहा है। केंद्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा में गुणवत्ता के लिये और उसमें सुधार के लिये एन.ए.पी. योजना लायी, नयी शिक्षा प्रणाली की योजना लायी परंतु पिछली सरकार ने उस योजना को यहां छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया, जिससे यहां पर हमारे जो होनहार बच्चे हैं, वह उस योजना का लाभ लेने से वंचित हो गये, जिससे उनको शिक्षा अध्ययन में कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर आयी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां एन.ए.पी. लागू करके फिर से हमारे बच्चों के भविष्य को और हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह अभी कई योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। इन्होंने आपके समय से साईकिल योजना बंद करके रखी थी और फिर से जैसे ही हमारी सरकार आयी

तो हमारी बेटियां जो यातायात की असुविधा के कारण शिक्षा को बंद कर देती थी, फिर से यह साईकिल योजना चालू होने से हमारी बेटियां अब फिर से स्कूल जाने लगी है। उनमें एक नये उत्साह का संचार हुआ है और पालक भी अब अपनी बेटियों को भेजने के लिये उत्साहित रहते हैं। ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एन.ए.पी. के माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं, जो कई बार भाषा के कारण पढ़ने में हिचकते हैं या स्कूल जाने से डरते हैं, उनको स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में पढ़ने के लिये उत्साहित किया गया है कि बच्चे स्कूल आये और अपनी मातृभाषा में पढ़े और उस उम्र में सीखे । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह प्रावधान लाकर बहुत बड़ा उपकार का काम किया है। इस प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में बच्चे हिन्दी भी नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, बोलना नहीं जानते हैं, लेकिन उनको मातृभाषा में पढ़ने का अवसर देकर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विकास का काम किया है, उनके भविष्य को संवारने का काम किया है। हमारे स्कूलों में ऐसे बहुत से कार्यक्रम आयोजित होते हैं। देश के प्रधान मंत्री जी ने जो न्यौता भोज कार्यक्रम हम सबको अपने क्षेत्र के स्कूलों में रखने के लिए कहा कि हम अपने क्षेत्र के स्कूलों जायें, चाहे बड़े व्यापारी, नेता, उद्योगपति जायें। जिस प्रकार से स्कूलों में जाकर अपना और बच्चों का जन्मदिन मानते हैं, उन बच्चों के साथ बैठें, वहां एक पारिवारिक वातावरण बने। उनको भी यह लगे कि हम छोटे और गरीब बच्चे हैं, हम शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे साथ भी कोई नेता, जनप्रतिनिधि बैठकर भोजन करता है, कोई प्रधान पाठक भी उनके साथ बैठता है तो उनको भी एक आत्म स्वाभिमान लगता है। उनकी रूचि बढ़ती है। उनकी स्कूलों के प्रति... ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह इतनी कीमती बात बता रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, कीमती बात हे तो में ओकरे बर कहात हौं कि छत्तीसगढ़ में एक ठन कानून पास कर देवौ। चाहे नेता के लइका रहाए, चाहे वह कलेक्टर एस.पी. के नेता रहाए, चाहे गांव के गड्ढा माटी कोड़ईया के लईका रहाए, सब एक ठन स्कूल में पढ़ही। अइसे शिक्षा व्यवस्था हो ही तो सुधरही।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एन.ई.पी. की व्यवस्था वही है। आप एन.ई.पी. का मतलब समझिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। तें मोला ए बता कि हर बात बर कानून बनाने का? अगर पिता जी के पैर पड़ना हे तो ओकरो बर कानून बनाने का?

श्री रामकुमार यादव :- नहीं। एला बना देवव। नेता के लईका अलग, कलेक्टर के लईका अलग, गड्ढा माटी कोड़ईया के लईका अलग स्कूल में पढ़त हे। अब व्यवस्था ला सुधारबो कहात हौ। वह कहां ले सुधरही।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मोतीलाल साहू जी इतनी बढ़िया बात बोल रहे हैं। आपको उनकी बात सुननी चाहिए। पिता जी के पैर पड़ना है तो कानून बनाओ, हर चीज में कानून नहीं बनता है।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर लईका दिल्ली, मुम्बई अउ कलकत्ता में पढ़य। हमर नेता जी राम विचार नेताम के लईका बम्बई में पढ़ए। आदिवासी के लईका फूटहा स्कूल में पढ़ए।

अध्यक्ष महोदय:- आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। अगर मैं प्रदेश के महाविद्यालयों की बात करूं तो इसके लिए भी बजट में 1 हजार 822 करोड़ रूपये का प्रावधान लाया गया है। इसमें 22 महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 51 करोड़ रूपये का प्रावधान लाया गया है, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के अमलीडीह कॉलेज के लिए दो करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, मैं, उनको उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ। साथ ही साथ इस बजट में मेरे क्षेत्र के दो स्कूलों, हाईस्कूल निर्माण के लिए 75-75 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को पुरैना स्कूल और लाभांडी स्कूल के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ। इस प्रकार से शिक्षा के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के और सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किये जा रहे हैं। शुरूआती दौर में माननीय दलेश्वर साहू जी ने ऊर्जा के विषय में बहुत सारी बातें कह रहे थे। वह एकल बत्ती, हाफ बिजली योजना, पी.एम.सूर्यघर योजना, मजरे टोले की बात कह रहे थे। मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसी भी प्रकार की योजना बंद नहीं की है। प्रदेश की सभी योजनाओं के लिए बजट प्रावधान लाया गया है। इसमें मजरे टोले के लिए भी 50 करोड़ रूपये का प्रावधान है। एकल बत्ती के लिए 30 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ लगभग 16 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को यह सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके लिए 1 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है इसमें उपभोक्ताओं के छूट और हाफ बिजली के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसमें ऊर्जा के लिए भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में 100 प्रतिशत बिजली हो और हर घर में यह सुविधा हो। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधान मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी नियमित रूप से प्रयासरत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हम खनिज के विषय में कहें तो यह रत्नगर्भा धरती जिसे हम छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं। यह रत्नों से भरा-पूरा है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कोयला, लोहा, चूना पत्थर, डोलोमाईट, बॉक्साईट, टीन अयस्क, लिथियम जैसे हीरा, सोना ऐसे बहुमूल्य खनिजों से भरा है। हम सब ऐसी धरती के रहने वाले हैं तो यहां पर भी डी.एम.एफ. के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का हम सब कैसे क्रियान्वयन करेंगे। इसके लिए पिछली सरकार ने बहुत कुछ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया था ..।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय साहू जी, आप संक्षिप्त करिये। आज सी.एम. साहब का जवाब भी आएगा। आपने बहुत अच्छा बोला है। यहां पर आपके सारे बिन्दु आ गये हैं।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ मांगें हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय साहू जी, अपने क्षेत्र की मांग रख दीजिए।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बार बहुत से स्कूलों के उन्नयन के लिए लिखा था कि मेरे क्षेत्र में मिडिल स्कूल का हाई स्कूल और हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जाये। चूंकि यह शहरी क्षेत्र है। मैंने जैसे कहा कि वहां उन स्कूलों में स्ट्रेन्थ बहुत बड़ी संख्या में है। वहां बड़ी संख्या कमें गरीब बेटियां पढ़ती है, वे दूर नहीं जा सकती हैं इसलिए वहां पर स्कूलों का उन्नयन किया जाना आवश्यक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुरैना, लाभांडी, उरकुरा, रावांभाठा, उरला में ऐसे हाईस्कूल हैं, इनको हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाना बहुत अति आवश्यक है। माना कैंप में महाविद्यालय चल रहा है। उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। वहां से बच्चे छोड़ करके दूसरे महाविद्यालय जा रहे हैं क्योंकि वहां भवन नहीं है और अन्य सुविधाओं का अभाव है, इसलिए वहां की स्थिति में सुधार लाने के लिये आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 12, 27, 36, 37 और 44 में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं पर्यटन विभाग से शुरू करती हूं। संस्कृति एवं प्राकृतिक सुंदरता तथा पर्यटन किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण धरोहर एवं उस राज्य की पहचान होती है। पर्यटन से रोजगार भी उपलब्ध होता है और राजस्व की प्राप्ति भी होती है। साथ ही साथ लोगों को मानसिक एवं आध्यात्मिक शांति का भी अनुभव प्राप्त होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं शिवरीनारायण के बारे में बात कर रही हूं। इतने बड़े बजट में शिवरीनारायण का कहीं भी उल्लेख नहीं है जो मेरे विधान सभा में आस्था और पर्यटन का एक बहुत बड़ा केन्द्र है। हमारी सरकार ने शिवरीनारायण को राम वनगमन पथ में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था, क्योंकि वनवास के दौरान श्रीराम जी ने माता शबरी के हाथ से जूठे बेर वहीं खाये हुये थे। प्रत्येक वर्ष माघी पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक 15 दिन तक भव्य ऐतिहासिक मेला का आयोजन शिवरीनारायण मे होता है, वहां पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। शिवरीनारायण में बृहद रूप से व्यापारिक केन्द्र भी विकसित हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूं कि राजिम के लिए सरकार ने जो बजट में प्रावधान रखा है, वही शिवरीनारायण के लिए भी रखे। क्योंकि हमारी सरकार ने शिवरीनारायण मेला के लिये 20 लाख रुपये का बजट रखा था, इस सरकार ने उसको घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। मैं यह मांग करती हूं कि यह ऐतिहासिक जगह को बनारस, उज्जैन जैसे महाकाल की तर्ज शिवरीनारायण में जो नदियों का संगम हैं, उन नदियों के घाट को विकसित किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा विभाग के लिए दो लाईन बोलना चाहती हूं। अप्रत्याशित बिजली कटौती से क्षेत्र में अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण कृषि और औद्योगिक कार्य तो प्रभावित हो ही रहे हैं, लो-वोल्टेज और बार-बार फॉल्ट आने की समस्या से ग्रामीण उपभोक्ता भी परेशान हो रहे हैं। कई गावों में ट्रांसफार्मर क्षमता कम होने के कारण बार-बार फ्यूज उड़ने और बिजली गुल होने की समस्या भी बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि और फॉल्ट में सुधार में तेजी लाई जाये। सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाये ताकि क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से बिजली आपूर्ति में सुधार हो। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा में एक ग्राम पंचायत जेवरा है जिसमें 20 मार्च 2024 को एक एफ.ओ.सी. कर्मचारी और अभी रिसेन्ट में 16 मार्च 2025 को एक एफ.ओ.सी. कर्मचारी दोनों जेवरा गांव के हैं और दोनों लाईट गोल होने के बाद ट्रांसफार्मर में बिजली सुधारने के लिए चढते ही ऐसा क्या होता है कि पहले विभाग को सूचना दी जाती है कि लाईन को कट किया जाता है, फिर वह ट्रांसफार्मर में चढ़ते हैं और कहां पर से बिजली आ जाती है कि एक ही गांव में एक साल में दो मौत हो गई है। 2024 में जिनकी मौत हुई थी इनमें 4 लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान है, स्थानीय जनप्रतिनिधि और गांव वालों के दबाव से विभाग ने उनको 2 लाख रुपये दिया, लेकिन 2 लाख रुपये आज तक नहीं दिया गया। मैंने विभाग से आज ही बात की है, अभी 16 तारीख की जिनकी मृत्यु हुई है, उनके मुआवजा की प्रक्रिया चल रही है। साल भर से 2024 वाले की मुआवजे की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और 2025 वाले की प्रक्रिया चल रही है। न जाने कितने साल तक प्रक्रिया चलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा और बेहतर प्रशिक्षण की मांग करती हैं ताकि वह अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिये जीवित रह सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पामगढ़ नगर में 8 महाविद्यालय और 10 से अधिक विद्यालय हैं। तहसील कार्यालय और जनपद कार्यालय, अस्पताल सहित अनेक शासकीय, अशासकीय संस्थान भी स्थित हैं जिसमें रोजाना लाखों की संख्या में लोगों की आवाजाही लगी रहती है। नगर के मुख्य मार्ग से महानदी व शिवनाथ नदी से उच्च गुणवत्ता की रेत की भी सप्लाई अन्य नगरों को होती है। साथ ही पॉवर प्लाण्ट से निकले फ्लाईएश को बलौदाबाजार के आसपास सीमेंट प्लांट में भी पहुंचाने के लिए केप्सूल वाहन भी इसी मार्ग से होकर जाते हैं। ऐसे में सड़क पर भारी वाहनों की संख्या बढ़ने से आमजन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाएं होती रहती हैं । कल एक दुर्घटना हो गयी, ओवरलोडेड बस और ओवरस्पीड यानी वह ओवरलोडेड भी थी और ओवरस्पीड भी थी । मोटर साईकिल को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर दुर्घटना हो गयी और 37 लोग उसमें घायल हो गये जिसमें से 8 लोग गंभीर अवस्था में हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करती हूं कि पामगढ़ और राहौद नगर के मुख्य मार्ग से भारी

वाहनों की आवाजाही को कम करने के लिये बाईपास रोड की आवश्यकता है । चंडीपारा पामगढ़ से धरदई गांव तक जाने वाली नहर जो मुख्य मार्ग से लगभग समानांतर है । यदि उसके दोनों तरफ पक्की सड़क का निर्माण हो जाये तो आमजनों को एक अच्छी सुविधा का विकल्प मिल जायेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि हमारा शिक्षा तो तभी बेहतर हो सकता है जब हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हों लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि बजट में सभी हाईस्कूल और हॉयर सेकेंडरी स्कूलों में ग्रंथालय का उल्लेख तो है लेकिन विद्यार्थियों के लिए ग्रंथालय की उपयोगिता कितनी है इसे बताने की आवश्यकता नहीं है । आज विद्यालय में सुव्यवस्थित ग्रंथालय की जानकारी लेने की हमको जरूरत है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वैज्ञानिक युग है । विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए हर सरकार अपने-अपने कार्यालय में विभिन्न योजनाएं चलाती हैं इसके लिए प्रथम आवश्यकता है कि विद्यालयों में सर्वसुविधायुक्त एक प्रयोगशाला होनी चाहिए । अधिकांश विद्यालयों में प्रयोगशाला का अभाव है यदि कहीं है भी तो उसमें सामग्री की कमी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि विद्यार्थियों के हित में सभी हाईस्कूल और हॉयर सेकेंडरी स्कूलों में अनिवार्य रूप से सर्वसुविधायुक्त प्रयोगशाला के लिए कक्ष निर्माण एवं सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में उच्च शिक्षा के लिए दो ग्राम पंचायत से कॉलेज की मांग आई है । चूंकि वृहद रूप में गांव वाले और बच्चे लोग आंदोलन भी करते हैं और चुनाव का बहिष्कार करने की भी कोशिश करते हैं, जो मेरे विधानसभा के ग्राम सलखन विकासखंड नवागढ़ जिला जांजगीर-चांपा में है । मैं वहां एक कॉलेज खोलने की मांग करती हूं ताकि वहां के बच्चों को, आसपास के गांव के बच्चों को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके इसी प्रकार मेरे ही विधानसभा पामगढ़ में ग्राम ससहा विकासखंड में...।

अध्यक्ष महोदय :- बस, हो गया भई ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट में पढ़ लीजिये ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पामगढ़ में महाविद्यालय खोले जाने की मांग करती हूं । बलौदा बाजार होते हुए रायपुर के लिए मुख्य मार्ग में ससहा स्थित है, यहां महाविद्यालय खुल जाए तो जांजगीर जिला के साथ-साथ बिलासपुर जिला के भी अंतिम छोर के ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- गुरू खुशवंत जी आप अपनी मांग रख दें । आप जल्दी से अपने क्षेत्र की मांग रख दीजिए ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब (आरंग) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा वह माध्यम है जिसके माध्यम से सब-कुछ पाया जा सकता है और शिक्षा के बिना समाज का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता । अगर हम चाहते हैं कि राष्ट्र का विकास, समाज और राज्य का विकास हो तो शिक्षा जीवन में बहुत आवश्यक है और हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल शिक्षा को न केवल मजबूत बना रही है इसके साथ ही साथ गुणवत्तापूर्वक व्यवस्था भी कर रही है । आपको मालूम ही है कि पिछले 5 साल में किस प्रकार शिक्षा को पूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त कर दिया गया था, पूरा चौपट कर दिया गया था। किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी । आपने देखा है कि किस प्रकार शिक्षकों के ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार किया जा रहा था लेकिन हमारी सरकार ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त और मजबूत करने के लिये इस बार बजट में 22,473 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । न केवल हम स्कूली शिक्षा के अधोसंरचना को मजबूत कर रहे हैं बल्कि गुणवत्ता पर भी ध्यान दे रहे हैं । पिछला वर्ष 2024-25 में भी जो बजट था उससे भी 4.06 से अधिक इस बार बजट को रखा गया है इसके साथ ही साथ स्कूल के बच्चों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के लिये भी इसमें बजट का प्रावधान किया गया है इसमें लगभग 144.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। निश्चित ही जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते तो वे निश्चित ही पुस्तक नहीं खरीद पाते हैं, अपना जो गणवेश है वह नहीं खरीद पाते या अन्य बहुत सारी चीजें हैं और विशेष रूप से मैं उस समाज से आता हूं, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. कहीं न कहीं इस समाज में विशेषकर यह समस्या होती है लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो प्रावधान किया है इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिसके माध्यम से निश्चित ही समाज के ऐसे बच्चों का भविष्य सुधरेगा और वे आगे बढ़ेंगे । इसके साथ ही साथ पांचवीं और आठवीं के एग्जाम को बोर्ड एग्जाम करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे समाज के बच्चे विशेष रूप से सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो निश्चित ही उनकी नींव इसके माध्यम से बहुत अच्छी होगी और वे अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ एन.सी.आर.टी. के माध्यम से शिक्षा में जो 16 स्थानीय भाषाओं और बोलियों एवं चार अंतरजातीय भाषाओं को पाठ्य पुस्तक में लागू किया गया है, निश्चित ही यह बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमारी मातृ भाषा है, उसमें बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और जब वे उससे शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आसानी से शिक्षा को अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। साथ ही साथ व्यवसाय को भी कहीं न कहीं शिक्षा से जोड़ा गया है। नई शिक्षा नीति कहीं न कहीं रोजगार प्रेरक है, जिसके माध्यम से 652 शालाओं में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। शासन के द्वारा स्वीकृति दी गई है। विद्यालयों में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी पॉवर, अपीयर हेल्थकेयर, रिटेल टेलीकॉम जैसी 15 विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह

बहुत अच्छी बात है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चों को स्कूल के बाद एक अलग से कोर्स करना पड़ता था, लेकिन ऐसे पाठ्यक्रम स्कूलों में अगर लागू किया गया तो उससे उनकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप होगी और वे आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ उनको दो बार बोर्ड एग्जाम में भाग लेने का उनको चांस मिल रहा है, वह भी एक अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों में एक डर होता था कि हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। लेकिन उनको दो बार चान्स मिल रहा है, वह भी कहीं न कहीं एक बहुत ही अच्छी बात है और बच्चों के लिए खुशी की बात है। उनको इससे संबल मिलेगा। साथ ही साथ हमारी शिक्षा नीति में न्योता भोज प्रारंभ इस बार जो लागू किया गया है, वह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गांव में एक सामाजिक वातावरण बन रहा है। उस स्कूल में उन बच्चों को एक ताकत मिल रही है, शक्ति मिल रही है कि लोग हमारे साथ हैं, हमको पढ़ने में, लिखने में और हर तरीके का सहयोग कर रहे हैं। जब वे बैठकर खाते हैं और उनके साथ बहुत सारी व्यावहारिक बातें करते हैं तो उनको मजबूती मिलती है और उनको एक संबल मिलता है और वे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद देता हूं। बात तो बहुत सारी और हैं, लेकिन मैं मांग की बात करता हूं।

सभापति महोदय :- आप मांग पढ़ दीजिए।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो अभी नेटवर्क के लिए जो नए-नए टावर लगाए जा रहे हैं तो मैं इस विषय में बोलना चाहूंगा। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सदन के माध्यम से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी इसी मार्च महीने में गिरौदपुरी धाम का मेला था और निश्चित ही पिछले कई वर्षों से मैं उस मेला की व्यवस्था देखते आ रहा हूं, लेकिन किसी प्रकार का पानी, बिजली की जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, आवागमन की ट्रैफिक की जो व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन इस बार मेला की जो व्यवस्था थी, बहुत ही सुदृढ़ थी। सुरक्षा की व्यवस्था की बात करूं तो मात्र 365 पुलिसकर्मी की सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाती थी, लेकिन इस बार 1100 से ऊपर सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था वहां पर लगाई गई थी। साथ ही साथ पानी की व्यवस्था की भी बात करूं तो वहां पर मुश्किल से 8 से 10 टैंकर लगाये जाते थे, लेकिन इस बार 30 से ऊपर टैंकर वहां पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ एम्बुलेंस की भी बात करता हूं तो वहां मात्र तीन एम्बुलेंस पहले रहते थे। इस बार 19 एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां पर की गई थी और जिसके माध्यम से आज जब मेला संपन्न हुआ और सभी लोगों से जब बात हुई चर्चा हुई और जब यू-ट्यूबर्स ने अपनी सोशल साइट में डाला तो सभी ने कहा और पुलिस वालों से भी हमने पूछा कि क्या कोई कंप्लेंट आयी तो एक पॉकेटमारी की भी कंप्लेंट वहां पर नहीं आई तो इतनी सुंदर व्यवस्था जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गिरौदपुरी धाम के लिए की, उसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) साथ ही निश्चित ही

वहां पर नेटवर्क की एक समस्या है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि छाता पहाड़ जहां धाम है, जहां गुरू घासीदास बाबा जी ध्यान लगाए थे और 6 महीने के लिए उन्होंने तप किया था, ऐसी जगह में एक टावर की आवश्यकता है तो वहां टावर लग जाए, जिसके माध्यम से एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए सुविधा होगी। साथ ही साथ मेरी जो आरंग नगरी है, वह धर्म की नगरी है। राजा मोरध्वज की नगरी है, वहीं माता कौशल्या माता का भी मंदिर है और वह धर्म की नगरी होने के नाते वहां पर जब भी किसी प्रकार की खुदाई होती है तो बहुत ही प्राचीन अवशेष वहां से निकलते हैं। जब भी प्राचीन अवशेष निकलते हैं तो देखते हैं कि पुरातत्व वाले उसको बाहर ले जाते हैं या रायपुर ले जाते हैं या और कहीं ले जाते हैं तो मैं चाहता हूं पिछली बार जब संस्कृति मंत्री थे, वहां राजा मोरध्वज महोत्सव मनाये थे तो एक संग्रहालय बनाने की वहां घोषणा हुई थी तो निश्चित ही इस बार वह इस बजट में नहीं आया तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आरंग नगरी में धर्म की नगरी में जो प्राचीन मूर्तियां निकलती हैं, उन मूर्तियों को वहीं स्थापित किया जाए । वहां पर एक संग्रहालय बनाया जाए ताकि देश दुनिया से लोग आकर दर्शन करें, मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता हूं । साथ ही उनकी सभी अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि सिंगल बत्ती को जो 30 यूनिट बिजली दी जाती है, यह बहुत पुरानी व्यवस्था है उसे 50 यूनिट तक किया जाए । एक मेडिकल कॉलेज मुंगेली में होना चाहिए, उसके लिए एक अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पास हुआ है उसे दिल्ली भेजा गया है । मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज खोला है मुंगेली में भी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे । मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि कंतेली में आपने कॉलेज खोलने के लिए बजट प्रावधान किया है, उसके लिए धन्यवाद् देता हूं । चकरभाठा में 133 केव्ही का विद्युत सब-स्टेशन हो, ऐसी मांग करता हूं । 10+2 का हाईस्कूल देवरी में हो, मिडिल स्कूल हो, यह मांग करता हूं । कोचियों द्वारा शराब बिक्री की प्रथा को समाप्त किया जाए । शराब के नशे में बहुत से परिवार बर्बाद हो जाते हैं । कई लोगों का लीवर खराब हो जाता है, मृत्यु हो जाती है और ऐसी परिस्थिति को देखकर नशा मुक्ति केन्द्र कई स्थानों में खोला जाए, जिससे लोगों में जागरूकता आए, समाज में शांति की स्थापना हो, मैं ऐसी मांग करता हूं । बहुत बहुत धन्यवाद् ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विभागों से संबंधित अनुदान मांग संख्या 1, 2, 7, 12, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 56, 60, 65, 71, 26, 27, 37, 44, 51, 77 पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग प्रतिपक्ष में हैं और यह हमारा धर्म बनता है कि जहां-जहां भी हमारी सरकार या माननीय विष्णुदेव जी की सरकार या डबल इंजन की सरकार गलतियां कर रही हो, उनकी तरफ उंगली

रखें और बताएं कि आप यहां गलत कर रहे हैं, सही कर लीजिए । इस नाते मैं समझता हूं कि हम इनके दुश्मन नहीं हैं । हमको उस नज़र से न देखा जाए, हम इनके शुभचिंतक हैं और चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को ज़रा देखें झांके और समझें कि कैसे आपकी सरकार, जैसा वित्त मंत्री जी चाहते हैं वैसी द्रुतगति से काम हो, इस पर ध्यान दें ।

माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो यहां रहते हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यहां नहीं रहते । मगर सदन में कम और अपने कक्ष में ज्यादा रहते हैं, अक्सर हर मुख्यमंत्री ऐसा करता है, कोई तकलीफ नहीं है । मगर जब तक यहां बैठे रहते हैं आपके लोग हैं, मित्र हैं, विधायक हैं वे आपकी ऐसी तारीफ करते हैं कि हम लोग देखकर थोड़ा सहम जाते हैं, तारीफ के पुल बांधेंगे, विष्णुदेव जी की सरकार है, काम होगा, ये होगा, वो होगा और जैसे ही आप यहां से बाहर जाते हैं तो यह सरकार नरेन्द्र मोदी जी की हो जाती है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार है । चूंकि सबसे विख्यात और कुख्यात आदमी यहां बैठे हुए हैं चंद्राकर जी ।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनकी तारीफ कर रहे हैं या ..(हंसी)।

डॉ. चरणदास महंत :- मजबूरी है, मित्र हैं तारीफ करनी ही पड़ेगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सब चलेगा क्योंकि अवैध संबंधों का सवाल है (हंसी)।

डॉ. चरणदास महंत :- इन लोगों को सिखाइए कि आपकी सरकार है विष्णुदेव साय जी की सरकार है सांय सांय काम करने वाली सरकार, ये आप तक ही सीमित रहें और तीसरा चौथा इंजन लगाकर काम न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं, हम लोगों ने गाड़ी में देखा है, कोयला के इंजन में जब ट्रेन जाती थी तो उसका कुछ नट वगैरह बिगड़ जाता है तब या जब कमजोर पड़ता है तब या पुराना होता है तब एक दूसरी इंजन लगाकर खींचते थे, उनको डबल इंजन लगे हे, डबल इंजन लगे हे बोलते हैं। ये डबल इंजन वाला कब तक चलेगा आप जानिए।

आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने चुनाव के समय नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी प्रस्तुत की थी, तीसरे नंबर की गारंटी 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे। आपने एक लाख पदों की भर्ती के संबंध में पिछले साल कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है, ये मेरा आरोप है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में आपकी सरकार ने कहा था कि हम आर्थिक सलाहकार परिषद बनाएंगे, आपने घोषणा की थी। आपने घोषणा की थी कि दिव्यांगजनों के बैकलॉग की भर्ती करेंगे, मगर आज तक इन दोनों के संबंध में कहीं अता-पता नहीं है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, इसको दिखलाईयेगा। ये बहुत छोटा सा एक ही पद का है, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति अभी सुन रहे हैं। पिछले 7 फरवरी को शायद इसका विज्ञापन हुआ था, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपकी सरकार में कितने-कितने दिन बाद काम होना है, वह आप तय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं खनिज विभाग के अंतर्गत थोड़ा सा कहना चाहूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके हर विभाग का कुछ न कुछ बताऊं कि गलतियां कहां हो रही है, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, आपकी गलतियों को बता रहा हूं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में समस्त खनिजों की कुल उत्पादन मात्रा 25694 लाख मीट्रिक टन थी, वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में मेरे पास 8 महीने के आंकड़े हैं, उसमें उत्पादन मात्रा 3973 लाख मीट्रिक टन हो गई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत कम है। जबकि अवैध खनन, उत्खनन, परिवहन, भ्रष्टाचार, आप इन सबको नियंत्रित कर ही नहीं पा रहे हैं, ये बढ़ रहा है, मगर ये मात्रा कैसे कम हो रही है, यदि आपके अधिकारीगण बता दें तो मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग की बात करें तो आपने कहा था कि 7300 मेगावाट से बढ़ाकर 18 हजार मेगावाट कर दिया। ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में इतनी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। मगर उसकी जो बेहतरी की ओर परिणाम आना चाहिए, वह दिख ही नहीं रहा है, जब हम सरप्लस स्टेट हैं तो हमारे यहां की बिजलियां क्यों कट रही हैं ? चाहे गांव में हो, चाहे किसानों के हो, चाहे संसाधनों की बात करें, चाहे ट्रांसफार्मर की बात करें, जिस गांव में जाते हैं, वहां ट्रांसफार्मर की शिकायत आती है, ट्रांसफार्मर बदलने में 1-1 माह, 2-2 माह लग रहे हैं, एक बड़ी बात हो रही है, आपने रायपुर और रायगढ़ में आग लगने की घटना सुनी होगी। अभी तक इस प्रकार की आग लगने की घटनाएं नहीं हुआ करती थी, सरप्लस स्टेट बनते ही आग लगने की घटनाएं यहां हो रही हैं, आप उसको दिखवाईए। अध्यक्ष महोदय, जनसंपर्क विभाग सिवाय आपके और प्रधानमंत्री जी की तारीफ के अलावा कोई काम कर नहीं रहा है। मैंने पिछली बार शिकायत की थी कि उन्होंने प्रयागराज में पंडाल लगाकर बहुत कुछ लूटने की कोशिश की है, इनको कौन टेंडर दिलाता है या ऐसे ही देते हैं, आप उसको जांच करवाईए और हम लोगों को भी बताईए कि ऐसा कौन व्यक्ति है।

अध्यक्ष महोदय, वाणिज्य कर विभाग जिसको आबकारी विभाग कहते हैं। अभी हमारे भाई जी कह रहे थे, माननीय सीनियर बुरा मत मानियेगा। शराबखोरी बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। आप दुकान कम करने की बात कर रहे थे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय पुन्नूलाल जी, सिर्फ बुड्ढा कहने में बुरा मानते हैं, बाकी आप कुछ भी बोल लीजिए, वे बुरा नहीं मानेंगे। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं बुरा नहीं मानता।

डॉ. चरणदास महंत :- मैंने उनको कभी बुड्ढा नहीं कहा। वे तो हमेशा जवान हैं, बाल सफेद करा लिए हैं। सर, आप लोग हम पर आरोप लगाते रहें।

समय :

7.00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता हूं। चंद्राकर जी, मगर संविधान के अनुच्छेद-47 में तो ऐसी व्यवस्था है कि उसमें लिखा हुआ है कि शराब एक सामाजिक बुराई है और शराबखोरी को बढ़ावा देना संविधान के अनुच्छेद-47 के विरूद्ध है। अभी आपने 67 नयी दुकानें खोली हैं। इसके साथ ही साथ इसकी संख्या 741 हो गई है। बाकी जगह सबके दाम बढ़ रहे हैं। हम लोग रोज चिल्लाते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, मगर आपके यहां आपकी कृपा से शराब के दाम कम हो रहे हैं। जिससे पीने वालों की संख्या बढ़ रही है और दुकानों की संख्या बढ़ रही है तो आने वाले समय में आप छत्तीसगढ़ को कहां ले जायेंगे, इसको आप देखिये और इस पर विचार कीजिये। हम लोग भी कोशिश करेंगे। अभी तो नया-नया है और 2-4 महीने गुजर जाये। आपका परिवहन विभाग राजस्व अर्जित करने वाला विभाग था। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले समय क्या हुआ, उसको मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूं। मगर हमने अपने जमाने में 75 प्रतिशत तक दलालों से मुक्ति दिलाई थी। अब वहां दलालों की संख्या बढ़ रही है और फिर से हमारे साथी, परिवहन विभाग में काम कराने वाले हमारे लोग दलालों की चपेट में आ रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ के लिए उचित बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के बजट में आपने सभी विभागों के लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था। उसके बावजूद भी ई-गवर्ननेंस, ई-पोर्टल और ई-तकनीक में कितना विकास हुआ है, इसको आप अपने लोगों से नपवाइये। आपके विभाग की जितनी भी वेबसाइट हैं, वह आज तक अपडेट नहीं हुई हैं। यदि आज आप उसमें सूचना लेने के लिए जाएंगे तो 3-4 साल पहले की सूचना देते हैं। वह अपडेट नहीं हुई है। यह मेरा आरोप कहिये या आपकी तरह मैं आपके विभागों की गलतियों की ओर इंगित कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास विमानन विभाग भी है। वर्ष 2024-2025 में आपने इसमें 2 सौ करोड़, 48 लाख, 30 हजार रूपये की व्यवस्था रखी थी। महाराज, इसमें इतने का बजट आवंटन था। इसके बावजूद भी अभी दिसम्बर, 2024 तक मात्र 107 करोड़, 77 लाख, 25 हजार रूपये खर्च हुए हैं। आप ये पैसे बचा रहे हैं। यदि आपको इसको खर्च नहीं करना है तो आप इसको बजट में क्यों ला रहे हैं? इसको मैं समझ नहीं पाता हूं। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि आपने किराये में हेलीकॉप्टर लिया है और इतना भुगतान किया है। अभी मुझे उसका exact figure याद नहीं है। अध्यक्ष जी, हम एक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं खरीद सकते ? एक हेलीकॉप्टर खरीदने में कितना खर्च आता होगा ? वह 25-50 करोड़ रूपये का आता होगा। आप उसके किराये में इससे ज्यादा पैसे दे रहे हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर खरीदेंगे तो शायद कभी-कभी वह मुझको भी मिल जायेगा। आप लोग तो जायेंगे ही। जशपुर दूर है। आप

दूसरे के हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो अपना हेलीकॉप्टर खरीदिये। इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप लोग सचेत नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग में जो औद्योगिक दुर्घटनाएं हो रही हैं और श्रम कानून के तहत उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो नुकसान हो रहा है, मानव क्षति में आप लगातार वृद्धि के आंकड़े दिखा रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपकी सरकार की प्रशंसा नहीं करूंगा। जन शिकायत निवारण, इसमें तो आपने एक अच्छा काम किया था। जैसा हम लोग करते थे कि आपके मुख्यमंत्री जी के घर में या उनके आवास में प्रदेश के बहुत से गरीब लोग उनसे मिलने जाते थे। आप उनके दरख्वास्त लेते थे। कुछ निराकरण करते थे, कुछ करवाते थे। मगर उसमें अचानक क्या हो गया कि आपने उसको बंद करा दिया ? क्या कोई शिकायत आई या कोई थ्रेट आया ? गृहमंत्री जी, आखिर मुख्यमंत्री जी का जो मिलने-जुलने और जन समस्याओं को जानने का कार्यक्रम था, उसको बंद कराने के पीछे आपका हाथ तो नहीं है ?

गृह मंत्री (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव था व आचार संहिता थी। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी सबको बुलाकर बात करते तो फिर यह कहते कि उसी कारण से हार गये। फिर बाद में ई.वी.एम. भी नहीं रहता।

डॉ. चरण दास महंत :- यह बहाना अच्छा नहीं है। आप दिखवा लीजिये। आप कोई अच्छा बहाना खोजिये तो चलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामोद्योग विभाग में वर्ष 2024-25 में 118 करोड़ रूपए का आवंटन दिया था। इसमें 9 महीने में 67 करोड़ खर्च हुए हैं। यह क्या है ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने दिखाने के लिए हर विभाग में पैसे तो दिया है लेकिन, आपने नहीं पूछा, आप दौरे में व्यस्त रहते हैं, आप जशपुर गए, आप कोरबा गए, यहां गए, वहां गए। ये लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। उसमें आपकी डबल इंजन की सरकार लगातार बदनाम हो रही है। आप इसको देखिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पशुधन विकास विभाग के एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि राजधानी की सड़कों में आवारा पशुओं को cow cacher के माध्यम से पकड़कर गौठानों में रखा जायेगा, आपने ऐसा कहा था। आपने गलती से कहा था या सही कहा था, यह आप चेक करा लीजिए। मगर गौठान तो हमारा है, आप वहां कैसे रखोगे ? नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी, गौठान तो हमारा है। आप उसकी जगह नया गौठान बना रहे हैं तो जरूर बताइयेगा। लेकिन आज भी कहीं भी जाईये, सड़क में जिस तरह से गाय को मरा हुआ देखते हैं, बैल को मरा हुआ देखते हैं, जानवर को मरा हुआ देखते हैं तो आपका दिल पसीज जायेगा। बहुत खराब स्थिति है। आप इसको रूकवाईये। हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आवारा पशुओं का सरंक्षण और संवर्द्धन के विषय में आपका विभाग काम करे, आप काम करें, आप सफल हों, यह हम कह सकते हैं। आपने वर्ष 2023-24 में 1214.21 लाख रूपए का बजट रखा था।

लेकिन अभी तक मात्र 657.68 लाख रूपए ही व्यय हुए हैं। वित्त मंत्री जी पैसा बचाकर क्या करेंगे, हमको भी बताईये ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा दुग्ध उत्पादक सदस्यों की समिति के माध्यम से दूध संकलन, संग्रहण करने का काम लिया गसर था। मगर 16.12.2024 को एक आदेश निकला है जिसमें आप उसको 3 साल के संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को दे रहे हैं। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तो गुजरात में है। क्यों चौधरी जी, गुजरात में ही है न ? वहां तो भरा पड़ा हुआ है। क्यों दे रहे हैं ?

श्री विजय शर्मा :- वह PAN INDIA है।

डॉ. चरण दास महंत :- PAN INDIA मान लिया। मुख्यालय कहां है ? चलिये मैं बता देता हूं, वही मान लीजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मछली पालन विभाग के लिए कुल 18,182 लाख रूपये स्वीकृत किया था। इसके विरूद्ध सिर्फ 4,252 लाख रूपए खर्च किया है। ग्रामीण क्षेत्र में मछली पालन छोटा-मोटा उद्योग हो सकता है। हमारे बहुत सारे गरीब बच्चें और उसके मां-बाप भी काम में लग सकते हैं तो आप ग्रामीण रोजगार में लोगों को रोजगार देने की सहायक भूमिका निभा रही है, उस रोजगार को क्यों छीन रहे हैं ? मैं ऐसा सुनता हूं कि जो मछली का धंधा करता है, उसकी दुर्गति ही होती है। वित्त मंत्री जी, अगर आप मछली का पैसा खायेंगे तो दुर्गति होगी। हमारे यहां मछुआरे लोग बैठे हैं, इनकी आर्थिक और सामाजिक दशा को सुधारने में काम करिये, राशि को ग्रामीण रोजगार में लगाईये। आप बजट का सिर्फ 23 प्रतिशत राशि ही उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो रहा है ? आपके हर विभाग में बजट की राशि का कम उपयोग हो रहा है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी, मैंने उनको सुझाव भी दिया है कि ग्रामीण स्तर में मछुआरे काम करते हैं। इन्होंने नदी, तालाब, पोखर में बीज डालना बंद कर दिया है। इसलिए उनके पास रोजगार के संसाधन नहीं है। नरवा में बीज डाले, डबरी में बीज डाले, तालाब में बीज डाले। क्योंकि इन लोग तालाब और बड़े-बड़े बांध में मछली बीज डालते हैं। अगर वहां मछली बीज डालेंगे तो उनके लिए जीविका का साधन उपलब्ध होगा।

डॉ. चरण दास महंत :- भाई जी, ऐसा है हम लोग इधर से जितनी भी अच्छी बात करें, मगर विरोध में है। आपको विरोधी समझेंगे, आप अच्छे से अच्छा बात करोगे तो यह विरोधी आदमी बोल रहा है, हमारा विरोधी है, सुनना ही नहीं है, कहेंगे। भले 5 साल, 3 साल में वह भी चले जायें, मगर नहीं सुनेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आयाकट विभाग में कर वसूली लंबित है। आप भी बाहर गये थे, पता नहीं आपकी कितनी तैयारी होगी, यह मैं नहीं कह सकता। अगर मैं आपको सीधे-सीधे कहूं तो हमारे बड़े-

बड़े उद्योगों से वसूली करने के लिए कितनी राशि बची हुई है? मैंने तो सुना है कि शायद 8 हजार करोड़ रूपये वसूली के लिए बकाया है। आप क्यों वसूली नहीं कर पा रहे हैं? आप इसको दिखवाईये, उनसे वसूली करवाईये। आपका पुनर्वास विभाग तो माशाअल्लाह है, वह विभाग सिर्फ कागजों तक सिमिति है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। चन्द्राकर जी, जैविक प्रौद्योगिकी विभाग में ही नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी की बात आती थी, जिसकी आप अधिकतर प्रशंसा करते हैं। यदि आप गोबर से जैविक खाद नहीं बनायेंगे तो आप किससे बनायेंगे? आपने उसके लिए कोई और विधि सोचा है या गौमूत्र से खाद बनेगा? आप गोबर कहां से लायेंगे? आप छत्तीसगढ़ में जैविक खाद की खेती करना चाहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आप पुनर्वास विभाग को माशाअल्लाह बोल रहे थे। आपने भूपेश जी को कहां डिकोड कर दिया है?

डॉ. चरणदास महंत :- क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या आपने भूपेश बघेल जी को कहां डिकोड कर दिया है? आपने पुनर्वास दूसरी जगह दिलवा दिया है क्या?

डॉ. चरणदास महंत :- चन्द्राकर जी, आप मेरे को विचलित मत करिये। (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी जब भी बोलते हैं तो पड़ोस की बेंच अपने आप खाली हो जाती है। (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- किसके?

श्री राजेश मूणत :- जब भी आपने बोला तब पड़ोस की बेंच खाली रही है। आप हाऊस की आज तक की रिकॉर्डिंग उठा कर देख लीजिये।

डॉ. चरणदास महंत :- जब मैं बोलता हूं तब भी आप लोग उधर इशारा करते हैं। वह बोलते हैं तब भी इशारा करते हैं तो कोई भी आदमी कितनी देर बैठेगा? (हंसी) हम लोग खुद ही भागने के पक्ष में हैं।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय नेता जी, कुछ लोग तो आपके बारे में यह भी कह रहे हैं कि आप बहुत जादू-टोना कर इनको भगा रहे हैं। (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- भैया, जादू-टोना गड़बड़ वाला मामला है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, मैं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बारे में बोल रहा था। आप लोगों ने पिछले साल हमारे नरवा का, गरूवा का, घुरूवा का, बाड़ी का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी जगह आप कुछ सब्टिट्यूड बनाईये। बिना नरवा के, बिना घुरूवा के, बिना गोबर के कुछ काम हो सकता है तो बताईये, हम लोग भी वही काम में लग जायेंगे, हम लोगों के पास काम कम है। मैंने पिछले बार सुशासन और अभिकरण के बारे में बोला था। पता नहीं आप उस दिन थे या नहीं थे। माननीय वित्त मंत्री जी के कहने से आपने दिल्ली में दो एन.जी.ओ. से संपर्क किया, आपने उनको यहां बुलाया, मुझे उसी दिन से शक है कि आपके शासन के

अंदर काम करेंगे तो आपकी केबिनेट की फाईल को क्या वह देख सकते हैं? क्या वह देखेंगे? आपके विभाग में जो अंदर का मामला है, आपके विभाग में एक सुरक्षा की बात होती है, क्या वह बाहर नहीं जाएगी? मैंने उस दिन भी कहा था कि आपके पास इतने बड़े-बड़े अधिकारी हैं। आपके पास चीफ सेक्रेटरी के साथ कई ऐसी सेक्रेटरी हैं, वहां बड़े सचिव महोदय हैं। वे सब विदेश से पढ़कर आए हैं, इजीनियरिंग किए हैं, डॉक्टरी किए हैं तो आपको अपने लोगों में भरोसा नहीं करने की बात तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि कहां से एन.जी.ओ. आ जायेंगे? आप स्वयंसेवी संस्थाएं, सी.जी.आई.एस. और टी.आर.आई. के साथ कैसे काम करेंगे? इसमें हमारी सरकार, आपकी सरकार और पूरे छत्तीसगढ़ की जो गुप्त बातें हैं, उसको तो वह कहीं गड़बड़ नहीं करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको आप देखिये। इस बारे में मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, वित्त मंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि इसमें कुछ करिये। मैं नहीं समझता कि यह ठीक है। चलिये साहब, शिक्षा विभाग आपका प्रमुख विभाग है, जहां आपको लोग डरा रहे हैं, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने यहां 33,000 पदों पर भर्ती करने की घोषणा कर दी थी और उन्होंने यह भी कह दिया था कि 33,000 भर्ती के लिए हमें वित्त मंत्री जी से स्वीकृति मिल गई है। जैसे ही उन्होंने कहा, उस दिन वित्त मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही दिन बाद उनकी छुट्टी हो गई, वे दिल्ली चले गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके नाम की जो भर्ती प्रक्रिया बची हुई है, उसको आप पूरा करिये। उसमें ऐसा थोड़ी होगा कि उसको बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा है तो भर्ती नहीं होगी। उसकी भर्ती होनी चाहिए। वर्ष 2024 खत्म हो गया, चुनाव संपन्न हो गये। पहली इंजन, दूसरी इंजन, तीसरी इंजन और चौथी इंजन के भी चुनाव संपन्न हो गये और आपने जितने इंजन में डीजल-पेट्रोल डाल कर हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं बाद में बात करूँगा । मैं आपको याद दिलाता हूँ कि वर्ष 2023-2024 अपेक्षा वर्ष 2024-2025 अगर इनके स्कूल के छात्रों की दर्ज संख्या को आप देखें तो 1 लाख 37 हजार 280 की कमी हुई है । यह मुझे गलत आंकड़े मिल रहे हैं कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, मैं आपके प्रतिवेदन से कहीं बाहर नहीं गया हूँ । मैं आपके प्रतिवेदन को पढ़कर, समझकर, कुछ बनाया हूँ, उसके बाद देखिये, मेरी गलती हो तो आप सुधारिये । वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-2025 में प्रशासकीय प्रतिवेदन में संचालित शालाओं की संख्या का आंकड़ों में बहुत विरोधाभाषी है। वर्ष 2023-2024 में आपने प्राथमिक शाला 32,570 बताया था, वर्ष 2024-2025 में 16 नवीन स्कूल आपने खोला, इसके बाद आपने इसे जोड़ दिया तो क्या हुआ 32,586, ऐसा आप बता रहे हैं, जो कि 32,461 है । अध्यक्ष महोदय, उसी तरीके से अगर इसको देखें तो आप कह सकते हैं कि 125 शालाओं को बंद किया है, अगर आपने 125 शालाओं को बंद नहीं किया है तो आंकड़ो कैसे गड़बड़ हो गया ? यह धान और चावल में तो समझ आता है, धान को आपने कोष्टक में डालकर चावल कर दिया, मगर यहां कैसे करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार माध्यमिक शाला 16,376 थी, आपने 4 नवीन शालायें खोली, होना चाहिये 16,380, परन्तु आप उसमें दिखा रहे हैं, 16570 ? इसमें 190 शालायें बढ़ गई है तो बढ़ गई हैं,

किताबों में बढ़ी है कि हिसाब में बढ़ा है ? आपको बताने वाले क्या बताते हैं, यह किताबों में बढ़ा है, संख्या में बढ़ा है कि हिसाब में बढ़ा है ? अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हाई स्कूल की बात करूँ तो 2713 हाई स्कूल था और नवीन स्कूल नहीं खोला गया, आपने फिर भी इसको घटाकर 2704 लिखा है । आपने जब इसे घटाया ही नहीं है, बंद नही किया है तो 2704 और 2713 में अंतर क्यों है ? आपके प्रतिवेदन में बार-बार गलतियां क्यों हो रही है ? अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी 4674 से बिना प्लस-माईनस किये अभी प्रतिवेदन में 4880 हो गया है । यह आपके आंकड़ें हैं । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-2024 में 56,333 स्कूल खुले थे, आपने 20 स्कूल नये खोले, भले ही अपने क्षेत्र में खोला हो, यह 56,353 हो जाता है, परन्तु आंकड़ा अचानक बढ़ गया है और वह 56,665 बता रहा है । प्रतिवेदनों में किस बात को को कैसे बढ़ाया और चढ़ाया और सिखाया जाता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपने उच्च शिक्षा विभाग में वर्ष 2024-2025 में कुल बजट प्रावधान 1333 करोड़ रूपया का रखा था और 6 जनवरी 2025 तक मात्र 795 करोड़ 53 लाख खर्च हुये हैं, अब बताईये मैं क्या कहूँ ? अध्यक्ष महोदय, पूरा का पूरा कॉलेज, उच्च शिक्षा विभाग अभी तक, वैसे हमारे जमाने से चल रहा है, आप उसको ठीक करिये ना ? अतिथि प्राध्यापकों के नाम यह देखा जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग अतिथि प्राध्यापकों के लिये ही बना है । अध्यक्ष महोदय, धार्मिक न्यास और धर्मस्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2024-2025 के लिये 4920 लाख के बजट के विरूद्ध आपने 197 लाख अर्थात 4 प्रतिशत की राशि ही 9 महीने में खर्च की है । धार्मिक न्यास और धर्मस्य के मामलों में बजट का सिर्फ 4 प्रतिशत ही खर्च हुआ है, आपका धार्मिक उन्माद कहां है, आप लोग रामलला जी के दर्शन कराना चाहते हैं, कुंभ में डुबकी लगवाना चाहते हैं, एक बात कहता हूँ कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं । 33 करोड़ ही है न या गलत कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

डॉ. चरण दास महंत :- आपने उसके हिसाब से कह दिया कि 66 करोड़ नहाने आये थे । मतलब एक देवता के सिर्फ दो आदमी हैं । हिसाब लगाओ, कुछ प्लस-माईनस करिए । माननीय, कुछ करिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके लिए तो ऊपर से सर्क्यूलर जारी था कि कुंभ स्नान में नहीं जाना है ।

डॉ. चरण दास महंत :- ऐसा कुछ नहीं है, सर्क्यूलर बिल्कुल जारी नहीं था । हम तो गए थे, कई बार कुंभ नहाकर आये हैं । राम लला के दर्शन करके आते हैं और जो राम लला के दर्शन करके आते हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया था । आप यह कैसे बोल रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमने तो कहीं पढ़ा था कि हाईकमान ने सर्क्यूलर जारी किया था ।

डॉ. चरण दास महंत :- हम लोग सभी सनातनी हैं, आप कहां जा रहे हो । आप ही चिढ़िचढ़ा रहे हो, आप ही बढ़ा रहे हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो । आप कुछ माला पहने हो क्या, बताओ न ?

आप गए थे ? (गले में पहनी हुई माला दिखाते हुए) ये देख लें, ये क्या है ? आप देख रहे हो कि ये क्या है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माला ।

डॉ. चरण दास महंत :- काहे का ? ये एक मुखी रूद्राक्ष है । लूट मत लेना और इसको मैं स्वयं जाकर राम लला के चरणों में रखा हूं और फिर वहां से वापस मिला है । तुम्हारे किसी के पास हो तो बता दो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अगर आप इतने धार्मिक हैं तो राहुल गांधी जी का गोत्र क्या है, यह बता दीजिए ।

डॉ. चरण दास महंत :- छोड़ो, आप यहां की बात करो । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तो आपसे सिर्फ यह पूछा कि राहुल गांधी जी का गोत्र क्या है ?

श्री रामकुमार यादव :- मोदी जी के गोत्र का हे ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :- माननीय नेता जी, आप कुंभ में नहाए होते तो रूद्राक्ष देख लिए होते । आज दिखाना नहीं पड़ता । आप नहाने के लिए उतरे होते तो रूद्राक्ष दिख गया होता ।

डॉ. चरण दास महंत :- कुंभ में कितने लोग रूद्राक्ष को, पैसे को, मोबाईल को निकाल रहे थे, यह आपको पता है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जैसे आपको प्रमाण दिखाना पड़ रहा है न कि मैं सनातनी हूं करके । उनको भी चुनाव के समय बताना पड़ा कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का हूं करके ।

डॉ. चरण दास महंत :- चलिए, बढ़िया है । आप तो एक ही राम को मानते हो, हम तो कबीर पंथी हैं, चार-चार राम को मानते हैं । एक राम दशरथ घर डोले, दूजा राम घट-घट में बोले, तीजा राम का सकल पसारा और चौथा राम पूरे जग से न्यारा । (मेजों की थपथपाहट) हमारे चार राम हैं । तुम एक राम में इतना तनतनाएं बैठे हो, हम चार राम वाले सीधे-साधे लोग हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यटन के बारे में पिछले सत्रों में प्रश्न लगाया था कि पर्यटन की सुविधा देने के लिए जो भी केन्द्र विकसित किये गए थे, वह तो गायब हो चुके हैं, पूरे प्रदेश से गायब हो चुके हैं । कुछ 18 केन्द्रों में शायद काम चल रहा है, उसमें भी पूरे में काम नहीं चल रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक सलाह दे रहा हूं कि पर्यटन स्थलों को वन मंत्री जी के साथ या वन मंत्री जी के विभाग से मिलाकर बनाएं तो पर्यटन के बहुत सारे स्थल बन जाएंगे । जैसे बस्तर को यदि पर्यटन स्थल बनाया जाता है, आप ही लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं, सब लोग कहते हैं । माननीय चौधरी जी, यदि बस्तर का पर्यटन हम ठीक ढंग से कर सकें तो हमारा प्रदेश पर्यटन के मामले में नार्थ ईस्ट से भी बहुत अच्छा हो जाएगा और उसको बनाईए । आपको मौका मिला है । नहीं तो फिर हम लोगों को मौका दे दीजिए, फिर हम बनाएंगे ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय नेता जी, अभी बस्तर पंडुम बनाया जा रहा है । बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है ।

डॉ. चरण दास महंत :- ऐसा थोड़ी होता है कि खुद 15-15 रखो और हमको 5 दो । यह कौन सा मौका हुआ ?

श्री केदार कश्यप :- बस्तर पंडुम बनाया जा रहा है ।

डॉ. चरण दास महंत :- ठीक है, अच्छी बात है ।

श्री केदार कश्यप :- आप सादर आमंत्रित हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- आप कहां कह रहे हैं । आप करिए न, आप अच्छा काम करिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता जी, मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि बस्तर नार्थ ईस्ट या *स्विट्ज़रलैंड* से भी अच्छा हो सकता है । आपने कहा कि हमको मौका दे दीजिए । आपको मौका मिला तो दंतेवाड़ा सौंदर्यीकरण जांच के दायरे में आ गया । सौंदर्यीकरण कैसे-कैसे हुआ, किस मद से हुआ, क्या हुआ, वह जांच का विषय बन गया ।

डॉ. चरण दास महंत :- वह तो आपका मद कहां-कहां जा रहा है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, क्या फायदा, आपको फिर बुरा लग जाएगा। मैं चलते-चलते संस्कृति विभाग की बात कर लेता हूं। आपका यह छोटा सा विभाग बचा हुआ है। इसमें 3815 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध 9 महीने में 1282 लाख, मतलब सिर्फ 34 प्रतिशत ही खर्च हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी आदिवासी वर्ग से आते हैं। यह आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। हम लोग कोशिश करते थे कि बाहर के आदिवासी संस्कृति को, नृत्यों को यहां दिखाते थे, उसके बाद भी पैसे को आप बचा रहे हैं? इसे खर्च क्यों नही कर पा रहे हैं? इन बातों के साथ मैं आपको जो सुझाव दिया हूं, मैंने कोई बुराई के नाम से सुझाव नहीं दिया है। हमारे प्रदेश का अच्छा हो, आपके माध्यम से अच्छा हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप करिए और हम लोगों को कोई विरोधी- उरोधी मत समझिए। हम आपके शुभचिन्तक हैं और इनसे (भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा) ज्यादा हैं। आपको अच्छा रास्ता दिखायेंगे, कहीं गलती होगी तो बतायेंगे। मैं अभी किसी का लिख रहा था-प्रयत्न करने से कभी नहीं चूकें। प्रयत्न करने में कभी मत चूकिए क्योंकि हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। इसलिए हम आपकी प्रगति के लिए विरोधी बनकर आपको सलाह दे रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ये लोग तो आपकी आंख में पट्टी बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी पट्टी खोलने की कोशिश कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं इनकी मांगों का विरोध करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्य मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विभागों से संबंधित अनुदान मांगों की चर्चा में भाग लेने वाले सभी सम्माननीय सदस्यगण आदरणीय डॉ. चरण दास महंत, श्री

दलेश्वर साहू जी, श्री अजय चन्द्राकर जी, श्री अटल श्रीवास्तव जी, श्री धरम लाल कौशिक जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, श्री राजेश मूणत जी, श्री कुंवर सिंह निषाद जी, श्री नीलकंठ टेकाम जी, श्री दिलीप लहरिया जी, श्री अनुज शर्मा जी, श्रीमती अंबिका मरकाम जी, श्री मोतीलाल साहू जी, श्रीमती शेषराज हरवंश जी, श्री गुरू खुशवंत साहेब जी एवं श्री पुन्नूलाल मोहले जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले सवा साल से हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए अपनी पूरी उर्जा से काम कर रहे हैं। वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना के अनुरूप हमने छत्तीसगढ़ की प्रगति का बजट तैयार किया है और इसे प्राप्त करने बेहतर योजनाएं भी गढ़ी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार का पहला बजट ज्ञान पर आधारित बजट था। ज्ञान अर्थात् गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। हमारा यह बजट ज्ञान के लिए गति पर आधारित है। गति से हमारा आशय गुड गवर्नेंश, एक्सलरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नालॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। हम इस वर्ष हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, शपथ ग्रहण के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पुन: खड़ा करने की थी, जो कि पिछली सरकार में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। छत्तीसगढ़ महतारी के अमूल्य संसाधनों का [xx] करने के लिए पिछली सरकार में जिस तरह से नियमों को तोड़ा-मरोड़ा गया था, पारदर्शिता को ताक पर रख दिया गया था, यह पूरे प्रदेश ने देखा था। हमने इस पारदर्शिता को पुन: स्थापित किया। भ्रष्ट मैनुअल पद्धतियां समाप्त कीं और इसके स्थान पर डिजिटल गवर्नेंश पुन: आरंभ किया। मैनुअल पद्धति की जगह ऑनलाईन सिस्टम आरंभ करने का सीधा असर उन विभागों पर भी दिखा, जिनसे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। जो राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, वह राज्य के खजाने में आ रही है और इसे जनकल्याण के लिए लगाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सुशासन पर हमारा सबसे अधिक फोकस है। पुरानी डिजिटल परंपराओं को पुन: आरंभ करने के साथ हमने नये जमाने के अनुरूप नयी डिजिटल पारदर्शी प्रक्रियाओं को भी अपनाया है। लोक प्रशासन में अनेक नवाचार विकसित हुए हैं। प्रशासनिक प्रणाली को बेहतर करने के लिये नई सोच विकसित हुई है। इन सारी पद्धितयों को अपनाने के लिये हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना की है। शायद इस मामले में हमारा प्रदेश पहला प्रदेश है। (मेजों की थपथपाहट) इस विभाग ने प्रशासनिक प्रणाली में सुधार के अनेक उपाय सुझाए हैं, जिन पर हम लगातार अमल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब मन सच्चा हो, आपके भीतर संवेदनशीलता हो, तो वैसी योजनाएं बनती हैं, जिनसे आम जनता के जीवन में बहुत बेहतरी आती है। उदाहरण के लिये हमने उन इलाकों के लिये ग्रामीण बस योजना बनाई है, जहां सड़क तो पहुंच गयी है लेकिन सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था नहीं पहुंची। सड़क की सार्थकता तो तभी होती है, जब आम आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इसका इस्तेमाल कर सके। हम बस चलाने के लिये स्थानीय लोगों को वित्तीय सहायता देंगे।

अध्यक्ष महोदय, नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता और समय पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिये हम Ease of Doing Business और Ease of living के अनुरूप नीतियां तैयार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की ताकत हमारी सुंदर संस्कृति और अद्भुत प्राकृतिक परिवेश है। इसे वैश्विक पर्यटन नक्शे में लाने के लिये एक मजबूत नींव हमने इस बजट में रख दी है। हमने प्रचार प्रसार के लिय बजट बढ़ाया है ताकि अधिकाधिक लोग छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित हो। होम स्टे जैसे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिये हमने विशेष अनुदान रखा है। विमानन सेवाओं के विस्तार और गुणवत्ता पर भी हम काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बार हम छत्तीसगढ़ निर्माण की रजत जयंती मना रहे हैं। संयोग से यह वर्ष हमारे प्रदेश के निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। हम इसे अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है, इसके अनुरूप हम भी विकसित छत्तीसगढ़ के लिये सुशासन पर चलते हुए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप लगातार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा इरादा दृढ़ है, लक्ष्य ऊंचा है और इसके लिये मेहनत करने का भी अडिग संकल्प है। बजट प्रावधानों में इसकी साफ झलक देखने को मिलती है।

अध्यक्ष महोदय, आज जितने भी सदस्य हमारी चर्चा में भाग लिये हैं, उनकी बातों को हमने नोट कराया है और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि उनकी जो भी जायज मांगें होंगी, उनको बिना भेदभाव के हमारी सरकार पूरा करेगी। (मेजों की थपथपाहट) अंत में मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हमारे शुभचिंतक हैं, हमेशा सही सलाह देते हैं, भलाई के लिये सलाह देते हैं, उसके लिये धन्यवाद। आपने जो सलाह दी है, हमने उसको भी नोट किया है। हम अंत में उसका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आपके सही उपदेशों का पालन भी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने विभागों की अनुदान मांगों को सदन के समक्ष रखता हूं। पहला, सुशासन एवं अभिसरण विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुशासन को बढ़ावा देने के लिये अनूठी पहल करते हुए हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना की है। इस नये विभाग के बजट में 74.37 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना के लिये 1 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। नवाचारों के प्रोत्साहन हेतु आर्थिक सहायता हेतु बजट में 4 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के लिये 7.20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अटल मॉनिटरिंग डेशबोर्ड के लिये राज्य शासन की प्रमुख परियोजना और योजनाओं की जमीनी हकीकत की निगरानी की जा सकेगी। इस प्रयोजन हेतु 12 करोड़

रूपये का प्रावधान बजट में रखा गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं और शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक और एकीकृत मुख्यमंत्री हेल्पलाईन प्रणाली के लिये 22 करोड़ रूपये का प्रावधान बजट में किया गया है। जनसंवाद कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सीधे आम जनता से फीड बैक लेने के लिए एक एकीकृत नागरिक डाटा बेस बनाने और नागरिक कॉल सेन्टर स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को जन संवाद का नाम दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए बजट में 13 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन 2047 हेतु पी.एम.यू. नवाचारात्मक एवं प्रशासन की प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने के साथ-साथ अनेक नवीन जनोपयोगी योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री हेल्प लाईन, जन संवाद, मुख्यमंत्री सुशासन फैलोशिप प्रोग्राम अटल मॉनिटरिंग डेस बोर्ड आदि संचालित किये जाएंगे। इन कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु योजना निर्माण डेटा विश्लेषण तथा सूचना प्रबंधन जैसी गतिविधियों को संपादित करने हेतु विभाग अंतर्गत डी.एम.यू. का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, नवगठित सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 में प्राप्त बजट से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और डिजिटल नवाचार को नई ऊंचाईयों तक ले जाएंगे। सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने में सुशासन एवं अभिसरण विभाग का बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 380 करोड़ रूपये का बजट रखा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है। हमारी सरकार आई.टी. का उपयोग कर राज्य के नागरिकों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं विश्वसनीय तरीके से देने के लिए संकल्पित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सर्वप्रथम नवीन मद से प्रारंभ की जा रही हमारी मुख्यमंत्री आई.टी. फैलोशिप एवं इंटर्नशिप कार्यक्रम के विषय में बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री आई.टी. फैलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के पेशेवर युवाओं की प्रतिभा का राज्य हित में उपयोग करना है। हम ट्रीपल आई.टी. नवा रायपुर के सहयोग से डाटा एनालिटिक्स पर जोर, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रोग्राम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने बजट में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) मुख्यमंत्री आई.टी. इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से आई.आई.टी. भिलाई, ट्रीपल आई.टी. नवा रायपुर, एन.आई.टी. रायपुर से स्नातक किये प्रतिभाशाली युवाओं को सरकारी विभागों में इंटर्न के रूप में कार्य करने का अवसर मिलेगा। हमने इसके लिए बजट में 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। राज्य के बस्तर एवं सरगुजा जिलों के कम जनसंख्या वाले दूरस्थ

क्षेत्रों में वी.जी.एफ. के माध्यम से मोबाईल टॉवर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हमने नेटवर्क क्रांति योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, इसके लिए हमारी सरकार ने 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। साइबर Security ऑपरेशन सेन्टर स्थापित करने के लिए हमारी सरकार ने 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, हमने शासन की योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु ऑन लाईन एडवांस प्लेटफार्म बनाने के उद्देश्य से अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, सी.एम. डेसबोर्ड परियोजना विकसित की है। जिसके लिए बजट में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय, नियल नेल्ला नार जिसका हिन्दी अनुवाद है आपका अच्छा गांव डेसबोर्ड । सुशासन का सपना साकार करने के लिए विकास कार्यों को और अधिक गति प्रदान करना अति आवश्यक है। हमारे सरकार ने नियल नेल्ला नार के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों के लिए डेसबोर्ड का निर्माण किया है। डेसबोर्ड में चिन्हित 25 बुनियादी सेवाओं तथा 18 सुविधाओं और राज्य के वामपंथी प्रभावित जिलों में 35 बुनियादी सेवाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति का डेटा जिला स्तर से रियल टाईम में फीड किया जा रहा है। आधार आधारित सेवाएं विगत 14 महीने में नियल नेल्ला नार के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के 7 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में कुल 806 विशेष आधार शिविर आयोजित कर 33 हजार 905 आधार नामांकन एवं अद्यतन किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रीक्ट परियोजना। विगत 14 महीने में ई-डिस्ट्रीक्ट परियोजना अंतर्गत 39 लाख 89 हजार से अधिक नागरिकों ने इस पोर्टल से शासकीय सेवाओं का लाभ उठाया है। प्रति वर्ष औसतन 32 लाख नागरिक इस ऑन लाईन सुविधा से लाभांवित हो रहे हैं। प्रधान मंत्री गति शक्ति पोर्टल में अब तक राज्य के 10 हजार से अधिक ग्रामों का जिओ रिफ्रेशिंग कार्य किया जा चुका है और शेष ग्रामों का कार्य प्रगति पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दी के शब्दकोश में एक शब्द "लालफीताशाही" होता है। जिसका भी काम रोकना हो तो भ्रष्ट अफसर फाईल में लाल फीता लगाकर इसे डंब कर देते हैं। फाईल का लाल फीता तब खुलता है जब आवक आ जाती है। भ्रष्टाचार को रोकने के सारे उपाय तब तक बेईमानी है जब तक भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार न किया जाये। भ्रष्टाचार की मूल जड़ यही मेनुअल फाईल प्रणाली है। हमने इस पद्धति को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाहट) आम जनता का कार्य पारदर्शिता एवं सुगमता से हो, इसके लिए ई-ऑफिस का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2025 से किया जायेगा। अब फाईल कम्पयूटर पर चलेगी। फाईलों को निपटाने की तिथि तय होगी। फाईलों पर अपनी टिप्पणी दर्ज करनी होगी जिसे बदला नहीं जा सकेगा। तय समय पर आवेदन प्रकरणों का निराकरण होगा, इससे लालफीताशाही और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।(मेजों की थपथपाहट) भ्रष्टाचार को लेकर हमारा जीरो टालरेंस है। हमारी कथनी करनी में भी दिखता है। इसी कारण हमने हर स्तर पर पारदर्शिता को अपनाया है। इससे न केवल समय कम लगेगा, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और शासकीय कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग के साथ जवाबदेही भी तय होगी।

ई-ऑफिस के क्रियान्वयन हेतु बजट में नवीन मद के रूप में कुल 22 करोड़ 67 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई-ऑफिस प्रणाली में सभी फाईलें ऑनलाईन कम्पयूटर के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी। चरणबद्ध तरीके से नोटशीट एवं डाक का ऑनलाईन माध्यम से निपटान किया जायेगा। मंत्रालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन, अचल संपत्ति विवरण SPARROW के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। e-HRMS के माध्यम से समस्त अवकाश से संबंधित कार्य पूर्णत: ऑनलाईन संपादित किये जा रहे हैं। मंत्रालय के अलावा विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं जिला स्तर के कार्यालयों में भी ई-ऑफिस के माध्यम से शासकीय कार्यों का त्वरित निपटारा किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हर दिन प्रदेश के बहुत से नागरिक अपनी जरूरतों के लिये एवं सेवाभावी कार्यो के लिये मुझसे मिलते हैं। मुझे यह महसूस हुआ कि स्वेच्छानुदान का बजट मेरे और मंत्रीगणों के लिये बढ़ाना आवश्यक है ताकि जनकल्याण का कार्य अधिकाधिक मात्रा में किया जा सके। जरूरतमंद लोगों और संस्थाओं को विभिन्न कार्यों के लिये दिये जाने वाले स्वेच्छानुदान हेतु बजट में 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) स्वेच्छानुदान की स्वीकृति सीमा में बढोत्तरी की गई है। मुख्यमंत्री प्रत्येक प्रकरण में अधिकतम 5 लाख रुपये, उपमुख्यमंत्री तथा माननीय मंत्रीगण अधिकतम 40 हजार रुपये की स्वीकृति दे सकेंगे। मुख्यमंत्री घोषणाओं को पूरा करने के लिये कुल 49 करोड़ 59 लाख रुपये का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ दुलार योजना 2021 हेतु मुख्यंमत्री अधोसरंचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण मद अंतर्गत 5 करोड़ 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस मद से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं आवागमन से संबंधित अधोसंरचनाओं के रखरखाव एवं उन्नयन संबंधी कार्यों का भी पोषण किया जा रहा है। इस मद से ही प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद विद्यालयों हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। अन्य विभागों से मांग प्राप्त होने पर भी इसी राशि से अनुदान दिया जा सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार बनी तब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की पूर्व सरकार का शराब घोटाला पूरे देश में चर्चित था। प्रवर्तन निदेशालय और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच और कार्रवाई की जा रही थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के साथी कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ है तो कितनी राशि बरामद हुई है यह बतायें? आपकी पार्टी की राजनीति समझने वाला एक छोटा कार्यकर्ता भी इस बात को समझ चुका है कि यह राशि कहां गई। छत्तीसगढ़ को लूटकर लूट का माल कहां भेजा गया। (मेजों की थपथपाहट) मुझे दुष्यंत कुमार जी का लिखा याद आता है-

यहां तक आते-आते सूख जाती हैं कई नदियां

मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी इस सदन को बताता हूं जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि शराब घोटाला कितना बड़ा था । वर्ष 2019-2020 में आबकारी से प्राप्त होने वाले राजस्व की राशि 4952.79 करोड़ थी तो जब हम लोग वर्ष 2024-25 में सरकार में आए । मैं मार्च तक का आंकड़ा बता रहा हूं कि यह 9573 करोड़ रुपए हो गई है । (मेजों की थपथपाहट) 4 हजार से 9 हजार यानी 5 हजार करोड़ की बढ़ोतरी हम लोगों की सरकार में हो गई है । यह जो राशि बढ़ी है वही राशि सिंडीकेट के खाते में चली जाती थी और सिंडिकेट कुछ राशि हजम कर ऊपर उन्हें भेज देता था जिसकी कृपा से इनकी पद-प्रतिष्ठा बनी हुई थी । एक साल के भीतर ही छापे पड़ने के बाद इतना बड़ा परिवर्तन राजस्व की प्राप्ति में हुआ है इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बचती है । (मेजों की थपथपाहट) सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी की तरह स्पष्ट हो जाता है । (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार द्वारा अनेक बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिससे विभागीय कार्य प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन हुआ और राजस्व प्राप्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । हमारी सरकार आने के पूर्व में डिस्टलरी से देशी शराब के वेयरहाऊस तक शराब का परिवहन ऑफलाईन परमिट के माध्यम से होता था । हमने सभी प्रकार के लाईसेंस की समस्त प्रक्रिया को ease of doing business के तहत Online किया है । (मेजों की थपथपाहट) समस्त प्रकार की शराब की परमिटों को भी Online किया गया जिससे कर चोरी नहीं की जा पा रही है । हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विदेशी शराब की थोक खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को पुनः लागू किया है । (मेजों की थपथपाहट) जिससे विदेशी शराब की सप्लाई में जो मध्यस्थ होते थे उनका सफाया हुआ है । हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया कि होलोग्राम के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता को दूर रखने के लिए सीधे शासकीय मुद्रणालय से होलोग्राम प्राप्त किया जाए । (मेजों की थपथपाहट) वर्तमान में भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक महाराष्ट्र के द्वारा बनाए गए ई.ए.एल. का क्रय कर उपयोग किया जा रहा है । (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ State Marketing Corporation limited द्वारा किया जा रहा है । आबकारी उड़नदस्तों द्वारा लगातार छापा की कार्यवाही और इन सभी सुधारों से आबकारी विभाग से आने वाले राजस्व राशि में काफी इजाफा हुआ है जिसका उपयोग जनकल्याणकारी कार्यों में किया जा रहा है । आबकारी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 33 जिला स्तरीय उड़नदस्ता के लिए 425 नवीन पदों का सृजन किया गया है । इसमें से 225 पदों पर भर्ती की स्वीकृति भी दे दी गई है । बजट में पदों के वेतन भत्ते हेतु 19 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । नवीन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है । आबकारी अपराधों की रोकथाम के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित जांच चौकियों हेतु 70 वाहनों की व्यवस्था के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है । वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 30 हजार मेगावाट है । प्रदेश में निजी एवं शासकीय पॉवर प्लांट को मिलाकर कुल 1 लाख 65 हजार 187 मिलियन यूनिट का वार्षिक उत्पादन किया गया है जो देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरे क्रम पर है । छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी वर्ष 2023-24 के प्रदर्शन अनुसार 84.45 प्रतिशत पी.एल.एफ. के साथ देश में प्रथम स्थान पर अपना छत्तीसगढ़ है । प्रदेश की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2211 यूनिट है जो कि संपूर्ण देश में गोवा, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा के बाद पांचवें क्रम पर है । विद्युत शुल्क एवं उपकर के मद में राज्य शासन को वर्ष 2023-24 में राजस्व मद में 4188 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ था जबकि वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक 4599 करोड़ रूपये की प्राप्ति हो चुकी है । ईलेक्ट्रिक पॉवर सर्वे के अनुसार विद्युत की मांग में लगभग 6.5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है । पिछली सरकार द्वारा विगत् 5 वर्षों में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कोई ठोस पहल नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप लगातार बढ़ रही विद्युत की मांग की पूर्ति हेतु महंगी दरों पर बिजली क्रय करना पड़ रहा है । हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आगामी पांच से सात वर्षों में विद्युत परियोजनाओं में लगभग 3 लाख करोड़ रूपये के निवेश की कार्ययोजना बनाई है। इनमें से कुछ परियोजना का कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ऊर्जा की चिंता कर रहे थे तो आने वाले 10 वर्षों की चिंता हमारी सरकार कर रही है। (मेजों की थपथपाहट) आने वाले 5-7 साल में 3 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव आया है, जिसमें अतिरिक्त करीब 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। विद्युत अधोसंरचना में विकास की योजना बनाते समय माननीय प्रधानमंत्री..।

डॉ. चरणदास महंत :- महाराज, क्षमा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका विकास बस्तर में ही होगा न।

श्री विष्णु देव साव :- नहीं, पूरे प्रदेश में। यह एक तरह का नहीं है। यह थर्मल भी होगा, आपका न्यूक्लियर भी होगा, सोलर भी होगा।

डॉ. चरणदास महंत :- मतलब हमारे हसदेव अरण्य में होगा और बस्तर में होगा। दोनों जगह होगा।

श्री विष्णु देव साय :- नहीं-नहीं, आपके जशपुर में भी होगा। आप देखते रहिए। विद्युत अधोसंरचना में विकास की योजना मनाते समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप गैर परंपरागत स्रोतों व हरित ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. द्वारा अब सुनिए मैं बता रहा हूं कि कहां-कहां क्या लग रहा है। एन.टी.पी.सी. द्वारा 80,000 करोड़ की निवेश लागत से कुल 4,200 मेगावाट क्षमता के संयंत्र की स्थापना की जा रही है। (मेजों की थपथपाहट) ये सीपत में लगेगा। ताप विद्युत परियोजना के क्षेत्र में

लगभग 1,07,840 करोड़ की निवेश लागत से कुल 12,100 मेगावाट क्षमता के संयंत्र की स्थापना, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा लगभग राशि 15,800 करोड़ की लागत से 320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल परियोजना की कोरबा में स्थापना होगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- नेती जी, आप ही के विधान सभा में हो रहा है।

श्री विष्णु देव साय :- सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की निवेश लागत से कुल 2500 मेगावाट क्षमता के संयंत्र की स्थापना की जाएगी। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना के क्षेत्र में लगभग 57,000, 46,000 करोड़ रुपए के निवेश से कुल 12,300 मेगावाट क्षमता के संयंत्र की स्थापना सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी क्षेत्र में होगी। उप परियोजनाओं की स्थापना गरियाबंद, जशपुर, बलरामपुर एवं कबीरधाम जैसे दूरस्थ एवं आदिवासी बाहुल जिलों में भी की जा रही है। विद्युत पारेषण क्षेत्र में उप विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु 17,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। विद्युत वितरण के क्षेत्र में पहले से स्थापित अधोसंरचना के उन्नयन एवं नवीन सब स्टेशन निर्माण हेतु लगभग 11,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के उत्तरोत्तर विकास के कारण विद्युत की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। विगत वर्ष विद्युत की अधिकतम मांग 6,372 मेगावाट रही, जो इस वर्ष अभी तक 6,319 मेगावाट दर्ज हुई है, जो आगामी माह में 6,600 मेगावाट तक बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित भारत की 20वीं विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2022 के अनुसार वर्ष 2031-32 तक छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत मांग 9,713 मेगावाट संभावित है। वर्तमान में प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2,978 मेगावाट है। मांग की कमी को पूरा करने के लिए उत्पादन कंपनी द्वारा 1,320 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया जा रहा है तथा वितरण कंपनी द्वारा एन.टी.पी.सी. सहित अन्य उत्पादकों से करार किये गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत पारेषण प्रणाली की वर्तमान में स्थापित क्षमता 10,800 एम.वी.ए. है। बढ़ती मांग को देखते हुए अगले 5 वर्षों में राज्य की पारेषण क्षमता वृद्धि करने हेतु लगभग 17,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। वर्ष 2025-30 की प्रस्तावित कार्ययोजना में 400 के.व्ही. के साथ 7 नग अतिरिक्त दाब उप केंद्र ग्राम धरदेही, पिथौरा, कुनपुरी, कन्हैरा, बिलाईगढ़, आरंग एवं देवरी में प्रस्तावित है तथा 220 के.व्ही. के 20 नग एवं 132 के.व्ही. के 40 नग नए उप केंद्र का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिससे राज्य की पारेषण प्रणाली की स्थापित क्षमता बढ़कर 19,680 एम.वी.ए. संभावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष में प्रदेश में 33 के.व्ही. लाइन की लंबाई 24,713 किलोमीटर से बढ़कर 25,708 किलोमीटर हो गयी है। एक वर्ष में प्रदेश में 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों की संख्या 1,409 से बढ़कर 1,447 हो गई है, इस कड़ी में विगत 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों में 57 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना की गई एवं 53 स्थानों के 33/11 केव्ही के उपकेन्द्रों में स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि की गई है । एक वर्ष में प्रदेश

में 11 केव्ही लाईन की लंबाई 1 लाख 31 हजार 139 किलोमीटर से बढ़कर 1 लाख 37 हजार 245 किलोमीटर हो गई है । एक वर्ष में प्रदेश में वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या 2 लाख 23 हजार 601 से बढ़कर 2 लाख, 41 हजार 837 हो गई है । वर्ष 2023-24 में वितरण हानि 44.56 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 13.97 प्रतिशत हो गई है । वितरण हानि की निर्धारित सीमा 15 प्रतिशत है जो कि राज्य के उत्कृष्ट कार्य क्षमता का परिचायक है । आप ऊर्जा के विषय में चिंता कर रहे थे तो हमार ऊर्जा विभाग यह सब काम कर रहा है । अध्यक्ष महोदय, आरडीएसएस योजना है इसके अंतर्गत कृषि पम्प एवं घरेलू कनेक्शन मिश्रित 1067 फीडरों का पृथकीकरण का कार्य प्रगति पर है । डोमेस्टिक और पम्प कनेक्शन अलग-अलग कर रहे हैं । इसी प्रकार ओवर लोडेड 11 केव्ही विद्युत लाईनों के भार विभाजन का कार्य भी किया जा रहा है । जिससे उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज एवं बिजली ट्रिप्टिंग की समस्या से निजात मिलेगी । आगामी एक वर्ष में उपभोक्ता परिसर में लगभग 50 लाख प्री-पैड स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने की योजना है, जिससे ऑटोमेटिक रीडिंग एवं बिलिंग होगी एवं उपभोक्ताओं को विद्युत बिल प्राप्त न होने एवं त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल प्राप्त होने की शिकायत समाप्त हो जाएगी । पिछले समय आपकी सरकार में बिल भी नहीं मिलता था तो लोग समझते थे कि बिल माफ हो गया इसलिए पटाया नहीं । उसके निपटान के लिए हमारी सरकार प्रयासरत् है । साथ ही उपभोक्ता हर आधे घंटे में अपने परिसर में हो रही विद्युत खपत को देख सकेगा । वर्तमान में रायपुर, दुर्ग, भिलाई शहर में स्काडा सेंटर स्थापित है । वर्ष 2030 तक आरटीडीएएस योजना के तहत कोरबा एवं बिलासपुर शहर में स्काडा सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । आरटीडीएएस योजना के अंतर्गत विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ किए जाने हेतु 18,147 किलोमीटर नई 11 केव्ही लाईन निर्माण का कार्य एवं 44,168 किलोमीटर खुली निम्नदाब लाईनों को केबल में परिवर्तित करने का भी कार्य प्रगतिरत है । इसी योजना अंतर्गत 7,544 करोड़ रूपए के कार्य प्रगतिरत् हैं एवं 3,500 करोड़ के व्यय पर 400 नवीन 33/11 केव्ही उप केन्द्रों के निर्माण के कार्य प्रस्तावित किये जा रहे हैं । नियद नेल्लानार योजना राज्य के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा कैम्पों के समीप 5 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत आने वाले 115 गांवों के सर्वांगीण विकास हेतु चयन किया गया है, जिसमें 73 करोड़ की लागत पर 88 ग्रामों, मजरों टोलों के 8051 अविद्युतीकृत घरों को ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है । आजादी के 78 वर्षों उपरांत पहली बार नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत 133 गांवों में 132 नग सोलर हाई मास्ट, 319 सोलर पेयजल पम्प और 203 नग सोलर सेल पम्पों की स्थापना की जा रही है, 78 साल बाद (मेजो की थपथपाहट) । पीएम जनमन योजना के तहत प्रदेश के 7 जनजातीय यथा अबूझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, बिरहोर, भुंजिया एवं पंडों जाति के सर्वांगीण विकास के तहत 40 करोड़ के लागत व्यय पर 7,077 अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण किया जा रहा है तथा 1,578 अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण सोलर माध्यम से किया जा रहा है । पीएम धरती आबा जनजाति

ग्राम उत्कर्ष योजना जिसको संक्षेप में पीएम जुगा कहते हैं, इसके तहत प्रदेश में छूटे हुए 65,711 अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकण हेतु 323 करोड़ रूपए की योजना बजट में शामिल है । (मेजों की थपथपाहट)

समय :

8.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान। इसके अंतर्गत प्रतिमाह 30 यूनिट की खपत पर नि:शुल्क बिजली प्रदान की जाती है जिसमें कुल 15.59 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, इस हेतु 496 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। हमारे मोहले जी बोल रहे थे कि 30 यूनिट को बढ़ाकर 50 यूनिट करना चाहिए। मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि अब हमारी सरकार हाफ बिजली से नि:शुल्क बिजली की ओर बढ़ रही है जो प्रधानमंत्री जी की योजना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना जिसमें 78 हजार रूपए की सब्सिडी का प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट से है, हम लोग प्रदेश से सब्सिडी का प्रावधान कर रहे हैं और हर घर के छत में सोलर पैनल लगेगा और उनको नि:शुल्क बिजली मिलेगी, इस तरफ सरकार का प्रयास है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- क्या उसको 30 यूनिट से 50 यूनिट करेंगे ?

श्री विष्णुदेव साय :- फ्री में देंगे, हर घर में सोलर प्लेट लगाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 44 लाख 92 हजार घरेलू उपभोक्ता खपत की गई बिजली की यूनिटों में 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, इस हेतु 1 हजार करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत् एक करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सौर संयंत्र स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत सरकार द्वारा तीन किलोवाट की क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना के लिए राशि रू. 78 हजार सब्सिडी दी जा रही है, राज्य शासन ने भी योजना के तहत् घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी दिये जाने हेतु वर्ष 2025-26 के लिए 217 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान किया है जिसके परिणामस्वरूप हाफ बिजली से लाभान्वित घरेलू उपभोक्ता मुफ्त बिजली की ओर अग्रसर होंगे। (मेजों की थपथपाहट) मॉडल सोलर विलेज के तहत् भारत सरकार द्वारा पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मॉडल सोलर विलेज विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत् प्रदेश के समस्त 35 जिलों के 1-1 गांवों का चयन करके उस गांव के समस्त सामुदायिक स्थल भवनों में विद्युतीकरण पेयजल और सिंचाई हेतु सोलर पंप की स्थापना तथा ग्राम के चौक चौराहों एवं मार्गों को सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों से प्रकाश

व्यवस्था किया जाना है, इस हेतु 33 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, 33 जिले में 1-1 गांव का चयन करेंगे और मॉडल सोलर विलेज बनाने की सरकार की मंशा है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, सोलर हाई मास्ट एवं सौर संयंत्रों की स्थापना। प्रदेश में सोलर हाई मास्ट एवं सौर संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में अब तक चौक चौराहों पर कुल 7200 नग सोलर हाई मास्ट संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है जो कि आम जनता द्वारा अत्यंत सराहा जा रहा है। इस हेतु राज्य शासन द्वारा इस साल के बजट में 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, कृषि पंपों का ऊर्जीकरण। कृषि पंपों के विद्युतीकरण हेतु आवश्यक लाईन विस्तार कार्य के लिए प्रति पंप एक लाख रूपए तक छूट दी जाती है, इस कार्य हेतु 50 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। पी.एम.कुसुम योजना के तहत् सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर कृषि पंपों की स्थापना हेतु 10 हजार पंपों का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए 319 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना। इसके अंतर्गत 3 HP क्षमता के कृषि पंपों को 6 हजार यूनिट एवं 5 HP क्षमता के पंपों को साढ़े सात हजार यूनिट वार्षिक खपत पर शासन द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। (मेजों की थपथपाहट) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संवर्ग के उपभोक्ताओं को बिना किसी सीमा के संपूर्ण खपत नि:शुल्क है। योजना के अंतर्गत 7 लाख 73 हजार किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के लिए बजट में 3500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण। अविद्युतीकृत मजरे टोलों को इस योजना अंतर्गत विशेष रूप से अंबिकापुर एवं बस्तर राजस्व संभाग के ग्राम एवं मजराटोलों में विद्युत लाईन विस्तार कर विद्युत प्रदाय की जा रही है। इस हेतु 50 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना भी है। इस योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में निवासरत BPL परिवारों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय के साथ-साथ सड़क चौड़ीकरण हेतु विद्युत लाइनों एवं उप केन्द्रों की सिफ्टिंग, भूमि आदि के कार्य किये जा रहे हैं। इस हेतु 25 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी धरती रत्नगर्भा है। खनिज संसाधनों से संपन्न राज्य होने के चलते छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास की पूरी संभावनाएं भी हैं। केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2015 में अधिसूचित नवीन खनिज अधिनियम के नियमों के तहत मुख्य खनिज ब्लॉक खनिज पट्टा composite license के लिए आवंटन हेतु ई-ऑक्शन टेण्डर के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक कुल 39 खनिज ब्लॉक में 13 चूना-पत्थर, 9 लौह अयस्क, 7 बाक्साइट, 3 गोल्ड, 2 निकिल-कोमियम इजी ब्लॉक्स, 2 ग्रेफाइट एवं 2 ग्लूकोनाइट की नीलामी राज्य शासन द्वारा तथा 1 लिथयम एण्ड आर.ई.

ब्लॉक की ई-नीलामी भारत सरकार द्वारा सफलतापूर्वक की जा चुकी है। (मेजों की थपथपाहट) वर्ष 2024-2025 में खनिज बाक्साइट के कुल 2 ब्लॉक की सफलतापूर्वक ई-नीलामी की गई है एवं चूना-पत्थर के 1, लौह-अयस्क के 4 एवं बाक्साइट के 4 खनिज ब्लॉक्स की ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। लौह-अयस्क के इन 4 खदानों के प्रारंभ होने से एक ओर जहां खनिज राजस्व में वृद्धि होगी, वही राज्य के उद्योगों को भी लाभ होगा। इसके अलावा खैरागढ़ जिले के 2 लौह-अयस्क ब्लॉक की नीलामी की कार्रवाई भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत की जायेगी। लौह-अयस्क के उपरोक्त ब्लॉक्स में 3 दंतेवाड़ा जिले में तथा 1 कांकेर जिले में हैं। दंतेवाड़ा के तीनों ब्लॉक्स में अनुमानित 287 मिलियन टन का भण्डार है। पिछली सरकार में DMF फण्ड के दुरूपयोग के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार DMF फण्ड का उपयोग पारदर्शी तरीके से किये जाने के लिये कृतसंकल्पित है तथा इसके लिए संबंधितों को कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। सरकार की मंशा है कि इस फण्ड की राशि का सदुपयोग विशुद्ध रूप से खनिज प्रभावित क्षेत्र में लोगों के हित में ही हो। DMF फण्ड के सदुपयोग से दंतेवाड़ा जैसे जिलों में मेडिकल कॉलेज की पहल की गई है। (मेजों की थपथपाहट) इससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य का स्तर भी बेहतर होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में कोयला, लौह-अयस्क, बाक्साइट, चूना-पत्थर, डोलोमाइट आदि खनिजों को मिलाकर लगभग 300 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन हो रहा है। नवीन खदानों का संचालन शीघ्र प्रारंभ करने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है। आगामी 2 वर्षों में उक्त उत्पादन की मात्रा लगभग 375 मिलियन टन तक होने का अनुमान है। इसके फलस्वरूप लगभग 2000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व आने का अनुमान है। खनन कार्य में तेजी लाने एवं उत्पादन में वृद्धि किये जाने के लिए विभाग योजनाबद्ध तरीके से कार्यरत है। इसके फलस्वरूप राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश की जनता को परिवहन से संबंधित सुगम सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। परिवहन विभाग के लिए बजट में 209 करोड़, 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इसमें हम मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों, जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, वहां last mile connectivity के तहत कस्बों से ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय एवं शहरों को जोड़ने के उद्देश्य से ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट) इससे ग्रामीण अपने रोजमर्रा के कार्य शिक्षा व इलाज आदि के लिए आसानी से आ-जा सकेंगे। इन इलाकों में जहां आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, वही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। प्रथम चरण में बस्तर एवं सरगुजा संभाग का चयन इस योजना के लिए किया जायेगा। बस संचालकों को शासन द्वारा viability gap funding (VGF) के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जायेगी। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 25 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बस संगवारी एप भी बनाया गया है। हमारी सरकार ने यात्रियों के आवागमन को आसान और सुविधाजनक बनाने हेतु बस संगवारी एप बनाई है। प्रदेश में संचालित प्रत्येक यात्री वाहनों के गंतव्य स्थान के रूट, समय व मार्ग में उपलब्ध बसों की जानकारी एप के माध्यम से यात्रियों को उपलब्ध हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में संचालित सभी यात्री वाहनों के लिए एप के माध्यम से आनलाईन टिकट बुकिंग की सुविधा भी प्रारंभ होगी। घर बैठे बस का टिकट भी बुक हो जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ड्रायविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और वाहन चालकों के कौशल में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश में केन्द्र सरकार के सहयोग से ड्रायविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की स्थापना अटल नगर नवा रायपुर में की गई है। I.D.T.R. द्वारा व्यवसायिक चालकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारी सरकार इन संस्थान को Centre of Excellence for Logistics के रूप में विकसित करने जा रही है। इस संस्थान में वाहनों के रखरखाव और ड्रायविंग प्रशिक्षण के साथ-साथ हैवी कामर्शियल वाहन भी विशेषकर खनिज क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों एवं उपकरणों के इस्तेमाल सम्बन्धी रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिया जायेगा। विशेषकर महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मूलक ड्रायविंग प्रशिक्षण इस संस्थान में दिया जायेगा। इससे महिला सशक्तिकरण से संबंधित हमारे लक्ष्य भी पूरे होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से गांवों में खुशहाली आयेगी। किसानों को फसल का उचित दाम दिलाने की हमारी योजना से किसान आर्थिक रूप से समृद्ध भी होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने का सीधा असर ट्रेक्टर, हार्वेस्टर तथा दोपहिया वाहनों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि पर दिख रहा है। राज्य में वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में वाहनों की बिक्री में 24 प्रतिशत ट्रेक्टर्स की बिक्री में 28 प्रतिशत, हार्वेस्टर की बिक्री में 26 प्रतिशत एवं दोपहिया वाहनों की बिक्री में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (मेजों की थपथपाहट) वाहनों के पंजीयन आदि से होने वाले राजस्व में सरकार को भी 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह सब धान की कीमत और अंतर की राशि एकमुश्त देने की वजह से संभव हो पाया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, परिवहन में लोगों को और सुविधा दिलाने के लिए राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त प्रकार के वाहनों में H.S.R.P. PLATE लगाना अनिवार्य किया गया है। H.S.R.P. PLATE नंबर हर वाहन को एक यूनिक आयडेन्टिटी देता है, जिससे वाहन के मालिक और ड्रायवर का पता लगाना आसान होता है। यह अपराधों के रोकथाम और जांच में भी मददगार होता है। खासतौर पर चोरी, सड़क दुर्घटनाओं या यातायात उल्लंघन के मामलों H.S.R.P. PLATE नंबर होने से आसानी होगी।

अध्यक्ष महोदय, Automated Computerized Driving Test Track की स्थापना, ड्रायविंग टेस्ट की प्रक्रिया आधुनिकीकरण तथा आटोमेशन के लिए Automated Computerized Driving Test

Track की स्थापना के लिए बजट में 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जिला परिवहन कार्यालय अम्बिकापुर, जगदलपुर, जशपुर, दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर, महासमुन्द एवं कबीरधाम में Automated Computerized Driving Test Track स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आधुनिक परिवहन लायसेंस केन्द्र, राजधानी रायपुर में पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर ड्रायविंग लायसेंस बनवाने हेतु आधुनिक परिवहन लायसेंस केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इसके लिए बजट में 1 करोड़ 33 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इस केन्द्र में आनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से ड्रायविंग टेस्ट देने हेतु समय का चयन के साथ-साथ बायोमेट्रिक एवं अन्य समस्त गतिविधियों को संपादित किया जायेगा। इससे आम नागरिकों को कार्यालय में अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन चेक पोस्ट, हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में संचालित समस्त अन्तर्राज्यीय परिवहन जांच चौकियों की गतिविधियों के स्वरूप को परिवर्तित करते हुए चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजना बनाई है। पूरे प्रदेश से इस चेक पोस्ट क्रमश: बंद करने की सरकार की योजना है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में घरेलू विमान सेवा के सफल संचालन के लिए लगातार प्रयासरत है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, कोलकाता से जुड़ चुका है, इसके फलस्वरूप राज्य में व्यापारिक गतिविधियों का विकास और अधिक हुआ है। रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान योजना के अंतर्गत जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर एयरपोर्ट्स का विकास सतत् रूप से जारी है, इस हेतु विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए बजट में 7 करोड़ 60 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। राज्य के नागरिकों को सस्ती विमान सेवा उपलब्ध कराने के लिए वी.जी.एफ. सहायता व आर.सी.एस. एयरपोर्ट के संचालन को ध्यान में रखते हुए बजट में 40 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। Bureau of civil aviation security के सुरक्षा मापदण्डों की पूर्ति व बिलासपुर एयरपोर्ट में नाईट लैंडिंग की सुविधा सुगमता से संचालित किये जाने हेतु इस बजट में 10 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) एयरपोर्ट्स के नियमित संधारण व रख-रखाव की आवश्यकता को देखते हुए जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर एयरपोर्ट हेतु बजट में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किय गया है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर में इंटरनेशनल कारगो हब स्थापना के लिए केन्द्रीय उड्डयन मंत्रालय द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है। (मेजों की थपथपाहट) जगदलपुर एवं बिलासपुर एयरपोर्ट में खराब मौसम में भी विमानों की सफल लैंडिंग के लिए उपकरण की स्थापना की जा चुकी है और साथ ही अंबिकापुर एयरपोर्ट में उक्त उपकरण की स्थापना हेतु कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार के सफल प्रयासों के प्रतिफल के रूप में 15 मार्च, 2024 से आगामी पांच वर्षों के लिए अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए ऑपरेशन लाईसेंस जारी कर दिया गया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल शिक्षा

विभाग हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता का विभाग है। स्कूली शिक्षा की बेहतरी के लिए हमने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है तथा इस वर्ष बजट में स्कूली शिक्षा में 4.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अलग-अलग मदों में बालने में काफी समय लगेगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। इसी शिक्षा विभाग में एक एन.सी.सी. भी आता है। एन.सी.सी. एयरविंग प्रशिक्षण केन्द्र, जो जगदलपुर और जशपुर में चल रहे हैं, जिससे हमारे प्रदेश के बच्चे वायुयान चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो आगे चल कर पायलट और वायु सेना में अपना अग्रणी स्थान रखेंगे। इसके लिए बजट में 1 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में विद्यालय भवन निर्माण हेतु 23 करोड़ 89 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 44 प्राथमिक तथा 43 पूर्व माध्यमिक शालाओं, 7 हाई स्कूल तथा 7 हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवनों का निर्माण कराया जाएगा। 3 प्राथमिक शालाओं का पूर्व माध्यमिक शालाओं में उन्नयन, 8 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन तथा 8 हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन का भी बजट में प्रावधान किया गया है। डोंगरगांव एवं बिलासपुर बी.टी.आई. का डाईट के रूप में उन्नयन हेतु 1 करोड़ रूपये तथा 41 नवीन पदों का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर, अटल नगर में बी.एड. कॉलेज की स्थापना के लिए 1 करोड़ रूपये तथा 17 नवीन पद प्रावधानित किए गए हैं। प्रथम चरण में डाईट पेण्ड्रा, बेमेतरा, रायपुर एवं कांकेर का डाईट ए.जे. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकास के लिए 24 करोड़ 75 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। द्वितीय चरण में डाईट दुर्ग, बीजापुर, महासमुंद एवं बस्तर का डाईट ए.जे. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकास किया जाएगा। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है। इसके तहत कक्षा पहली एवं दूसरी में राज्य की 16 स्थानीय भाषा, बोलियों एवं चार अंतरराज्जीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें प्रचलित हैं। विद्यार्थियों में तनाव कम करने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पी.एम. ई-विद्या अंतर्गत कक्षा नवमीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए पांच चैनलों से 24 घंटे शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक शासकीय विद्यालय में गत वर्ष से समर कैम्प का आयोजन भी किया जा रहा है। पालकों को विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने तथा सामुदायिक सहभागिता के विकास के लिए पालक शिक्षक पी.टी.एम. का आयोजन भी किया जा रहा है। प्री बोर्ड परीक्षा पांचवीं एवं आठवीं केन्द्रीयकृत परीक्षा का आयोजन भी किया गया है। शैक्षणिक सत्र वर्ष 2025-2026 हेतु 1 लाख 75 हजार 666 शिक्षकों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है । सत्र वर्ष 2025-2026 हेतु शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास हेतु 50 घण्टे प्रशिक्षण का भी लक्ष्य रखा गया है । प्रथम बार शिक्षण प्रशिक्षण के लिये शिक्षण प्रशिक्षण मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित किया जा रहा है । लगभग 7 हजार शिक्षकों की पदोन्नति की गई है । प्राचार्यों के लगभग 300 पदों पर पदोन्नति की डी.पी.सी. की जा चुकी है, व्याख्या के लगभग 2500 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । 32,916 विद्यालयों में 1 लाख 16 हजार 336 न्यौता भोज का आयोजन किया जा चुका है । (मेजों की थपथपाहट) स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत

संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की ऑनलाईन मानिटरिंग एवं आंकड़ों के विष्लेषण करने के लिये राज्य में समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना की गई है । ए.आई. के उपयोग से डाटा के विश्लेषण की सुविधा विद्या समीक्षा केन्द्र के अंतर्गत तैयार की गई है । योजनाओं के मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाईन पोर्टल एवं मोबाईल एप तैयार किये गये हैं । योजनाओं की सतत मानिटरिंग हेतु कॉल सेंटर स्थापित किया गया है । प्रदेश में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय के नाम से बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा जिले में संचालित 7 पोटा केबिन के लिये उच्च श्रेणी शिक्षक के लिये 300 एवं सहायक शिक्षकों के 600 पदों के सृजन हेतु 2 करोड़ रूपये का व्यय संभावित है । (मेजों की थपथपाहट) प्रत्येक आवासीय विद्यालय 500 सीटर क्षमता के हैं, यहां कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक 23,332 बच्चे अध्ययनरत् हैं । 652 शालाओं में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है, इन विद्यालयों में टूरिज्म एवं हॉस्पीटलिटी, पॉवर, अपैरल, हेल्थ केयर, रिटेल, टेलीकॉम जैसे 15 विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । (मेजों की थपथपाहट) पी.एम.धरती जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र हेतु छात्रावास निर्माण के लिये 30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । समग्र शिक्षा योजना में कार्यरत् संविदा अनियमित कर्मचारियों के ई.पी.एफ. भुगतान हेतु 7.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है । भारत सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में छत्तीसगढ़ हेतु 341 पी.एम.श्री स्कूलों का चयन किया गया है । वर्ष 2025-2026 हेतु राज्य सरकार द्वारा 277 करोड़ 84 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है । इन विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 के समस्त घटकों का प्राथमिकता से पालन किये जाने के लिये व्यवस्था है । पी.एम.जनमन के तहत छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजातियों जो पी.बी.टी.जी.कहलाते हैं, उनके शैक्षणिक विकास हेतु वर्ष 2023-2024 में 21 छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं, जिनके निर्माण के लिये 46.24 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । शिक्षा सत्र वर्ष 2025-2026 हेतु नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण से प्राप्त प्रमाणित छात्र संख्या के आधार पर किया जा रहा है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 द्वारा अनुसूचित उल्हास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम प्रदेश में संचालित है। इस हेतु छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में 10 लाख असाक्षरों को साक्षर किये जाने का लक्ष्य है । अब तक 8 लाख 86 हजार 843 साक्षरों को पंजीकृत किया गया है । 23 मार्च 2025 को आयोजित बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा में 5 लाख 9 हजार 910 शिक्षार्थियों को शामिल किया जा रहा है । वर्ष 2030 तक प्रदेश को शत-प्रतिशत साक्षर किये जाने का लक्ष्य है । राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 के तहत इस कार्यक्रम हेतु 8 करोड़ 63 लाख रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा से रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं और इसकी गुणवत्ता पर भी सरकार विशेष चिंता कर रही है । इसे देखते हुये उच्च शिक्षा के बजट में पर्याप्त वृद्धि की गई है । हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा के बजट में 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 2025-2026 में 1822 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । उच्च शिक्षा

विभाग के शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 को लागू कर दिया गया है । छत्तीसगढ़ को विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनाने के लिये छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन के लिये 50 करोड़ रूपये राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है । 25 जिलों में स्थित एक महाविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का लक्ष्य हमारी सरकार का है । इसके लिए 75 करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में किया जा रहा है । (मेजों की थपथपाहट) इस वर्ष 22 महाविद्यालयों के भवन निर्माण किये जाने हेतु 51 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है । प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों जैसे करडेगा, फरसाबहार जिला जशपुर, नगरनार किलेपाल जिला बस्तर, ग्राम कंतेली, जिला मुंगेली एवं रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर में नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु 6 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) रायगढ़ में नवीन संगीत महाविद्यालय तथा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है । दोनों महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 2 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है । अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए 13 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष हेतु 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । 13 महाविद्यालयों में स्थित छात्रावास भवनों के रेनोवेशन हेतु 3.9 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । 5 महाविद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल निर्माण के लिए 1.35 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । शासकीय महाविद्यालयों के मरम्मत हेतु 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर में 500 सीटर छात्रावास निर्माण हेतु 3 करोड़ तथा महाविद्यालय के बॉटनिकल गार्डन को ऑक्सीजोन बनाने हेतु 1 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । राज्य रिसर्च इनोवेशन योजना के लिए 3 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा संस्थाओं के आधारभूत संरचना का आईटी डेटा बेस बनाने और विभाग में ई एचआरएनएस डेव्हलप करने हेतु 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । महाविद्यालयों में वित्तीय साक्षरता संबंधी जागरूकता और अध्ययन कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है । उच्च शिक्षा संस्थानों को उद्योग के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु अकादमिक उद्योग सहयोग योजना शुरू करते हुए 1 करोड़ की राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सहभागिता से शैक्षणिक संस्था विकसित करने हेतु पीपीपी मॉडल के तहत 1 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 4 वर्षीय बी.एड कार्यक्रम को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किये जाने हेतु 1 करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में किया गया है । छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा विभाग का बजट राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा अधोसंरचना विकास, अनुसंधान, तकनीकी सुधार और नये विद्यालयों की स्थापना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने वाला है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुपालन को प्रोत्साहित करने और इसके माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 के बजट में 15.32 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 748.85 करोड़

रूपए का बजट प्रावधान किया गया है । पिछली कांग्रेस सरकार ने पशुधन विभाग के कामों के बड़े दावे किये, गौठानों की जांच के लिए जब हमारे पक्ष के लोग पहुंचे तो वहां की स्थिति बड़ी भयावह थी । अधिकांश गौठानों में गाय भी नहीं थी, गाय का चित्र तक नहीं था । जिन गौठानों में गाय थीं, वहां चारा नहीं था और पानी की व्यवस्था भी नहीं थी । गौठान समिति के नाम पर आने वाली राशि का [xx] किया गया । इस बार पशुधन विकास विभाग का बजट हमने 609 करोड़, 21 लाख, 84 हजार रूपए रखा है । हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पशुधन को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं । इसके लिए प्रोफेशनल एप्रोच बहुत जरूरी है । सौभाग्य से हमारे देश में अमूल के रूप में एक शानदार मॉडल है । राज्य में डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से 16 दिसम्बर, 2024 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ त्रिपक्षीय समझौते के पश्चात् 17 जनवरी, 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ का प्रबंधन एनडीडीबी के द्वारा ग्रहण किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) इससे डेयरी सहकारिता का कवरेज विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण प्रसंस्करण, अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन में सुधार, पशु प्रजनन, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य सेवा आयोग, प्रजनन और क्षमता निर्माण का विस्तार होगा । एनडीडीबी के डेयरी सहकारिता कवरेज के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण प्रसंस्करण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 624 गांव 13 हजार सदस्य संख्या एवं 68 हजार किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संकलन को वित्तीय वर्ष 2031-32 तक क्रमश: 4600 गांव, 1.3 लाख सदस्य संख्या तथा 7 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संकलन का लक्ष्य प्रस्तावित है, जो कि एनडीडीबी के सहयोग से होगा। तरल दूध बिक्री 45 हजार लीटर प्रतिदिन से 4.90 लाख लीटर प्रतिदिन, दुग्ध उत्पादों का थोक बिक्री के लिए दूध का उपयोग 23 हजार लीटर प्रतिदिन से 2.10 लाख लीटर प्रतिदिन, प्रशीतन क्षमता 1.13 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 7.61 लाख लीटर प्रतिदिन, प्रसंस्करण क्षमता 1.44 लाख लीटर प्रतिदिन से 07 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाना वर्ष 2031-32 तक सरकार का लक्ष्य है। प्रसंस्करण और अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत मुख्य डेयरी प्लांट उरला की मौजूदा क्षमता 1 लाख लीटर प्रतिदिन को एक नए स्वचालित डेयरी संयंत्र की स्थापना कर 3 लाख लीटर प्रतिदिन, कोनी डेयरी प्लांट बिलासपुर की क्षमता को नये डेयरी संयंत्र की स्थापना कर 20 हजार लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 50 हजार लीटर प्रतिदिन एवं जगदलपुर डेयरी प्लांट की क्षमता को नये डेयरी संयंत्र की स्थापना कर 10 हजार लीटर प्रतिदिन से 50 हजार लीटर प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, पशु आहार संयंत्र 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन, बाईपास प्रोटीन प्लांट एवं 15 मीट्रिक टन प्रतिदिन मिनरल्स मिक्चर प्लांट की स्थापना करने का लक्ष्य है। एनडीडीबी के साथ समझौता उपरांत उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2029-30 तक कुल राशि 676 करोड़ की आवश्यकता होगी, जिसमें राज्यांश राशि 296 करोड़, नाबार्ड से ऋण राशि 217 करोड़ तथा केन्द्रांश राशि

110 करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। इससे प्रदेश के पशुपालकों को दूध का उचित बाजार भाव मिलने पर डेयरी व्यवसाय आय का प्रमुख साधन बन जाएगा एवं प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में आशातीत वृद्धि भी हो पाएगी। डेयरी विकास अंतर्गत 62.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आदिवासी परिवारों को डेयरी व्यवसाय से जोड़ने हेतु प्रदेश के 6 जिलों क्रमश: जशपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 325 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 2 दुधारू गाय प्रदाय करने 7.62 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) बजट में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे 1700 हितग्राही लाभान्वित होंगे। भारत सरकार की परिकल्पना सहकार से समृद्धि अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों को सहकारी समिति से आच्छादित करने के अभियान अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 209 नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है। वर्तमान में कुल 1202 दुग्ध सहकारी समितियां गठित हैं, जिसमें से कुल 991 दुग्ध सहकारी समितियों का पंजीयन किया जाकर दुग्ध संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में 12 नवीन पशु औषधालय खोले जाने हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य में 366 पशु चिकित्सालय, 844 पशु औषधालय, 27 चलित चिकित्सा इकाई संचालित है, जिसके माध्यम से पशुओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु नवीन पशु औषधालय खोलने हेतु 3 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 20 पशु चिकित्सा संस्थाओं के लिए नवीन भवन निर्माण हेतु 3 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। जिला सक्ती, दुर्ग एवं गरियाबंद के एक-एक पशु चिकित्सालय, जिला रायगढ़ के दो पशु चिकित्सालयों एवं जिला बलौदा बाजार के तीन पशु चिकित्सालयों तथा जिला सक्ती, बलौदाबाजार, कांकेर, बिलासपुर एवं बेमेतरा के दो-दो पशु औषधालयों, जिला जांजगीर एवं बालोद के एक-एक पशु औषधालय के नवीन भवन निर्माण का भी बजट में प्रावधान किया गया है। व्यक्तिमूलक योजनान्तर्गत वार्षिक बजट में वृद्धि, पशुपालन को आजीविका का प्रमुख साधन बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा हितग्राहीमूलक योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने हेतु बजट में 5.44 करोड़ रुपए प्रावधानित किया गया है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सुकर पालन को बढ़ावा देने हेतु बजट में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान प्रदाय हेतु 1 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये अनुदान प्रदाय हेतु 1 करोड़ 80 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को बढ़ावा देने से गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम को गति प्रदान की जावेगी, जिससे दुग्ध उत्पादन में आच्छादित वृद्धि लायी जा सकेगी। कामधेनु विश्वविद्यालय अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु बजट में वृद्धि की गयी है। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय बिलासपुर के मुख्य भवन के प्रथम तल के निर्माण कार्य एवं उपकरण एवं फर्नीचर हेतु 4.62 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग अंतर्गत पशुधन

फार्म कॉम्प्लैक्स निर्माण हेतु राशि 2 करोड़ 30 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग हेतु निदेशक प्रक्षेत्र के 40 पदों एवं निदेशक विस्तार शिक्षा हेतु 6 पदों का श्रृजन करने हेतु 1.72 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वेटेनरी पॉलिटेक्निक महासमुंद में 50 सीट के बालक छात्रावास हेतु 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। मछली पालन कम लागत एवं कम समय में अधिक मुनाफे के कारण कृषि के सहायक व्यवसाय के रूप में ग्रामीण अंचल में अत्यंत लोकप्रिय है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सरल एवं रोजगारमुखी साधन है। स्वरोजगार का साधन होने के साथ-साथ मछली जैसे पौष्टिक खाद्य का उत्पादन बढ़ाकर कुपोषण दूर करने में अत्यंत प्रभावी है। मछली पालन विभाग हेतु वर्ष 2025-26 के बजट में 247.43 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 3.52 प्रतिशत अधिक है। हमारी सरकार कृषि अंतर्गत मछली पालन पर विशेष ध्यान देते हुए इस व्यवसाय से जुड़े मछुवारों के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। संचालित योजनाओं में मत्स्य बीज उत्पादन से लेकर मत्स्य उत्पादन, मत्स्य विपणन के कार्यक्रम लिये जा रहे हैं। राज्य गठन के पूर्व 1.47 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में मछली पालन हो रहा था, इसमें बढ़ोत्तरी करते हुए वर्तमान में 2.03 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र विकसित कर उन्नत किस्म का मछली बीज तथा मत्स्य उत्पादन कार्य किया जा रहा है। मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में हम 27.21 करोड़ वार्षिक उत्पादन से वृद्धि कर आज हम 572 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन कर रहे हैं तथा देश में 6वें स्थान पर है। (मेजों की थपथपाहट) इसी प्रकार मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भी राज्य 93 हजार मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन से प्रारंभ कर आज हम 7.81 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन विभिन्न तालाबों, जलाशयों एवं केज के माध्यम से कर रहे हैं। मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है। वर्ष 2030 तक हम इसे तीसरे या चौथे स्थान पर लाने के लिये प्रयासरत् है। हमारे राज्य का मत्स्य खपत 19 किलो प्रति व्यक्ति है, जो हमारे राज्य के लिये कुपोषण दूर करने का अच्छा स्त्रोत है। तीव्र बढ़वार वाली तिलापिया मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में हमारा राज्य अग्रणी है। पूरे देश के बराबर ही हमारे राज्य के निजी क्षेत्र में तिलापिया मत्स्य बीज उत्पादन हो रहा है। प्रदेश के तीन जिलों क्रमश: बलरामपुर, मोहला-मानपुर-चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में एक-एक सर्कुलल हेचरी सह संवर्धन पोखर निर्माण हेतु 2025-26 के बजट में 75 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इस तरह से और भी कई प्रयास मत्स्य के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में किये जा रहे हैं। हमारी सरकार मछली पालन में अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है। राज्य में परंपरागत मछली पालन के अलावा केज कल्चर, आर.ए.एस. बायो फ्लॉक एनिकट्स में तीव्र वृद्धि वाली मछली पंगेसियस, मोनोसेक्स, तिलापिया के पालन को बढ़ावा दिया जाकर 19.85 प्रतिशत मत्स्य पालन उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्तमान में 7.813 लाख मीट्रिक टन मत्स्य का उत्पादन हमारे प्रदेश में किया जा रहा है। राज्य

में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हुआ है। इसके अंतर्गत 272.90 हेक्टेयर नवीन जल क्षेत्र का निर्माण 122 बायो फ्लॉक पॉन्ड का निर्माण, 947 इकाई जलाशयों में केज की स्थापना 3 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, मछली चारा के रूप में आहार उपलब्ध कराने हेतु 20 टन एवं 8 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता की 2 इकाई फीड मिल स्थापित की गयी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि संकल्पना को साकार करने हेतु 206 नवीन मछुआ सहकारी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही 13 क्रियाशील मछुआ सहकारी समितियों को क्रियाशील किया गया है। कोरबा जिले में हसदेव बांगों जलाशय में एकीकृत मछली पालन एवं पयर्टन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क निर्माण किये जाने का भी प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, शताब्दियों तक भारत का जी.डी.पी. विश्व में सबसे अधिक रहा । इसका कारण हमारे मजबूत ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प रहे। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के हस्त शिल्प और ग्रामोंद्योग की परम्परा एक बार पुन: मजबूत हो चली है। छत्तीसगढ़ में भी हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग को मजबूत करने हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी की स्थापना करेंगे। ग्रामोद्योग विभाग के लिए 138 करोड़ 38 लाख 84 हजार रूपये का बजट प्रावधान किया गया है और इस क्षेत्र में हम लोग रेशम टसर निर्माण को विशेष बढ़ावा दे रहे हैं। नैसर्गिक टसर कोसा उत्पादन विकास योजना मद में 59 करोड़ 27 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। इससे 17 करोड़ 50 लाख रूपये टसर कुकुन का उत्पादन होगा। इसी प्रकार मलबरी रेशम विस्तार कार्यक्रम उत्प्रेरण विकास योजना मद हेतु 8 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। प्रशिक्षण एवं अनुसंधान योजना के अंतर्गत 76 लाख 60 हजार रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। जिसके अंतर्गत 550 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र में कोसा सिल्क, छत्तीसगढ़ के कोसा सिल्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अच्छा काम कर रही है। प्रदेश के बुनकरों को प्रशिक्षण, उन्नत करघे प्रदाय एवं कर्मशाला भवन आदि मद में समग्र हथकरघा विकास योजनान्तर्गत इस बजट में 5 करोड़ 7 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। बुनकर वर्कशेडस् आवास योजनान्तर्गत बजट में 4 करोड़ 90 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। खादी बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार मूलक इकाईयों की स्थापना के लिए बजट में 8 करोड़ 10 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। हस्त शिल्प विकास बोर्ड के परम्परागत शिल्पकरों को उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत औजार एवं मशीनरी उपलब्ध कराने हेतु बजट में 3 करोड़ 75 लाख 66 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2025-2026 में परचनपाल बस्तर में अंबिकापुर में कालीन बुनाई शिल्प, बेगनडीह सारांगगढ़ ढोकरा शिल्प में कुल 2 हजार 400 शिल्पियों को लाभांवित किया जायेगा। इसके लिए केन्द्र विस्तृत हस्त शिल्प कल्स्टर विकास योजना के अंतर्गत 7 करोड़ 20 लाख रूपये केन्द्रांश सहायता स्वीकृत है जबकि राज्यांश सहायता के रूप

में 1 करोड़ 80 लाख रूपये का प्रावधान बजट में रखा गया है। कुम्हारों को माटी कला बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2025-2026 में नि:शुल्क चाक वितरण हेतु 3 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने संस्कृति विभाग का बजट 58 करोड़ 67 लाख रूपया रखा है इसके तहत हम भारत भवन का निर्माण कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा तथा छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का निर्माण विविध कला संस्कृतिक केन्द्र एवं संग्रहालय, कला दीर्घा, ललित कला संग्रह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु इंडोर एवं आऊटडोर ऑडिटोरियम, रिहर्सल रूम, हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य हेतु पुस्तकालय, छत्तीसगढ़ फिल्म टेलिविजन बोर्ड का गठन तथा एफ.टी.आई.आई. की तर्ज पर एकादमी का निर्माण शामिल है। गोड़ी भाषा, हल्बी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। घोषणा पत्र के अनुसार 100 दिन के अंतर्गत चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत 6 हजार 208 रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन हेतु 3 करोड़ 10 लाख 40 हजार रूपये का बजट आवंटन, 33 जिला कलेक्टरों को प्रदान किया गया है।(मेजों की थपथपाहट) माननीय राष्ट्रपति जी के रायपुर प्रवास के अवसर पर दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 को पुरखौती मुक्तांगन नवा रायपुर में सरगुजा प्रखण्ड का लोकार्पण, आदिवासी लोक नृत्य की प्रस्तुति एवं आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद का आयोजन किया गया।(मेजों की थपथपाहट) बस्तर दशहरा 2024 के अवसर पर विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन में होने वाले कार्य व्यवस्था हेतु 40 लाख बजट आवंटन प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में जो कलाकार हैं, उनके भुगतान में भी भुगतान नियम 2021 में आंशिक संशोधन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति कला प्रदर्शन हेतु निर्धारित ग्रेड A-3 के लिये 10, A-2 के लिये 20 तथा B+, B श्रेणी के लिये 24 कार्यक्रम के अवसर अधिकतम सीमा में वृद्धि की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के लिये हमने 98 करोड़ 90 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा है। (मेजों की थपथपाहट) प्रदेश के पुरास्थलों के उत्खनन एवं संरक्षण के लिये 1 करोड़ 28 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा संरक्षित 63 प्राचीन मंदिरो, स्मारकों, पुरास्थलों और अवशेषों के रखरखाव, अनुरक्षण एवं विकास कार्य हेतु 1 करोड़ 20 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों, दस्तावेजों के digitalization हेतु राशि 3 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। सांस्कृतिक धरोहरों के प्रचार प्रसार एवं प्राचीन कलाकृतियों की प्रतिकृति तैयार कर धरोहर झरोखा निर्माण के लिये 57 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। कार्यशाला एवं संगोष्ठी आयोजन हेतु 86 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीमन सुतत हवय, ए मन ला जगा देव। अतेक बड़े होत हवय, रतिया हो गये, खातिर भले हम मन चल देबो।

श्रीमती भावना बोहरा :- पहले संख्या गिन ले।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर में बूढ़ापारा स्थित देव भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान के रूप में विकसित करने के लिये 4 करोड़ 80 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधान सभा भवन परिसर में संग्रहालय निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) राज्य के शासकीय, अर्द्धशासकीय स्कूलों, महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति जागरूक करने, गौरवशाली इतिहास से जुड़े विविध पक्षों को जानने, युवा पीढ़ी में धरोहरों के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना के लिये 44 लाख 70 हजार रुपये, मुख्यमंत्री विरासत धरोखा योजना के लिये 99 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ अपने अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक विविधता के लिये पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बना चुका है। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। वर्ष 2025-26 में पर्यटन विभाग के लिये 222 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।(मेजों की थपथपाहट) विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार हेतु 30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बृहद स्तर का पर्यटन इवेंट का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन समारोह W.T.M. London, ITB Berlin, A.T.M. Dubai, Fitur Madrid तथा अन्य देशों में सहभागिता कर छत्तीसगढ़ पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास जारी हैं। (मेजों की थपथपाहट) राज्य के पर्यटन स्थलों, रिसार्ट, छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, पर्यटन योजना आदि पर आधारित वित्त चित्र, प्रमोशनल वीडियो आदि निर्माण किया जायेगा। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड हेतु ई-गवर्नेंस तथा ई-ऑफिस के लिये लगभग 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। मेला उत्सव, प्रदर्शनी अनुदान मद के लिय 5 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन के लिये 1 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। श्री रामलला दर्शन योजना के लिये 36 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) सिरपुर को हेरिटेज स्थल के रूप में विकसित करने के लिये 10 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 एवं नवीन औद्योगिक नीति 2024 के अंतर्गत पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। (मेजों की थपथपाहट) पर्यटकों के लिये होम स्टे सुविधा एवं अन्य सब्सिडी देने के लिये इस योजना के अंतर्गत बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।(मेजों की थपथपाहट) adventure toruism विकास कार्य के अंतर्गत व्यापक पर्यटन नियोजन एवं अधोसंरचना विकास कार्य हेतु बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 1 हजार किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना की शुरूआत कर छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को उत्तराखंड की चारधाम परियोजना की तर्ज पर विकसित करने और जोड़ने का कार्य किया जाना है । (मेजों की थपथपाहट) अत: इस हेतु अनुमानित 112 करोड़ 16 लाख रूपये की लागत संभावित है अत:

प्रथम वित्तीय वर्ष में 2025-26 हेतु लगभग 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है इसके तहत् झुमकाबांध जिला कोरिया तथा घुनघुटा जलाशय जिला अंबिकापुर एवं तातापानी जिला बलरामपुर का सर्वांगीण विकास किया जायेगा । (मेजों की थपथपाहट) गिरौदपुरी धाम एवं छाता पहाड़ बांधा मुंगेली में गुरु बालकदास शहादत स्थल को तीर्थ रूप में विकसित करना राजिम माता मंदिर और राजिम के अटल बिहार व त्रिवेणी संगम का विकास किया जाएगा । (मेजों की थपथपाहट) बस्तर टूरिज्म के अंतर्गत जिला बस्तर में दंडामी लग्जरी रिसॉर्ट चित्रकूट ग्राम धुड़मारास, ग्राम नेंद्रीघुमड़ तीरथगढ़ जिला दंतेवाड़ा में ढ़ोलकल एवं बारसूर में पर्यटक रिसोर्ट वुडन कॉटेज एवं कैफेटेरिया निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) जशपुर टूरिज्म सर्किट अंतर्गत बलरामपुर जिला में सेमरसोत अभ्यारण्य एवं तातापानी जशपुर जिला में पण्डरापाट, जशपुर मयाली, कुनकुरी, कैलाश गुफा, सरगुजा जिला में मैनपाट, अंबिकापुर, कुरकुटरा महेशपुर एवं रामगढ़ में विभिन्न विकास कार्य हेतु 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) रायगढ़ जिला में नगरवन एवं पहाड़ मंदिर में पर्यटक रिसोर्ट, वुडनकॉटेज एवं कैफेटेरिया निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । मयाली जिला जशपुर, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव, चंपारण जिला रायपुर, उड़दना जिला रायगढ़ एवं कुरूद जिला धमतरी में विभिन्न पर्यटन संबंधी विकास कार्य हेतु 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय योजना के अंतर्गत नवा रायपुर में चित्रोत्तपला के अंतर्गत फिल्म सिटी निर्माण एवं नया रायपुर में कन्वेंशन सेंटर, लाइब्रेरी, जिम, रेस्टोरेंट आदि का निर्माण कार्य किया जाएगा इस हेतु भारत सरकार द्वारा 147 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है । (मेजों की थपथपाहट) जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में 97 करोड़ 46 लाख रुपए प्राप्त हुए तथा शेष 50 करोड़ 20 लाख वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त होगा । छत्तीसगढ़ टूरिज्म को बेस्ट रूलर टूरिज्म डेस्टिनेशन एवार्ड प्रदाय किया गया है । भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा द बेस्ट टूरिज्म विलेज काम्पीटिशन 2024 के तहत छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर के ग्राम धुड़मारास द बेस्ट विलेजेस एंड इन द एडवेंचर टूरिज्म 2024 के तहत ग्राम चित्रकोट का चयन किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित कुल 17 इकाईयों से 7 करोड़ 97 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है । पर्यटन में हम निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं इसके लिए हमने नई औद्योगिक नीति में आवश्यक प्रावधान किया है इस नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है तथा होम स्टे आदि के क्षेत्र में उद्यम करने वाली संस्थाओं को अनुदान के प्रावधान किए गए हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आस्थावान समाज ही मूल्यों को लेकर चलता है । वर्ष 2025-26 के लिए धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के लिए 49 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है । वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल नवीन योजनाओं के रूप में छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट

योजनांतर्गत अन्य राज्यों में भूमि क्रय हेतु राशि 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । इस योजना से अन्य प्रदेशों के प्रमुख तीर्थ स्थानों पर धर्मशाला बनाई जा सकेगी । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है । पिछली कांग्रेस सरकार ने मीडिया की जड़ों को कमज़ोर करने का काम किया था । कांग्रेस के 5 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा । उन्हें नौकरी से निकालने का दबाव डाला गया, जो लोग फिर भी नहीं माने उनकी नौकरी ही प्रबंधन को दबाव डालकर छीन ली गई और जो लोग इसके बावजूद भी नहीं माने तो उन्हें जेल में डाल दिया गया है । मीडिया और सरकार के बीच आम जनता की बेहतरी के लिए एक सकारात्मक संवाद का पुल बनता है, वह पुल पिछली सरकार के दौरान टूट गया । हमने इस संवाद सेतु को पुनः कायम किया है, उस समय पत्रकारिता जगत के कई लोग बताते थे कि ईमरजेंसी के जैसा वातावरण महसूस कर रहे हैं जहां लिखने-पढ़ने की आज़ादी पूरी तरह से खत्म हो गई है । अध्यक्ष महोदय, आम जनता तक शासकीय योजनाओं को त्वरित और आसानी से पहुंचाने तथा आधुनिक संचार प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों, फोटो-वीडियो एवं अन्य संदर्भ को एक स्थान पर एकत्रीकरण एवं अद्यतनीकरण का कार्य कन्टेंट स्टोर के तहत किया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) जनजातीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए तथा बस्तर मैराथन बस्तर मड़ई जैसे आयोजनों के प्रचार-प्रसार के लिए 19 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है। (मेजों की थपथपाहट) पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए हमने 2 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान रखा है। (मेजों की थपथपाहट) वरिष्ठ पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान निधि को 10,000 रूपये से बढ़ाकर 20,000 रूपये प्रति महीना कर दिए हैं। (मेजों की थपथपाहट) रायपुर प्रेस क्लब के रिनोवेशन के लिए 1 करोड़ रूपये का प्रावधान बजट में किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) बस्तर और सरगुजा में पर्यटन के प्रचार-प्रसार के लिए 8 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है। अध्यक्ष महोदय, पुनर्वास कार्यों के लिए पिछले साल की तुलना में इस साल 4 प्रतिशत अधिक 2 करोड़ 86 लाख रूपये का बजटीय प्रावधान रखा गया है। हमारी सरकार पुनर्वास नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाकर प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए संकल्पित है। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में 208 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत से सलाह दिए हैं, जिसमें नौकरियों में भर्ती की भी बात उन्होंने कही थी। मैं उनको बताना चाहूंगा कि विभिन्न विभागों में भर्ती की प्रक्रिया जारी है। पुलिस डिपार्टमेंट में, इरिगेशन में, बिजली विभाग में 7-8 हजार लोगों की नियुक्ति हो भी चुकी है और लगातार जारी भी है। छत्तीसगढ़ सूचना आयोग की भर्ती प्रक्रिया जारी है, इसके लिए विज्ञापन निकल चुका है। ऊर्जा की बेहतरी के लिए भी आपने चिंता की, उसके लिए हम बता ही चुके हैं और जनसंपर्क विभाग के काम के विषय में भी

चिंता कर रहे थे, इस बार प्रयाग में जो महाकुंभ हुआ, उसमें अकेला छत्तीसगढ़ प्रदेश था, जिसने साढ़े चार एकड़ में अपना पवेलियन वहां पर स्थापित किया था। (मेजों की थपथपाहट) अब इसमें 25-30 हजार से भी ज्यादा लोग जो हमारे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु थे, वहां पर उसका लाभ उठाएं और उसकी प्रशंसा सर्वत्र हुई और हेलिकॉप्टर की भी आप चिंता कर रहे हैं तो इसकी खरीदी की भी प्रक्रिया जारी है। (मेजों की थपथपाहट) सी.एम. जनदर्शन का कार्यक्रम बंद नहीं हुआ है, जैसे हमारे गृह मंत्री जी बता रहे थे कि ये चुनाव, आचार संहिता के कारण से ये गैप हुआ है, लेकिन इसको फिर शीघ्र शुरू करने वाले हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पुनर्वास में बोल रहे थे तो बघेल जी का स्थायी पुनर्वास पंजाब में हो जाये, उसके लिए अलग बजट कर दीजिए।

श्री विष्णु देव साय :- बाकी और सलाह हम नोट कर लिए हैं, आपके अच्छे सुझाव के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में सम्माननीय सभी सदस्यगणों से आग्रह करूंगा कि हमारे विभाग से संबंधित कुल 19 हजार 643 करोड़ 78 लाख 42 हजार रूपये की जो अनुदान मांग है, उसे सर्वसम्मति से पारित करें। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या -1, 7, 12, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 56, 60, 65, 71, 26, 27, 37, 44, 51 एवं 77 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 1 सामान्य प्रशासन के लिए- पांच सौ पच्चीस करोड़, उनतीस लाख, सोलह हजार रूपये,

मांग संख्या - 2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए- पैंतीस करोड़, चौवन लाख, अन्ठावन हजार रूपये,

मांग संख्या - 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिए- चार सौ तिरसठ करोड़, उनहत्तर लाख, चौतीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिए- तीन हजार एक सौ सतासी करोड़, पैतालीस लाख, बयासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिए- छः सौ नौ करोड़, इक्कीस लाख, चौरासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 16 मछली पालन के लिए- अन्ठानबे करोड़, सैतीस लाख, सात हजार रूपये

मांग संख्या - 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिए- नौ सौ सड़सठ करोड़, नवासी लाख, निन्यानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 32 जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिए-पांच सौ बावन करोड़, चौतीस लाख, चौरानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 35 पुनर्वास के लिए- दो करोड़, छियासी लाख, अड़तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 36 परिवहन के लिए- दो सौ सात करोड़, उन्यासी लाख, निन्यानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 56 ग्रामोद्योग के लिए- एक सौ अड़तीस करोड़, अड़तीस लाख, चौरासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए- दो सौ आठ करोड़, पचास लाख रूपये,

मांग संख्या - 65 विमानन विभाग के लिए- एक सौ अन्ठावन करोड़, तिरसठ लाख, चौसठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए- तीन सौ उन्यासी करोड़, निन्यानबे लाख, अन्ठानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिए- नब्बे करोड़, तिहत्तर लाख रूपये,

मांग संख्या - 27 स्कूल शिक्षा के लिए- दस हजार तीन सौ सैतालीस करोड़, सात लाख, निन्यानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 37 पर्यटन के लिए- दो सौ बाईस करोड़ रूपये,

मांग संख्या - 44 उच्च शिक्षा के लिए- एक हजार दो सौ चौरासी करोड़, अट्ठाइस लाख छिहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए- उनचास करोड़, तीस लाख रूपये तथा

मांग संख्या - 77 सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय के लिए- चौहत्तर करोड़, सैतीस लाख, दस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

समय :

9:03 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4, सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(09 बजकर 03 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 (फाल्गुन 29, शक सम्वत् 1946) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 19 मार्च, 2025